राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] **बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का चौथा दिवस** **[संख्या : 4**

गुरुवार;

21 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

संसदीय सचिव नियुक्ति विवाद पर सदन की समिति का गठन

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब। मुझे माननीय सदस्यों को व सदन को यह सूचित करना है कि सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता व दोनों दलों की ओर से मिल-जुलकर के यह निर्णय ले लिया गया है कि यह जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी इसके लिए कमेटी बना दी जाएगी हाउस की और वह कमेटी दो-चार दिन के अंदर यह तय कर देगी कि इसके अंदर एडवोकेट जनरल ने जो राय दी है उस पर आगे क्या निर्णय लिया जाए और इससे जो विवाद था वह करीब करीब समाप्त हो जाएगा। मैं इसके लिए सभी सदस्यों को और सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि सदन जो है वह शांतिपूर्वक सब के सहयोग से चले।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद): एक मिनट सुन तो लें आप, जिस तरह से सत्तापक्ष ने और प्रमुख विपक्षी दल तीन दिन से ...(व्यवधान) मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन कल जिस तरह माननीय सदन की नेता ने प्रतिपक्ष के नेता के साथ व्यवहार किया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह बात तो खतम हो चुकी है माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य वह बात आपस में ...(व्यवधान) समझौता हो चुका है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अगर जनतंत्र में ऐसा व्यवहार सदन की नेता ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समझौता हो चुका है, प्रतिपक्ष के नेता ने समझौता कर लिया है ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने बैठकर फैसला कर लिया है उस पर आप टीका टिप्पणी ...(व्यवधान) अब ये और क्या कहना चाहते हैं इसमें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान) माननीय सदस्य

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह सरकार प्रतिपक्ष के नेता का और राजस्थान की जनता का ...(व्यवधान) इसके लिए पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए ...(व्यवधान) जिस तरह से प्रहार किया यह निंदनीय है और सरकार की ओर से मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नंदीग्राम की बात कहलाई जाए इनसे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नंदीग्राम में कम्युनिस्टों ने कितने लोग मार दिए ...(व्यवधान) कम्युनिस्टों ने कितने लोग मार दिए नंदीग्राम में, तुम्हारी जुबान छीन गई क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य वह बात समाप्त हो चुकी है, उस बात को समाप्त कर दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बोला कि माफी मांगनी पड़े ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह तो नंदीग्राम के हत्यारे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सब ने राजस्थान की जनता के साथ ...(व्यवधान) सबको माफी मांगनी चाहिए ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता के साथ ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदन की नेता इस तरह का व्यवहार करेगी ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अशांति फैला रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में गुण्डागर्दी कर रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य मैं अलाऊ नहीं करूंगा, सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान) कह दी आपने बात, आप स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन की नेता का जो व्यवहार था निश्चित रूप से ...(व्यवधान) सत्तापक्ष की नेता का व्यवहार इस प्रकार का रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य चर्चा नहीं होगी इस पर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) जब सारी चर्चा हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी वह बात समाप्त हो चुकी है। वह चर्चा का विषय नहीं हो सकती, वह बात समाप्त हो चुकी है। माननीय सदस्य वह बात आपस में बैठकर समाप्त हो चुकी है। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा ...(व्यवधान) ऐसा कुछ नहीं कहा माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह सवाल सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता का सवाल नहीं है, यह इस सदन के नेता का सवाल है, यह राजशाही इस हाउस में नहीं चल सकती ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य वह बात समाप्त हो चुकी है, वह आपस में बहस करके समाप्त हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सवाल नेता और प्रतिपक्ष के नेता का नहीं है, यह सवाल सदन का है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): जब सारी बातें तय हो चुकी हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता को प्रतिपक्ष की पार्टी मानती नहीं है असली बात तो यह है ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष भी उसमें थे, माननीय सी.पी. जोशीजी उसमें थे और माननीय अमरारामजी भी उसमें थे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए मैं प्रश्नकाल शुरू करता हूं। श्री केशर देव बाबर।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांधीजी पर तो कम से कम बोलिए। गांधीजी की जब से यहां तस्वीर लगी है गांधीजी की आत्मा बराबर रो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनकी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद जो चाहे कहिए, बात तो आपको सुननी पड़ेगी ...(व्यवधान) यह भी एक पार्टी के नेता हैं ...(व्यवधान) बीच में मदन दिलावरजी खड़े हों जिनका कोई लेना देना नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कर दीजिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके वैश्म में उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और अन्य सभी लोगों ने आपस में विचार-विमर्श करके यह तय किया ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता विधान सभा में ऐसा सोचती है कि उनके हितों के मुद्दों पर यहां चर्चा होगी, सारी चर्चा समाप्त हो चुकी है और आपको सिर्फ वहां से व्यवस्था देनी थी इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को दबाने की बात है, आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी। आखिर यह एक पार्टी को ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी बात सुननी पड़ेगी, हम भी बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उनको बोलने नहीं देते हैं ...(व्यवधान) उनकी बात सुननी पड़ेगी ...(व्यधान)

श्री उपाध्यक्ष: **श्री केसरदेव बाबर**। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न संख्या-41

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, कल जो सदन में हुआ उससे सारा राजस्थान लज्जित और ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। बोलने का मौका, आवश्यकता होगी ...(व्यवधान) आप कोई प्रस्ताव लेकर आइए।

तारांकित प्रश्नोत्तर

लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर में ''अम्ब्रेला योजना'' की क्रियान्विति

41. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का अधिकांश भाग फ्लोराइडयुक्त है? यदि हां तो इसके निराकरण हेतु क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला सीकर के फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र को फ्लोराइड युक्त करने हेतु ''अम्ब्रेला योजना'' प्रस्तावित है? यदि हां तो उक्त योजना का लाभ कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) जी हां। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहर लक्ष्मणगढ़ एवं 164 ग्राम तथा फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के शहर फतेहपुर एवं रामगढ़ शेखावाटी तथा 119 गांवों में मानदण्ड अनुरूप गुणवत्ता एवं मात्रा का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ''अम्ब्रेला परियोजना'' के अन्तर्गत प्रस्ताव जांच प्रक्रिया में है।

योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

(2) उपरोक्तानुसार।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर शोर-शराबा करना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) सदन की थोड़े ही है चाहे जब खड़े हो जाए, यह सवाल पूछ रहे हैं, वह जवाब देना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) स्वीकृति जारी करने का प्रयास किया है मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा ...(व्यवधान) इस योजना में कितनी लागत आएगी? इस योजना के तहत कितने कलस्टर बनेंगे और इसका काम कब शुरू किया जाएगा?

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर शोर-शराबा करना)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): क्वेश्चन ऑवर चलने दो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) इस योजना के लिए पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से धन्नासर हैड वर्क्स से आएगा ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं होगा, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) आपणी योजना फेज द्वितीय ...(व्यवधान) के उपरांत टेण्डर इंवाइट करके इस योजना को प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीकर जिले में गत सरकार ने कितने नलकूप लगाये, कितने हैंडपंप लगाये, कितने ट्यूबवैल लगाये और वर्तमान सरकार ने इन चार सालों में सीकर जिले में कितने ट्यूबवैल लगवाये ...(व्यवधान) कितना खर्चा किया?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने पांच साल में 47 करोड़ रुपये खर्च किये और इस सरकार ने चार साल में 80 करोड़ रुपये खर्च किये। (व्यवधान) 5.356 किलोमीटर गत सरकार ने पांच साल में डलवायी और इस सरकार ने 730 किलोमीटर पाइपलाइन चार साल में डलवायी और 595 हैंडपंप गत सरकार ने पांच साल में लगवाये और इस सरकार ने 4109 ...(व्यवधान) गत सरकार ने 628 और इस सरकार ने 570 स्वीकृत कर लगाये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मैं धन्यवाद देता हूं मेरे क्षेत्र की ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, परमीशन से बोलिये। परमीशन से बोलिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य आपका।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम (धोद)। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बिना परमीशन के नहीं बोलें। आप स्थान ग्रहण करें नहीं तो आसन को मजबूर होकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई कुछ नहीं कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, श्री अमराराम (धोद)।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अमराराम (धोद): प्रश्न संख्या 43

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(श्री अमराराम, धोद, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम (धोद)। ...(व्यवधान) बैठिये। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्न संख्या 43 सहकारिता मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न संख्या 43 सहकारिता मंत्री।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप विराजिए आपकी बात सुनी जायेगी।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): हाउस आर्डर में आयेगा तभी तो उत्तर दूंगा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(तारांकित प्रश्न संख्या-42)

(स्थगित)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा फसली ऋण पर ब्याज

43. **श्री अमराराम** (धोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा नए सदस्यों को फसली ऋण नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

(2) दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक वितरित ऋण में पुराने एवं नये सदस्यों का प्रतिशत क्या है तथा ब्याज दर क्या लगाई जाती है?

(श्री अमराराम धोद)

(3) क्या यह सही है कि किसानों से मूल ऋण से दुगनी से ज्यादा राशि वसूल नहीं किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या उनकी अनुपालना की जा रही है। यदि हां, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (डा. एन.एस. गुर्जर): (1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पुराने एवं नये सदस्यों को फसली ऋण वितरित किये जा रहे हैं। नये सदस्यों को फसली ऋण वितरित करने पर वर्तमान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक वितरित ऋणों में पुराने सदस्यों का प्रतिशत 96.17 रहा, जबकि पहली बार प्राप्त करने वाले सदस्यों का प्रतिशत 3.83 रहा। वर्तमान में ब्याज दर 7 प्रतिशत है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पुराने और नये सदस्यों का क्या प्रतिशत है। आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं है तो सीकर जिले में जितने नये सदस्य थे जिन्होंने सदस्य बनने के बाद लोन नहीं लिया उनकी साख सीमा क्यों नहीं बनाई गई और पूरे राज्य में इसके लिये लोन क्यों नहीं दिया गया। बकायादारों से मूलधन से ज्यादा ब्याज लेना क्या न्यायोचित है। बकाया जमा कराने के बाद 7 दिन के बाद वापस ऋण दिया जाता है जबकि बाकी बैंकों में नेक्स्ट दिन लोन दिया जा सकता है। चौथा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों पर 100-100 करोड़ की बकाया होने पर भी उनका नाम नहीं बताया जाता है जबकि सहकारी बैंकों में 5-7 हजार बकाया रहने पर ही वहां फोटो लगाकर गांव में ढोल पीट कर उसकी सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है, क्या यह न्यायोचित है। क्या इसको बंद करने का सरकार इरादा रखती है या नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह नये और पुराने का हमारे यहां नहीं चलता यह निरन्तर प्रक्रिया है। यह जो सोसायटी होती है इसमें जो पैसा होता है वह किसानों का पैसा होता है। जो 2001 के पहले का जो प्रावधान था, उसको 2001 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और समाप्त इसलिए किया

(डा. एन.एस. गुर्जर)

गया क्योंकि उसमें किसानों का ही पैसा लगा हुआ है और अगर लोन वापस नहीं आयेगा तो ज्यादा लोगों को लोन दे नहीं सकते, बैंक की स्थिति खराब हो जायेगी, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। दूसरा जहां तक कहा कि नयों को नहीं दिया जाता है, पुरानों को नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यह निरन्तर प्रक्रिया है। सदस्य कोई भी बन सकता है लेकिन जिसके पास जमीन है साख सीमा उसकी तय करते हैं, उनमें जितना हमारे पास पैसा उपलब्ध होता है उसको बांटा जाता है। अब जितना पैसा उपलब्ध होगा उतना ही तो बांटा जायेगा उसके अलावा तो हम बांट नहीं सकते। इसलिए इसमें कोई रोक नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भीलवाड़ा जिले में भी नहीं दिया जा रहा। आप स्थिति पता कर लें।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन रिकार्ड कहना चाहता हूं कि ऐसी कहीं कोई रोक नहीं है कि जो पहली बार सदस्य बना है और जिसकी साख सीमा बनी हुई है और जमीन है उसको लोन पर कोई पाबंदी लगा रखी है ऐसा कहीं कोई सरकार का आदेश नहीं है। जितना पैसा उपलब्ध है, यह बात सही है कि कई बार पैसा लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होता है और लेने वाले ज्यादा हैं तो उसमें वह यह देखते हैं कि जो टाइम पर जमा करा रहा है उसको पहले देते हैं और जो डिफाल्टर हो जाता है उसको नहीं देते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का पैसा है और इसलिए 2001 में उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि जो ऋण चुकाता है, मैं कह रहा हूं जो पहली बार सदस्य हुए हैं, सीकर जिले में जो पहली बार सदस्य हैं, बने हैं न उनकी साख सीमा बनाई गई न उनको लोन दिया गया है। अगर प्रतिबंध नहीं था तो वहां के को-आपरेटिव बैंक के एमडी ने साख सीमा क्यों नहीं बनाई, नये सदस्यों को आज तक एक भी लोन नहीं दिया गया और दिया हो तो आप बता दें। सीकर जिले में जो पहली बार नये सदस्य बने हैं...(व्यवधान) मैं पहले प्रश्न तो पूछ लूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने लोन टाइम पर दे दिया उनको देते हैं, लिमिट हो सकती है कि इतना लोन सीकर में सहकारी बैंक को देना है लेकिन जो सदस्य पहली बार बने हैं उनकी साख सीमा नहीं बनाने, आर्डर नहीं होने के बाद भी उन्होंने नहीं बनाया तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

(श्री अमराराम)

या आप यह बता दें कि जो नये सदस्य बने हैं जिन्होंने एक बार भी लोन नहीं लिया है उनकी साख सीमा बनाई है तो आप वह संख्या बता दीजिए। सीकर में तमाम सोसायटी के अध्यक्ष सभा करके कलक्टर के पास गये हैं, जो प्रशासक हैं और आज तक उनकी साख सीमा नहीं बनाई गई और न उनको लोन दिया गया। सरकार का आदेश नहीं होने के बाद जिन्होंने ऐसा काम किया उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं और जो मूलधन से कई गुना ज्यादा ब्याज ले रहे हैं उसको निरस्त करके मूलधन के बराबर ही ब्याज लेने का क्या सरकार इरादा रखती है।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो मेरे पास ईयर वाइज राजस्थान के फीगर भी हैं कि कितने नये सदस्य जो पहली बार बने हैं उनको ऋण दिया गया है और सीकर जिले का पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिये कि वर्ष 2004-05 में सीकर में 2765 नये सदस्य ....

श्री अमराराम (धोद): मैं इस साल की पूछ रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इस साल की सुनिए, आप सुन लीजिए। बता रहा हूं ना आगे आप सुनिये। 6-7 की बता देता हूं। 2006-07 में 1067 नये सदस्यों को फसली ऋण दिया गया है और जहां तक इस साल का सवाल है वह फीगर अब आयेंगे।

श्री अमराराम (धोद): अब कहां से आयेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): क्यों नहीं आयेंगे।

श्री अमराराम (धोद): मैंने सवाल ही इस साल का पूछा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 2004-05 का बता रहे हैं, मैंने इस साल का पूछा है।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 6-7 का बता रहा हूं ना।

श्री अमराराम (धोद): 7-8 की साख सीमा बन गई, साख सीमा बनने के बाद लोन फाइनेंस कर दिया, रबी की फसल पाले से मारी गई और अब आप कह रहे हैं कि इस साल के आंकड़े अब आयेंगे। विधान सभा के प्रति यह विभाग और मंत्री कोई जवाबदेह नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा है इस विधान सभा के लिये और वह उत्तर बाद में आयेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो इन्होंने प्रश्न में सीकर का कहीं जिक्र ही नहीं किया है, राजस्थान का किया है।

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान का कर दिया और अब सप्लीमेंट्री सीकर का पूछ लिया तो अन्याय कर दिया मैंने। मैंने पूरे राजस्थान का पूछा है और उसमें सीकर का स्पेसिफिक पूछ लिया तो ...

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप सीकर का पर्टीकुलर पूछते तो हम देते लेकिन फिर भी 6-7 के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं ....

श्री अमराराम (धोद): मैं 7-8 का पूछ रहा हूं यह 6-7 का बता रहे हैं। 7-8 जो चल रहा है मैं उसका पूछ रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): 7-8 तो अभी चल रहा है।

श्री अमराराम (धोद): उसका फाइनेंस कर दिया, रबी की फसल में साख सीमा बन कर खतम होने जा रही है और आप कह रहे हैं कि उत्तर अब आयेगा, क्या उत्तर आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष: चल रहा है, चल रहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी रोक नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): मैं कह रहा हूं कि जब रोक नहीं है तो फिर जिन्होंने नहीं दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, वह बताइए।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप विराजिए, यह सुनते भी नहीं है और बोले जा रहे हैं। मेरा उत्तर सुनिए पहले। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सीकर का पूछा मेरे पास 6-7 के आंकड़े हैं, 5-6 के आंकड़े मेरे पास हैं। इन्होंने अभी 7-8 का पूछा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 7-8 के भी अगर यह चाहेंगे तो मैं इनको आंकड़े लाकर उपलब्ध करा दूंगा कहीं कोई रोक नहीं है। राजस्थान के फीगर चाहते हैं तो वह फीगर भी मेरे पास हैं। यहां नये पुराने सदस्य कोई नहीं है। सवाल यह है कि वह उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं और साख सीमा बनी है तो उसको हम लोन देते हैं । लेकिन जितना पैसा उपलब्ध होता है उसी में से उनको लोन बांटा जाता है। ऐसा नहीं है, आप मुझे उदाहरण दें कि इतना पैसा उपलब्ध था इतना इन्होंने रख लिया और नहीं दिया और इतने लोगों ने मांगा, उसमें कोई गफलत हुई हो तो वह बताइये, मैं उसको दिखवा सकता हूं। (व्यवधान) लेकिन आप कहते हैं किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ऐसा कहीं नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि केवल यह जो सात प्रतिशत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हो गया।

श्री अमराराम (धोद): जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं 12 से 7 प्रतिशत की है ब्याज दर उससे बचने के लिए को-आपरेटिव बैंक ने पूरे राजस्थान में जिन सदस्यों ने जो नये बने, आज तक जिन्होंने लोन नहीं लिया, नये और पुराने का मैं इतना ही कह रहा हूं जिन्होंने लोन ले लिया वह पुराने हैं, जिन्होंने आज तक लोन नहीं लिया वह संख्या बता दीजिए सीकर में, कि सीकर को-आपरेटिव बैंक में ऐसे सदस्य जिन्होंने एक दफा भी पिछले साल तक लोन नहीं लिया, उन्होंने इस साल लोन लेने के लिए कहा, बैंक ने उनकी साख सीमा नहीं बनाई, रोक नहीं होने के बाद अगर नहीं बनाई साख सीमा, उनके पास जमीन उपलब्ध है उन्होंने साख सीमा नहीं बनाई न उनको फसली ऋण दिया और इसके लिए तमाम राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर सीकर को-आपरेटिव सोसाइटी के तमाम अध्यक्षों ने सम्मेलन करके एम डी और प्रशासक, जिला कलक्टर के सामने प्रदर्शन किया है, अब आप उनकी संख्या बता दीजिए। नहीं बनाया उनमें आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं पूरे राजस्थान का पूछकर, सीकर का स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, नम्बर बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सीकर में....

श्री अमराराम (धोद): साख सीमा नहीं बनाई, इन अधिकारियों ने क्यों नहीं बनाई, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यह बताइये। 2004-05, 2006-07 का मैं पूछ नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि रोक नहीं सकते, जितना पैसा उपलब्ध होगा बैंक में.... (व्यवधान) साख सीमा बनाना अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष: क्रेडिट खतम हो जाएगी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जितना उपलब्ध होगा उतना... (व्यवधान) एक मिनिट सुनिये, जितना पैसा उपलब्ध होगा वह ही दिया जाएगा। सीकर की यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिया, यदि पैसा उपलब्ध है...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप तो कह रहे हैं धन की कमी नहीं है...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सुनिये, आप सुन लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सरकार तो कह रही है धन की कमी नहीं है, आप तो कह रहे हैं..(व्यवधान) धन की कमी नहीं है तो क्यों नहीं उपलब्ध है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यदि पैसा उपलब्ध है और साख सीमा भी बना दी गई.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने सीकर के बारे में स्पेसिफिक पूछा भी नहीं है। सीकर के बारे में आपने स्पेसिफिक पूछा भी नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री में सीकर का पूछ रहा हूं। राजस्थान के बाहर नहीं है सीकर।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सीकर राजस्थान से बाहर है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: किसी बेसिक का पूछने लग जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ऐसे सदस्य जिन्होंने अभी तक लोन नहीं लिया उनकी संख्या क्या है, उनकी साख सीमा बनाई गई है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप बैठो तो सही, सुनिये (व्यवधान) आप बोले जा रहे हो, एक ही बात रिपीट करते जा रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार कह रही है धन की कमी नहीं है, एक तरफ किसानों के लिए धन नहीं है, इससे बड़ा अन्याय आप क्या करेंगे? (व्यवधान) एक तरफ तो कह रहे हैं राजस्थान में धन की कमी नहीं है, एक तरफ तो सरकार कह रही है, धन की कमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मूल रूप से एक ही बात है कि मूल धन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाये, मंत्री महोदय इसका उत्तर दें, क्या सरकार विचार रखती है, मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा कम से कम यह तो कर दो। पुराने वाले कर गये तो वह भोगेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे थे कि धन की उपलब्धता को देखते हुये ऋण वितरण किया जाए, आपका खजाना तो भरा हुआ है और उस पर आप पालथी मार कर बैठ

(श्री हेमाराम चौधरी)

गये, लोगों को लोन दे नहीं रहे हो तो फिर यह खजाना भरा ही रहेगा खाली कहां से होगा। आप इस खजाने को खोलिये। किसानों को ऋण दीजिए। सात प्रतिशत ब्याज पर मिल रहा है, पहले ब्याज ज्यादा था अब ब्याज कम हुआ, सात प्रतिशत केन्द्र सरकार ने किया है, उनको लोन दीजिए, लोग खेती करें, रोजगार कर अपना पालन पोषण करें। खजाना...(व्यवधान) इस तरह से पालथी मार कर बैठ जाएंगे तो भरा ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की चिंता कहां से होगी, मंत्री को, डेली अख़बार में आता है भ्रष्टाचार...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, एक तरफ तो कह रहे हैं धन की कमी नहीं है एक तरफ कर्जा माफ नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक एक का नाम पुकारिये। एक साथ चार आदमी खड़े हैं। (व्यवधान) एक, दो, तीन, चार, उत्तर कैसे देंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या सात प्रतिशत ब्याज दर की गई है यह पुराने जो लोग ऋणी हैं उन पर भी करेंगे? श्रीमती वसुन्धराजी राजे ने अपने चुनाव अभियान में दस हजार का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी... (व्यवधान) लेकिन पूर्व सहकारिता मंत्रीजी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, क्या नये सहकारिता मंत्री उस ढोल को बंद करेंगे और लोगों की कुड़कियां बंद करके जो यह मूल प्रश्न है कि मूलधन से ब्याज ज्यादा नहीं होना चाहिए उस पर विचार करके कोई निर्णय करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री अशोक कुमार नवलखा। (व्यवधान) मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसके बारे में स्पेसिफिक आप कोई प्रस्ताव लाकर के, यह ऐसा एकदम से ऐसा इश्यू नहीं है कि यहीं पर सारी की सारी बातें तय हो जाए। प्रश्न के अंदर जो जवाब था वह जवाब आ चुका है। श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ढोल बजाना शुरू किया था उसको बंद कर दें, हम तो यही चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप बिराजिए, मैं खड़ा हूं। एक मिनिट सुनिये तो सही।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मंत्रीजी यह बतायें कि क्या मूलधन का जो ब्याज है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक एक करके पूछें जवाब दे देंगे। बिना अनुमति के बोलना चालू कर देते हैं, आपकी अनुमति तो मांगें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कोई बारात आई हुई है क्या, कोई बारात आई हुई है क्या एक-एक ही तो पूछ रहे हैं। क्या बाहर से कोई बारात आई हुई है क्या, एक-एक ही तो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने प्रश्न पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या मूलधन के ब्याज के बराबर का जो ब्याज है वह ले रहे हैं या उससे अधिक लेने की इच्छा रखत हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात आपकी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह से...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बोल रहा हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने ऐसा सवाल पूछा है यह बैंक्स है जेएसएस, सीसीपी इसका आपको शायद यह पता होना चाहिए कि इनका पैसा कहां से आता है और किस प्रतिशत में कहां से आता है, क्या सिस्टम है, कुछ तो सदस्यों का पैसा होता है...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी चेयरमैन रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। (व्यवधान) शेयर मनी होता है (व्यवधान) यही मैं बोल रहा हूं। किसानों का पैसा होता है और किसानों का पैसा होने के कारण उस पर, 2001 में इन्हीं की सरकार थी तब इन्होंने यह कहा कि जो एक्ट में शर्त थी पहले उसको 2001 में इन्होंने ही हटाया कि बैंक डूब न जाए..(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): बैंक डूब नहीं जाए। हमने तो उस शर्त को नहीं हटाया, इन्होंने ही हटाया। एक्ट में पहले प्रावधान था, 2001 में आपने ही हटाया है ...(व्यवधान) नक्शे कदम का सवाल नहीं है ...(व्यवधान) सुनिये, बार-बार, बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं, यह नंदीग्राम थोडे ही है जो बार-बार, बीच-बीच में खड़े हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं फिर कह रहा हूं कि बैंक बैठ नहीं जाए, जिन लोगों की आदत है बार-बार लोन कई साल तक ले लेते हैं और देते नहीं है, फसली ऋण, फसली ऋण का मतलब यह है फसल आते ही ऋण लिया और उसको वापिस जमा करा दिया जाएगा यह कोई लोंग टर्म लोन नहीं है इसलिए इसके लिए यह व्यवस्था की गई। यह पैसा टाइम पर आये और ज्यादा किसानों को वापिस दिया जा सके और उनको लाभ मिले। अब एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि ज्यादा लोन दीजिए दूसरी तरफ कह रहे हैं उस कंडीशन को समाप्त कीजिए, यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। 2001 के अंदर इन्हीं की सरकार ने वह प्रस्ताव लाकर जो एक्ट में प्रावधान था उसको डिलिट किया। आज एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक नवलखा। (व्यवधान) प्रश्न के अंदर यह तय है कि...(व्यवधान) श्री अशोक नवलखां।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्री अशोक नवलखा।

ग्राम गणेशपुरा (छोटी सादड़ी) में आश्रम छात्रावास

44. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति उपयोजना एवं माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड बनाये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में रहने वाले एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये आश्रम छात्रावास स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में कितने आश्रम छात्रावास कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

(3) क्या सरकार छोटी सादड़ी तहसील के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में आश्रम छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): (1) अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में नवीन आश्रम छात्रावास के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है:

1. प्रस्तावित छात्रावास के नजदीकी विद्यालय में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं।

2. प्रस्तावित छात्रावासों से कितनी दूरी पर वर्तमान में छात्रावास संचालित हैं, उसकी क्षमता क्या है व उसमें कितने जनजाति छात्र/छात्रायें निवास कर रहे हैं।

3. प्रस्तावित छात्रावासों के लिये जिला कलक्टर द्वारा कितनी दूरी पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जावेगी।

4. प्रस्तावित छात्रावासों का स्तर एवं क्षमता क्या होगी।

5. ब्लाक स्तर पर बालक/बालिका का शैक्षणिक स्तर क्या है।

(2) जी हां। जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो नवीन छात्रावास खोलने के बारे में जो बिन्दु बताये हैं, क्या मैंने जिस छात्रावास को खोलने की बात रखी है, वह गणेशपुरा का छात्रावास खोलना इन बिन्दुओं के आधार पर उस परिधि में आता है, नम्बर-एक। नम्बर-दो, छोटी सादड़ी तहसील में धौलापानी छात्रावास, जो यहां से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहां पर यह जो भी छात्रावास आपने दोनों परिशिष्टों में बताये हैं, उसमें सर्वाधिक छात्राएं, 140 छात्राएं, वहां अध्ययनरत हैं, पड़ता है। क्या 20 किलोमीटर दूरी पर जाकर के छात्रावास में छात्राओं का पढ़ने जाना आज के समय में सम्भव है। नम्बर-तीन, क्या भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि प्राप्त करने के लिये आप इस छात्रावास को खोलने के लिये प्रस्ताव भेजेंगे, कृपया आप बताने का कष्ट करें।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नवीन छात्रावास खोलने का सवाल है, छोटी सादड़ी में जो प्रतापगढ़ जिले का भाग है, धौलापानी और करजू में दो जगह छात्रावास खोलने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जहां तक विशेष केन्द्रीय सहायता का सवाल है, आदिवासी क्षेत्रों में और माडा क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का अनुपात क्या है, बालकों का अनुपात क्या है और जिस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बालक बालिका का अनुपात कम है, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास खोले जाएंगे। भारत सरकार का जो भी पैसा प्राप्त होता है, उसका 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होता है। प्रस्ताव 3 साल से भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं इस साल 31 मार्च के पहले-पहले मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को दिल्ली भेजकर के वह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी वहां से पास हो, पैसा मिले और आने वाले वित्तीय वर्ष में, अप्रैल-मई में नये छात्रावास खोल दिये जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कितने प्रस्ताव हैं?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): तीन साल से पड़े हुए हैं वहां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पड़े हुए तो ठीक हैं, लेकिन राजस्थान के कुल कितने प्रस्ताव हैं? (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछने दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के समक्ष जो...

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं आपको बता देता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के समक्ष जो प्रस्ताव विचाराधीन है, यह राजस्थान में किस-किस जिले के कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं, कब-कब भेजे गये हैं, यह जानकारी दीजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं और भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं, बांसवाड़ा जिले के... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): मेरे मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं आया, दूसरा शुरू हो गया। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बांसवाड़ा जिले के 7 छात्रावासों के प्रस्ताव, डूंगरपुर जिले के लिये इसी तरह से आसपुर, झाड़ोल उदयपुर, आबू रोड के लिये गिरवर है, उपजा खेजड़ है, मूंथला है, और आबू रोड है। इसी तरह से सभी टी.एस.पी. एरिया के हर जिले में शिक्षा के अनुपात के आधार पर जो छात्रावास खोले....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गैर अनुसूचित क्षेत्र में सिरोही में कितने भेजे हैं?

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): मेरे मूल प्रश्न का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): शिड्यूल एरिया में आबू रोड में गिरवर, उपला खेजड़, मूंथला और आबू रोड, जहां 50-50 छात्र संख्या के, दो तो बालक छात्रावास हैं और तीन बालिका छात्रावास हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया और दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, आपने गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने प्रस्ताव भेजे हैं, आप बता रहे हैं, ट्राइबल सब प्लान के। मैं पूछ रहा हूं नॉन ट्राइबल सब प्लान के। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): इनके प्रश्न का पहले जवाब आने दीजिये। इनके बाद पूरक प्रश्न करवाइये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जहां तक गैर अनुसूचित क्षेत्र का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता को पहले अपने सारे प्रश्न पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, ठेका ले लिया है क्या सरकार का। पूरी सरकार का ठेका ले लिया क्या आपने? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी अनुमति से, आपकी अनुमति से पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाए, उसके बाद में आप कर लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन छात्रावासों की बात कर रहे हैं, धौलापानी और करजू, ये दोनों छात्रावास अभी संचालित हैं। धौलापानी में 140 छात्राएं पढ़ती हैं और करजू के अन्दर 50 छात्राएं पढ़ती हैं। मेरा निवेदन यह है कि गणेशपुरा, जो इन दोनों गांवों के बीच में पड़ता है, यहां पर 3 साल पहले राजस्थान की सरकार ने वहां सैकण्डरी स्कूल खोला था, वहां पर पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल के अन्दर जाती नहीं हैं, क्योंकि आसपास के गांवों में लोग पढ़ने भेजते नहीं हैं। यदि वहां पर छात्रावास आप खोल देंगे तो वहां पर उसके आसपास के आदिवासी अंचल की छात्राएं वहां पढ़ने आएंगी। यह मेहरबानी होगी, और वैसे भी मैं आपके क्षेत्र का आदमी हूं, इसलिये आप मेहरबानी करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइण्टेड इन्फार्मेशन मांगी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में भारत सरकार के समक्ष कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, देंगे जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, नया छात्रावास खोलने की, वहां पर इनकी भावना की कद्र करते हुए आने वाले वित्तीय वर्ष में यह प्रावधान किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पूछें, क्या पूछना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गैर अनुसूचित क्षेत्र में नये छात्रावास खोलने के लिये भारत सरकार के समक्ष कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): चित्तौड़गढ़ में बेगूं, बड़ी सादड़ी, जहाजपुर, माण्डलगढ़, जयपुर जिले में चाकसू, जमुवारामगढ़, आमेर और दौसा में दौसा, लालसोट, महुवा, बांदीकुई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिरोही का बता दीजिये, सिरोही का। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सिरोही का नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गैर अनुसूचित क्षेत्र का कह रहा हूं मैं तो। (व्यवधान) गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो आप छात्रावास खोलते हैं, उसमें सिरोही जिले का पूछ रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सिरोही जिले में नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं है तो सिरोही जिले का भेजो आप, भेजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप से राय लूंगा मैं, भेजना है कि नहीं भेजना है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, बार-बार अखबारों में आता है कि अपनी पार्टी के लोगों ने मंत्री के ऊपर आक्षेप लगाये हैं कि वन विभाग में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और वह 794 ट्रांसफर कैंसिल कर दिये। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह बिलकुल इर्रिलेवेंट है, यह किसने कहा। (व्यवधान) कौन से मेम्बर ने कहा, यूं ही। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह अखबारों में आया है। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया मैंने, अंकित नहीं होगा। श्री सुभाष बहेड़िया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, श्री सुभाष बहेड़िया।

प्रश्न संख्या-45
(स्थगित)

भीलवाड़ा जिले में राजस्व पटवारियों के रिक्त पद

46. **श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में तहसीलवार राजस्व पटवारियान के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) तहसीलवार स्वीकृत पदों के विपरीत वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व पटवारियान के रिक्त पदों को भरने के लिये नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पूरी सूचना नहीं आ पाई।

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी): (1) भीलवाड़ा जिले में तहसीलवार राजस्व पटवारियों के निम्न पद स्वीकृत हैं :

क्रम संख्या	नाम तहसील	स्वीकृत पद
1.	भीलवाड़ा	54
2.	माण्डल	59
3.	बनेड़ा	32
4.	सहाड़ा	31
5.	रायपुर	26
6.	हुरडा	31
7.	आसीन्द	57
8.	शाहपुरा	57
9.	जहाजपुर	45
10.	बिजौलिया	20
11.	माण्डलगढ़	37
12.	कोटड़ी	38
	योग	**487**

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) तहसीलवार स्वीकृत पदों के विपरीत रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्व पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2007-08 में 1500 पदों पर नई भर्ती करने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु भर्ती से संबंधित नियमों में संशोधन कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी से मिल लेना, वह बता देंगे। बता देंगे वह।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा प्रश्न। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न आ गया है। दूसरा प्रश्न पुकार लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस प्रश्न के अन्दर ...(व्यवधान) इस प्रश्न में जितना समय लगा है ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। मैंने नेक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। आप मंत्रीजी से मिल लीजिए, वह सूचना दे देंगे आपको। माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी से सूचना ले लेना।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में पटवारियों के 487 पद स्वीकृत हैं और उसमें से 151 खाली हैं। यह हर्ष की बात है कि राज्य सरकार ने नये 1500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी की है। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भर्ती की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ हो जाएगी और कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। ठहरो-ठहरो। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह मेरे जिले का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें, मंत्री महोदय, क्या यह सही है ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, क्या यह सही है, वह हमारे जिले का ही मामला है। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं। मेरे को बोलने दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप बाद में बता देना।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता पूछ लें। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारे जिले में ही है और मेरे क्षेत्र का बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उनके बाद बोल लेना।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भीलवाड़ा जिले का ही है।

श्री उपाध्यक्ष: उनके बाद बोल लेना। हां, उनके बाद दूंगा मैं टाइम आपको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मूल प्रश्नकर्ता का तो जवाब आने दो पहले, गुरुदेव। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1500 पटवारियों की भर्ती राजस्थान के अन्दर विभिन्न जिलों में पटवारियों की कमी को देखते हुए, 1500 पटवारियों की भर्ती की स्वीकृति दिनांक 20.06.2007 को प्राप्त हुई और इन सभी 1500 पटवारियों के पद सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति इस विभाग को प्राप्त हुई। मगर कुछ अड़चनें थीं। (व्यवधान) एक तो योग्यता जो सैकण्डरी थी उस योग्यता को बढ़ाकर सीनियर सैकण्डरी करने का इस भर्ती के अन्दर प्रावधान रखा और सीनियर सैकण्डरी के भर्ती करने के प्रावधान रखने के कारण कुछ नियमों में संशोधन करना पड़ा और उसके बाद के अन्दर पहले जिलेवार, रेवेन्यू बोर्ड के तहत जिलेवार भर्तियां होती थीं और उसमें हमने पारदर्शिता को दिखाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती करने का निश्चय किया और वह रूल्स के अन्दर अमेंडमैंट किया और इसके बाद के अन्दर यह सारा करने के बाद के अन्दर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां जिलेवार जो 80-20 का जो पहले भर्ती की प्रक्रिया थी और प्रावधान था, उसके अन्दर भी हमने यह देखा कि पूरे राजस्थान से भर्ती की जाए मगर इस दरम्यान राजस्थान हाई-कोर्ट के अन्दर एक याचिका रामस्वरूप इन्दौरिया के नाम से 2001 के अन्दर दायर की और उसको

(श्री रामनारायण डूडी)

एग्जामिन करने के बाद में हम यह निश्चित तौर पर पहुंचेंगे कि यह सारा करने के बाद 1500 व्यक्तियों की भर्ती, पटवारियों की भर्ती बहुत ही थोड़े समय के अन्दर जो परीक्षणाधीन है, हम उनकी भर्ती की तारीख वगैरह निश्चित कर देंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसमें भीलवाड़ा जिले में कितने होंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें से भीलवाड़ा जिले में कितने होंगे? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक सवाल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्रीजी से हम यह जानना चाहते हैं कि कितने वर्ष के बाद पटवारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। मूल प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं। आपको भी समय देंगे। समय देंगे आपको भी। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा जिले में इसमें कितनी भर्ती होगी? भीलवाड़ा जिले में कितने पद देंगे आप इन 1500 में से? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी आज्ञा हो तो सवाल पूछ लूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, आज्ञा है। (व्यवधान) वह पूछ लें, उसके बाद आप पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा जिले में कितने पद देंगे? कितने पटवारी देंगे, माननीय मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में पटवारियों के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ठहरिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, यह बता दें सदन में कि कितने वर्षों के बाद पटवारियों की नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है? यह बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, भीलवाड़ा जिले में जो पटवारियों के पद स्वीकृत हैं उसमें तहसील रायपुर में एक-एक पटवारी के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं और जिनकी दूरी 15-15 किलोमीटर है। क्या वह पटवारी उन पटवार मंडलों में काम सुचारु रूप से कर सकता है, एक। नम्बर-2, क्या आप उन पटवारियों को टी.ए., डी.ए. और भत्ते देते हैं? नम्बर 3, जिले के अन्दर जितने पद स्वीकृत हैं, क्या जिले के सभी पटवार मंडलों को बराबर, तहसीलों को बराबर ट्रांसफर करके पद सृजित करने का अधिकार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक पटवारी की भी नियुक्ति करी क्या, यह बता दें, मंत्री महोदय। उनकी सरकार ने पांच साल में कितने पटवारियों की नियुक्ति की है? मंत्री महोदय, यह बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): जिले के अन्दर जो आपने पक्षपात कर रखा है, एक तहसील में बराबर पद है और दूसरी में 26 पद स्वीकृत हैं और छह-सात पटवारी ही लगा रखे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गयी बात आपकी। माननीय सदस्य, यह भाषण नहीं होगा। आपने पूछ लिया प्रश्न। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं यह कह रहा हूं, साहब, जिले में जितने पद स्वीकृत हैं क्या सभी तहसीलों में बराबर उसकी समानता के, पदों के अनुरूप पदस्थापित करने का विचार रखती है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार में, पूरे राज्य में 20 साल तक कांग्रेस के शासन में एक पटवारी की नियुक्ति नहीं की और आज वकालत कर रहे हैं इस ढंग से। आज करोड़ों रुपये रुके हुए पड़े हैं। (व्यवधान) और पटवारी भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, नहीं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): देखिये, परीक्षा के आधार पर इनका सलेक्शन होगा। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की, हमारी सरकार आने के बाद के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप जवाब तो आने दो। ...(व्यवधान) नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब तो आने दो। सुन तो लो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर 1500 पटवारियों की भर्ती हम कर रहे हैं और जहां पर कमी-बेशी है उनके अनुपात के अन्दर यह रेगुलर प्रक्रिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास आंकड़ा है यह 31.1.08 का आंकड़ा है। उनके अनुसार 1829 रिक्त पद हैं, उनके विरूद्ध पटवारियों की भर्ती के आदेश कर दिये गये हैं और यह शीघ्र ही इनके प्रोफार्मा तैयार होने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। मैं आपको यह बात बता देता हूं कि यह भर्ती हमारे कार्यकाल में होगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारे राजस्थान की भाजपा सरकार के अंदर हमने मास्टरों की भर्ती की, हमने ए.एन.एम. की भर्ती की ... (व्यवधान) ....

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारी सरकार ने सभी पदों पर भर्ती की है। आज जो जनता भुगत रही है वह आपकी पिछली सरकार की बदौलत भुगत रही है। हमने अधिकारियों, पटवारियों और सभी की भर्ती हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछना चाहते हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके आर.पी.एस.सी. के सदस्य के पद तो खाली पड़े हैं, भरवाओगे कहां से? जरा यह तो बता दो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमारे पास सब कुछ है। आप चिन्ता मत करो, एक ही बात है। इस प्रकार से घिरने वाले नहीं हैं हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया। प्रश्न काल का समय एक घण्टा है, उसके बाद सवाल पूछने की अनुमति नहीं है।

एक माननीय सदस्य: संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप नेता मत बनो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चेयर कर रही है अलाऊ। He can allow. The Chair can allow. Mr. Parliamentary Minister he can allow. आप यह राठौड़ी कर रहे हो यहां पर।

श्री अमराराम (धोद): उन्होंने अनुमति दी है और आप बीच में ही राठौड़ी कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, यहां पर एक मेरा सरकार से सुझाव है, मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं यहां पर, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, जो अपने आपको यहां मुख्य मंत्री के रूप में सदन में प्रस्तुत करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो मंत्रीजी से पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है। इस सदन के अंदर वरिष्ठ सदस्य हैं और कुछ भी बात कह दें। प्रश्न काल समाप्त हो गया। नियमों में आपने एक घण्टे का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान कर रखा है और कोई नियम में आ जाये अगर इनको किसी मामले में बहस करनी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह इनको ज्ञात नहीं है कि इस सदन के अंदर प्रश्न काल दो-तीन बजे तक चला है 67-72 के बीच में। यह स्पीकर का डिस्क्रिशन है, स्पीकर अलाऊ कर सकता है। सिर्फ दो मिनट हुए हैं, आपको याद नहीं है। आपसे पुराना सदस्य हूं। मुझे जानकारी है The Speaker can allow. आप किस रूप का हवाला दे रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल है, मैं ज्यादा नहीं पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं। आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक मैम्बर रह गया है। आप हर भर्ती को पी.एस.सी. के मार्फत कराना चाहते हैं। सरकार पटवारियों की भर्ती को भी पी.एस.सी. के मार्फत कराना चाहती है। क्या पी.एस.सी. के लिये संभव है? क्या सरकार सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड राजस्थान के अंदर गठन करने का विचार रखती है या नहीं? जिनके माध्यम से इस प्रकार की भर्तियां हो सकें। इसके ऊपर कोई कुछ मंत्री अगर यहां पर कह सकें तो मैं उनका इस बारे में बहुत आभार प्रकट करूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई नहीं बोलेगा, डर गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल खड़े किये हैं एक तो पी.एस.सी. में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में किया, चूंकि मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार कर रही हैं और शीघ्र निर्णय करेंगी। दूसरा सबोर्डिनेट सर्विस की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत निर्णय पूर्व में सरकार ले चुकी है और यहां भी कार्यवाही विचाराधीन है जल्दी कार्यवाही होगी इस पर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री अमराराम एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में शीतलहर एवं पाले से नष्ट हुई फसल का पर्याप्त मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

दिनांक 19 फरवरी, 2008 को इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है, पुनरावृत्ति है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री बृजकिशोर शर्मा एवं श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जयपुर में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण लोगों की मौतें होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर शर्मा को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तो प्रश्नकाल के बाद यह अपन ने तय किया है कि आज केवल अभिभाषण पर चर्चा करेंगे, इसको बाद में लेंगे अगले दिनों में।

श्री उपाध्यक्ष: अभी लेने दो, इसमें क्या है?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी फिर आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोल नहीं रहा, याद दिला रहा हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जब उन्होंने दो मिनट बोलने की व्यवस्था दे दी, व्यवस्था आपकी चलेगी या उपाध्यक्ष महोदय की चलेगी?

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने इस सचिवालय से गया है कि 19 तारीख को प्रश्नकाल नहीं हुआ इसलिए इनको 26 तारीख में लिया जायेगा और हमारे स्थगन प्रस्ताव थे, मैं आपकी व्यवस्था का आदर तो करता हूं, लेकिन जिससे राजस्थान का तमाम किसान पीड़ित है, जिस दिन प्रश्न काल नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस शीतलहर और पाले से राजस्थान के किसान की रबी की फसलें करीब-करीब तबाह हो गयी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आज नहीं तो बाद में, जैसा आप व्यवस्था बता रहे हैं, उसके बाद कभी भी इस पर व्यवस्था दें जिससे इस पर चर्चा हो सके। यह नहीं है कि उस दिन प्रश्न काल नहीं हुआ और कार्यवाही नहीं हुई उन प्रश्नों को आप आगे ले रहे हो तो इस स्थगन प्रस्ताव को भी आप आगे अनुमति दें जिससे राजस्थान के उन पीड़ित किसानों की बात को रखा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर भी चर्चा हो जायेगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपको मौका दिया जायेगा, उस समय आप चर्चा कर सकते हैं।

जयपुर में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण मौतें होने के संबंध में

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की राजधानी में दूषित पानी की वजह से जो मौतें हुई हैं, की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है। यह मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं और हमारे कांग्रेस के साथी समय-समय पर इस बारे में सरकार को विभिन्न मौकों पर विधान सभा में तारीख 20-3-2004 को स्थगन प्रस्ताव के जरिये, तारीख 10-5-2005 को विशेष उल्लेख के जरिये, तारीख 10-4-2006 को कटौती प्रस्ताव के जरिये, तारीख 9-3-2006 को तारांकित प्रश्न संख्या 390 के जरिये उठाया था। सरकार ने 30-6-2007 को इन लाइनों को ठीक करने का काम पूरा करने का आश्वासन दिया था, यह सब चीजें मेरे पास आन रिकार्ड है और मैं इनको टेबल करने को तैयार हूं। सरकार का जवाब इनके पास मौजूद है। इन सबके बाद तो हम यह उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान की जनता को, जयपुर शहर के लोगों को दूषित पानी मिलना बंद होगा और सरकार वाजिब कार्यवाही करेगी। लेकिन इस सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाते हुए, राजस्थान के विभिन्न शहरों में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रदूषित पानी पिला रही है। इससे राहत मिलना तो दूर रहा, यहां पर 11 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें से पांच लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पांच मुरलीपुरा क्षेत्र में और एक शास्त्री नगर के नाहरी के नाके में हो चुकी है। अगर यह मौतें गंदे पानी से नहीं हुईं तो क्यों एक ए.ईएन. को सस्पैण्ड किया गया, क्यों सेठी कालोनी के सेटेलाइट अस्पताल के डाक्टर को सस्पैण्ड किया गया और अगर यह मौतें गंदे पानी से नहीं हुईं तो क्यों नहीं 11 मौतों में से किसी एक का पोस्टमार्टम कराया ताकि लोगों को पता लगता कि क्या हुआ? 11 मौतें होने के बाद भी न तो कोई मुआवजा दिया गया और तो और इस गैर जिम्मेदार सरकार के गैर-जिम्मेदार मंत्री ने यह कहा कि जो आया है, सो जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह हत्यारी सरकार इतने लोगों की मौतें होने के बाद मुआवजा देगी और मैं इसके लिए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह मुआवजा दे और अगर इन्होंने मुआवजा नहीं दिया तो मैं इस सदन में धरने पर बैठ जाउंगा।

एक माननीय सदस्य: पानी तो आप भी पीते थे, आप क्यों नहीं मरे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रश्न किया है ...

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं आप, माननीय सदस्य। आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब मंत्रीजी की बात सुन लो, पंडितजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनिये आप, पहले जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई परमिशन दी है बोलने की? यह सदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जब चाहे जो बोलने लगेंगे...(व्यवधान) यह सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय बर्बाद नहीं करें। ...(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता को शुद्ध पीने का पानी मिले, इस बात का प्रयास सरकार बराबर कर रही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 4 साल हो गये, मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप सुन तो लो या ज्यादा एलर्जी हो रही है आपको या केवल इसी मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहते हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हां ...(व्यवधान) हम जीतना चाहते हैं और जीतेंगे ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, मैंने कोई गलत बात कही है क्या ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कह रहा हूं कि शुद्ध पानी पिलाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं जो बात कह रहा हूं, सुनें ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप जवाब दीजिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चार साल हो गये, मंत्रीजी, आपको कहते हुए, चार साल से आप कर क्या रहे हो?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बीच-बीच में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उचित नहीं है कि आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहो। आप सुनिये उसके बाद में आपका कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने हमारे पास जो तथ्य हैं ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपको क्या हो गया? (व्यवधान) आप क्या सिविल लाइन्स से पिलाओगे पानी? आप सिविल लाइन्स से पिलाओगे पानी?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप सिविल लाइन्स से पिलाओगे न? आपकी मुख्य मंत्री वहां ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री को पिलाओ पानी गंदा। (व्यवधान) इन मंत्रीजी को पिलाओ पानी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निश्चित रूप से हमारी सब की भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी अगर दूषित पानी आता है तो सरकार की जानकारी में लाकर उसमें सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस सम्बन्ध में उस दिन यह बातचीत चली उसके बाद में माननीय सदस्य कोई जनहित याचिका में गये। उसके बाद में जनहित याचिका का राज्य सरकार ने जवाब दिया, वो डिसमिस हुई। आज भी, कल कोई माननीय सदस्य जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट के अन्दर गये हैं और हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये कि 14 तारीख तक आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं, नियमित सैम्पल वगैरहा की, तो वह कार्यवाही करके हम माननीय उच्च न्यायालय को भी उसका जवाब दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी, आज अगर न्यायालय ने आपको कह दिया तो क्या विधान सभा का मतलब कुछ नहीं है? आपका यह दिया हुआ जवाब है। (व्यवधान) आपने 2007 में इन लाइनों को पूरा करने का जवाब दिया था और आज आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री उपाध्यक्ष : महोदय बीच में नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): क्या है यह ...(व्यवधान) यह स्थगन प्रस्ताव मेरा है, उनका नहीं है, यह क्या बात है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं केवल जो तथ्यात्मक जानकारी सरकार के पास है वो रखना चाहता हूं। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला अभी लम्बित है इसलिए ज्यादा मैं ...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप इसमें उच्च न्यायालय में लम्बित करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। आप इस विधान सभा के प्रति, यह सरकार उत्तरदायी है, आपको, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जब तक मुरलीपुरा क्षेत्र से जानकारी हमारे पास आयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुरलीपुरा क्षेत्र से जैसे ही दूषित पानी की शिकायत आयी, 10 तारीख को हमने क्लोरिन की जांच की, आठ-दस नमूने लिये, सब ठीक पाये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह बातें मत करिये। लक्ष्मीनारायणपुरी में आप खुद गये हैं, मंत्रीजी, आपने खुद ने वादा किया है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 11 तारीख को 24 नमूने लिये, सभी ठीक पाये। 12 तारीख को 16 नमूने लिये, 16 ठीक पाये, 13 तारीख को 160 नमूने लिये, 160 ठीक पाये, 14 तारीख को 126 लिये, 126 ठीक पाये, 15 तारीख को 197 लिये, 197 ठीक पाये ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अख़बार के नमूने भी देखो जो लोगों ने प्राइवेट कराये हैं। यह आपके नमूने हैं, इसकी कोई सैंक्टिटि नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 16 तारीख को 122 लिये, 122 ठीक पाये, 17 तारीख को 104, 104 ठीक पाये, 18 तारीख को 66 लिये, 66 ठीक पाये, 19 तारीख को 63 लिये, 63 ठीक पाये, 20 तारीख को 51 लिये, 51 ठीक पाये। यह क्लोरिन के नमूने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें क्लोरिन पायी गयी, अगर क्लोरिन नहीं होती तो उसमें यह पानी डिफेक्टिव होता।

इसी प्रकार से पेयजल के अन्दर कोई जिवाणु तो नहीं हैं, जिवाणु टैस्ट भी हमने कराया जिसमें 10 तारीख को हमने लिये दो सैम्पल और दो ही ठीक पाये, 11 को 6 लिये, 6 ठीक पाये, 12 को 9 लिये, 9 ठीक पाये, 13 को 10 लिये, 10 ठीक पाये, 14 को 9 लिये, 9 ही ठीक पाये, 15 को 20 लिये और 20 ठीक पाये, 16 को 16 लिये, 16 ठीक पाये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किसके नमूने लिये आपने? यह आप लोगों के बयान हैं जिसमें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक बार मैं कम्प्लीट कर लूं उसके बाद पूछ लीजिए ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): टैस्ट किये हैं जिसमें लोगों ने, यह फैसला अख़बार वालों ने और लैबोरेट्री से तय हुआ है कि पानी दूषित है, आपकी रिपोर्ट गलत है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें तो सही। आप सुनना नहीं चाहते?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 18, 19, 20 जो भी सैम्पल लिये ठीक पाये गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह भी मैं बता दूंगा, आप एक बार पूरा तो सुन लो न, उसके बाद आपका कोई भी सवाल होगा तो जवाब देंगे हम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले लक्ष्मीनारायणपुरी में इस सम्बन्ध में शिकायतें आयी थीं। उसके बाद में हमने पाइप लाइन चैंज करने का और सारा निर्णय लिया। कई बार सर्विस लाइन जो उपभोक्ताओं को चैंज करानी होती है और समय पर वो चैंज नहीं कराते हैं तो सरकार ने इस सम्बन्ध में भी निर्णय लिया कि सर्विस लाइन भी सरकार चैंज करायेगी, जहां-जहां भी डिफैक्टिव होगी, चूंकि लाइनें बहुत पुरानी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने पहले चैंज कर दी होतीं तो यह मौतें नहीं होतीं, हम चार साल से आपको कह रहे हैं कि यह गंदा पानी आ रहा है, आप इसको बदल दीजिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप मेरी बात सुनने के बाद सवाल करिये, मेरी बात सुनने के बाद में।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने बदल दी होती तो यह मौतें नहीं होतीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब नहीं सुनना चाहते?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह हत्यारी सरकार है, इसके आप जिम्मेदार हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप यों एक-एक खड़े होकर के बीच में इण्टरवीन करेंगे क्या ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, यह क्या है बीच-बीच में। पहले जवाब सुन लें फिर सवाल कर लें। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने किसी से परमिशन ली नहीं ... (व्यवधान) कोई बहस थोड़ी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पूरा जवाब नहीं सुनें, माननीय सदस्य, अच्छी परम्परा नहीं है। अगर आपकी समस्या है, इसमें फिर भी आपकी कोई क्वैरी रहती है तो मैं रिप्लाई करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रश्न करने का आपका अधिकार है, कौन मना कर रहा है माननीय सदस्य। जवाब देने की मेरी ड्यूटी है तो आप सुन लीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी आपने अभी जो आंकड़े दिये थे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक लाइन नहीं बोल पा रहा हूं मैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): संसदीय कार्य मंत्रीजी, इन्होंने जो असत्य आंकड़े दिये हैं उसकी सच्चाई बता रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी तकलीफ से मैं सहमत हूं। आपके एरिये की यह खबरें आ रही हैं, स्वाभाविक है आपका चिन्ता करना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अकेले की खबर नहीं है, पूरे जयपुर शहर की है, राजस्थान की है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): देश आजाद होने के बाद शहर के अन्दर पापुलेशन का लोड बढ़ा है ...(व्यवधान) पाइप लाइनें पुरानी हैं ... (व्यवधान) इसलिए पानी प्रेशर से नहीं जाता है। कई जगह पाइप लाइनें कुछ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। पहली बार हमने सत्तावन करोड़ रुपये सैंक्शन करके पाइप लाइनों का काम किया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कब किया, कब किया मन्त्रीजी, आपने यह काम जब किया है जब हम राज्यपाल के पास गये, उसके पहले नहीं किया। अगर आपने यह पहले कर दिया होता तो यह ग्यारह मौतें नहीं होतीं।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपको जरुरत नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान के अन्दर माननीय सदस्य चौदह हजार करोड़ की योजनाएं हमने सैंक्शन की हैं। अब आप कह दोगे कि हमारे कहने से की हैं। आप भी जन प्रतिनिधि हैं तो अगर आपके कहने से कर दी तो अपराध कर दिया क्या हमने। आप यह कहना चाहते हो कि हमारे कहने से मत करिये। मैं यह कहना चाह रहा हूं एक्जिस्टिंग जो सैंक्शन है 52 करोड़ कुछ है। वर्क एक्जीक्यूटेड हमारा 41.2 करोड़ है और 18 किलोमीटर लाइन हमने 13.2.08 तक चैंज कर दी है। न्यू सैंक्शन हमारी एक और की है हमने और शिफ्टिंग आफ सर्विस कनेक्शंस 3920 हमारा टार्गेट था उसमें 3201 पूरा कर दिया। पाइप लाइन का 45 का टार्गेट था, साठ हमने चैंज कर दी। वाटर क्वालिटी रिजल्ट्स हमने 4884 लिये हैं। सैम्पल 4884 की हमने जांच करवाई इसमें 4853 सैटिस्फैक्टरी पाये, 99.00 परसेंट।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी, मैं आपसे सिर्फ यह बात पूछना चाहता हूं कि जो काम आपने आज किया है यह अगर पहले कर देते तो यह मौतें नहीं होती। आपका खुद का स्टेटमैंट है। आपने खुद ने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अभी आप जवाब दे रहे हैं बीच में नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 1281 सैम्पल हमारे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपके जानकारी में आने के बाद हमने सैंक्शन किये ...(व्यवधान) इसलिए यह बात निराधार है कि आपके यह अख़बार में आने के बाद ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): राजस्थान के हर शहर के अन्दर यह सरकार आने के बाद ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई भी गंदा पानी अगर किसी के घर की टोंटी में आएगा ...(व्यवधान) आप फैसला कर लीजिए कि क्या उस पानी को पियेंगे ...(व्यवधान) आप बता दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उसके बावजूद हुई है श्रवण कुमार की मौत ...(व्यवधान) मौत हार्ट अटैक से हुई है किसी की, ...(व्यवधान) बलवीर सिंह लम्बे समय से बीमार था ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) पीला पानी पीया क्या ...(व्यवधान) अपने राज में तो किया नहीं ...(व्यवधान) हजारों करोड़ रुपये ......

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): टैंकर हम लगवा रहे हैं ...(व्यवधान) कौन किस कारण से मरा है ...(व्यवधान) खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) हम करवा रहे हैं और आने वाले समय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवायेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

धरना

(माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर शर्मा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) राजस्थान में पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी प्रायोरिटी है, हम करवा रहे हैं और आने वाले समय में भी पेयजल उपलब्ध करवायेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर का पानी सितम्बर तक जयपुर में लाएगी यह सरकार ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ही बोलूंगा मैं तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, दूषित पेयजल से जो मौतें हुई हैं जयपुर शहर में उसका मुद्दा हमारे माननीय सदस्य ने उठाया। वह इससे बहुत दुःखी हैं और पीड़ित हैं। स्वाभाविक है कि उनके क्षेत्र की जनता की दूषित जल से मौत हो रही है। जो दूषित जल सरकार उनको पिला-पिला कर उनकी हत्या कर रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। बोलने दीजिए आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह अनुरोध है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य नहीं रोकेगा आप सुनो। कोई सदस्य नहीं रोकेगा। बैठिये-बैठिये। कोई नहीं रोकेगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूषित जल से जो मौतें हुई सारे न्यूज पेपर्स में यह आया। हाई कोर्ट में भी रिट लगायी। पुख्ता सबूत, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गयी है। मीडिया ने यह अख़बार में भी आया है मौतें हुई हैं। अब मैंने कह दिया इन्होंने सरकार ने दूषित जल पिलाया उससे मौतें हो गयी, इनको एकदम बहुत बुरा लगा। आप तो कह दो आप सरकार में बैठे हो और आप बहुत जिम्मेदार आदमी हो, सरकार चला रहे हो। पानी की व्यवस्था आपकी जिम्में है। पानी आपके द्वारा उनको दिया गया है। आपकी व्यवस्था है पी.एच.ई.डी. की। उससे मौतें हो गयी और आप मरने वाले तो मरेंगे ही। अब मरने वाले मरेंगे यह कोई जवाब है क्या। यह कोई सरकार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह क्या जवाब दे रहे हैं सुनो ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, यह जवाब ठीक है क्या? इनको कुछ तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी जवाब नहीं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अभी इनको जो लोगों की मौत हो रही हैं इसकी चिन्ता नहीं है सरकार को। इनको चिन्ता किस बात की है? इनकी चिन्ता अन्दर से जबरदस्ती बाहर निकल आयी। इनके जो मन की भावना थी दिल में वह इन्होंने खड़े हुए कहा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हो। किसने कहा? हम इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमने तो कोई चुनाव की बात ही नहीं की। हमने तो दूषित

(श्री हेमाराम चौधरी)
जो पीने का पानी मिल रहा है उसकी बात माननीय सदस्य कह रहे थे, इनको बीच में पता नहीं चुनाव कहां से आ गया? चुनाव कैसे याद आ गया? इनके दिल में यह है कि यह दूषित जल का मुद्दा अगर यह उठायेंगे तो वास्तव में पब्लिक को यह मैसेज जायेगा कि यह कांग्रेस वालों ने जो पब्लिक की दूषित पानी से जो मौतें हो रही हैं इस बात को उठाया इसलिये तो यह विधान सभा नहीं चलने देना चाहते। ऐसे कोई मुद्दे उठे नहीं, यह ऐसे राला रप्पे में चलती रहे तो यह मुद्दे उठे ही नहीं, इन्होंने अपने दिल की बात एकदम चुनावी मुद्दा, किसने कहा आपको चुनावी मुद्दा? आप बनाओ चुनावी मुद्दा। आगे की बात है। अभी जब चुनावी मुद्दे की बात कही, यहां कहा चुनावी मुद्दे की बात है। यहां तो बात लोगों की समस्या और तकलीफ की है। कल पाले की बात करेंगे तो आप कहोगे चुनावी, चुनावी मुद्दा। आज नहर के अन्दर किसानों को पीने का पानी, पीने का छोड़ो फसल के लिए नहीं मिल रहा है। मैंने आपको आप अजमेर में थे फोन किया ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय का आदर करते हुए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं माननीय नेता महोदय का आदर करते हुए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक मिनट ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब कृपा करके आप यह बात समाप्त कर दीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह नेता महोदय मुझे बार-बार इशारा करके कह रहे हैं इसलिये मैं साथ का साथ रिप्लाई करना भी जरूरी समझ रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आप सैम्पल टैस्ट करके जानकारी दीजिये। हमने सैम्पल टैस्ट लाकर दिये और यह बात कोई अख़बार के अलावा कोई सबूत हो तो हमको दो ना। यह किस आधार पर आप कह रहे हो दूषित पानी पिलाया जा रहा है। आप अपने अतीत और इतिहास को याद कीजिये। आपके जमाने में नहरों में कितना पानी दिया आपने? कितना पैसा दिया आपने? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने अपने इतिहास में कुछ किया पांच साल के राज में तो वह उपलब्धि हमको बताइये। पाले के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का एहसान प्रकट करता हूं कि पहली बार राजस्थान सरकार ने ... (व्यवधान) सवा सौ करोड़ रुपया दिया ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपने खजाना खाली के अलावा कुछ नहीं किया। केवल यह मुद्दा बनाना चाहते हो। कोई एक सैम्पल जांच करायी हो तो बताइये। पीला-पीला पानी आपने पिया? (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय बहुत नाराज हो गये। होना स्वाभाविक है। मैंने ऐसा कुछ व्यक्तिगत तो उनके बारे में नहीं कहा। मैंने सरकार की बात कही। सरकार है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाराज नहीं हुए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसका काम है शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना। अगर शुद्ध पेयजल आप उपलब्ध नहीं करा सको तो मेहरबानी करके कराओ ही मत। इससे अच्छा तो आप पानी उपलब्ध कराओ ही मत। गांवों में आज पानी कहीं जा ही नहीं रहा है फिर भी लोग पानी की वजह से मरे तो नहीं। कष्ट पा रहे हैं यह बात सही है लेकिन मर नहीं रहे हैं। इसलिये आप मेहरबानी करके गांवों में जैसे पानी की कई लाइनें सूखी पड़ी हैं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

हौदियां सूखी पड़ी हैं, यहां पड़ी रहने दो ना ऐसे ही ताकि दूषित जल से कोई मरे तो नहीं। इसमें कौनसी बुरी बात है? अब चुनावी मुद्दे की बात मैंने तो की नहीं, बात इन्होंने की। मैंने उसका वापस थोड़ा सा कह दिया तो इनको बुरा लग गया। आज यह पाले की बात करते हैं अब किसानों की नहर के अन्दर फसल बो रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हो अगर फरवरी में फसल को लास्ट पानी नहीं मिला तो आप समझते हो किसानों की जो मेहनत, जो उसका खर्चा, उसने पैसा लगाया वह सब बेकार जायेगा। उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिले एक रुपया भी, बर्बाद नहीं होगा क्या? ऐसे मुद्दे हम यहां उठाना चाहते हैं और उठाते हैं तो इनको बुरा लगता है। ऐसी क्या बात है? आप जवाब दे दो ...(व्यवधान) मैंने ऐसी क्या आपको गाली तो निकाली नहीं ना? मैंने अपनी एक बात कही। आपको इतना ही कह दिया कि मौत हो गयी। मैंने शब्द प्रयुक्त किया हत्या ...(व्यवधान) हत्या वाले शब्द को आप भले ही कार्यवाही से निकाल दो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो मंत्रीजी, सबकी अपनी-अपनी पीड़ा होती है। हर आदमी अपनी पीड़ा लेकर यहां आया है और उनके जो लोग हैं जिन्होंने उनको चुनकर यहां भेजा है उनकी पीड़ा को आपके सामने रखने के लिए हम आए। हम आपके सामने अपनी पीड़ा रखेंगे उसका समाधान आप हो तो मेहरबानी करके करना ...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने कृपा की, कुछ आप भी तो कृपा करो ना। आप भी तो उनके सहयोगी हो ना तो आप कृपा कर देना और आप न कर सको, आप कृपा न करो तो मर्जी आपकी है। हमारे पास क्या है? हम तो बोल रहे हैं। बोलने की वैल्यू, पपीहा बोल सकता है बरसना इन्द्र के हाथ में है। आप बरसो तो ठीक फसल मिलेगी किसानों को पानी दोगे तो। नहीं तो फसल तो सारी जल जायेगी, बर्बाद हो जायेंगे, रोते रहेंगे। अब और तो किसको जाकर गुहार करें आपके सिवाय? कोई भी किसी के पास जनता के पास जाकर वह अपनी बात कह सकें, रख सकें, यह एक सदन है बाकी तो कहीं जाकर हम अपनी बात कह नहीं सकते। मुश्किल से साल भर में आप थोड़े दिन चलाते हो उसमें हमेशा आपका प्रयास यह रहता है यह भी नहीं चले और हम वापस जहां हैं वापस अपने घर चले जाएं बिना कुछ

(श्री हेमाराम चौधरी)

यहां तकलीफ पाये तो थोड़ी तो लोगों की सोचो ना। आपको बुरा लगा होगा मैंने कुछ कह दिया। मेरी पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है उसकी बात को कहना चाहते थे। मुझे आप कह रहे हो भावुक ...(व्यवधान) भावुक की काहे की बात हुई? आज भावुक की क्या बात हो गयी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भावुक की क्या बात है? नहीं-नहीं, मैं भावुक नहीं हूं। मुझे दुःख होता है यहां आखिर लोगों ने क्यों भेजा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कहा भावुक। भावुक की बात नहीं है। लोगों की पीड़ा है, उसकी पीड़ा पर मैं भावुक नहीं हुआ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो आपने समझा, जो आपने कहा वह बात नहीं है। मेरा कोई आपसे दुराग्रह है क्या? हमारा आपसे कोई दुराग्रह है क्या? हमारा तो काम है आपके सामने आज कोई भी समस्या है उसको रखें। आप अच्छी तरह से रख नहीं सकते क्योंकि यह आपकी तो ड्यूटी ही नहीं है। आपकी तो ड्यूटी वाहवाही करने की है इस राज की। इसके गुणगान के अलावा आपका कोई काम नहीं है।

यह दायित्व आपको दिया है और हमारे को दायित्व दूसरा दिया। अलग-अलग अपना-अपना काम है? न तो आप अपना काम करो।

अभी मुझे पता है धन्यवाद का प्रस्ताव आयेगा, समर्थन आयेगा, मुख्य मंत्रीजी करोगे। हम भी करते थे। हम भी यह आप वाला काम कोई कहीं करते थे और हमारा हाल आप देख रहे हो। वह हाल आपका भी हो सकता है। जनता ही सबसे बड़ी अदालत है देश की। आज हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें आपकी और हमारी अदालत कौन है? आपकी और हमारी अदालत तो वह जनता है ना जो गांवों में बैठी है, शहरों में बैठी है। जो गांवों में बैठी है, शहरों में बैठी है। वह आपको और हमको देख रही है, उसके लिये सुनो और कुछ करो तो ठीक है नहीं करो तो बस, अब थोड़ा ही टाइम रहा है। यही सेशन है, हम भी यही सोचकर आये कि यही सेशन आखिरी है, कुछ आपको सुना

(श्री हेमाराम चौधरी)
देंगे। हमने सोचा कि शायद ईश्वर आपको कुछ सदबुद्धि देगा। सदबुद्धि देगा तो आपके ही काम आयेगी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मेरे पास क्या इलाज है। अब आपने कह दिया कि हेमारामजी ने यह कर दिया तो हेमाराम करे क्या आखिर। यहां कोई बात कहने खड़ा हो जाये तो आपके मैम्बर्स के एकदम यूं चरड़का लग जाये, ऐसी कौनसी मैंने बात कह दी। आपको शांति से बात सुननी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। अगर समाधान हो सके तो और अगर समाधान नहीं हो सके ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नेता, प्रतिपक्ष मुद्दे पर आयें ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात अलग है। जनता भी जानती है कि यह समस्या है इसका समाधान सरकार के पास है और समस्या है इसका समाधान सरकार के पास नहीं है यह फालतू की बातें करते हैं। यह जनता भी जानती है, हम भी फालतू की बातें करेंगे तो उसको भी जनता पसंद नहीं करेगी। लेकिन सही बात कहेंगे तो उसको जनता कहेगी कि बात तो सही कही पर यह मानते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, धन्यवाद, इसलिए मैं बैठता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए बृजकिशोरजी अपने पास और कोई शस्त्र नहीं है, अपने पास एक ही यह मुंह है जो ईश्वर ने दिया है बोलने के लिए, जनता ने भेजा है इसको काम में लेने के लिए तो हम इसको काम में लेंगे और अवसर मिलेगा और उसके बाद में भी यह नहीं सुनें तो अब क्या करें। अब आप तो धरने पर बैठे हो। जो कल मेरी पीड़ा थी, तकलीफ थी, वह भी आपने देखी पर इस पीड़ा का भी कौन इलाज करेगा, भगवान करेगा या आप करेंगे। करेंगे तो ठीक नहीं तो ईश्वर तो करेगा ही।

धरना समाप्त

(श्री बृजकिशोर शर्मा, माननीय सदस्य धरने पर से उठे)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चुनाव को नजदीक देखकर कांग्रेस के लोग लोगों को भड़का रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, जो इनका जवाब है वह गैर जिम्मेदाराना जवाब है। यह नाराज हो जायेंगे, हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम इस सरकार की बात से सहमत नहीं हैं, यह गैर जिम्मेदार सरकार है, इसके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है। यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

फिर और नाराज हो जायेंगे। थोड़ा कहना ही ठीक है। समझ में आ जायेगा तो इतने में ही आ जायेगा...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप बुला रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम अगर घंटा भर भाषण दें तो इनके समझ में आने वाली बात नहीं है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं ...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बातें बतायी हैं उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है मंत्रीजी से, एक प्रश्न है मेरा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के प्रतिपक्ष के नेता का पहला आधे घंटे का भाषण हुआ है, यह सदन गौरवान्वित हुआ है उनके मूल विचार को सुनकर के, पर इसका कोई अर्थ ढूंढ लें, कहना क्या चाहते थे आधे घंटा, फिर आप हमें कहते हो कि हम टोका-टोकी नहीं करें, बिलकुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक भी किसी शब्द का कोई अर्थ निकला हो तो आप खुद उसका आंकलन कर लें ...(व्यवधान) यह प्रतिपक्ष के नेता का पहला भाषण है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी के लोगों, राजेन्द्रजी ने आपको तो पानी पिला दिया और यह कांग्रेस को और पिलायेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक संकट कल से आपने और खड़ा कर दिया, आपने कह दिया कि आप बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो फिर यह भावुक हो उठते हैं, यह भावुक हो उठते हैं तो फिर कोई दूसरी बात हो जाती है सदन में।

श्री उपाध्यक्ष: अब मत बोलें और आगे मत बोलें ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी के भावों से ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): छोड़ो ना ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न एक बार भी ...(व्यवधान) आने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हमारी सारी बातें दूषित जल के विषय में अखबारों में छपी, इन्होंने उठायी, वह कौनसी विश्वस्त एजेंसी है जिसने यह टैस्ट करके कह दिया हो कि यह पानी दूषित है और इससे पीलिया होता है, नम्बर एक। नम्बर दो, किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, क्या किसी चिकित्सक ने यह बात आपके समक्ष रखी है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया है कि यह जो व्यक्ति मरा है या इसकी जो मृत्यु हुई है वह दूषित पानी के कारण हुई है। इसका जवाब कृपया दें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य के जो सवाल हैं वह बिलकुल प्रासंगिक सवाल हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह जानकारी एक मिनट में दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में बात खत्म हो रही है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपका सवाल बिलकुल ठीक है, प्रेस कांफ्रेंस जब ली, वहां भी मैंने अख़बार वालों से भी निवेदन किया था, हमारे जन-प्रतिनिधियों से भी किया कि हमारे अफसर के सामने अगर पेयजल विभाग के नल से अगर पानी आता है, सामने सैंपल भरवायें, उनके सामने लेबोरेट्री से हम जांच करवा देंगे। ऐसी कोई विश्वस्त लेबोरेट्री से इन्होंने जांच नहीं करवायी, सैंपल भी कहां से लाये, यह मेरे समझ से बाहर की बात है। दूसरा, मैं माननीय सदस्य आप सबको बताना चाहता हूं कि जो छप रहा है कि काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, क्या इस तरह का पानी टूंटियों में आने के बाद कोई भी व्यक्ति उसको पी लेगा? उपाध्यक्ष महोदय, यह सबके समझ के बाहर की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे सैंपल हमने जांच किये, तथ्य हमने दिये और जो मृतकों वाली बात

(श्री सांवर लाल)

है, जो कारण हमारी जानकारी में आये हैं, आपको बता दूं, उनके स्वयं के परिजनों द्वारा उनके पोस्टमार्टम नहीं करवाये जाने के कारण उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन उनकी बैक हिस्ट्री के आधार पर जो मेडिकल विभाग ने रिपोर्ट दी है, वह हमने बार-बार बताने की कोशिश की है। जैसे श्रवण कुमार लखोटिया, उम्र 60 वर्ष, हार्ट अटैक से, श्री रामप्रसाद सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी, पुराना दमा रोगी, तीसरा, बलवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह, उम्र 25 वर्ष, यह भी पीलिया रोग से लंबे समय से पीड़ित था। इसी प्रकार से 15.11.2007 को ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): एक मिनट, एक मिनट।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपका तो वाक आउट हो गया ना इस विषय पर ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ऐसा मत करें। मेरा प्रश्न है, इसको क्यों डिस्टर्ब करते हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं ...(व्यवधान) बीच में टोका-टोकी नहीं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): क्यों डिस्टर्ब करते हो, आप बैठें तो सही ...(व्यवधान) बाद में पूछ लेना ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने अलाऊ नहीं किया तो नहीं पूछेंगे ...(व्यवधान) जवाब मेरा पूरा आने दें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं करायें ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): जितना इनका हक है उतना ही मुझे भी हक है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में टोका-टोकी नहीं करें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मेरे हिसाब से दूषित जल सप्लाई नहीं हो रहा है कहीं पर भी अगर टेलीफोन आयेगा तो हम टैंकर से सप्लाई करेंगे। कोई भी मौत पीने के पानी की वजह से नहीं हुई हैं। मैं सदन के माध्यम से जयपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे अधिकारी हर जगह पर ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर, एक मिनट ...(व्यवधान) कांग्रेस के सदस्य जिस विषय पर एक बार धरना दे चुके, एक बार वाक आउट कर गये, प्रतिपक्ष ...(व्यवधान) ऐसा नहीं कर सकते हैं यह नियमों में है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी अपने स्तर पर सैंपल लाकर के अपने हिसाब से जांच कराने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई टूंटियों से लाता है तो हमारे सामने लाये। कौन कहां से ले रहा है, सरकार की जानकारी में ही नहीं है। हमारे यह जो सैंपल हैं बिलकुल औथेंटिक हैं। हमारा पानी जहां से सप्लाई होता है, वहां से अगर किसी को शिकायत है तो हमारे अधिकारी को मौके पर बुलवायें, उनके सामने सैंपल भरवायें तब मैं कहूंगा कि इसमें यह दोषी हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसकी परमिशन से बोल रहे हैं, कोई अंकित नहीं हो रहा है, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समय बर्बाद मत कीजिये सदन का, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

(1) प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से पूर्व सैनिकों के पुर्नवास के सम्बन्ध में।

(2) श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले में पृथक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से कालाडेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य की ओर से माही डेम की दांयी मुख्य नहर के कठांव माइनर के टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुखलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर के राजकीय विद्यालयों में पंजाबी विषय की विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(7) श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से सांचौर में एस सी, एस टी बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

(8) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से लाचार व गरीब वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, भीम में व्याख्याताओं, मंत्रालयिक कर्मचारियों के सृजित पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(11) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से नगरपालिका/नगर परिषद् के चेयरमैन, नगर निगम के महापौर, पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव जनता के मत द्वारा करने का अधिनियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि यह सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई हैं।

(नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पर्ची के माध्यम से प्राप्त मुद्दे।

श्री केसरदेव बाबर, सीकर में विश्वविद्यालय स्थापित करने बाबत। श्री मांगीलाल गरासिया, एस डी एम कोर्ट, गोगुन्दा में नहीं खोलने से किसानों को हो रही समस्या के सम्बन्ध में। श्री राजकुमार रिणवा, गौ वंश वध को रोकने एवं मिनी गौ शालाएं गांवों में खोले जाने के सम्बन्ध में। श्री हरिसिंह रावत, भीम विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में।

आज पर्चियों के सम्बन्ध में चर्चा न होकर 26 फरवरी को वापस इन्हीं पर्चियों पर चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006-07

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007,

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल),

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-07

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

ग्राम सरपंच का झौंपड़ा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्राम सरपंच का झौंपड़ा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोखर/गांगवा में 33 के वी, जी एस एस की स्वीकृति जारी करवाने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परबतसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोखर/गांगवा में 33 के वी, जी एस एस की स्वीकृति जारी करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

निवाई सामुदायिक चिकित्सालय को ट्रोमा हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने बाबत

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवाई सामुदायिक चिकित्सालय को ट्रोमा हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2007-08 (दो प्रतिवेदन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरलाल सिंह खर्रा, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2007-2008 समिति के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2007-2008 के षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुनर्स्थापित बोल गए, पुरःस्थापित होता है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वही तो बोला है, पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कर दिया, साहब।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 4 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं, विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

भारतीय जनता पार्टी- 2 घण्टे, 26 मिनट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस 1 घण्टे 06 मिनट, इण्डियन नेशनल लोकदल- 2.5 मिनट, जनता दल (यूनाइटेड)- 1.5 मिनट, बहुजन समाज पार्टी- 4 मिनट, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)- 2.5 मिनट, लोक जन शक्ति पार्टी- 1.5 मिनट, निर्दलीय- 16 मिनट। कुल समय- 4 घण्टे।

मैं सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि विरोधी पक्ष के नेता और सदन की माननीय नेता ने सर्व सम्मति से यह तय कर दिया है कि शाम के साढ़े छह बजे से पहले-पहले यह सारा डिस्कशन समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे बीच में मारीशस के प्रधान मंत्री, श्री नवीन रामगुलामजी आएंगे, जिनका असेम्बली की तरफ से स्वागत किया जाएगा। (व्यवधान) आ चुके हैं, शाम के छह बजे उपस्थित होंगे सदन में विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठेंगे और सदन की तरफ से उनको आदर सत्कार दिया जाएगा। श्री शांतिलाल जी, चपलोत। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं अपनी एक बात करना चाहूंगा, मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विराजो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं इस सदन का सदस्य हूं, जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे दें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: किस बात पर?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कतई समय नहीं लूंगा, मैं आसन के निर्णय का सम्मान करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट चपलोत साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन की व्यवस्था हो गई और आसन ने प्रस्तावक का नाम पुकार लिया।

श्री उपाध्यक्ष: अब इस बारे में क्या बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसको बाद में बोल लेना। आपकी पार्टी की तरफ से समय लेकर बोल लेना, अपनी पार्टी के व्हिप को नाम दे दें और यह बोल लें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): रामनारायणजी, बाद में बोल लेना।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आपकी जनता ने यह थोड़े कहा था कि उपाध्यक्षजी के आदेश होने के बाद ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष: किस विषय में बोलेंगे?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा तो इतना सा अनुरोध है, मैं सम्मान करता हूं आसन के निर्णय का। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने मुझे यहां भेजा है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): जनता यह कहकर नहीं भेजती कि विधान सभा में स्पीकर का आदेश नहीं मानना। यह कहा है क्या आपको जनता ने?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 फरवरी को हमारे राज्यपाल महोदय ने हमारी विधान सभा में पधार कर हमें कृतज्ञ किया और अपने अभिभाषण में यह कहा कि राजस्थान विकसित प्रान्तों की श्रेणी में आ गया है, राजस्थान अब बीमारू प्रदेश नहीं रहा है। राजस्थान विकसित प्रान्त के रूप में आगे आ रहा है, किसी भी प्रकार से अब बीमारी की स्थिति में नहीं है। मैं, राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं उन्होंने इस प्रकार की बात कही। हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में जो काम किये हैं वे इतिहास में अमिट रहेंगे, अमर रहेंगे। इस प्रकार के काम कभी नहीं हुए। जिस प्रकार से योजना का आकार बढ़ाकर काम किये गये उसके लिए मुख्य मंत्रीजी, उनके मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

आदरणीय उपाध्यक्षजी, हमारी सरकार ने चराचर के सुख की कल्पना की है। "सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु:ख भाग्भवेत्।" सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग अच्छे हो, सभी लोग अच्छी तरह से काम कर सके, उसके लिए चराचर के सुख की कल्पना की है।

आदरणीय उपाध्यक्षजी, 19.1.2004 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बजट के पहले राज्यपालजी का अभिभाषण हुआ, उससे लेकर आज तक हमने इस प्रकार के काम करके बताये हैं कि भूतो न भविष्यति।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कांग्रेस के शासन में पांच सालों में 1575 दिन राज्य करीब-करीब ओवरड्राफ्ट में रहा। हमारी मुख्य मंत्रीजी के समय में केवल 5 दिन फरवरी, 2004 में ओवरड्राफ्ट में रहा, उसके अलावा कभी भी हमने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का सवाल है। कुशल वित्तीय प्रबंधन जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने किया है उसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार हम देखें और उससे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना करें आज वह दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है। उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं।

दिसम्बर, 2003 में जब हमने राज संभाला उस समय राजस्थान कितने कर्जे में था। परिसम्पत्तियों के नाम पर कोई परिसम्पत्तियां पांच साल में विकसित नहीं हो पाईं, किसी प्रकार की सरकारी नौकरियां युवकों को नहीं

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मिलीं। हे भाइयों, हे युवकों, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस तुम्हारी बहबूदी के लिए काम करेगी। हे युवकों, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस तुमको नौकरियां देगी। क्या किया उन्होंने? 60 साल से 58 साल किया, लेकिन एक को भी नौकरी मिली? मैं आज कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं एक को नौकरी मिली? हमारे शासन में हमने एक लाख से ज्यादा अध्यापक भर्ती किये और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले तो राजस्थान की सरकार को मिले, किसी भी कांग्रेस शासन को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिला।

मैं क्योंकि आज समय कम है, इसलिए मैं शार्ट में कहूंगा, सड़कों के मामले में माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान इस देश में सर्वप्रथम रहा है, इस प्रकार का काम सड़कों का किया है।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो केन्द्र सरकार ने दिया उसमें भी राजस्थान सर्वप्रथम रहा है। उदयपुर में हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय आये थे, मैं भी उनसे मिला था, रघुवंश प्रसाद सिंहजी ने कहा राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सर्वप्रथम है, उसने जितना काम किया है किसी भी सरकार ने काम करके नहीं बताया है। सारी की सारी केन्द्र सरकार हमारी प्रशंसा कर रही है, योजना आयोग हमारी प्रशंसा कर रहा है। योजना आयोग ने भी कहा है कि राजस्थान की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और उन्होंने इसीलिए हमको 59 करोड़ रुपये उस समय भी ज्यादा दिया और पांच वर्षों में जो 20220 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इन चार वर्षों में हमने उसका दुगुने के करीब 34140 करोड़ रुपये खर्च करके बताया है1 कहां तो 20 हजार पांच साल में, कहां चार साल में 34 हजार करोड़ रुपया।

मैं माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना चाहता हूं इस साल की योजना, मोंटेक सिंहजी अहलुवालिया, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं उन्होंने राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को देखकर राजस्थान सरकार की सराहना करके 14 हजार करोड़ की योजना स्वीकार की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना जितनी नहीं है उससे भी ज्यादा एक वर्ष की योजना योजना आयोग ने स्वीकार करके बतायी है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का सवाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सकल घरेलू उत्पाद 1999-2000 में 73 हजार करोड़ का था जो अभी 2006-07 में एक लाख 25 हजार 656 करोड़ हुआ। सकल उत्पाद डेढ़ा हुआ। ये उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पर केपिटा इनकम अशोकजी गहलोत की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में केवल मात्र 13 हजार रुपया थी जो बढ़कर अभी 19 हजार रुपया हो गई है। इस प्रकार से हमने काम करके बताया है।

अभी रिसर्जेंट राजस्थान, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने लिया। विदेश से हमारे प्रवासी भाई यहां आये। हमारे भाइयों ने, जिन्होंने सारी दुनिया में झण्डा गाड़ा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं भगवान राम ने लंका को जीता और जब लंका को जीता तो लक्ष्मण के मन में आया, हे राम, हमने अपने बाहुबल से लंका को जीता है, अब क्यों न हम लंका में बस जाएं, इसलिए यहीं रह जाते हैं। भगवान राम ने कहा, ''अपि येः स्वर्णमयी लंका, न में लक्ष्मण अस्ते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे।'' हे लक्ष्मण, यद्यपि यह सोने की लंका है, धन-धान्य से परिपूर्ण है, किन्तु इसमें मेरी रुचि नहीं है। मैं तो वापस अपने देश जाऊंगा, भले ही यह धन-घान्य से परिपूर्ण हो। हमारे प्रवासी भारतीयों ने दूसरे देशों में झण्डा गाड़ा, खूब काम किये, उन्होंने भी यहां आकर आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा उतना काम करके और इतने एमओयू साइन हुए, एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। सारे हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत में इतने एमओयू साइन नहीं हुए, किसी भी प्रांत में इस प्रकार का काम नहीं हुआ। यद्यपि गुजरात और मैसूर स्टेट में हुए या आंध्र में एमओयू हुए, किन्तु हमारे यहां जो एमओयू हुए वे सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बढ़कर हुए, उसके लिए मैं हमारी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं।

अभी हमारा टैक्स का सरलीकरण हुआ। टैक्स के सरलीकरण से और शांत राजस्थान होने की वजह से विश्व बैंक ने प्रशंसा की। विश्व के सारे देशों ने प्रशंसा की। विश्व बैंक ने प्रशंसा की और ''Doing Business in South Asia – 2007'' यह एक बुक निकाली, उसमें भी कहा है कि जयपुर 12 नगरों में से एक है, चेन्नई और मुम्बई से बढ़कर जयपुर को माना है। इसलिए आज हमारे यहां निवेश का एक वातावरण बना है, निवेश के लिए एक वातावरण बनाना आवश्यक है, वह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने करके बताया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में चार वर्षों में 5334 करोड़ रुपये व्यय किये गये, 5334 और जब कि पहले पांच वर्षों में तीन हजार करोड़ और चार साल में पांच हजार से ज्यादा यानी डबल। एक साल का और हिसाब लगाओ तो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। इतना काम करके हमने बताया है। रोजगार गारंटी

(श्री शांतिलाल चपलोत)
में हमारा प्रांत जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, प्रथम रहा ग्रामीण विकास में भी और भी कामों में प्रथम रहा। उदयपुर जिले में भी हमारे बिवार वाटरशेड में गिरवा और मावली तहसील सर्वश्रेष्ठ घोषित की गई। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने, 27 दिन का, योजना आयोग ने कहा है, वाटरशेड वालों ने भी कहा है, केन्द्रीय मंत्रीजी ने भी कहा है कि 27 दिन का रोजगार सारे राष्ट्र में जहां रोजगार गारंटी के काम चल रहे हैं वहां 27 दिन का रोजगार मिल रहा है पर हमारे यहां 54 दिन का रोजगार आया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों से भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपने काम तो बहुत कराया है, मेरा एक सुझाव भी है, इसमें आप जितनी सीसी रोड बना सकें गांव की क्योंकि अब रोजगार गारंटी का काम सारे ही प्रांत में चलने वाला है, अभी 12 जिलों में चल रहा है, अब सारे प्रांत में चलने वाला है, उन सभी प्रांत के 33 जिलों में जब काम चलेगा तो उसमें सीसी रोड गांव में बनाने की अनुमति दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा गंदगी हट सके और गांव स्वच्छ नजर आने लगेंगे।

इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है। हमारे यहां अभी तक स्कूल की बावण्डरी वाल का कहीं कोई मद नहीं है। केन्द्र सरकार को हमने भी लिखा है, मैंने भी चिट्ठियां लिखी हैं, मुख्य मंत्रीजी ने भी लिखी हैं, किसी प्रकार का कोई मद नहीं है, किसी प्रकार का बावण्डरी वाल के लिए पैसा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, लोग क्योंकि जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं इसलिए रोजगार गारंटी में बावण्डरी वॉल ली जाए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। यह माननीय पंचायत मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दें और केन्द्र सरकार को भी उसके लिए लिखें। हमने 1,64,809 होल पोंड बनवाये, टांकें बनवाये, खुदवाये, इन्दिरा आवास में 25 हजार रुपये मिल रहा था, हमारी सरकार ने कि यह जानते हैं सीमेंट का भाव बढ़ गया है, केन्द्र सरकार ने नहीं किया, पर हमारी सरकार ने उस 25 हजार को 50 हजार रुपये कर दिया है, इससे ज्यादा क्या काम हो सकता है? परदुःख कातरता हमारे मन में है। 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई, परपीड़ा सम, नहिं अधमाई' परहित के समान कोई काम हो नहीं सकता, जो हमारी सरकार कर रही है, सारे गरीब लोगों के लिए गरीब को दरिद्र को नारायण समझ करके हमने उसके लिए 25 हजार का जो आवास है उसको 50 हजार का किया है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल ग्रहण में भी पूर्व सरकार ने पांच सालों में 594 करोड़ रुपये खर्च हुआ, एक साल का सौ करोड़ रुपये ऊँट के मुंह में जीरा जितना है, जबकि जल ग्रहण के लिए हमारी सरकार ने इन चार वर्षों में 1050 करोड़ रुपये खर्च किये, दुगुने, इस जल ग्रहण से हमारी मिट्टी रूकेगी, मृदा का संरक्षण होगा और इस जल ग्रहण से हमारी खेती का काम अच्छा होगा। इस बात को सोच करके काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए जल ग्रहण में इस प्रकार के काम हमने किये हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी सरकार ने 80,500 विद्यालयों में 94 लाख बच्चों को मिड-डे-मिल दिया, 80,500 स्कूलों को 94 लाख, इतना बड़ा काम और यही नहीं, हमारी खनिज रायल्टी आती है, उस खनिज रायल्टी का एक परसेंट हमने पंचायतों को देने का फैसला किया है, उसमें भी करोड़ों रुपये 23-24 करोड़ रुपये हमने हमारी पंचायतों को दिया है। माननीय उपाध्यक्षजी, समर्पण संस्था में कुल 7 लाख 25 हजार 563 आवासीय शौचालय बनवाये और 33 हजार 818 स्कूलों में यह हमने शौचालय बनवाये। माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले से 40 गुना बनवाये। पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले में हमने 40 गुना ज्यादा शौचालय गांव के गरीबों के लिए भी और स्कूलों के लिए बनवाये। इस प्रकार से हमने काम करके बताया है। यह एक देखने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चपलोतजी, आप चार-पांच मिनट में कनक्लूड करें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): जरूर, आप कहेंगे जितनी देर में ही करूंगा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है। पहले जो 2020 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पूरे पांच सालों में और अब की बार हजारों करोड़ रुपये खर्च करके काश्तकारों की बहबूदी को बढ़ाया है और अतिरिक्त खालों का निर्माण कराया है, माही और चम्बल परियोजना पर 15 हजार 682 हेक्टेयर में सुधार का काम किया है और ऐसे भी अलग और जगह काम किये हैं, एक लाख व्यक्तियों पर हमारे यहां पहले 270 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी उनको हमने बना करके अब इन चार सालों में 27 हजार किलोमीटर सड़क बनाई है, 27 हजार किलोमीटर जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, राष्ट्र का औसत है उससे भी ज्यादा है, कांग्रेस के समय में 4 किलोमीटर प्रतिदिन एक सड़क बनती थी, हमारे समय में 18 किलोमीटर

(श्री शांतिलाल चपलोत)

प्रतिदिन सड़क बनाई जा रही है, 18 किलोमीटर, माननीय उपाध्यक्षजी, चार सालों में 24 हजार 84 किलोमीटर हमने सड़क बनाई है चार सालों में और 60 हजार 673 करोड़ हमने इस पर खर्च किया है। माननीय उपाध्यक्षजी, 6 गुना से अधिक पूर्ववर्ती सरकार से 6 गुना से अधिक निर्माण का काम हमने करवाया है। आदरणीय उपाध्यक्षजी, जहां पर पानी की मार पड़ती है, रास्ते खराब हो जाते हैं, वहां कंक्रीट सड़क बनाने का भी काम हमने किया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों के बारे में हमने बहुत तरक्की की है, राष्ट्रीय औसत, माननीय उपाध्यक्षजी, कालेज एजुकेशन में राष्ट्र में 75 हजार पर एक कॉलेज है पर हमारे यहां 53 हजार पर एक कालेज है और हमने यह इसलिए किया है कि जिस राष्ट्र में पढ़ाई नहीं होती, लिखाई नहीं होती, बच्चे पढ़ लिख कर होशियार नहीं होते, वह राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है, 'माता शत्रु, पिता बैरी, ये न बालो पाठिता:, न शोभते सभामध्ये हंस बक: या तदै।' ...(व्यवधान)

अभी हमने निजी क्षेत्र में दो मेडिकल कालेज और 10 महाविद्यालय बनाने का निर्णय किया है। एक निजी संस्था को भी मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनापत्ति पत्र दिया है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ये चैलेंज कर रहे थे कि मेरे सामने नहीं बोल सकते संस्कृत का श्लोक।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यह बिलकुल सही कहा आपने। मैं इनका मुकाबला थोड़े ही कर सकता हूं। दो संस्थान मेडिकल कालेज के और कर रहे हैं और उच्च शिक्षा में राजस्थान आज की तारीख में राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। कुल मिलाकर के हमने 45 हजार स्कूल इन चार सालों में खोले हैं। रोज 30 स्कूल, जितने दिन हमने शासन किया है उसमें रोज के 30 स्कूल खोले हैं। इसमें जरा गलत छप गया है। आंकड़े देखें तो राज्यपालजी के अभिभाषण में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, छपने में गड़बड़ हो गई है। रोज 30 स्कूल और रोज 50 अध्यापकों की भर्ती की है। यह गवर्नर साहब के एड्रेस के 41वें पैरा में जो आया है...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी यह सरकार सही नहीं छपा पा रही है, यह सरकार की स्थिति है तो गरीब किसान का क्या होगा?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कोई बात नहीं, अपने में अक्ल है तो हिसाब लगाओ न। अक्ल है न। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपने जीरो उड़वा दिया, कलाकारी की है। (व्यवधान) 50 था उसका जीरो आपने उड़वा दिया, आपकी कलाकारी लगी है मीणाजी इसमें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गांव में करीब किसान का कोई धणी-धोरी नहीं है। मैं कहता हूं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का...(व्यवधान) एक हजार करोड़ का सौदा इसमें...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 4 साल में टेक्नीकल एजुकेशन में हमारा ढाई गुना प्रवेश बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कि मानसरोवर इलाके में एक हजार करोड़ रुपया बी. जे. पी. वालों ने खा-खाकर के किसी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें। यह अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो। बीच में आप नहीं बोलें। मैंने परमीशन नहीं दी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। उनको बोलने दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): टेक्नीकल एजुकेशन में ढ़ाई गुणा प्रवेश बढ़ा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 4 वर्ष में 51539 प्रवेश स्थान बढ़े हैं।

आदरणीय उपाध्यक्षजी, हमने पिछड़ों को भी आगे करने के लिए पूरी कोशिश की है। 12 जिलों में पालिटिकल कालेज, 18 जिलों में इंजीनियरिंग कालेज, 106 आई. टी. आई. निजी क्षेत्रों में भी दिये हैं। अभी 4 वर्षों में 45 हजार जो स्कूल खोले हैं वो तो कीर्तिमान है ही और उसके लिए केन्द्र के एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी हमारी बहुत प्रशंसा की है और हमें...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय चपलोत साहब, यह भी बता दीजिये कि इसमें केन्द्र से कितना पैसा मिला है आपकी स्कूल में। आप तो यह बता दें कि राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से सड़कों के ऊपर और स्कूलों के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। कुछ नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोकें नहीं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने पूछा है, केन्द्र में हमारा हिस्सा है, केन्द्र भारत से बना है, भारत में राजस्थान प्रान्त भी है। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, दूसरे टैक्स भी देते हैं। इसमें केन्द्र सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। यह हमारा अधिकार है और हम उसको लड़कर लेते हैं। यह हमारा अधिकार है और हमारी मुख्य मंत्रीजी की कुशलता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब एन.डी.ए. का राज था तब क्या हम टैक्स नहीं देते थे? तब क्यों नहीं हमको मिलता था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वाह-वाही ले रहे हैं। और तो और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। हम भी नहीं छोड़ेंगे, बीच में हम भी टोकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये टोकेंगे तो हम भी टोकेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पूर्व में योजनाओं का हिसाब भी नहीं भेजा कि कितना खर्चा किया था आप लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं और व्यवधान हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, 2000-01 में 52,78,966 बालकों और 35,52,305 बालिकाओं का एडमिशन हुआ और हमारे इन वर्षों में 68,59,635 बालकों तथा 56,13,775 बालिकाओं का एडमिशन हुआ है। साक्षरता बढ़ाने के लिए डेढ़ा काम हमने इन वर्षों में करके दिखाया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे सदस्य कह रहे थे, हमने मदरसों को भी अछूता नहीं छोड़ा है1 मदरसों में 1,72,000 बच्चों को, छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें बांटी हैं। आदरणीय उपाध्यक्षजी, 330 मदरसों को कम्प्यूटरीकृत किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं तो खुद ही मदरसों में नहीं पढ़ा, हम तो स्कूलों में पढ़े हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 330 मदरसों को कम्प्यूटरीकृत किया है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कनक्लूड कीजिये। एक मिनट में कनक्लूड कर दीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में 487 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बी.एड. कालेज हमने खोले हैं। पहले 29 थे और उनके मुकाबले में 487 खोले। 164 में निजी शिक्षण प्रशिक्षण, एस टी सी खोली। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन का प्रचार-प्रसार हम कर रहे हैं।

हमारे सांवर लालजी, जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं, यहां नहीं है कोई बात नहीं, स्वच्छ जल के लिए 14480 करोड़ रुपया खर्च किया, स्वीकृति दी 4 वर्षों में। 14480 करोड़, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। माननीय उपाध्यक्षजी, 11412 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, शेष की स्वीकृतियां जारी होनी बाकी हैं। यह इतना काम करके बताया है। 841 गांवों में, 2 हजार ढाणियों में 7 हजार नलकूप और एक लाख एक हजार से ज्यादा हैण्डपम्प लगाकर के बताया है। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा रुपया पीने के पानी के लिए दिया है उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

चिकित्सा सेवा में भी राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज दिगम्बर सिंहजी मुझे यहां नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना

(श्री शांतिलाल चपलोत)

चाहता हूं कि उन्होंने भी खूब काम करके बताया। हमने संस्थागत प्रसव जो होते हैं उनको भी बढ़ाया है। पहले 28 थे, अब संस्थागत प्रसव 50 हो गये, यानि डबल हो गये। सरकार इन पर खर्चा कर रही है। 10 हजार से ज्यादा खर्चा कर रही है। बच्चों के लिए भी इस प्रकार का काम किया है।

बी. पी. एल. परिवारों के लिए हमने नि:शुल्क चिकित्सा का काम किया है और 5 जिलों, गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य बीमा प्रारम्भ किया है जिससे 7 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इतना बड़ा काम चिकित्सा के क्षेत्र में किया है।

चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा का ऐसा काम कृषि क्षेत्र में भी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। मैं नाम पुकार रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सड़क में भी हुआ है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): सड़क में तो कह दिया। 4 गुणा से ज्यादा अनाज, दलहन, तिलहन की वृद्धि हुई, दो गुणा से 3 गुणा ज्यादा हुआ। ग्रीन हाउस, टिश्यू कल्चर, झालावाड़ में लेब बनाई गई, गंगानगर में भी हुआ और एयरपोर्ट, जयपुर में कूलिंग चेम्बर की भी स्थापना की जिससे कि माल काश्तकार हिन्दुस्तान के बाहर भी बेचना चाहें, भेजना चाहें तो भेज सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद चपलोत साहब। बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, डी ए पी खाद का आज तक कभी राजफैड ने भण्डारण नहीं किया। यह हमारी सरकार की तारीफ है कि उसने डी ए पी खाद काश्तकारों को देने के लिए उसका राजफैड के थ्रू भण्डारण किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): एक-दो टन नहीं, दो लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा भण्डारण किया है। इससे ज्यादा काश्तकारों के भले के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद चपलोत साहब। आधा घंटा हो गया है। मैं राव राजेन्द्र सिंहजी का नाम पुकार रहा हूं। स्थान ग्रहण कीजिये आप।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्षजी, क्योंकि मैंने ओपनिंग की है इसलिए मुझे दो घंटे का समय आपने कहा है और चीफ मिनिस्टर का समय अलग है, हमारे समर्थक भी बोलेंगे, मैं चार-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सहकारिता के क्षेत्र में भी 10,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 7,888 स्वयं-सहायता ग्रुप हमने बनाये हैं और कृषि आयोग ने भी हमारी काफी प्रशंसा की है।

विद्युत के क्षेत्र में तो बड़ा भारी कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्युत क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8,460 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीन गुना बढ़ाकर, 25,606 करोड़ हो गया है, तीन गुना हो गया है, बिजली के क्षेत्र में तीन गुना हो गया है। 1411 मेगावाट विद्युत उत्पादन चार वर्षों में हमने करके बताया है। 125 मेगावाट क्षमता की गिरल लिग्नाइट परियोजना, 330 मेगावाट क्षमता की धौलपुर गैस तापीय विद्युत योजना और पवन बायोमास 410 मेगावाट और गिरल की 125 मेगावाट की द्वितीय इकाई, छबड़ा में तापीय विद्युत परियोजना, सूरतगढ़ में भी काम किया है और 250 मेगावाट और 195 मेगावाट के हमने कारखाने स्थापित किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस तरीके से काम हो रहा है, यह सारी जनता जान गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्रीजी मुझे यहां नजर नहीं आ रहे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। चार वर्षों में 400 के.वी. के दो, 200 के.वी. के 11 और 132 के.वी. के 47 सब-स्टेशनों का काम पूरा किया है और 33 के.वी. के तो 736 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर सारे हिन्दुस्तान में नाम किया है राजस्थान ने बिजली के मामले में। छीजत भी हमारे यहां कम हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद चपलोत साहब। एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैंने पांच मिनट का समय मांगा था। और छीजत कम होने की वजह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली में...

श्री उपाध्यक्ष: लास्ट, आप एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): हां, मैं कर रहा हूं। बिजली में छीजत कम होने से आज हमारे यहां कई गांव हैं, 18-19 हजार गांव हैं जिनको 24 घंटे बिजली दी जा रही है छीजत कम होने की वजह से और छीजत कम होने से 15-16 हजार गांवों को बराबर, कंटीन्युअस बिजली और दी जायेगी, ऐसा मेरा मानना है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमको गर्व है कि प्रतापगढ़ भी एक जिला बनाया गया जिसमें धरियावद मिलाया गया, पीपलखूंट, छोटी सादड़ी, अरनोद, ये उपखण्ड खोले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना काम हमारी सरकार ने करके बताया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 41 स्थानों का चयन किया है आई.एस.ओ. मार्का के लिए, 165 को प्रमाणीकरण जारी किया गया। 17 जिलों के 320 थानों को कम्प्यूटरीकृत किया, 162 नई चौकियां बनाई गईं। हाड़ी रानी आर्म्स बटालियन गठित की गई। इतने बड़े काम हमारी सरकार ने करके बताये हैं। एक-दो नहीं, 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती किये गये हैं। 8,168 की भर्ती हो गई है और 3,000 की और प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार का काम किया है। राजस्थान पहला राज्य है जिसमें पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम बनाया गया है। केवल तीन राज्य हैं हिन्दुस्तान में जिनमें इस प्रकार का काम हुआ है और जो राजस्थान में भी हुआ है।

आदरणीय उपाध्यक्षजी, कच्ची बस्तियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार चुंगी समाप्त करने पर केवल पांच प्रतिशत का अनुदान म्युनिसिपेलेटीज को देती थी, हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसको 10 प्रतिशत किया है। इससे ज्यादा क्या काम हो सकता है।

सामाजिक न्याय और आधिकारिता के द्वारा भी 400 करोड़ रुपये उस पर खर्च किये गये हैं, यह अपने आपमें एक कीर्तिमान है। माननीय दिलावर जी ने सामाजिक कामों में बहुत रुचि दिखाई है। उत्तर मैट्रिक छात्रों को, एस.सी. एस.टी. के बच्चों को पांच वर्षों में 103 करोड़ रुपये दिये जबकि चार वर्षों में हमने 214 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था, विकलांग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भी बता दो माननीय सदस्य कि केन्द्र सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने बच्चों की छात्रवृत्ति के कितने पैसे रोक रखे हैं? 58 करोड़ 35 लाख रुपये रोक रखे हैं, दिला दो देखें?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): केन्द सरकार ने अभी काफी पैसा हमारा रोक रखा है 60 करोड़ से ज्यादा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बोल रहे हैं उनकी जगह पर? आपको उनकी बुद्धि पर भरोसा नहीं है क्या? उनकी बुद्धि पर भरोसा नहीं है क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाटरशैड के भी 150 करोड़ रुपये बाकी है, वाटरशैड के भी बाकी है।

एक माननीय सदस्य: हरिमोहनजी, ये स्मरण दिला रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): पहली बार इस सरकार ने पाला पड़ने पर 126 करोड़ रुपये काश्तकारों को देने की घोषणा की है। आज तक कभी भी हिन्दुस्तान के इतिहास में और....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): इस राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। 126 करोड़ रुपये केवल पाला में दिये हैं। केन्द्र सरकार से हम मांग करते हैं, जो पाला से ग्रसित हो गये हैं, फसलें खराब हो गई हैं कि केन्द्र सरकार 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान करे। मैं मदेरणा साहब को, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आज उन्होंने केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे उस चिट्ठी का ओनर करें और 1,000 करोड़ रुपये उन्होंने मांगे हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने 2006 के अभिभाषण में यह वादा किया है...

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, बीच में नहीं माननीय सदस्य। आपका नम्बर आएगा माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 2006 के अभिभाषण में यह वादा किया है कि हम ऐसा कोष बनायेंगे जिसमें सी.आर.एफ. के तहत जिनको सहायता नहीं भी दी जाती है, इस कोष से उनको सहायता पहुंचायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चपलोत साहब, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप अपने भाषण में कहना, क्या कांग्रेस पार्टी ने समय दे दिया बोलने का?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...क्या दिक्कत है, कोई एहसान है? आपने 2006 में वादा किया है कि हम अलग से कोष बनायेंगे, सी.आर.एफ. के नियम जहां लागू नहीं होते, उनमें हम सहायता देंगे तो आप दे रहे हैं तो क्या हम पर एहसान कर रहे हैं क्या? आपने 2006 में कह दी थी यह बात।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका बोलने का नम्बर जल्दी आएगा, आप धैर्य रखिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हरिमोहनजी, 150 करोड़ रुपये वाटरशैड के बाकी हैं, वह तो दिलवा दो केन्द्र सरकार से। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्र सरकार ने जितना पैसा दिया है ना, यह...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह कांग्रेस के सदस्यों की केन्द्र सरकार में, भारत सरकार में चलती नहीं है। अगर चलती तो जनता में प्रचार करते कि हम लाये हैं पैसा। इनकी चलती तो है नहीं। इनकी सदन में नहीं चलती, सदन के बाहर नहीं चलती (व्यवधान) इसलिए आपका अगर कोई प्रभाव है तो भारत सरकार पर दबाव बनाकर किसानों को मुआवजा दिलवाओ आप। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो पैसा है, वह राजस्थान की जनता का पैसा है, राजस्थान का हिस्सा है उसमें, कोई एहसान नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ...और अगर किसानों के हितैषी हो तो किसानों को मुआवजा दिलवाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। हो गया माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): ...विधवा हो गई हैं माताएं, उनकी बच्चियों की शादी के लिए सरकार ने 6,549 बालिकाओं की शादी हेतु सात करोड़ रुपये खर्च किये हैं इन चार सालों में, पूर्ववर्ती सरकार ने पांच सालों में तीन करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद माननीय चपलोत जी, समाप्त कीजिये अपना भाषण। अपना भाषण कनक्लूड कीजिये। मैं नाम पुकार रहा हूं चपलोत साहब।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी सहायिकाएं पहले 35,675 थीं और अब 51,063 हो गई हैं। पहले थीं 35,000 और अब हो गई हैं 51,063, इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 500 रुपये था, 250 रुपये और बढ़ाया है। इससे बड़ा काम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मैं नाम पुकार रहा हूं शांतिलालजी।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं इतना ही कहते हुए, एक शब्द में अपनी बात खतम कर रहा हूं। राज्य को राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शिक्षा में साक्षरता के लिए यूनेस्को में अन्तरराष्ट्रीय यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार, 2006 अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राजस्थान को प्राप्त हुआ है। राजस्थान दुनिया का एकमात्र राज्य है और अब इसके बारे में आपको क्या कहना है कांग्रेस के भाइयों? राजस्थान एकमात्र राज्य है, मैं इसके लिए हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय घनश्यामजी तिवाड़ी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का काम करके बताया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर हटाया क्यों उनको? सारे अभिभाषण में घनश्यामजी के मंत्रालय की तारीफ कर रहे हो तो हटाया क्यों?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कहां हटाया? मंत्री हैं ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चित्र देखिये, सर्वजन हिताय, उदीयमान राजस्थान, इनमें मुख्य मंत्रीजी ने जो आदिवासी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जो दूर-दराज में रहती हैं, साइकिलें तो 16,000 को दी हैं, मोटर-साइकिलें और स्कूटी दी हैं जिस पर बच्ची चला रही है और मुख्य मंत्रीजी पीछे बैठी हुई हैं, यह चित्र है। यह उदीयमान राजस्थान है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आपने मुझे समय दिया उसके लिए तो धन्यवाद, वर्ना पर्यटन के क्षेत्र में हमारा रोजगार बढ़ा है। सारे लोग इस पर्यटन के लिए इस राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थान जैसा प्रांत नहीं है, स्वर्ग है तो यहां है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक वह यूएनओ का अवार्ड मिला था न, यूएनओ का।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अभिनिस्तो, अभिनिस्तो, अभिनिस्तो। स्वर्ग है तो यहीं है। स्वर्ग है तो यहीं है। यही बात कहकर के क्योंकि समय तो कम है और ऐसे ही सब में, उद्योग में काफी काम हमने किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चपलोत साहब, वह यूएनओ के अवार्ड का भी बता दो न। वह कौन सा यूएनओ का अवार्ड मिला था न।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यूनेस्को। यूनेस्को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं-नहीं, यूएनओ का मुख्य मंत्रीजी को मिला था न। आपने बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये थे न जयपुर में।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): लगाये हैं न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यूएनओ का वूमेन टूगेदर अवार्ड। यूएनओ का वूमेन टूगेदर अवार्ड।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): होर्डिंग और लगायेंगे और हिन्दुस्तान के तख्ते-ताज पर झण्डा गाड़ेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान की जनता को गुमराह किया है। एक एनजीओ के अवार्ड को यूएनओ का अवार्ड बता कर पूरे राजस्थान की जनता को गुमराह किया है आप लोगों ने। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मावली से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सदन की एक परम्परा है और सामान्यत: राज्यपाल सरकार की दिशा और दृष्टि को स्पष्ट करता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के द्वारा संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं के अन्तर्गत हम अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं। कई-कई बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक रिचुअल सा लगने लगता है, कुछ बातें तय हैं, कुछ सीमाएं तय हैं और अगर इन बातों और सीमाओं से कोई सच्चाई इससे परे है तो बरबस वह छोड़ दी जाती है। इस सम्पूर्ण परिशिष्ट में एक व्यापक सच्चाई जो सामने उजागर होती है उसके अवतरण के अंदर यह बात अनुभव की जाती है लोकतंत्र के इस मर्यादित सदन में दलतंत्र के आगे प्रजातंत्र ने घुटने टेक दिये हैं। कुछ बात जो इतनी सच होती है, इतनी स्पष्ट होती है, इतनी प्रखर होती है लेकिन इस सदन के किस हिस्से में हम बैठे हैं वह हमको दायरे और परिधि से सच्चाई को उल्लेखित करने में परेशानी उत्पन्न करता है। इन मर्यादाओं से परे हट कर कुछ ऐसा विवेचन है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आज की परिस्थिति में हम बीसवीं शताब्दी से इक्कीसवीं शताब्दी में आ गये। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था का आज इजहार नहीं हुआ है। इस लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस उत्तरदायित्व के नाते हम नेतृत्व की शक्ति से यहां पदस्थापित हुए हैं, उस नेतृत्व ने आखिर इस लोकतंत्र के लिए और इस लोक के लिए और इस जन के लिए क्या किया है और अगर वह सच्चाई से परे है तो वह मिथ्या है और आज इस बात को मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि चार साल के इस शासन के काल में एक आम जन की जो भावना थी, जो उसकी अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षओं पर खरा उतर कर इस सरकार ने उस लोकतंत्र के अंदर वह सारी चीजें प्रतिस्थापित करी हैं जो कभी शास्त्र ने अनुचित होने के नाते भी चरित्र के बल के साथ में हमें आगाह किया था कि प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप जनता की भावनाओं का स्वरूप होता है। जहां आंकड़ों से और यहां संख्या से लोग-बागों को नहीं गिना जाता, यहां भावनाओं से गिना जाता है और जिस शासन के चरित्र के अंदर भावनाएं हैं, मर्म है, सौहार्द्र है, वह शासन आज अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करते हुए आपके बीच में उपस्थित हुआ है।

मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, आने से पहले, आदरणीय, मेरे एक तेरह साल का लड़का है, उसने मुझसे एक बात यह पूछी कि आखिर चार साल, साढ़े चार साल के इस काल के अंदर हुआ क्या है जिसके बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, तो मैंने सहज भाव से कह दिया एक परिवर्तन हुआ है। क्योंकि यह बच्चे आजकल कम्प्यूटर ज्यादा चलाते हैं तो उसने कहा कि चेंज का क्या मतलब होता है, चेंज तो मैं आज रंगीन कपड़े पहने हुए हूं, कल सफेद कमीज पहन लूंगा, यह भी एक चेंज है। जब यह बात मुझसे कही गई तो शायद मैंने यह जरूरी समझा कि आज इस सदन में यह भी बता दूं कि चेंज का वास्तविक अभिप्राय क्या है, कि परिवर्तन का वास्तविक अभिप्राय क्या है। अगर लिटरल कंटेंट हम लें कि बर्नार्ड रसेल ने एक बात कही है – "Change is scientific .." हमने यह कहा कि परिवर्तन था, परिवर्तन जनता के हाथ में था, उन्होंने कर दिया। लेकिन उस परिवर्तन की शैली में हमने क्या किया। हमने इसमें सिर्फ चेंज के आगे प्रोग्रेस लगा दी। Change is scientific and progress is ethical. Change is indubitable, whereas progress is a matter of controversy. और यह जरूर है कि जब चीज हम कहेंगे कि हमने यहां प्रोग्रेस किया है तो वहां से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कहीं से आवाज उठेगी कि नहीं, यह बात सत्य नहीं है क्योंकि आखिर यह एक लिटरल कंटेंट है। लेकिन एक बात बताइये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री का उस पर चित्र था और उस पर यह बात लिखी हुई थी सहज भाव से, अपने बच्चे को एक गिलास दूध पिलाइये। That was a change. किसी मुख्य मंत्री ने कभी भी पिछले इतने दशकों के अंदर उस आम छोटे से बच्चे का कि जो शायद अगले इलेक्शन के अंदर वोट देने की भी मर्यादित उम्र नहीं प्राप्त करेगा, वहां यह लिखा हुआ था, अपने बच्चे को एक गिलास दूध पिलाइये। Wasn't that a change? लेकिन अगर वहां से और अगर हम आगे चले जाते हैं कि जब मां उस गिलास के दूध को बच्चे को पिलाती है और दूसरे हाथ से एक गिलास दूध को बच्ची को भी पिलाती है, that is progress कि एक ब्वाय चाइल्ड से गर्ल चाइल्ड की महत्ता को समझाने में जो इस सरकार ने और इस सियासी नेतृत्व ने किया है कि बच्चियां भी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर बच्चे हमारे घर के पालक हैं तो बच्चियां प्रदेश और राष्ट्र की पालनहार है। यह सारी की सारी व्यथा को किस मार्मिक दृष्टि से उन्होंने पहुंचाया है, यह हमारी भावी योजना है और योजनाओं को हमने आज धरातल पर उतार दिया है, वह इस मर्म की जीती-जागती तस्वीर है।

मैं, आदरणीय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी ने यह बात कह दी कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाये, मैं उस शब्दावली का वापिस इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में एक बार-बार बात उजागर होती है कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह चाहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाये। मैं यह नहीं कहता कि उनके जमाने में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छे काम हर प्रजातंत्र की सरकार करती है लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि बेबस हो जाते हैं, तो किसी ने कहा है कि आखिर इन परिस्थितियों से आप कैसे पार लेंगे। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही है कि "The reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable man persists in trying to adapt the world to itself. Therefore, all progress depends upon the most unreasonable man." जब मोस्ट अनरीजनेबल मेन हों, जब मोस्ट अनरीजनेबल परिस्थितियां हों, जब सारी की सारी स्थितियां प्रतिकूल हों, उसको अपने लिए अनुकूल बनाने को ही प्रोग्रेस कहते हैं और इस नेतृत्व ने खाली खजाने को भरे हुए खजाने की जो परिस्थिति प्रदान की है उसको हम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

प्रोग्रेस कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी संस्था है जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सोसियल आडिट को करार देती है, उसका नाम है इण्डिया ब्रांड इक्विटी फाउण्डेशन। इसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की एक इक्विटी है और इसका काम सिर्फ मानीटर करना है। नेशन की इकॉनामी को मानीटर करती है और इस पूरे राष्ट्र के अंदर जितने-जितने भिन्न-भिन्न हमारे जो प्रदेश हैं उनकी इकॉनामी को मानीटर करती है। उसकी एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का एक पैरा मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। इसमें इन्होंने दो पहलुओं पर बहुत कहा है और इसमें राजस्थान के बारे में जो इन्होंने लिखा है वह यह कहा है- "It is expected to lead to the development of downstream industries in petroleum and chemicals. The reforms in the electricity sector in the State are one of the most advanced in the country. Rajasthan is the first State in the country to permit open access to electricity and supply market." यह हमारी आज की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को यहां सदन में बैठ कर और सत्ता पक्ष का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक ऐसी ब्रांड इक्विटी के फाउण्डेशन की वह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि जो इस बात को, सत्यता को पूरा प्रकट करती है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आज की अर्थव्यवस्था और आज की हमारी डवलपमेंट एक रिपोर्ट के नाते हमारी साढ़े 11 बिलियन डॉलर्स की यह एन.एस.डी.पी. है और यही रिपोर्ट यह कहती है जिस तरीके से योजनाओं को, जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, in the next 10 years, we will grow 5 times. राजस्थान का एन.एस.डी.पी., मैं जी.एस.डी.पी. की बात नहीं कर रहा हूं, एन.एस.डी.पी. की बात कर रहा हूं, in the next 10 years, it will grow 2.5 times. And in the next 10 years after that, it will grow again 2.5 times. अगर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हम तैयार कर रहे हैं अगर हम सही ढंग से लागू कर लेते हैं और इस बात को मैं और आपको विश्लेषण करना चाहता हूं जहां पहले पर-केपिटा इनकम 327 पर थी आज की तारीख में पर-केपिटा इनकम राजस्थान की 400 डॉलर को पार कर गई है। कहां तो 13 हजार थी और कहां 20 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। यह आखिर यहां की वित्त व्यवस्था की और यहां के आमजन की उन्नति का प्रतीक है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। यह किसी सरकारी आंकड़े नहीं है, यह उन एजेंसियों के आंकड़े हैं जो यूएनओ का भी सर्वे करती है, जो देशों का भी सर्वे करती है और फाइनेंशियल फ्रिजमेंट के अंदर जो हमारा मानिटर्स है जिसको हम सीएमआई कहते हैं, उसका भी मानिटर करती है। इसी एक रिपोर्ट का आपको अंश पढ़ना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहता हूं। इसमें उन्होंने क्योंकि बिजली के बारे में बहुत बड़ी बात होगी, बिजली के संबंध में हम और आप भी बात करेंगे और चिंतित भी हैं कि जिस तरीके से बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आमजन से लेकर किसान या व्यापारी किसी-न-किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष में बिजली पर निर्भर है और अगर इस बिजली का तंत्र अगर हम सही नहीं कर पाए तो कहीं-न-कहीं ऐसा होगा कि साहब आज की तारीख में जो एक आधुनिक राजस्थान की हम कल्पना करते हैं बिजली के अभाव में हम कल्पना कर नहीं सकते। उसमें इन्होंने लिखा है - "The Plant Load Factor, a measure of efficiency of generation plants, has increased from 74% to 88% and has now reached 96%." जो हमारे खुद के प्लांट्स हैं, जहां से हम पावर जनरेट करते हैं 96 प्रतिशत एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो हमारा यह है उपाध्यक्ष महोदय कि जो हमारा शेयर सेंट्रल ग्रिड्स में जहां से हमको जितना मिलना चाहिए उसका 40 से 45 प्रतिशत बिजली ही मिल पा रही है। 96 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करने के बावजूद हमारे हिस्से की राशि का सिर्फ 44 प्रतिशत जब सेंट्रल ग्रिड से आता है तब काश्तकार को मजबूर होकर सर्दी में रात को खड़ा होना पड़ता है और सुबह-सुबह ठण्ड में जाकर अपने खेती के खलिहानों में पानी देना पड़ता है लेकिन यह राजस्थान सरकार है। हमारे किसानों की चिंता हम करेंगे, हमारे गरीब की चिंता हम करेंगे लेकिन एक काम हम और करेंगे कि राजस्थान के शब्दकोष के इतिहास से गरीबी का शब्द मिटा देंगे यह हमारा दायित्व है। गरीब नाम का कोई शब्द नहीं रहना चाहिए, दरिद्र नाम का कोई शब्द नहीं रहना चाहिए। अगर यह रहता है तो मानव धर्म और मानव समाज पर सबसे बड़ा कलंक है। इस उत्तरदायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए एक आंकड़ा और मैं आपको देना चाहूंगा। 21वीं शताब्दी इलेक्ट्रोनिक्स का युग है, 21वीं शताब्दी आईटी का युग है, 21वीं शताब्दी कम्प्यूटर का युग है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि 21वीं शताब्दी के अंदर जो मूल फिड्स जिसको हम कहते हैं जो इमर्जिंग फिड्स है उन इमर्जिंग फिड्स के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर और पूरे संसार में हिन्दुस्तान को कहां लाकर खड़ा किया है। मैं हिन्दुस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय जब प्रायरिटी सेक्टर में हिन्दुस्तान को लाकर खड़ा करुंगा तब यह पता पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर सरकार ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया है? आज आंकड़े इस बात को कहते हैं, रिव्यू रिपोर्ट्स

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस बात को कहती है – "Microsoft has built its largest development centre outside US in India." माइक्रोसोफ्ट वह कंपनी है जो साफ्टवेयर के अंदर और कम्प्यूटर के अंदर है. GE, General Electronics, is the largest research outfit. They want to put one of their units in India. अब आप यह बताइए अगर हम स्पेशल इकानोमिक जोन का अगर निर्माण नहीं करें, आईटी पार्कस नहीं खोलें, इण्डस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बनाये, अगर हम लोजिस्टिक पार्कस नहीं करें तो क्या यह सारे रिसर्च सेंटर राजस्थान में आ सकते हैं? सेज के बारे में इतनी सारी अंगुलियां उठती हैं सेज के बारे में बहुत सी बातें होती हैं लेकिन अगर सेज नहीं होगा, आईटी पार्कस नहीं होंगे तो ये रिसर्च सेंटर्स आपके राजस्थान में कहां से आएंगे? अगर इन रिसर्च सेंटर्स को राजस्थान में प्रस्थापित करना है, मैं आरएनडी की बात उपाध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूं कि किसी इण्डस्ट्री को लगाना तो बहुत आसान है लेकिन अगर आरएनडी लैब यहां लग जाता है, रिसर्च और डवलमेंट यहां होता है, माइक्रोसाफ्ट का रिसर्च और डवलमेंट यहां होता है, साफ्टवेयर का इजहार यहां होता है तो सारी जिंदगी राजस्थान को रॉयल्टी मिलती है, यहां का नागरिक उससे लाभान्वित होता है, यह एक पल की बात नहीं है, एक दशक की बात नहीं है जनरेशंस तक उसकी इनकम आती है। आखिर आईटी पार्कस हमने स्थापित किया, कितने ही लोगों ने यह कहा कि राजस्थान में और आईटी पार्क, राजस्थान में और इलेक्ट्रोनिक इण्डस्ट्री और जिस वक्त होण्डा राजस्थान में आई, उस वक्त तो लोगों को अचम्भा हुआ। आन्ध्रा, महाराष्ट्र, समीप में गुजरात, सिर पर दिल्ली फिर भी राजस्थान। क्योंकि यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर और यहां की फैसिलिटी वन विण्डो क्लीयरेंस जहां सबसे जल्दी काम होकर 45 दिन में प्रस्थापित हो सकता है ऐसी इण्डस्ट्री को और जापान वाले ऐसे नहीं आते, बिलकुल किसी प्रलोभन में नहीं आते, वह अपनी एफीशिएंसी को टाइम से देखते हैं, वो जिस इण्डस्ट्री को लगाने में उनको 6 महीने लगते हैं या 6 साल लगती है या 2 साल लगते हैं अगर उनको ऐसी स्टेट्स मिल जाए कि यह समय आधा हो जाए या इसमें परसेंटेज में बहुत कमी हो जाए, वो उस स्ट्टेस को चुनते हैं और इसका सीधा तात्पर्य यही है कि ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क से रेडटेपिज्म को हटाकर सीधा एक्सेसिबिलिटी जो हमने दिया है वह इस सरकार ने दिया है वरना राजस्थान तो पहले भी उतना ही था, उतना ही साढ़े तीन लाख स्क्वायर किलोमीटर भाग था, उतना ही बड़ा प्रदेश था लेकिन इस प्रदेश के अंदर ऐसी कहां व्यवस्था थी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कि यहां लोग आये और ग्लोबल जायंट जिनकी स्वयं की इकानोमी किसी एक देश की इकॉनोमी के बराबर है, जिनका स्वयं का फण्ड किसी देश की इकॉनोमी के बराबर है, वह आकर अपने उद्योग को यहां प्रस्थापित करें।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज के जमाने के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर में भी बहुत बड़ा रिफोर्म आ रहा है जीईई का जो जेनिक्रेडिट जेनिटिकली इंजीनियर्ड सेक्टर का है। उसने भी राजस्थान को चुनने की बात कहीं है। उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान ने वो सारे काम किए हैं जो इन लोगों को राजस्थान तक लाने के सारे रास्ते प्रशस्त करता है। इसका उत्पादन कब होगा? इसका कॉमर्शियल यूज कब होगा? इसका टेक्नीकल यूज कब होगा? वह बाद की बात है लेकिन अगर वातावरण सही होता है तो सारी चीज सहज में हमको मिल जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 240 हैक्टेयर में एक लाख ज़ैतून की खेती की बात आई है या जहां उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि और एक्सटेंशन फार्मिंग एक करोड़ रुपये का ईनाम तो या तो राशि हमको केन्द्र सरकार ने दी है, एक रेगिस्तान जिसके नाम से राजस्थान जाना जाता है वहां अगर कुछ है तो निर्जीव वहां की धरा है और वहां का अगर पुरुषार्थ है तो एक कर्मयोगी किसान है और उस कर्मयोगी किसान को इस राजस्थान के माध्यम से एक करोड़ रुपये का पुरुषार्थ केन्द्र की सरकार दे रही है तो कुछ तो हमने किया होगा, सारा कुछ तो निरर्थक नहीं है।

मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम जब से बच्चे हैं और क्योंकि अधिकांश इस राष्ट्र की और इस प्रदेश की जनता हिन्दू धर्म में विश्वास करती है। हम बार-बार सुनते आते थे ''वसुधैव ही कुटुम्बकम'' हमारा परिवार नहीं अपितु पूरा संसार हमारा है और आप यह देखिए जिस राज्य को यह कहा जाता था कि यह राज्य अभी भी बीमारू है, यह राज्य तो अभी अपने स्वयं की नहीं सोच सकता, इस राष्ट्र की, संसार की और संसार के वैभव की क्या सोचेगा या इस सृष्टि की या पर्यावरण की क्या सोचेगा? राजस्थान सरकार ने अपने कर्मों से, अपने नेतृत्व से पहली बार मेरे ख्याल से आधे से अधिक लोग-बाग़ तो यह भी नहीं समझेंगे कि पौने चार करोड़ रुपये के कार्बन क्रेडिट अर्जित करना यह उस दायित्व को पूरा करना है कि चाहे हम जूझ रहे हों, चाहें हम लड़ रहे हों लेकिन इस सृष्टि का और पर्यावरण के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है और चार करोड़ रुपये का कार्बन क्रेडिट लाना कोई मामूली सी बात नहीं है, तीन चौथाई लोग-बाग़ जो गलियारे में बैठे हैं उनको भी नहीं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मालूम होगा कि कार्बन क्रेडिट कैसे अर्जित किया जाता है? बगैर पर्यावरण को सुधारे हुए कार्बन क्रेडिट अर्जित नहीं किया जा सकता है। हम लड़ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हमने अपने दायित्व की वहां तक पूर्ति की है। यह राजस्थान सरकार अपने लोगों के प्रति दायित्व रखती है। अपने लोगों के प्रति संवदेनशील है लेकिन यह साथ ही साथ पर्यावरण और इस सृष्टि और इस प्रकृति के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है तभी जाकर चार करोड़ का सीसी हमको मिला है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह कार्बन मिलेगा कैसे। अगर पर्यावरण के अन्दर प्रदूषण कम करने के नायाब तरीके और टेक्नालाजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। हम जूझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं हमारे पास में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट हैं लेकिन यह भी बात सही है कि सीमेंट प्लांट सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं जब नयी-नयी तकनीक का सीमेंट प्लांट लगाने आया कोई तो यह कहा गया कि प्रदूषण कम से कम हो ऐसी टेक्नालाजी लेकर आइये और जितने टन कार्बन का एमीशन हमने कम किया उतने ही हमको क्रेडिट्स मिले। सीमेंट इंडस्ट्रीज में हमने किया, एनर्जी में किया क्योंकि हमने विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया, हमने एनर्जी के वो और तरीके इस्तेमाल किये जिनसे एमीशन कम होते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी एक सरकार को चार साल के अन्दर उत्तरदायित्व की कसौटी पर और सामर्थ्य के अर्थशास्त्रियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और उससे यह पूछा जाए कि चार साल के कार्यकाल में तूने क्या-क्या स्तम्भ स्थापित किये कि जिस सरकार को चार हजार करोड़ की वार्षिक योजनाओं का भी पूरा नियोजन नहीं मिला हो आज चौदह हजार करोड़ रुपये की और बात कर रहे हो उसने एक सफर इतना लम्बा तय किया है कि लोग-बाग दशक लगा देते हैं, पूरी की पूरी आधी शताब्दी लगा देते हैं उसके बाद भी इन अंजामों तक नहीं पहुंचते हैं, हम पहुंचे ही नहीं हमने उनको पा लिया है और आने वाला कल इस देश के और इस प्रदेश के नागरिकों का वो भावी सच होगा जो एक सुनहरे सूर्य के उदय के लिए उदीयमान होगा ये चार साल का राज्य सिर्फ कागजों में उदीयमान नहीं है यह चार साल का राज्य इस पांच साल की पूर्व अवधि के ऊपर पूरा का पूरा आज यहां के आम नागरिक और आम जन का उदीयमान कल होगा और इसी आशा के साथ मैं आप और हम अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए शहादत देंगे और हमारी उपस्थिति में वो हमें पुनः साकार होते देखेंगे। आज आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ... (व्यवधान) कंधे देने वाले चार। कांग्रेस को कंधे देने वाले चार ही रह गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक इधर है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हांडी ले जाने वाला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो काम आपका है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरे दल की संख्या बताने से पहले, मुझमें इतनी क्षमता है कि सब लोगों को उत्तेजित करके खड़ा कर दिया मैंने यह मेरी उपलब्धि है कि नहीं और जब आप प्रस्तावक और समर्थक ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आप अकेले ही सब में भारी हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ये तो आप पर भी भारी हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): पर बोलना सच्चाई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जरूरी नहीं है कि मेरी बात आपको सच लगे लेकिन बोलूंगा सच।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका और इस सदन का कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज बहस की शुरूआत हुई।

(समय : 14.02 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय एक असंवैधिक सरकार द्वारा असंवैधानिक रूप से राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण प्रस्तुत कराया गया यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस असंवैधानिक भाषण पर भी हमको अपने विचार अभिव्यक्त करने पड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभिभाषण की प्रथम चार पंक्तियां कि चार साल पहले का बीमारू राजस्थान आज जुझारू राजस्थान है। आत्मनिर्भर, ऊर्जावान, चेतनावान, उदीयमान राजस्थान की शान निराली है। चहुंमुखी बहुआयामी विकास की घर-घर में खुशहाली है और हमारी सरकार ने उत्कृष्टता के कीर्तिमान कायम करते हुए राज गगन पर गत चार साल में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये भी एक अजीब संयोग है माननीय सभापति महोदय,..

श्री सभापति: कोई टोकाटाकी नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये भी एक अजीब संयोग है कि चार चांद लगाने की बात करने वाले जिस संदर्भ में आज चन्द्रग्रहण के दिन ही इस अभिभाषण पर बहस चालू हुई तो आप यह भी देखेंगे कि चांद के साथ ग्रहण भी लगता है और आपके चार चांद क्या है उन चार बातों को मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा। पहला आपका जो चांद है जो बदनुमा चांद आपका जो पहला है वो आपने अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास करके अपने धार्मिक मूल्यों का अवमूल्यन करके एक अनैतिक मूल्यों की स्थापना की है एक चांद आपका यह है। दूसरा आपका चांद यह है कि इस पूरे ही राजस्थान में जितने भ्रष्टाचार की चर्चाएं और जितने आरोप-प्रत्यारोप मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित उच्चस्तर पर जो आपने एक दूसरे पर लगाकर यह साबित किया कि हां यह सरकार भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है दूसरा चांद आपका यह है। तीसरे चांद के रूप में जो मैं देखता हूं वो यह है कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों में जिस प्रकार का मतभेद जिस प्रकार का विचार भेद, जिस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप मुख्यमंत्री सहित एक दूसरे पर लगाते रहे यह आपका तीसरा चांद है और आखिरी चांद जो आपका है वो कानून व्यवस्था के साथ शराब की नीति को लाते हुए बीपीएल परिवार के गरीब लोगों को बेमौत मारने का जो काम इस राजस्थान सरकार ने किया चौथा चांद वो है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रूप से एक नैतिक रूप से अलग नीतियां लेकर के चलने वाली पार्टी अपने आपको मानती थी। एक धार्मिक रूप से वो अपने आपको एक अधिक नैतिक मूल्यों वाली पार्टी अपने आपको प्रदर्शित करती थी और अपने-अपने सिद्धांतों पर चलने की बात करती थी और उसी आधार पर उन नैतिक मूल्यों के आधार पर कि हम ऐसा आचरण चाहते हैं कि किसी भी सरकार का और किसी भी व्यक्ति का और किसी भी देश के नागरिक का, उन आचरणों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए धार्मिक मूल्यों के आधार पर, सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का प्रयास करते थे और उसमें कुछ हद तक उसको सफलता भी मिली और उन धार्मिक आधार पर आप उस स्थान पर पहुंचे भी सही। यह बात अलग है कि जिन नारों के आधार पर जिन राममंदिर बनाने के नाम पर जिन गौरक्षक ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो पुरानी बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सुन लें। आप बीच में न टोकें। आप नहीं टोकें। आपको याद दिला रहा हूं आपके मूल्य। आप यह कह दें कि हमने पुराने मूल्य छोड़ दिये, मैं नहीं बोलूंगा। आप कह दो कि छोड़ दिये मूल्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई मूल्य नहीं छोड़े हैं जो कुछ छोड़ा है, कांग्रेस ने छोड़ा है और उसकी स्थिति आज जो देश भर में बनी है वो अपने मूल्यों के आधार पर बनी है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राम नहीं श्रीराम बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, न तो यह हिम्मत... अभी मैं आप पर तो बाद में आ रहा हूं ठहरो आप। न तो ये हिम्मत ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं हरिमोहनजी, महावीरजी ने मुख्य मंत्रीजी का विरोध जरूर छोड़ दिया है, थक गये, समझौता कर लिया आपने। आप थक गये आपने आत्मसमर्पण कर दिया। यह बात सही है।

श्री सभापति: माननीय विराजें। आपको कम्प्लीट करने दें समय की लिमिटेशन है आज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां छोड़ दिया।

श्री सभापति: वो आज समय की लिमिटेशन है आप फरमायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुख्यमंत्री का हमने कभी न तो विरोध किया, हम तो विचारों से चलने वाले लोग हैं माननीय आजाद साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो विचार आपके थे वो आपने छोड़ दिये वो ही बात मैं कह रहा हूं। आप सुन तो लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं छोडे किसी हालत में नहीं छोड़े और हम आपकी तरह दोहरा आचरण नहीं रखते हैं, दोहरा आचरण नहीं रखते हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने हमारी धार्मिक भावनाओं को ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। बोलने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी धार्मिक भावनाओं को जिस प्रकार से ठेस इस धर्म की बात करने वाले इस राम मंदिर की बात करने वाले लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है वैसी ठेस राजस्थान के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं पहुंचायी है। आपको याद होना चाहिए कि व्यक्ति व्यक्ति होता है, व्यक्ति ईश्वर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

का स्वरूप नहीं हो सकता। क्या महावीरजी आप मानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर आप ईश्वर का स्वरूप बता दें तो क्या जनता उसको मान लेगी । क्या किसी व्यक्ति को ईश्वर का स्वरूप दिखा कर कलेंडर छपा कर जनता के सामने प्रदर्शित कर दें ...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य असत्य बोल रहे हैं। ईश्वर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है उसके कर्म कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। इनको जानकारी ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, झूंठ शब्द असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकालें।

श्री सभापति: हां मैं कह रहा हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह मनुष्य योनी श्रेष्ठ ही ईश्वर का स्वरूप है। जो मनुष्य है वही ईश्वर का स्वरूप है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह राम के नाम को ही भूल रहे हैं, राम तो निकल चुका।

श्री सभापति: Let him complete. कृपया शांति बनाये रखें। We have to complete the work in time.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सदन की गरिमा देखो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य यहीं बात कर रहे हैं, टेलीफोन लगा रखा है कान पर, मोबाइल से बात कर रहे हैं। सदन की कुछ तो गरिमा होनी चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, आप सदन को व्यवस्थित करें या यह कह दें कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह हिन्दुस्तान की और राजस्थान की परम्परा है हम तो पत्थर को पूजते हैं आप व्यक्ति की क्या बात करते हैं। हम हिन्दुस्तान के लोग पत्थर की पूजा करते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह मोबाइल सीज किया जाये।

श्री सभापति: बहुत अच्छा, कंकर-कंकर में शंकर है, बोलो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पत्थर की पूजा नहीं करते हैं ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बात तो आपने सही कही महावीरजी

खुदा ऐसे असीरों को रिहाई न दे जिन्हें सिवाय अपने कुछ दिखाई न दे।

ईश्वर तो एक ऐसे अहसास का नाम है कि रहे सामने और दिखाई न दे।

श्री सभापतिः अब आप इनको बोलने दें। माननीय सदस्य बिना अनुमति के अब कोई खड़ा नहीं होगा, बोलने दें उन्हें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो दृष्टिकोण मैंने सामने रखा है और उस दृष्टिकोण का स्वरूप जैसे ही सामने आने लगा और जो चीजें सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं सामने बैठे कुछ सदस्यों के अर्न्तमन में वह पिन चुभने लगा। तो पूरी बात सुनने से पूर्व ही चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत के हिसाब से वह अपने-अपने स्थान पर खडे हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धार्मिक भावनाओं को, जो हमारे धार्मिक मूल्य हैं उनका अगर किसी ने ह्रास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने किया है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया को हमारे राजस्थान के मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने दुर्गा के रूप में प्रदर्शित कर दिया और दुर्गा पूजा होने लगी, आरतियां उतारी जाने लगी। शाम के समय लोग वहां जाकर अपने-अपने स्वार्थवश उस आरती में शामिल होने लगे और 90बी का प्रसाद वहां चढाने लगे तो भीड़ वहां बहुत बढ़ गई, आपने देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा (व्यवधान) आप चुप रहे, हमको बोलने दें या आप बोल लें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य आप बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): कांग्रेस ने नहीं छपवाया क्या सोनिया गांधी का पोस्टर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, आप कम से कम यह तो कहें कि माननीय सदस्य अपने स्थान से बोलें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): सभापति महोदय, यह क्या बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की।

श्री सभापतिः दौसा से पधारने वाले माननीय सदस्य आप विराजें, उनको बोलने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और अपनी सीट पर जाओ, अपनी सीट पर से बोलें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप कौन होते हैं मुझे भेजने वाले।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं, सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप अपनी सीट पर से बोलिए, आप हर कहीं से नहीं बोल सकते। अब आप दूसरी बार आये हो आप नये सदस्य नहीं हो, अनुभव हो गया अब तो आप अपनी सीट से बोलिये, यह सिस्टम है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं तो यहां बैठा हूं, बैठूंगा यहां पर और यहीं से बोलूंगा।

श्री सभापति: विराजें आप। यह बार-बार टोका-टाकी में मजा नहीं आयेगा Let him complete.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी को 1 घंटा और 10 मिनट आबंटित किया गया है और उसमें से देख लें यह कितना समय ले रहे हैं।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया शांति बनाये रखें, टोका-टोकी नहीं करें, बीच में नहीं बोलें जिससे समय पर काम हो सके और अपने स्थान पर जायें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, दुर्गा पूजा ही नहीं राम मंदिर बनाना तो दूर की बात इन्होंने राम मंदिर बनाने के बजाय इनके खुद के नेताओं को और खुद को ही भगवान का प्रतिरूप समझा कर वहां कर दिया कि राम मंदिर हम नहीं बना सकते ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य मैं आपको टोकना तो नहीं चाहता पर मुद्दे की बात करो ना आप। इस तरीके से बात करके क्यो समय जाया कर रहे हैं क्योंकि आपका समय जाया हो रहा है और आपका टाइम हो रहा है। (व्यवधान) आप विराजें, मदनजी आप विराजें, हां बोलो। (व्यवधान) किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आप विराजो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ...राम निकल जाये तो इनके पास मुद्दा ही कहां है। राम निकल गया तो इनके पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं।

श्री सभापति: I will not allow you. At this time I will not allow you. बोलिए आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राम मंदिर नहीं बना सके, अपने वादे को नहीं निभा सके, असत्य आश्वासन देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठ गये तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इन्होंने यह सोचा कि वह मंदिर तो नहीं बना पाये इसलिए राजस्थान की जनता हमें खुद को ही भगवान के रूप में देखे। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि मुख्य मंत्रीजी को अन्नपूर्णा के रूप में प्रदर्शित करके राजस्थान में कलेंडर छपवा दिये। आपको यह भी याद होगा कि अटलजी के नाम पर, राजनाथ सिंहजी के नाम, आडवाणीजी के नाम पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बना कर हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया। शर्म नहीं आई आपको, आपको शर्म नहीं आई इस बात पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको टोकना तो नहीं चाहता ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको इस बात की शर्म नहीं आई कि हम इंसानों को ब्रह्मा, विष्णु महेश बना रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस कर रहे हैं या इधर-उधर की बात कह रहे हैं। I think you are not discussing about the Governor Speech.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और वह सोनिया गांधी जी की दुर्गाजी के रूप में फोटो छपी थी वह भी बता दो आप। सोनिया गांधी जी को दुर्गा का रूप दिखा कर वह फोटो छपी थी वह भी बता दें आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ....(व्यवधान) संसदीय मंत्रीजी इंदिरा गांधी को अटलजी ने मां दुर्गा कहा था, साक्षात दुर्गा कहा था बंगला देश बना था तब। अटलजी ने कहा था, आपके नेता ने कहा था क्या बात कर रहे हैं आप। अटलजी ने कहा था या नहीं कहा था बताइए आप। अटलजी ने कहा था मां दुर्गा। स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गाधीजी को अटलजी ने मां दुर्गा कहा था या नहीं कहा था (व्यवधान) आप समय-समय पर बदलते रहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर और मजबूती से कहा कि सोनिया गांधी दुर्गा के रूप में है आपके लिये और आप स्तुतिगान करते हो, आप कहो ना मजबूती से।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप क्या बात करते हो, किस विषय पर बोलना चाहते हो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, यह भारतीय संस्कृति है ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और आप राम-राम की रट लगा रहे हो जरा रामसेतु के बारे में भी बोलो ना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हमारे वेदों में भी कहा है कि 'मूल ब्रह्मा... वृक्ष राजे नमो।' हम तो पेड़ पौधों में भी भगवान का वास मानते रहे हैं ऐसी हमारी संस्कृति है। जैसे विचार, जैसी धारणा है उस हिसाब से हर घट-घट में राम है, भगवान विराजमान है। ऐसी हमारी संस्कृति है क्या गड़बड़ है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य राम-राम की रट लगा रहे हैं इनको रामसेतु के बारे में भी थोडा बोलना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह अरुण जेटली के समय योजना बनी थी, बोलो बनी थी या नहीं बनी थी। (व्यवधान) क्या बोल रहे हो आप बोल देना उस पर कोई मुद्दा हो इस बात का।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा अवसर आयेगा तब बोलूंगा मैं यह बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत समय खराब कर रहे हैं आप। बोलें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हाउस को कंट्रोल तो करो साहब।

श्री सभापति: मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि बार-बार खड़े ना हों।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इसको लाइटली मत लें नैतिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों के, हमारे राजस्थान की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा कर आप हंस कर उस बात को बदलना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): नैतिक मूल्यों की बात करने वाली कांग्रेस रामसेतु के बारे में थोडी स्थिति स्पष्ट करें। आप तो कहते हो कि राम हुए ही नहीं। (व्यवधान) कांग्रेस द्वारा ऐसी टिप्पणी करना बहुत निंदनीय है।

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ... यह माननीय आसन के लिये इतने जोर-जोर से बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापतिजी, यह राम के बारे में नहीं रोम के बारे में बोलेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, या तो आप इनको रोकिये या सदन की छुट्टी कीजिए। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इनको। मैं बोलूंगा, मेरा हक है।

श्री सभापति: हां बोलो ना आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप कहोगे जो नहीं बोलूंगा मेरी इच्छा होगी जो बोलूंगा। यह कहेंगे जो बोलूंगा क्या मैं। माननीय संसदीय मंत्री जी और खनिज मंत्रीजी का तो स्वाभाविक है कि वह जिस तरीके से वहां पर जमे हुए हैं तो चाहे उनको दुर्गा मानो, चाहे भगवान मानो इनको तो आत्म समर्पण करके जय-जयकार करनी ही है। इनके दुःख को मैं समझता हूं और इनकी वफादारी को भी मैं समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जिन मूल्यों का ह्रास किया है, जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों के ह्रास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है यह वह सरकार है यह वह सरकार है जिसकी न कोई नीति है, न कोई धर्म है, न कोई नीतियां हैं, राम के नाम पर विश्वासघात करती है जनता के साथ। यही नहीं मैं दाद दूंगा इस बात की कि श्रीमती शीतल कंवर ने हिम्मत की, जसवंत सिंहजी की पत्नी ने, हिम्मत की कि उन्होंने राजस्थान के इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया। मैं उनकी इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और इन लोगों को उस बात से आज तक कोई समझ नहीं आई, अपने सत्ता के सिंहासन पर स्वार्थ की पूर्ति करते रहे। यह गैरवावस्त्र धारी मंत्रिमण्डल के सदस्य चुपचाप बैठे-बैठे देखते रहे। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनको अभिभाषण पर बोलना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गैरवावस्त्र पहनकर जनता को धोखा देने वाले, हिन्दुत्व की भावना...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनको अभिभाषण पर बोलना चाहिए, यह काहे पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): व्यक्तियों को ...(व्यवधान) दुर्गा के रूप में प्रशासित करने वाले, अपनी सत्ता का सुख देखने के लिए चुपचाप बैठे रहे। जसवंत सिंहजी की पत्नी धन्यवाद की पात्र हैं लेकिन अफसोस इस बात का है माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनके जो सलाहकार हैं...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अहम ब्रह्मण्स्वामी....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बोलेंगे जब मैं भी खड़ा होऊगा, यह देख लेना आप। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आपमें भी मुझे भगवान दिखता है। आपमें भी मुझे भगवान दिखता है और यह अपनी संस्कृति है और मैं हिन्दू हूं, हिन्दू होने के नाते (व्यवधान) सुनो साहब, हिन्दू होने के नाते मैं रामायण और राम को भी मानता हूं। आपने शपथ पत्र भी दिया है कि राम नहीं हुआ इस देश के अंदर...(व्यवधान) मेहरबानी करके अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। पार्टी की संस्कृति का ध्यान रखे। राम का नाम नहीं ले तो अच्छा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राम का नाम लेने की नहीं लेने की सलाह देने के लिए आपसे नहीं सीखूंगा, आप जैसों को मैं सीखा सकता हूं। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अपन दोनों सीख लेते हैं।

श्री सभापति: बिराजिए, आप बिराजिए। माननीय आप कन्क्ल्यूड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं कनक्लूड नहीं करूंगा। या तो मैं बैठ जाता हूं, आप खतम कर दें।

श्री सभापति: आपका टाइम है चार...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप पार्टी का टाइम ...(व्यवधान) बोलने नहीं दिया एक इश्यू, अगर दूसरा भ्रष्टाचार का आ रहा है तो चुप और तीसरा और आ रहा है तो चुप।

श्री सभापति: एक घंटा था, जो समय दिया हुआ है वह एक घंटा है, पूरी पार्टी को एक घंटा दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां ठीक है।

श्री सभापति: और आपको बीस मिनट हो चुके हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां ठीक है।

श्री सभापति: फिर दूसरों को समय नहीं मिलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप देओ ही मत ना समय, आप तो बंद करवा दो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे चालीस मिनट इनको दे रहा हूं। मेरे चालीस मिनिट, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: बिराजिए आप। यह तो डिसिजन चेयर का है। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, लेकिन जिस महिला ने इस सारे सांस्कृतिक मामले को, नैतिक मूल्यों को उठाया, आपको याद होगा महावीरजी कि एनडीपीएस का मुकदमा, जसवंत सिंहजी से लेकर आप तक सरकार ने लागू कर दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो आपने ही कराया हमारे खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मदन दिलावरजी को याद होगा। जसवंत सिंहजी को याद होगा (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे खिलाफ मुकदमा ही करवा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन इसके बावजूद भी वह महिला अपने सिद्धांतों से नहीं हटी। इस बात के लिए जसवंत सिंहजी की पत्नी बधाई की पात्र है। जो उनके इर्द गिर्द घूमकर, जो इस सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी के समक्ष अपना विरोध प्रकट करते थे, राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य, मुख्य सचेतक सहित वह दुम दबाकर मुख्य मंत्री के इस डर से यहां से न जाने कहा से कहां इसलिए भागकर चले गये...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फालतू की बात करते हो। (व्यवधान)

पहले भी इसी सीट पर बैठते थे अभी भी इसी सीट पर है।

श्री सभापति: बिराजिए, आप बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने चाहे उसमें गृह मंत्रीजी हों, चाहे उसमें समाज कल्याण मंत्री हों, चाहे उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी, वर्तमान में एक साधारण से मंत्रीजी का विभाग वाले हों, चाहे कटारा साहब जैसे भले आदमी हों इन सब लोगों ने सेज से लेकर आज तक अनेक बातों में राजस्थान के मुख्य मंत्री की खुली आलोचना की है। इन लोगों ने समय-समय पर चाहे सेज का

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मामला हो, आरोप लगाये कि केबिनेट मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं लिये गये। (व्यवधान) इन लोगों ने यह हिम्मत दिखाने का, हम तो यह समझे थे कि यह मंत्रिमण्डल का गुट विशेष है यह कुछ नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कुछ सिद्धांतों के लिए मुख्य मंत्री से लड़ाई लड़ रहा होगा लेकिन नैतिक मूल्यों की बात करने वाले मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाने वाले, मुख्य मंत्रीजी की हर गतिविधियों को गलत बताने वाले, मुख्य मंत्रीजी द्वारा आयोजित केबिनेट में रूष्ट होकर नहीं जाने वाले और मुख्य मंत्रीजी द्वारा संघ के संबंध में उनकी सरकारी पत्रिका में पोंगापंथी शब्द लिखने पर मुख्य मंत्रीजी को स्वयं को त्यागपत्र देकर इस्तीफा दिलाने की मांग करने वाले भाई दिलावरजी (व्यवधान) इन सब परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने राजस्थान की जनता को भ्रमित किया। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान की मुख्य मंत्री जिस ढंग से शाही तरीके से, सामंती तरीके से जो कार्यवाही कर रही हैं, यह लोग, यह संघनिष्ठ लोग हैं, इनके कुछ अपने सिद्धांत हैं और इसी कारण यह सबके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जसवंतजी के खिलाफ मुकदमा चालू होने की शुरूआत हुई, चतुर्वेदीजी को उसमें जिस प्रकार से उलझाया गया और जगन्नाथ वर्मा पूर्व का भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय विधायक वर्षों से जुडा हुआ उनकी दुर्गति झालावाड़ में की गई। प्रहलाद गुंजल जिनको कंधे पर बिठाकर फिरा करते थे उनकी दुर्गति करके उनके घर और उनकी परेशानी को जिस प्रकार से राज्य सरकार ने, चाहे किसी का भी हाथ हो, जो दुर्गति की है, अतर सिंह भडानाजी की जिस प्रकार से दुर्गति की, वीरेन्द्र मीणा को जिस प्रकार से निपटा के अपने घर पर भेजा है। मैं किरोड़ीलालजी मीणा का सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं कि ये बड़े-बड़े मंत्री विरोध करने के बाद आरोप लगाने के बाद उनकी नहीं सुनने के बाद सार्वजनिक रूप से मतभेद करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करने के बाद, राजस्थान में ऐसी असंवैधानिक सरकार की स्थिति बनाने के बाद, इनमें थोडी सी मोरललिटी होती तो जिस प्रकार किरोडीलाल मीणा ने इस्तीफा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की इनको भी करना चाहिए था। विशेष रूप से मेरा तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी पर विशेष गुस्सा है। विशेष गुस्सा इसलिए कि यदि वह वर्ग की बात करें तो वह हमारे वर्ग से माने जाते हैं, जातिवादी तरीके से। ब्राहम्ण होकर इतना अपमान सह ले और जब सह ले कि डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट लेकिन इसके पीछे जो परिस्थितियां थी वह यह थी...(व्यवधान) आप चुप रहिये, आप उनको रोक दीजिए। आप मूकदर्शक न बनें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक ब्राह्म्ण का अपमान इन्होंने भी किया है। कल्ला साहब अच्छे भले चल रहे थे उनको चलता कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिए। राठौड़ साहब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छे भले चल रहे थे उनको चलता कर दिया, गजब कर दिया आपने, ब्राह्म्णों का सम्मान कहां से किया। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): नटवर सिंहजी और सोनिया का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं सम्मानीय नरपत सिंहजी का नाम लेना भूल गया था। वह भी इनके संयुक्त मंत्रिमण्डल के दायित्व में एकजुट विशेष प्रतिनिधि करने के रूप में (व्यवधान) लेकिन सब बातों पर थे न इन्होंने अपने स्वार्थों की खातिर, उसका कारण था, उसका मूल कारण यह था कि सरकार ने जैसे ही यह लोग बोलने लगे, अपनी बात कहने लगे अपने विचार अभिव्यक्त करने लगे...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हमारी पार्टी के समय में से काट लेना, आप चिन्ता नहीं करो। आप बोल लेने दीजिए, (व्यवधान) जिस प्रकार से इन लोगों को क्यों डर लगा फटाफट हाउसिंग बोर्ड से एक विज्ञप्ति निकली कि कटारियाजी ने एक मकान गलत ले लिया इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार अभी कर रही है वो जांच। सरकार ने विज्ञप्ति दी है सरकार ने हाउसिंग बोर्ड का रिकार्ड प्रेस वालों को दिया फिर दूसरी बात आई घनश्याम...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरा एक एतराज है। माननीय सदस्य सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं। किस आधार पर यह आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि सरकार ने विज्ञप्ति जारी करा दी, कोई प्रमाण है? मैं समझता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई कहे, राजस्थान के विकास की बात कहे, इन्होंने कुछ किया है तो उसकी बात कहे, बिना मतलब आरोप के नाम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के (व्यवधान) आप बिराजिए, मुझ पर कृपा कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मतलब यह...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां मेरी ही बात कह रहे हो, आपको धन्यवाद देता हूं। आपके पास हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको काट करने के लिए कोई वह ही हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने जो विकास के काम किये हैं, हमने जो जनता का काम किया है, उस पर आपके पास बोलने के लिये कुछ नहीं है। अब आपकी पार्टी में, आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, आपने कल्लाजी को क्यों... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बैठाइये ना साहब इनको। आप +++ क्यों बने हुए हैं? आप +++ क्यों हैं? बैठाइये ना इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप अपना कनक्लूड करें अब। (व्यवधान) This is my discretion. आप कनक्लूड करें अब। आप उनको क्यों... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बीच-बीच में कोई खड़े होकर बोलेगा, यह नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन के लिये +++ कहना, अपमान है आसन का।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी ठहरो तो सही।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आसन के लिये +++ बने रहना, यह आसन का अपमान है। सभापति महोदय, बार-बार आसन को इस प्रकार पुकारें, शर्म नहीं आती, आप कितने वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय, आप दो मिनट में कनक्लूड करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसके बाद, यदि ये स्वयं अपनी पार्टी की ओर देख लेते, यदि कल्लाजी का जो हाल हुआ, वह देख लेते, रामनारायणजी चौधरी का हाल हुआ, वह देख लेते.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): On a point of Order, on a point of Order. (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि अशोक गहलोत का हाल हुआ, वह देख लेते, और अभी-अभी नटवरसिंहजी का जो हाल हुआ, वह देख लेते...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): On a point of Order, मैं पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और अभी-अभी प्रतिपक्ष के नेता हेमारामजी का जो हाल हुआ और उनको जो आंसू बहाने पड़े, वह यदि देख लेते तो आपको समझ में आ जाता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनको देखकर तो गांधीजी की आत्मा हेमारामजी के माध्यम से रो रही थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह जो इन्होंने ही कोटा में सार्वजनिक रूप से वर्तमान संसदीय मंत्री पर जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं और अपनी सम्पत्ति का विवरण इसलिये पेश किया है कि सरकार में ताकत हो तो कर ले, मेरे ऊपर जो इतने करोड़ों की सम्पत्ति करने का आरोप लगाया है, मेरी सम्पत्ति है, लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसे शब्दों को काम में नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे मंत्री, चोर, भ्रष्ट, वह मेरे आगे कहां आकर के टिकते हैं। अख़बार निकालूं, आपका अख़बार निकालूं, आपके नाम से छपा है, क्या बात करते हैं आप। क्या बात करते हो, निकालूं, मैं आपका अख़बार। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): On a point of Order. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डाक्टर महेश शर्माजी का क्या हुआ, महावीरजी, डाक्टर महेश शर्माजी का क्या हुआ। बड़ा सम्मान दिया ना उनको आपने। कभी राजनीतिक व्यक्ति ए.पी.ओ. हुआ, आपने 3 दिन ए.पी.ओ. कर

दिया, ओम माथुर को। क्या किस मुंह से बात कर रहे हो आप यहां पर। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या किया आपने घनश्यामजी तिवाड़ी का, शिक्षा विभाग लेकर खाद्य आपूर्ति दे दिया। आपने क्या किया, लक्ष्मीनारायणजी दवे का, इनसे वन विभाग ले लिया। अब क्या हो रहा है, वन विभाग में, आखिर आप अपने अन्दर तो झांको। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने क्या किया था? आपने क्या किया कल्लाजी का (व्यवधान) आपने क्या किया रामनारायणजी चौधरी का। आपने क्या किया शिवचरणजी माथुर का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने कितना अपमान किया है लोगों का। बात कर रहे हो आप। आपको थोड़ा-बहुत ख्याल आना चाहिए, महेश शर्माजी का क्या हाल किया आपने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उस व्यवस्था में आपको कहने का कोई हक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल्लाजी को पहले तो प्रतिपक्ष के नेता पद से हटाया, फिर इनको कांग्रेस के प्रसीडेंट पद से हटाया। मैं इनका गुरु हूं, निश्चित रूप से मुझे दुःख है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपनी पार्टी की पंचायती करें। दूसरी पार्टी की पंचायती करने की जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों ही एक-दूसरे की पार्टियों का बखान कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी हर बार व्यवधान कर रहे हैं, आप। (व्यवधान) वह चन्द्रराजजी सिंघवी कहां हैं, 120 सीट, चन्द्रराजजी सिंघवी कहां हैं, वह लादूरामजी विश्नोई कहां हैं। कहां हैं आपके लोग, बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं बताता हूं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, माहिर आजादजी, आप कहां से आये, यह माहिर आजादजी कितनी पार्टियां बदलीं आपने। आप हर बार नई पार्टी ज्वाइन करते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो यह बताओ। (व्यवधान) दम है, दम है। दुबारा जीतकर आना तब पता पड़ेगा। दुबारा जीतकर आना, इस हाउस में फर्स्ट एण्ड लास्ट हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आगे आपको कांग्रेस भी टिकट देने वाली नहीं है। (व्यवधान) आप फिर कहां मुंह मारोगे। (व्यवधान) हमेशा मुंह मारते फिरते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जैसे आप मार रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहली बार जनता दल में थे, फिर दूसरी पार्टी में गये, तीसरी पार्टी में गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चार बार आया हूं, आप आना। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप हर बार अलग पार्टी से आते हो। दुबारा अपनी पार्टी से कभी नहीं आते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो आकर बताओ, तब पता पड़ेगा, दुबारा आना तब पता पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, आउंगा, आपकी छाती पर ऐसे ही मूंग दलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब, आप विराजें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो बताओ, जसवंत सिंहजी की पत्नी ने अच्छा काम किया या गलत किया, मुकदमा दर्ज कराकर, बताओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गलत किया, गलत किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मुख्य मंत्रीजी के साथ हो, जसवंत सिंहजी के साथ हो?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मुख्य मंत्रीजी के साथ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बदल लिया दल, दल बदल लिया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कोई नहीं बदला। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं सभी सदस्यों से टोकाटाकी करना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप समय पर काम करवाना चाहते हैं तो बीच-बीच में टोका-टाकी न करें और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संयत भाषा का प्रयोग करें। कोई असंसदीय भाषा नहीं हो, जो दूसरों को उकसाने वाली हो। आप कम्प्लीट करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी ये भी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या उकसाया मैंने? (व्यवधान)

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े नहीं हों। (व्यवधान) विराजिये आप। आप कम्प्लीट करें तीन मिनट में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, तीन मिनट में नहीं, या तो आप कह दो, नहीं बोलना। (व्यवधान)

श्री सभापति: तीन मिनट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, आप कितना बोले थे, आपको कितनी बार टोका था।

श्री सभापति: वह इसलिये कि एक घंटा बोलना था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो बस ठीक है, हमारे समय में से काट लेना आप।

श्री सभापति: आपके पांच नाम हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हमारे घंटे में से काट लेना आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: पौन घण्टा हो गया है आपको। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अभी और दर्दनाक घटनाक्रम आयेगा आप विचलित नहीं हों। मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह मेरा घण्टा क्या चीज है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बढ़ा देना घण्टा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं बेबुनियाद बात नहीं कर रहा हूं। यह सम्माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने कोटा में जो वक्तव्य दिया है, मुख्य मंत्रीजी माफी मांगें। (व्यवधान) सुन लें आप ...(व्यवधान) मैं पढ़ सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) सभापतिजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: अख़बार की कटिंग नहीं, आप बोल दें। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में कई बार अध्यक्षीय व्यवस्था हुई है। (व्यवधान) आप कहो, मैं कोट करके बता दूं।

श्री सभापति: जब यह साफ कहा गया है कि अख़बार को संदर्भित करके कोई भी बात सदन में नहीं कही जा सकती है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, हां, नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य एक अख़बार को कोट कर रहे हैं। यह व्यवस्था, सभापति महोदय, 18.03.1975 को हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: हमने मना कर दिया उन्हें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह कह दो, यह बात सुनें। आप यह बात सुनें। मैं पढ़कर सुना दूं, ये खण्डन कर दें कि इन्होंने नहीं कहा है, I agree. मैं मान लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अख़बार को संदर्भित भी नहीं किया जा सकता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यह वक्तव्य पढ़ रहा हूं इनका। यह उसका खण्डन कर दें कि अख़बार में गलत छपा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समाचार-पत्र को कोट नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके आरोप सब गलत हैं। जो आप कह रहे हैं, सब गलत हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अख़बार में कटिंग से बात नहीं चलेगी। वह आप ऐसे ही बोल दें। आप इसमें से पढ़कर क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वे मुझसे क्या टकराएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था अनेकों बार है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह आपके लिये कहा है।

श्री सभापति: This is not be allowed.

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह आपके लिये था कि कांग्रेस के भ्रष्ट लोग मेरे से क्या टकराएंगे। (व्यवधान) कांग्रेस के भ्रष्ट लोग मेरे से क्या टक्रा सकते हैं।

श्री सभापति: This is not allowed.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दिलावर ने यह टिप्पणी शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ उनका नाम लिये बगैर की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह अलाउड नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इसको डिलीट कराइये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसको डिलीट कराइये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कार्यवाही से यह डिलीट करवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं लिखेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। वह कांग्रेस की ओर इशारा था मेरा। कांग्रेस के लिये कहा था मैंने। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह क्या कहा, सुनो, क्या कह रहे हैं, मैंने कांग्रेसियों के लिये कहा था यह। यह कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के लिये कहा था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने कांग्रेस के लिये कहा था, आप लोगों के लिये कहा था। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप गलत पर गलत बोले जा रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कालीचरणजी साहब, इस समय आपका यह बोलना घनश्यामजी तिवाड़ी की दुर्गति करके बड़े-बड़े स्थान पर आपका बैठना, इसके अलावा आपसे कोई न्याय की बात कैसे करें...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ऐसे आप कितना ही बोल लें। आपकी दुर्गति भी बी.डी. कल्लाजी की जैसी होगी, रामनारायणजी चौधरी की जैसी होगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई बात नहीं। यह लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के आमजन से जुड़ी हुई बात, एक बार भी इन्होंने अपने भाषण में नहीं उठाई। यह व्यक्तिगत एक पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं, इनको क्या है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कल्ला साहब, हेमारामजी को टार्गेट बना रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, जब व्यवस्था का प्रश्न आता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना जाता है और आपका फैसला आता है। उन्होंने एक पाइंट आफ आर्डर का प्रश्न उठाया। उस पर न आपने कोई बहस सुनी और न कोई फैसला दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई बहस नहीं, मैंने उनको भी अलाऊ नहीं किया और मैं यह कह रहा हूं कि कोई अख़बार की कटिंग की बात नहीं चलेगी यहां पर। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्यों नहीं किया? कोट कर सकते हैं।

श्री सभापति: कोट कर सकते हैं लेकिन ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, कोट कर दी। कोट कर दी।... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोल दो मन में। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अख़बार के आधार पर सवाल करते हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोट किया है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अखबार की कटिंग नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्षीय व्यवस्था है यह। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पहले अध्यक्ष के नाते मैंने भी दिये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के जितने भी सदस्य हैं (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, हमारे समय की बलि चढ़ती जा रही है। इस बहस में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तक लिमिट करें। आप इधर-उधर की बात कहकर समय जाया कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इनके पास कुछ नहीं है कहने को। माननीय सभापति महोदय, आप कितना भी कहें, इनके पास राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहने को एक शब्द भी नहीं है। कह दें तो मेरी शर्त है। एक शब्द भी नहीं कहेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं बोल रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक शब्द भी नहीं है। एक शब्द भी नहीं कहेंगे, कोई भी माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सिर्फ यह कहेंगे कि यह हुआ, वह हुआ, यह हुआ, वह हुआ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको पौन घंटा हो गया है बोलते-बोलते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक शब्द नहीं कहेंगे। विकास का, बिजली का, पानी का, सड़क का, खेती का, किसान का ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप विराजिये न, अभी बोलता हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक शब्द भी नहीं कहेंगे। सिर्फ यह कहेंगे कि कल्ला साहब के क्या हुआ, फलां साहब का क्या हुआ। ... (व्यवधान) एक शब्द नहीं कहेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, आप इनको तो नहीं बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक शब्द सरकार की उपलब्धियों के बारे में या नाकामियों के बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपसे सलाह नहीं लूंगा। आपसे सलाह नहीं लूंगा। मैं क्या बोलूंगा, आपसे सलाह नहीं लूंगा। आपसे नहीं लूंगा सलाह। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक शब्द भी नहीं कहा इन्होंने। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सलाह तो समझदार को दी जाती है, जो समझदार हो। जो समझता नहीं हो, उनको क्या सलाह दे रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बोलो यदि दुबारा जीत कर आना है तो नहीं होगी जमानत जब्त। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सलाह समझदार को दी जाती है।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जो समझदार नहीं उसको क्यों सलाह दें। जो मानता नहीं उसको क्यों सलाह दें? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को इसलिए चिन्ता है कि अब की बार इनको टिकट मिलने में बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है इसलिए सी.आर. भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह तो खुद ही दुविधा में हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह खुद परेशानी में हैं इसलिए इनको अपना अंक बढ़ाना है। अब की बार इनको टिकट का भय है। बहुत दु:खी हैं यह तो। अभी यह ...(व्यवधान) इसलिए यह देख रहे हैं कि कैसे मेरा काम बन जाए इसलिए ऊल-जलूल बातें कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कहीं यह हिण्डौली की सीट खतम हो गयी उसके कारण से तो नहीं है? नहीं-नहीं, हिण्डौली की सीट खतम हो गयी इसलिए तो दर्द नहीं है? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अपने मुद्दे की बात पर तो आते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये-विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मुद्दा इनके पास है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा। आप राजनैतिक जागरूक हैं, निष्पक्ष हैं और आपकी उपेक्षा करने के बावजूद भी आप शालीन तरीके से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आप ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आसन पर लांछन लगा रहे हो आप। आप कर क्या रहे हो? (व्यवधान) आप आसन पर लांछन लगा रहे हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यही है इनका अभिभाषण पर। पूरी चर्चा के दौरान एक शब्द भी नहीं बोल सके यह अभिभाषण पर। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अभी माननीय सदस्य की बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इन्होंने कहा सभापति महोदय से कि ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस केबिनेट के हर मंत्री को, हर विधायक को इस बात की याद है, इस बात की अच्छी तरह से याद है, केबिनेट के सभी सदस्यों को और मदनजी साहब को और सभी लोगों को याद है कि राजनाथ सिंहजी की मीटिंग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने माननीय मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, किस आधार पर कह रहे हैं यह? यह किस आधार पर कह रहे हैं? यह क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह तथ्यहीन आरोप है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक शब्द भी नहीं कहा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, एक भी शब्द नहीं कहा। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर यह बात कर रहे हैं? किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। मेरी मांग है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाए। कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति: एक्सपंज कर दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और राजस्थान के मंत्रि मण्डल के सदस्यों ने उन आरोपों का आज तक खण्ड़न नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह आरोप अपनी प्रोसीडिंग से निकाला जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) हम यह देखना चाहते हैं कि कैलाशजी मेघवाल सच है या फिर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये। माननीय, शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इधर-उधर की बात करके समय जाया कर रहे हैं। आप टू द पाइंट राज्यपाल महोदय के एड्रेस पर बात करिये। मन चाहे जो बोलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। आप पांच मिनट में कनक्लूड कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार है कि कैलाश मेघवाल सच है या माननीय मुख्य मंत्रीजी सच है। (व्यवधान) यह हमको जानने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। वे भी माननीय सदस्य हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप खंडन कीजिए न, आपको किसने रोक रखा है? आपने अब तक खंडन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, हमने खंडन किया था। सभी समाचार पत्रों ने खंडन किया था और मीडिया में खंडन किया था, हमने उसी समय खंडन किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने खंडन नहीं किया। आपने नहीं किया क्योंकि वह कैलाश मेघवाल को जानते हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप शांति बनाये रखें। आप विराजिये। आपका भाषण खतम। समय समाप्त आपका। मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं। नो-नो, प्लीज These sort of things will never be allowed. No. No. I can not allow. जोगेश्वरजी गर्ग। माननीय जोगेश्वरजी गर्ग।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री सभापति: मत बोलो। एक घंटा हो चुका है। पौन घंटे के ऊपर हो गया है। कई माननीय सदस्यों को बोलना है। मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आपका बहुत आदर करता हूं। कई माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं। यह फोरम ठीक ढंग से डिस्कशन करने के लिए है। आप वह ही बात पौन घंटे में भी कह सकते थे। पौन घंटे से ज्यादा समय हो गया और आपने अभी तक अपना भाषण भी स्टार्ट नहीं किया। अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा। नहीं-नहीं, यह नहीं चलेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। इन्होंने भाषण भी स्टार्ट नहीं किया है। भाषण दिया नहीं है इसलिए भाषण करने दो। तो इनको भाषण तो करने दो, साहब। ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: माननीय विपक्ष के नेता महोदय, कांग्रेस पार्टी को एक घंटा छह मिनट का समय दिया गया है, उसमें से 47 मिनट आप बोल चुके हैं। यह तो आप जबरदस्ती इन्वाइट करें ट्रबल तो बात अलग है। Why he is inviting the troubles? यह तो खुद के लिए ट्रबल इन्वाइट करते हैं, नहीं आप इनको। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको भी पाबंद करें थोड़ा आप। (व्यवधान) इनको भी पाबंद करो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप कैलाश मेघवाल का नाम लेकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सारवान बात तो आगामी दिनों में भी अपनी कह सकते हैं। दो मिनट में आप बात करिये। आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है। आप इधर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, माननीय सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह सदन में, ...(व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर का सवाल है, आप बैठिये। माननीय सभापति महोदय, आपने इस आसन से, ...(व्यवधान) जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं हो, उसका नाम लेकर कोई बात नहीं कह सकते। यह अध्यक्षीय व्यवस्थाएं भी हैं और यहां का नियम भी है। कोई भी व्यक्ति, कोई हमारा माननीय सदस्य, यह बात ठीक है कि हमको स्वतंत्रता है बोलने की लेकिन बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है। हम भी नियम और कायदों में बंधे हुए हैं और नियम और कायदे यह हैं कि जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वह कोई भी पत्रों के आधार पर, अख़बार के आधार पर चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उधर से बोल ले कोई बात नहीं। जसवंत सिंहजी पर तो आपत्ति नहीं हुई। जसवंत सिंहजी पर आपत्ति नहीं हुई। संसदीय सचिव ने, यहां तक कि संसदीय सचिव सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे थे, वह तो अलाऊ है, जसवंत सिंहजी पर तो आरोप अलाऊ है और यहां कोई कैलाश मेघवाल की बात कह दी तो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नियम यह है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कोई यहां पर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। उसके बारे में यहां पर नहीं बोल सकते और इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं, इस सदन में गरिमा रखनी है, मैं समझता हूं कि इनको मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। वह मेरे से पुराने सदस्य हैं, वह जानते हैं, तो हमने हमारी जो विफलताएं हैं, हमारी सरकार में जो कमी-खामी रही है, उसके बारे में कहें, क्योंकि इनके पिछले पांच साल में न तो कोई उपलब्धियां हैं, न चार साल की हमारी आलोचना करने का इनके पास में कोई विषय है। अब कांग्रेस में क्या हुआ, कांग्रेस टूटी-फूटी क्यों? इसकी यदि हम चर्चा करें कि बीजेपी में क्या हो रहा है तो यह हमारा घर है, हम क्या करेंगे, यह हमारा विषय है। आपका कांग्रेस का विषय है। अभी जैसे कल्लाजी ने कहा कि हमारा घर है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बीजेपी, बीजेपी वालों के लिए कहें तो हमें एतराज नहीं है, लेकिन सरकार के पदों पर बैठे रहने वालों के लिए अगर बीजेपी का पदाधिकारी बोलता है तो जनता को जानने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जनता को क्या जानने का अधिकार है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपको कैसे पता, क्या सपना आया? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो नहीं था लेकिन (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कैलाशजी मेघवाल ने कोई शब्द नहीं कहे, आप बिलकुल गलत बयान कर रहे हैं। बिलकुल गलत बयान कर रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप उसका खण्डन करें, मुझे ऐतराज नहीं है ना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप खण्डन करें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कहा ही नहीं है तो क्या खण्डन करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सवाल यह है कि जो यहां स्पष्टीकरण नहीं दे सकते उस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सभापति: जो आदमी यहां नहीं है, जो स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद नहीं है, जो बोलने के लिए सक्षम नहीं है, उनकी चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी जंचे जो फैसला करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बोलने तो दें साहब, दो मिनट क्या बोलने तो देते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, सभापति महोदय, जो सवाल चीफ व्हिप महोदय ने उठाया है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने न तो राजनाथ सिंहजी पर कोई आरोप लगाया, न कैलाशजी मेघवाल पर कोई आरोप लगाया, फिर यह स्पष्टीकरण के लिए, पाइंट ऑफ आर्डर उठाया, वह गलत है। इसलिए सदन के कोई माननीय सदस्य हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या उसके बारे में बात की है, इसलिए उनके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं, आपको क्या पता? उन्होंने क्या कहा, वह आपको क्या पता? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो इन्होंने कहा, उसका आप उत्तर दे देना। जो कैलाशजी ने कहा कि राजनाथ सिंहजी के यहां क्या हुआ और मुख्य मंत्रीजी नाराज क्यों हुई, वह आप बता देना। (व्यवधान) ...पाइंट ऑफ आर्डर गलत है।

श्री सभापति: कैलाशजी ने क्या कहा, नहीं कहा, वह यहां उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगायें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरी तरफ से किसी पर कोई आरोप नहीं है। मैं तो तथ्यों का विवेचन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या तथ्यों का विवेचन कर रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो चीजें सामने हैं, उनको बता रहा हूं। मेरी तरफ से किसी पर कोई आरोप नहीं है। जो तथ्य हैं, उनका विवेचन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कैलाशजी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वह आज यहां आंसर देने के लिए नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तथ्यों को सदन पटल पर रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे यहां पर लोकतंत्र है और हमारे यहां पर आन्तरिक लोकतंत्र है। अभी आपने एक अख़बार में पढ़ा कि ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुख्य मंत्री पर आरोप लगाये, मुख्य मंत्री हमारी सब की है, इसलिए पीड़ा हुई है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको इतनी पीड़ा नहीं है जितनी हमको है। दिलावरजी को नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके आन्तरिक लोकतंत्र पर आप कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इनको बिठाओ ना साहब। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शिवचरणजी माथुर हैं, उनको इतना डांटा कि इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यह कांग्रेस पार्टी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): इनके पास कोई एवीडेंस नहीं है, यह यूं ही बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं कह रहा हूं कि सी.पी. जोशीजी ने माथुर साहब यहां सदस्य हैं, माथुर साहब को इतना डांटा कि उनको भर्ती होना पड़ा। यह तो इनकी कांग्रेस की संस्कृति है। यह लोकतंत्र है, आपने किया होगा, अच्छा किया होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इनको बिठा ही नहीं पा रहे हैं सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो आप इनको पहले बिठाओ तो सही।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें सब। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारी पार्टी में हम क्या कह रहे हैं, आपकी पार्टी में क्या कह रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं-नहीं, अब आप बोलें। दो मिनट में समाप्त करें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, वह पांच मिनट ही अभी बाकी हैं। माननीय सभापति महोदय, 17 लाख बी पी एल परिवार (व्यवधान) अब इनको बहुत कष्ट हो चुका इसलिए अब मैं टर्न ले रहा हूं, साढ़े 17 लाख बी पी एल परिवार हैं, जो आपने घोषित किये थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनायें, नो कमेंट्स, लैट हिम कम्प्लीट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नैतिकता की बात करने वाले और जो मुझे सलाह दे रहे थे कि अभिभाषण पर भी तो बोलो। अभिभाषण पर क्या बोलूं? जब से आपने अभिभाषण चालू किया है, आप खुद ही मानते हो कि उपलब्धियां कम से कम होती जा रही हैं। बताऊं इसका कारण आपको। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहला अभिभाषण आपका था, आप देखें नये माननीय संसदीय सचिव। पहला जो अभिभाषण था, उसमें आपने 50 पेज की उपलब्धियां गिनाईं, दूसरे में आप 45 पर आ गये, तीसरे पर 52 पर आ गये और चौथे में फिर 52 पर और आखिर में आपकी उपलब्धियां 37 पेजों पर आ गयीं। अगर आपकी उपलब्धियां 3-4 सालों की होतीं तो 100 पेज का होना चाहिये था।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह आंकड़े कहां से लाये?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 100 पेज का होना था, लेकिन मंत्रिमण्डलीय समिति, जो इसको बनाने और अप्रूव कराने के लिए बनी, उसमें जिसमें दिमाग था, उसने उसका उपयोग कर लिया और जो उसमें सिपहसालार थे मुख्य मंत्रीजी के, वह मूकदर्शक होकर बने रहे और यह उपलब्धियां कम से कम करा दीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अमृत भर दिया उसमें थोड़ा सा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो अब तक यह बेकार पेज उसमें क्यों छापे? यह अमृत ही छापते ना। हमें तो अफीम क्यों खिलाई, यह अमृत ही छापते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप यह पृष्ठ गिन रहे हो क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं साढ़े 17 लाख बी पी एल परिवार बने, तीन लाख इन्होंने कम कर दिये, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोष किसका है? 2002 में चयन किसने किया? मापदण्ड किसने बदले? सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 2002 में चयन किसने किया? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक भी बी पी एल का कार्ड नहीं बना पाये इन सालों में। डेढ़ साल में एक भी बी पी एल परिवार का कार्ड नहीं बना पाये। हर साल एवरेज जो राजस्थान का है 1000 में से सात आदमी मरते हैं और इस प्रकार साढ़े 17 लाख में से 12 हजार लोग हर साल इलाज के अभाव में आप मार रहे हो। साढ़े 17 लाख बी पी एल परिवारों के एक भी आदमी को आपने गेहूं आबंटित नहीं किया, आपको शर्म नहीं आती। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं। आप हमसे यह कहना चाहते हैं। आपने अभी यह जो अभिभाषण दिया है, इसमें कहा है हमने 305 एम ओ यू (व्यवधान) अब आप इनको बिठा दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन इस तरह का नहीं है कि कुछ भी कहते जाओ, कुछ भी कहते जाओ। अब यहां तथ्यों के आधार पर कहें कि 17 लाख बी पी एल परिवारों को गेहूं नहीं मिला।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप जवाब दो, आपने उनको गेहूं दिया क्या? आप जवाब दो आपने उनका मेडिकल कार्ड बनाया क्या? जवाब दो न इस बात का? आप जवाब दो कि आपने इनका कार्ड बनाया? एक का भी कार्ड नहीं बनाया आपने और डेढ़ साल हो गये और शर्म नहीं आ रही सरकार को। उन गरीब लोगों को इलाज के अभाव में, जो योजनाएं अशोक गहलोत के समय में चालू हुई थी, आप उनका लाभ नहीं पहुंचाकर बेमौत मार रहे हो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): 2002 में चयन किसने किया?

श्री सभापति: अब आप बिराज जाइये ना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बिराज जाइये मैंने सबका इतिहास बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अवसर आये तब बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने अपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आप पढ़कर सुना रहे थे, लेकिन न तो आपने पुराने पढ़े, जब आप धन्यवाद का प्रस्ताव पास कर रहे थे, आपने कहा नवम्बर, 2007 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप कान्फ्रेन्स के अवसर पर राज्य में 1,62,607 करोड़ रुपये के निवेश हेतु एम ओ यू और लैटर ऑफ इंडेंट किया। इनमें से आपने आगे नहीं पढ़ा, आप इसको पढ़ देते - प्रस्तावों के अन्तर्गत हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने कहा इसके बाद आपने पहले जो 2006 में भी आपने कहा था महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा एण्ड रीको के तहत जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर स्पेशली इकोनोमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। जयपुर-अजमेर रोड पर भूमि आरक्षित कर दी गयी है। इससे एक ओर निवेश में प्रोत्साहन होगा और दूसरी ओर राजस्थान के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। आपने इसी प्रकार 2007 में ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पांच मिनट हो गये सभापति महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सुनो, आपको याद नहीं है, यह आपका काम नहीं है। आप तो सरकार चलाओ, ऐश करो, ट्रांसफर करो और मौज करो।

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में कनक्लूड कर दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार की सकारात्मक नीतियों के परिणामस्वरूप 2006-07 में माह दिसम्बर, 2006 तक प्रदेश में 3,323 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हुआ और गत तीन वर्षों में यह निवेश 7,174 करोड़ रुपये का रहा है। राज्य में नई सीमेंट इकाइयां निर्माणाधीन एवं वर्तमान इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें चार हजार करोड़ का नियोजन अनुमानित है और मैंने जब प्रश्न लगाया, आपसे पूछा कि आपने कितने लोगों को रोजगार उद्योगों में सीधा दिया है, कतई शर्म नहीं आयी। माननीय राज्यपाल महोदय से असत्य बयान करवाया। आज गलत लिखाया, पहले भी गलत लिखाया। इनका जवाब है माननीय उद्योग मंत्रीजी का कि हमने तो केवल एक उद्योग लगाया है साढ़े चार साल में पूरे राजस्थान में और 2200

(श्री हरिमोहन शर्मा)
लोगों को रोजगार दिया है। इतना असत्य बयान माननीय संसदीय सचिव साहब, तीनों भाषण आप पढ़ लेना। माननीय उद्योग मंत्रीजी का जवाब पढ़ लेना, एक लाख हजारों करोड़ का निवेश करने की बात करने वालों, साढ़े चार साल में एक उद्योग आप नहीं लगा पाये, सारे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सम्बोधन करना सीख लो सम्बोधन कैसे किया जाता है हाउस में, वह सीख लो पहले तो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐश और आराम करने के अलावा उन लोगों को बुला करके, उनके साथ आयोजन करने के अलावा लाखों रुपया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहले सम्बोधन किस को किया जाता है, वह सीख लो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेवल पर खर्च करने के बाद आपके राजस्थान में नियोजन की यह हालत है आपकी यह हालत है ...

श्री सभापति: अब हो गया आपका समय, आप विराजें। आपने पांच मिनट कहा, हमने सात दे दिये, अब विराजें आप। आप विराज जाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अब मैं इन सब बातों के बाद मैं उस पर विशेष बात नहीं कह करके एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के हित में कोई ऐसा काम आप नहीं करें, जो यह आपकी आदत में ऐसा बन गया है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वो तथ्य अंकित करें जिनको आप पूरा नहीं कर पाये। आपके अब तक के जो मैंने उदाहरण दिये वो यही दिये हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय से यह असंवैधानिक सरकार उन तथ्यों पर अपना भाषण दिलवाती है जिनको पूरा करने में, उनको पूरा करके लागू करने में कतई न सोच है, न दृष्टिकोण है, न विचार है, न ताकत है और न सामंजस्य है और न केबीनेट में सामंजस्य है। आरोप-प्रत्यारोपों से जुड़ी ...

श्री सभापति: विराज जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, विराज जाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आखिर में एक शेर है।

श्री सभापति: हां, शेर सुनाओ, चलो सुना दो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आखिर में एक शेर है। वैसे मैंने अभी शराब वाली और यह बातें नहीं कहीं, भाई, घर-घर में दुकान खोल दी, वह नहीं कही। ...(व्यवधान) आप नाराज होंगे, यह संघ निष्ठ लोग नाराज हो जायेंगे, मैंने कहा, शराब की मत बोलो।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सियारों का शेर से क्या लेना-देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो आपके लिए खोल रखी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अच्छा, खैर चलो। 'हर सितम लूटमार गबन देखा, हर दिशा में, माथे पर हिमालय के शिकन देख रहा हूं, जमहूरियत का दौर है क्या कह रहे हैं आप, गोलियों में आपका चाल-चलन देख रहा हूं।' गोली चलाओ, लोगों को मारो ...(व्यवधान) धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय जोगेश्वरजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय।

श्री सभापति: बाद में करायेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बीच वालों की बारी भी आयेगी अभी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बीच वालों की बारी? मुझे लगता है लास्ट में बलि चढ़ेगी।

श्री सभापति: मैं करूंगा। (व्यवधान) आप बोलें पहले।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मुख्य सचेतक महोदय का शेर आधा रह गया।

श्री सभापति: माननीय कासनिया साहब, आप विराजें, आप बोलने दें। अभी करता हूं, मैं एडजस्ट करता हूं, विराजो आप, बोलने दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण इस सदन के पटल पर पढ़ा है उस अभिभाषण पर महामहिम का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसके समर्थन बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस पुस्तिका में बहुत कुछ लिखा है और अभी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य इस पर बहस कर रहे थे तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा था कि ग्रन्थों में तो लिखा अलग है और पंडितजी ने पढ़ा अलग है। जो कुछ लिखा वो उसमें से कुछ नहीं बोले और जो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसमें नहीं था वो सब कुछ बोले और बाद में मुझे समझ में आया जब आखिर में उन्होंने खुद अपनी पोल खोल दी कि उन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ पन्ने गिने हैं। सिर्फ पेज गिन कर रह गये और इस अभिभाषण पर एक घण्टा इस सदन का समय जाया किया। जिस व्यक्ति ने इसको सीरियसली पढ़ा ही नहीं वो इस पर बहस करे तो इससे अधिक दुर्भाग्य सदन का नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं जानता हूं पर जिस बात की बहुत बढ़-चढ़कर चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य बी.पी.एल. परिवारों की बहुत चिंता कर रहे थे। (व्यवधान) ले चुका एक बार आपसे पहले।

श्री सभापतिः कृपया शांति बनाये रखें, रघुवीरजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बी.पी.एल. परिवारों की चर्चा कर रहे थे, बी.पी.एल. परिवारों के प्रति बहुत सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को कि दिल्ली में इनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, बी.पी.एल. के लिए क्या नीति होगी दिल्ली तय करती है, बी.पी.एल. में किस को लिया जायेगा, किस को नहीं लिया जायेगा, दिल्ली तय करती है। जब दिल्ली की सरकार ने केन्द्र सरकार ने तय किया इस बार सेंसस के आधार पर बी.पी.एल. के परिवारों की पुनर्गणना तय की उस समय राजस्थान में 20 लाख 97 हजार परिवार थे बी.पी.एल. की सूची में, अब वास्तविक सर्वे जब शुरू हुआ तो वह संख्या आगे जाने लगी, 24 लाख के आस-पास जाने लगी, दिल्ली की सरकार ने कहा, नहीं, यह तो आंकड़े गड़बड़ हो जायेंगे, देश की छवि खराब हो जायेगी, इतने सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हमने चलाये उसके बावजूद गरीब बढ़ कैसे गये, घटने चाहिए। गरीब घटे कि नहीं घटे गरीबों की संख्या घटाओ। यह निर्देश मिले, तुगलकी फरमान जारी हुआ दिल्ली से और उन्होंने कहा 17 लाख से ऊपर नहीं जायेगी, वास्तविक संख्या कितनी है, उससे मतलब नहीं है, वास्तविक धरातल पर स्थिति क्या है, उससे इस पार्टी को मतलब नहीं, इनकी सरकार को मतलब नहीं, 17 लाख से ऊपर आप नहीं जायेंगे, यह एक तुगलकी फरमान राजस्थान सरकार के लिए जारी कर दिया और उसके कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई कि 3 लाख 16 हजार लोग बी.पी.एल. की सूची से कम करने पड़ गये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कटौती की ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सरकार ने कटौती की। करी न? भारत सरकार ने करी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पी.एम. अटलजी थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): गलत, गलत। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): इस सरकार ने उस तुगलकी फरमान को मान लिया?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, यह प्रमाणित हो गया कि जोर से चिल्ला-चिल्ला कर गलत तथ्य देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह गलत है तो यह सरकार उस वक्त की भारत सरकार की चिट्ठी टेबल पर रख देवे। अगर यह गलत है तो टेबल कराओ वो चिट्ठी आप, मेरी चुनौती है। वो एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने राजस्थान के गरीबों के साथ कुठाराघात करने का काम किया था।

श्री सभापति: आपका नम्बर आये जब बोल देना, विराजो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और वो सीमा घटायी थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने घटायी थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय लोढ़ा साहब, विराजें आप, इनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बहुत जोर से बोलने से सच झूठ नहीं होता, झूठ सच नहीं होता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं पूरी सरकार से कह रहा हूं, सारे अधिकारी आपके पास हैं, टेबल करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका टाइम आयेगा तब बोल लेना आप। विराजें आप, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टेबल करा दीजिए वह चिट्ठी। राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए इस सदन का प्रयोग मत करिये।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपके कहने पर बहुत सारे पत्र यहां पर टेबल हुए हैं और हर बार आपने मुंह की खायी है, इस बार भी आप मुंह की खाओगे।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बी.पी.एल. की संख्या जबरदस्ती घटवाने का तुगलकी आदेश देने वाले पार्टी के लोग जब गरीबों के बारे में सहानुभूति प्रकट करते हैं या संवेदनशीलता की बात करते हैं तो वह लफ्फाजी के सिवाय मुझे कुछ नजर नहीं आती। वास्तविक संवेदनशीलता क्या होती है, इसका नमूना इस बार हमने देखा। सी.आर.एफ. के नोर्म्स क्या हैं, ओला पड़े तो प्राकृतिक आपदा है, पाला पड़े तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। पाला कोई इन्सान डालता है क्या? पाला ऊपर से ही आता है। इस प्रकार के जो बेतुके नोर्म्स बना रखे हैं, जिसमें संवेदनहीनता स्पष्ट नजर आती है, राजस्थान सरकार ने मांग करी कि यह नार्म्स सी.आर.एफ. के बदलिये और इन गरीबों को, इन किसानों को फायदा दीजिए पर वहां बैठे हुए, दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगी और यहां इनमें से एक भी नेता को फुर्सत नहीं मिली जो जाकर कहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परसरामजी मदेरणा का जिन्होंने पहली बार हिम्मत करके एक पत्र लिखा सोनियाजी को कि इस पर विचार करें, आप में से किसी को फुर्सत नहीं मिली।

एक माननीय सदस्य: वह भी एक माह बाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वह भी एक माह के बाद। उनको उम्मीद थी कि यह नौजवान जो विधान सभा में बैठे हैं या संसद में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें कोई बोलेगा। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया तब उस बुजुर्ग आदमी को आगे आना पड़ा और यह लिखना पड़ा राजस्थान की जनता के हित में। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं पर आप में से किसी को नहीं सूझी यह बात, आप में से किसी को याद नहीं आयी यह बात।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय मुझे पता नहीं वो किस बात पर आंसू बहा रहे थे पर इस बात पर आंसू बहाये कि फुर्सत उनको भी नहीं मिली। यह आपकी संवेदनशीलता है और जब हम संवेदनशीलता में काम कर रहे हैं, 126 करोड़ रुपये हमने दे दिये तो कह रहे हैं कम है। कम सही, दिये तो हैं, 126 करोड़ कम होते हैं तो राजस्थान सरकार की जितनी सीमा थी कर दिया, और कम पड़ रहे हैं तो आप वहां से लेओ न दिल्ली से, पर नहीं जायेंगे। दिल्ली से बात नहीं करी एक महीने तक फुर्सत नहीं मिली बात करने की आपको और वो कह रहे हैं हम संवेदनशील लोग हैं। यह राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता कैसी है, इसका उदाहरण हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

और संवेदनहीन कितने हैं यह लोग, इन्होंने भी अपनी तरफ से अपना उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।

सभापति महोदय, मैं दूसरी चर्चा करना चाहूंगा। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को जिन्होंने जालौर और बाड़मेर दो जिलों के लिए नर्मदा से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विशालकाय योजना को आकार दिया, 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया उसके लिए और बहुत खुशी की बात है, जालौर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, उसमें एक जो एफ.आर. प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें प्रभावित होने वाला है, जालौर जिले के 697 गांवों में से मैग्जिमम गांव जिसमें कवर होने वाले हैं, ऐसे उस एफ.आर. प्रोजेक्ट के 310 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को उन्होंने चालू कर दिया एवं धरातल पर काम शुरू है, पाइप लाइन बिछ रही है और अन्य सारी कार्यवाही जारी हैं। इसके साथ ही साथ इसका सेकण्ड प्रोजेक्ट जो है 129 करोड़ का डी.आर. प्रोजेक्ट, उसके टेण्डर काल हो चुके, बहुत जल्दी वो टेण्डर खुलेंगे, उसका भी काम शुरू होगा। इस सन्दर्भ में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जरा सी बात ध्यान में लाना चाहता हूं, तीसरा प्रोजेक्ट जो है, भीनमाल तहसील और जालौर तहसील का जिसमें कवर होना है जो पीडी कौर नाम की एक संस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर दिया है। उसका काम जरा धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहूंगा सरकार से कि उसमें हस्तक्षेप करे और उसको तीव्र गति से चलाए उस काम को ताकि जालौर और बाड़मेर की जनता को पीने के लिए शुद्ध पेयजल बिना फ्लोराइड, बिना नाइट्रेट का शुद्ध जल पवित्र नर्मदा का जल पीने के लिए मिल सके। यह कल्पना हम शीघ्र साकार कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बार-बार प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्य चर्चा करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं वह केन्द्र के पैसे से कर रहे हैं, विशेषकर हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। जो भी बात चले यह तो केन्द्र से आया है, यह तो केन्द्र से आया है। केन्द्र से आया है तो किसका है, हमने केन्द्र में भेजा पैसा, राजस्थान की जनता ने अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में भेजी तब आया है। हमारा हिस्सा आ रहा है, हमारा अधिकार आ रहा है, कोई भीख नहीं और उसके बावजूद केन्द्र से पैसा कोई पहली बार तो नहीं आया है। जब से देश आजाद हुआ तब से आ रहा है और उस केन्द्र के पैसे का सदुपयोग कितना हो रहा है, उसकी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

चर्चा करने की फुर्सत आपको नहीं है। इस पुस्तक को यदि पढ़ा होता हरिमोहन जी ने तो तुलनात्मक आंकड़े इसमें हैं। पी एम जी एस वाई की चर्चा करें, आपके पांच साल के कार्यकाल में 3936 किलोमीटर सड़क बनी पूरे पांच साल में। हमने इन चार साल में 24 हजार 84 किलोमीटर बनाकर दे दी। कहीं तुलना है, आस-पास भी फटकते हो कहीं? आपने पूरे पांच साल में 918 गांवों को सड़क से जोड़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरु किया था, एक यूनिक कल्पना थी वह। उसमें हमने इन चार सालों में 7643 गांवों को जोड़ दिया उसकी तारीफ करने की फुर्सत नहीं है आपको। केन्द्र का पैसा आपको भी मिल रहा था, नहीं कर पाये आप खर्च, खर्च करने की ताकत नहीं थी आपमें, काम में लेने की ताकत नहीं थी केन्द्र के पैसे को, वह पैसा लैप्स होता था। हमने उसको काम में लेकर दिखाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब दिल्ली में आपकी सरकार थी राजस्थान को 1300 करोड़ रुपया साल का मिलता था आज 4300 करोड़ रुपया मिल रहा है ...(व्यवधान) क्योंकि हमारी सरकार ने राजस्थान का शेयर सैण्टर की रेवेन्यू में पाइंट सिक्स परसेंट बढ़ाया है ...(व्यवधान) उस वजह से राजस्थान को हजारों करोड़ रुपये का फायदा हुआ। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): महाराष्ट्र में करके बता दो, आन्ध्रा में करके बता दो, कर्नाटका में करके बता दो, पैसा वहां भी मिलता है। राजस्थान फर्स्ट नम्बर है, खर्च करता है, मैनेजमैंट है, काम करता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया, आपका टर्न आए तब बोलना।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): वह ढंग से खर्च करके बताया ना तब उन्होंने बढ़ाये थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं धन्यवाद करता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का। आपने प्रमाणित कर दिया भारत सरकार तब भी देती थी, आपकी सरकार सक्षम नहीं थी उस पैसे का उपयोग करने में, इसलिए कम मिलता था। आज हम सक्षम हैं, उपयोग करके दिखा रहे हैं इसलिए मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा केवल, पैसे के साथ शाबाशी भी मिल रही है कि शाबाश राजस्थान सरकार, वहां पर अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश वसुन्धरा जी, आप अच्छा काम कर रही हो, आपका एक-एक मंत्री आकर शाबाशी लेकर जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पड़ा हुआ है 1800 करोड़ रुपया राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, क्या खर्चा कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें, आपका टर्न आए जब बोल लेना आप कोई मनाही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, उन्होंने खजाना खोल दिया राजस्थान के लोगों के लिए ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): गिरवी रख दिया भारत को ...(व्यवधान) गिरवी रख दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज राजस्थान के कोने-कोने के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका टर्न आए तब बोल लेना ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह देश के प्रधान मंत्री, सोनिया गांधी की देन है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, भारत आजाद होने के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में These sort of things will not be allowed.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एक-एक नौकरी जो नौजवान को मिल रही है, विकास की एक-एक ईंट जो लग रही है वह भारत सरकार की देन है, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की देन है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप। इस प्रकार की बातें अलाऊ नहीं की जाएंगी, विराजें आप ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक मिनट मैं निपट लूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: Let him complete.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को उन्होंने याद दिलायी नरेगा की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पूरे देश में जैसा काम चल रहा है उसमें राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है प्रति व्यक्ति 27 दिन का रोजगार हम दे पाये हैं पूरे देश में। राजस्थान का क्या

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आंकड़ा है यह पुस्तक पढ़ी होती तो आपको समझ में आता 55 दिन कहां 27 कहां 55, डबल राष्ट्रीय औसत से दुगुना औसत हम दे रहे हैं राजस्थान में और तीन लाख बारह हजार परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सौ दिन का रोजगार का उपभोग कर लिया है और इस बारे में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, रिकार्ड पर लाना चाहूंगा जालौर जिले ने इस मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है और इतने योग्य तरीके से उस योजना को लागू किया है, एक पैसे की गड़बड़ी नहीं होने दी, एक पैसे का फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया जो मेरे पड़ौस के जिले में आप करवा रहे थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुख्य मंत्री के खुद के गृह जिला मनोहरथाना ब्लाक के अन्दर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार रोजगार गारंटी योजना में हुआ है।

श्री सभापति: You are not allowed. Expunge it.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रोजगार गारंटी योजना के अन्दर मजदूरों को रोजगार देने के पांच-पांच सौ रुपये लिये गये, सभापति महोदय, लाखों रुपये का गबन मनोहरथाना के अन्दर हुआ है।

श्री सभापति: This is not allowed. (व्यवधान) संयमजी, मैं आपको नाम लेकर पुकार रहा हूं Mr. Sanyamji, this is not allowed. बैठिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अब यह आपका दृष्टि दोष है, सभापति महोदय, यह इनका दृष्टि दोष है। मनोहरपुर, झालरापाटन और झालावाड़ में जो हो रहा है वह इनको दिखाई दे रहा है और जो जालौर में इनकी नाक के नीचे इतना बढ़िया काम हो रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे-बैठे कोई कमेंट्स नहीं होंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जालौर में, सिरोही में पहले ही योजना शुरू हुई। आपने उस योजना में बहुत हस्तक्षेप किये और उसके कारण वहां गड़बड़ियां पैदा हुईं। जालौर में वही योजना आदर्श रूप में लागू हुई और इतनी आदर्श रूप में हुई कि आज देश भर के आई ए एस अफसरों को भेजा जा रहा है, जाओ नरेगा देखना है तो जालौर में जाकर देखकर आओ, आप भी करके बता देते, नहीं कर पाये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान का सबसे बड़ा काम रोजगार गारंटी योजना में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: This is not allowed. विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) इलाके में हुआ है सबसे बड़ा काम जो है रिकार्ड है यह।

श्री सभापति: No. This is not allowed. संयमजी क्या हो गया आपको, असंयमित क्यों हुए जा रहे हैं आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह मुझे कोट कर रहे हैं Why he is quoting me? Why again and again he is telling by my name? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं।

श्री सभापति: ना तो यह आपका नाम लें ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा नाम लेकर कहेंगे तो हर बात का मैं जवाब दूंगा ...(व्यवधान) हर बात का जवाब है मेरे पास।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपका नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप बीच में टोक रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमें इंगित करके बार-बार कहेंगे। या तो आप इनको कहिये कि मुझे इंगित नहीं करें। अगर मुझे करेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ना तो आप इंगित करें ना ये इंगित करें। आसन की तरफ इंगित करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, अगर ये मुझे सम्बोधित करके कहेंगे तो हर बात का जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन को इंगित करेंगे। आप भी इधर करेंगे, आप भी इधर करेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और जितनी बार आप टोकेंगे उतनी बार आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, डिस्टरबैंस तो कम से कम नहीं होना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता थोड़ा सा सम्भालें, बीच में फिर कोई दूसरा बोलेगा फिर इधर से आब्जेक्शन करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आनें दें जो भी जवाब देना है दीजिए, कहां दिक्कत है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अभी यह फिर बात कर रहे थे सर्व शिक्षा अभियान की, केन्द्र का पैसा आ रहा है। मैं फिर धन्यवाद देता हूं अटल बिहारी जी वाजपेयीजी को, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान जैसी एक सर्वश्रेष्ठ योजना इस देश को दी जिसके कारण इस देश में शिक्षा का इतना अधिक फैलाव हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस सर्व शिक्षा अभियान के दौरान उस अभियान का लाभ लेने में तत्कालीन सरकार राजस्थान में सबसे फिसड्डी रही, सारे देश में सबसे पीछे। हमने हमारे कार्यकाल में उसमें जो काम करके दिखाया है 45 हजार 188 विद्यालय या तो नये खुले या क्रमोन्नत हुए। सिर्फ चार साल में और शिक्षकों की भर्ती उसके बारे में तो यह बोलने लायक हैं ही नहीं, पांच साल में एक अध्यापक भर्ती नहीं कर पाये आप, चपरासी तक भर्ती नहीं कर पाये, आप कोई पटवारी भर्ती नहीं कर पाये, कोई ग्राम सेवक भर्ती नहीं कर पाये, कोई डाक्टर भर्ती नहीं कर पाये, कोई नर्स भर्ती नहीं कर पाये, 73 हजार शिक्षक अब तक भर्ती हो चुके हैं राजस्थान की धरती पर और भी छह महीने हमारे हाथ में और बाकी हैं, और भर्ती होंगे ...(व्यवधान) अब आपकी बारी है वह तो थक गये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तरीका ठीक नहीं है आप बता दो, रिकार्ड पर रखो कितने चपरासी भर्ती किये, लाओ रिकार्ड पर लाओ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): चपरासी कितने किये बताइये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान में चपरासियों के सारे पद खतम किये हैं, सारे पद खतम किये हैं ...(व्यवधान) हर बार चपरासियों के पद खतम किये हैं। एक भी चपरासी की भर्ती राजस्थान में नहीं हुई है एक भी भर्ती ...(व्यवधान) अगर की है तो रिकार्ड पर रखो यहां पर। एक चपरासी की भर्ती नहीं की ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, यह पद खतम कर ...(व्यवधान) आपको मालूम होना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में 1,12,740 पद दिये थे वह भी नहीं भर पाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी विराजें, बोलने दें।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापकों की बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य बताएं कि चपरासी कितने किये, चपरासियों की पोस्टें गिनाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप, बाद में प्रश्न करना ...(व्यवधान) नेता दे देंगे जवाब दे देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में यह एक परम्परा शुरू हुई जो चपरासी रिटायर हो गया वह पोस्ट एबोलिश। चपरासी रिटायर पोस्ट खतम। साथ के साथ ले गये। वह लोग इतना बढ़-चढ़कर बोल रहे हैं उनको थोड़ा आइने में अपनी शक्ल देखते रहना चाहिए।

सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा माहिर आजाद साहब बिराज रहे हैं सुन लें ध्यान से। मदरसे राजस्थान की धरती पर सालों से चल रहे हैं, दशकों से चल रहे हैं और सबसे ज्यादा हिमायती बनते हैं आप लोग उस समाज के। साठ साल से आप लोग उस समाज को बरगला रहे हैं, विकास की किरण उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उन मदरसों के बारे में झांक कर देखने की फुरसत आपको नहीं मिली 60 साल में। हमारी सरकार ने, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उन मदरसों की तरफ देखना शुरू किया। मदरसा बोर्ड का गठन किया और मदरसा बोर्ड के माध्यम से उन मदरसों का पंजीकरण किया। रिकार्ड में लाए उनको। 2490 मदरसे अब तक पंजीकृत हो चुके, पंजीकृत होने की व्यवस्था चालू है और पंजीकृत होने का फायदा क्या मिला? उनके वहां जो टीचर्स लगे हुए हैं उनको तनख्वाह सरकारी कोष से मिलनी शुरू हुई। वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकारी कोष से पुस्तकें निशुल्क मिलनी शुरू हुई। अब क्यों नहीं कर पाये यह लोग यह बात? नहीं कर पाये, करना नहीं चाहा। आपको सिर्फ उनको बेवकूफ बनाकर वोट लेना था। हमको तन, मन से सच्चे मन से उनका विकास करना था इसलिए हमने यह सब करके दिया।

बिजली की बहुत बात करते हैं। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली की चर्चा भी जब होती है, माननीय सभापति महोदय, वैसे अब बहुत इस विषय पर बोल चुके। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8460 करोड़ रुपया बिजली पर खर्च हुआ। ग्यारहवीं योजना का प्रावधान 25,600 करोड़ और राजस्थान राज्य की कुल योजना का बिजली के हिस्से में कितना पैसा 36 प्रतिशत। इससे अधिक प्राथमिकता क्या मिल सकती है बिजली के सैक्टर में। बिजली के सैक्टर को प्राथमिकता मिलने का मतलब है आम गरीब छोटे किसान को फायदा मिलना। 1411 मेगावाट नया उत्पादन इन चार सालों में हमने शुरू कर दिया है और पांचवां साल अभी हमारे हाथ में है। जी.एस.एस. 400 के दो जी.एस.एस. राजस्थान की धरती पर नये बन गये और 220 के 11 एक साथ जिसमें से एक जालौर में अभी बना और 400 का जालौर में बनने वाला है भीनमाल में। 132 के 47 जी.एस.एस. चालू हो चुके और 32

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के.वी.ए. जी.एस.एस. की तो गिनती नहीं। 800 के आस-पास जी.एस.एस. 736 तो चालू हो चुके और बाकी अभी प्रोसेस में है। इतना एकदम जो क्रान्तिकारी परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में लाया है हमारी सरकार ने उसके कारण आज सरकार किसानों को अच्छी बिजली, अच्छे वोल्टेज उपलब्ध हो पा रहे हैं लेकिन फिर भी बिजली की कमी है। वह बिजली की कमी कहां है? यह नार्थ ग्रिड जिस पर आपकी सरकार का कब्जा है, आपकी पार्टी की सरकार का कब्जा है वह नार्थ ग्रिड बे-ईमानी करता है। राजस्थान का हिस्सा कम देता है और देता है तो भी इसमें फ्रिक्वेंसी कम देता है ताकि हमारे काश्तकारों को अच्छी बिजली समय पर नहीं मिले। हमने नये कनेक्शन जो जारी किये जितने आपने पांच साल में नहीं किये होंगे उतने हमने अब तक कर लिये। 1,30,000 नये कनेक्शन जिसमें से 30,000 केवल एस.सी. के लिए है। इतने सारे कनेक्शन हमने नये दे दिये और उसके कारण जो स्थिति बनी है वह बहुत अनुकूल स्थिति बनी है। बिजली की निश्चित रूप से अब भी कमी लग रही है उसमें नार्थ ग्रिड का जो शेयर आता है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है उस पर यदि आप लोग कुछ बात कर सको, अपने नेताओं को समझा सको, अपने काश्तकार के हित में, तो यह सदन आपको बहुत धन्यवाद देगा, राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में चर्चा करना चाहूंगा जिस वर्ग से मैं आता हूं। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो काम हुए हैं प्रतिवर्ष औसत व्यय समाज कल्याण विभाग का कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 200 करोड़ रुपये, हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रतिवर्ष औसत व्यय 400 करोड़ रुपये। आपसे दुगुना। छात्रवृत्ति हो, चाहे हास्टल्स हो, चाहे और किसी प्रकार की सुविधा हो, सब में हमने आपसे दुगुना काम करके दिखाया है। आपने पांच साल में 103 करोड़ की छात्रवृत्ति दी, हमने इन चार वर्षों में 214 करोड़ दे दिये छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को। इतना सब जो हमने किया है निश्चित रूप से उस वर्ग में, उस तबके में बहुत अच्छा मैसेज गया है। बहुत अच्छी राहत महसूस की जा रही है।

विशेषकर जो अनुकृति योजना शुरू की है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी का और समाज कल्याण मंत्रीजी का भी। उस गरीब वर्ग का बच्चा आर.ए.एस और आई.ए.एस. बनने का सपना देखता था केवल और पैसे के अभाव में वह रुक जाता था। कोचिंग नहीं कर सकता था वह ढंग की उसके कारण रुक जाता था, अटक जाता था। उसको जो आर्थिक सम्बल इस सरकार ने दिया है उसका गुणगान आज गांव-गांव में हो रहा है और उसके कारण निश्चित रूप से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें अब।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और अंत में कहूंगा मैं विधवाओं की पुत्री के विवाह पर जो मदद सरकार से मिलने की एक यूनिक, योजना श्रद्धेय भैरोंसिंहजी शेखावत ने शुरू की थी, आपके शासनकाल में उसमें भी कोताही हुई। नहीं मिलते थे पैसे लोगों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इधर इशारा करके कहो आप। उधर-उधर मत कहो। इधर ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अब इशारा करने लायक वह लोग उधर ही हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की तरफ देख करके बोलो आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इन्होंने पूरे पांच वर्षो में 3683 विधवा पुत्रियों के विवाह में सहयोग किया दो करोड़ तीन लाख रुपये केवल, हमारे चार वर्षो का आंकड़ा है 6549 केस और सात करोड़ चालीस लाख रुपये। मुक्त हस्त से दिया हमने ताकि उन विधवाओं को जिनके साथ भगवान ने क्रूर मजाक किया है, उनकी बच्चियों को यह अहसास नहीं हो कि उनकी शादी कैसे होगी और शादी में खर्चा निपटेगा। यह जो एक योगदान इस सरकार ने किया है, माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय की कमी थी इसमें मैंने संक्षेप में कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद। वीरेन्द्रजी बेनीवाल।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और इस पुस्तक को यदि ...(व्यवधान) मेरे मित्र पढ़ सकें तो इसमें इतनी सारी बातें हैं जो आई ओपनर हैं। आंखें खोल सकती है और इस सबके लिए मैं न केवल राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कृपा पूर्वक यह अभिभाषण सदन में रखा।

श्री सभापति: वैसे पार्टी का सारा समय तो माननीय हरिमोहनजी ने ले लिया था पर फिर भी ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, समय के हिसाब से दो इधर से बोलेंगे, एक उधर से। अब एक इधर से बोलने के बाद उधर बोलेंगे।

श्री सभापति: कोई बात नहीं अब के कर लेंगे। आप पांच मिनट में कनक्लूड करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बैठ ही जाऊं फिर तो साहब।

श्री सभापति: नहीं, ऐसा है कि एक घण्टा छह मिनट थे अपने तो। एक घण्टा तो वह बोल चुके, आप बोलो पांच मिनट।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): साहब, पांच मिनट?

श्री सभापति: बोलना चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। फरमाओ आप तो। बोलना चालू करो आप तो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ठीक, धन्यवाद साहब। यह आपने ठीक फरमाया बोलना चालू करूं मैं।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलना चालू करो का कह कर जो मौका दिया उसके लिए तो धन्यवाद आपका।

एक और राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत कर सरकार के कार्यों का बखान जो प्रस्तुत किया गया, हालात यह है कि राज्य पूरा अकाल और पाले की चपेट में आकर के किसानों की फसलों के हुए नुकसान के दृष्टिगत किसानों के दुःख से डूबे हुए चेहरों को दृष्टिगत आज के हालात में राज्य सरकार द्वारा एक राहतों की बरसात नाम से 126 करोड़ रुपये की घोषणा करने का जो एक अखबारी समाचार प्रस्तुत किया गया, हालात इससे ठीक विपरीत हैं। आज मौके की स्थिति का आंकलन करने की दुहाई वर्तमान सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि आंकलन करने के लिए आज तक कोई नुमाइंदा किसी खेत तक नहीं पहुंचा। राज्य की इच्छा के अनुरूप जिस प्रकार गत खरीफ की फसल के खराबे का चित्रण करते हुए अकाल के हालात में प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि अधिकांश इलाका खुशहाल है। उस वक्त की गिरदावरी रिपोर्ट को अगर सत्य माना जाए तो हमारा राजस्थान देश के खुशहाल राज्यों में से एक नम्बर पर होना चाहिये था और हमारी मंडियों के अन्दर अनाज के ऊंचे-ऊंचे ढेर होने चाहिये थे लेकिन उसके विपरीत क्योंकि तब की गयी गिरदावरी महज एक ढोंग थी। आज इलाके का आमजन भुखमरी की स्थिति में है। गांवों के हालात बहुत खराब हैं। बड़ी मुश्किल से किसान ने अपनी मेहनत से रबी की फसल का बीजान किया लेकिन दैवीय प्रकोप कहना चाहिये जिसके चलते अत्यधिक ठण्ड पड़ने से जो पाला पड़ा और उस पाला पड़ने के कारण लगभग फसल नष्ट हो गयी। आज उस फसल का जो आंकलन किया जा रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ऊपर का आज के समय में खराबा किसानों

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

का हुआ है। हम अगर केवल बीजाण की बात करें तो सरसों मुख्य रूप से इससे प्रभावित हुई है। उसके साथ चना, इसबगोल, गेहूं तक पर इसका असर पड़ा है और इस सबसे अलग जो हमारे यहां पर अभी औषधीय खेती के नाम पर एक पहल शुरू हुई थी, आंवले का पौधा तक जो लगभग तीन-तीन फीट की हाइट तक आ गया था वह तक नष्ट हो गया है इस खराबे से।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार आज राहत देने की बात तो कर रही है लेकिन किसको, आज दिन तक तो जब हम यह नहीं जान पाये कि किस खेत में क्या बीजाण था, गिरदावरी भी जब तक पिछली नहीं हुई तो आज के खराबे का आंकलन करने की हम बात कैसे करते हैं। सभापति महोदय, आप तथ्यों पर जायें, हालात को देखें, वास्तविक रूप से आपके निचले तबके का कर्मचारी मौके पर जाकर, सही जांच करे और तभी हमारे सामने जो दृश्य है वह आयेगा। आज राज का विकास के बहुत से कार्य करने का बखान बार-बार हम देखते, सुनते और पढ़ते रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा अभी थोड़े ही दिन पहले ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि यह पाला और शीतलहर को आप आपदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह मानता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनको बोलने दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं यह मानता हूं कि किसानों की फसल नष्ट हुई है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): यह नेचुरल केलेमिटी है कि नहीं है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): किसान तकलीफ में हैं ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आपदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं शीतलहर और पाले को?

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपदा है और आपने यह कहा है बजट में ...(व्यवधान) अभिभाषण में यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आप आपदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं यह बतायें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिनके लिये सीआरएफ में प्रोविजन नहीं है, हमने अलग फंड बनाया है और हम उसके लिए सिर्फ आपदा राहत कोष के बजाय अपनी तरफ से देंगे। फिर आप दे क्यों नहीं रहे हो ...(व्यवधान) आप क्यों नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, राज्य सरकार ने शीतलहर और पाले पर जो अभी घोषणा की है, पैकेज दिया है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने फंड बनाने की घोषणा की है या नहीं की 2006 में ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हां, की है, हमने की है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने यह कहा कि नहीं कहा कि सीआरएफ के जो नार्म्स हैं उसमें जो फसल नहीं आयेगी उसका भुगतान हम करेंगे ...(व्यवधान) आपने कहा कि नहीं कहा ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हम यह कहते हैं कि शीतलहर और पाले को आपदा मानते हो कि नहीं मानते हो ...(व्यवधान) सीआरएफ नार्म्स के अंदर परिवर्तन के लिए आप मंजूर कराते हो कि नहीं कराते हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह अलग दृष्टिकोण है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह तो बतायें ना आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह अलग दृष्टिकोण है कि सीआरएफ में परिवर्तन किया जाये ...(व्यवधान) लेकिन आपका अपना वादा है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): राजस्थान में आज तक शीत लहर और पाले पर पांच रुपये भी आपने दिये, स्वीकृत किये हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उस वादे से हटने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): शीतलहर और पाला वर्षों से पड़ता रहा है, पहली बार यह सरकार है जिसने शीतलहर और पाले पर पैकेज दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दिया है तो कोई एहसान नहीं है, कमिटमेंट है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हम एहसान की बात नहीं करते हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका कमिटमेंट है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आपने अपने शासनकाल में एक धेला नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने गवर्नर के अभिभाषण में यह कहा है कि हम देंगे ...(व्यवधान) मैं पढ़कर सुना दूं आपको ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जब हमारी सरकार ने 126 करोड़ रुपये दिये, क्या अशोकजी वहां दिल्ली में इसको सीआरएफ में इनक्लूड करवायेंगे ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, करवायेंगे, कोशिश करेंगे ...(व्यवधान) इसमें कोई अलग बात नहीं है ...(व्यवधान) सीआरएफ की घोषणा में है ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अगर राज्य सरकार इस पर राहत देती है ...(व्यवधान) तो हम दिल्ली की सरकार से ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने तो रोडवेज का किराया बढ़ाकर के जनता के ऊपर कुठाराघात कर दिया। आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। आपने इस सदन में कहा कि रोडवेज का किराया नहीं बढ़ायेंगे ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): डीजल का भाव बढ़ा दिया आपकी यूपीए सरकार ने ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं जब तक मंत्री हूं रोडवेज का किराया नहीं बढ़ने दूंगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): डीजल की कीमत किसने बढ़ायी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने किराया बढ़ा दिया रोडवेज का ...(व्यवधान) आप तो अपनी बात करें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): डीजल की कीमत किसने बढ़ायी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने कहा था कि किराया नहीं बढ़ने दूंगा, जब तक मैं रोडवेज में मंत्री हूं ...(व्यवधान) आपने किराया बढ़ा दिया, आपने गरीब जनता पर कुठाराघात किया है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): डीजल, डीजल ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके डिपो तो घाटे में जा रहे हैं ...(व्यवधान) वह आपसे सुधर नहीं रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) आप रोडवेज की बात करें ना ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप तो दिल्ली जायें, दिल्ली जाकर के बात करें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप रोडवेज की बात करें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): डीजल को डाउन करें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, 22 फरवरी, 2006 पैरा नम्बर 14, राज्य सरकार ने पहली बार राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है जिसके अन्तर्गत उन आपदाओं पर सहायता देने का प्रावधान किया है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह हरिमोहनजी किस पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिसमें आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायता देय नहीं है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): यदि सीआरएफ के अमेंडमेंट के बारे में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इनसे एक बात पूछों कि क्या यह परसरामजी मदेरणा के साथ हैं ...(व्यवधान) क्या यह लोग परसरामजी मदेरणा के साथ हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): करोड़ों रुपया आपके पास पड़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): परसरामजी मदेरणा के साथ हो?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इन्होंने किसानों का शोषण किया है, किसानों के बलबूते पर इन्होंने राज किया है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मदेरणाजी ने चिट्ठी लिखी है, आप उनके साथ हो क्या ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): किसानों को लूटा है इन्होंने ...(व्यवधान) किसानों को एक धेला नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): परसरामजी मदेरणा के साथ हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सीआरएफ में नार्म्स बना नहीं सकते हैं और यहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने यह स्वीकार किया है कि सीआरएफ के नार्म्स के अंदर पाले को शामिल किये जाने में हम भी सम्मिलित हैं। वास्तव में आज किसान तकलीफ में है और इन्होंने जो कहा है कि राजस्थान में सरकार ने जिस आपदा राहत कोष की घोषणा की थी, उसमें पहले ओलावृष्टि में 106 करोड़ रुपये और 126 करोड़ रुपये इस पाले में इस सरकार ने दिये हैं। सीआरएफ के नार्म्स में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या यह सम्भव नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेता प्रस्ताव रखें या सदन की नेता प्रस्ताव रखें। पूरी विधान सभा, पूरा हाउस यह प्रस्ताव पारित करे कि सीआरएफ के नार्म्स में ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप राजनीति मत करो ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): राजस्थान के किसानों की अगर पैरवी करनी है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजनीति करने का प्रयास मत करो ...(व्यवधान) राजनीति करने का प्रयास मत करो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं में तो होगा ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजनीति करने का प्रयास मत करो ...(व्यवधान) आपका यह फर्ज बनता था कि आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय हरिमोहनजी विराजें ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बैठकर के बात करते और चर्चा करते ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेन्द्रजी बहुत सीधे आदमी हैं, यह कह रहे हैं कि मैं बहुत सीधा आदमी हूं। आप ही सीधे हो तो फिर टेढ़ा कौन है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, सभापति महोदय, यह पहली बार है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे ज्यादा कोई टेढ़ा हो सकता है क्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इसमें किसी राज्य की बात नहीं है। यह तो थ्रू आउट कंट्री होगा, सीआरएफ तो ...(व्यवधान) यह राजस्थान प्रांत के लिए अलग थोड़े ही हो जायेगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट में कम्प्लीट कर रहा हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी चिंतित हैं, सदन की नेता भी चिंतित हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी किसानों के सच्चे हमदर्द हैं। किसान के दर्द को गहराई से जानते हैं। सदन की नेता भी जानती हैं। अब हमें केन्द्र सरकार से किसान के लिए मांग करनी चाहिए। एक-दूसरे का हाथ पकड़ करके मांग करें तो इसमें संकोच कहां है। इसलिए या तो कांग्रेस पार्टी कह दे कि जो प्रस्ताव हम ला रहे हैं वह इसका विरोध करती है कि सीआरएफ के नार्म्स में परिवर्तन करें और पाले को शामिल नहीं किया जाये ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रस्ताव लायें क्या कोई कभी चर्चा हुई ...(व्यवधान) राजनीतिक मसले पर राजनीतिक ढंग से बैठकर के बात करें ...(व्यवधान) राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मत करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): यह राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रस्ताव रख देंगे, अकाल राहत मंत्रीजी प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज तक दिमाग में नहीं आयी क्या बात ...(व्यवधान) हमने उठाया तभी आयी क्या आपके दिमाग में ...(व्यवधान) अब तक नहीं क्या बात ...(व्यवधान) आपके दिमाग में आज तक यह बात क्यों नहीं आयी आयी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन तो पहली बार मिला है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इस पर निर्णय करें ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज गम्भीरता से सदन में पहली बार इस विषय पर चर्चा हुई है और प्रतिपक्ष के नेता का मन किसानों के प्रति हमदर्दी लिये हुए है इसलिए इसमें संकोच किस चीज का है। सीआरएफ नार्म्स में परिवर्तन किया जाये और पाले को शामिल किया जाये। यह बात हम कह रहे हैं। आप मांग करो हम समर्थन कर देते हैं। संकल्प पारित करके दिल्ली की सरकार को भेजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भेजो ना, मैं बताता हूं ...(व्यवधान) आप विराजें तो सही ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता मैं तो यहां तक कहूंगा कि सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता सच्चे किसानों के हिमायती, दोनों मिलकर के एक शिष्टमंडल लेकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री को जाकर के कहें कि इस नार्म्स में परिवर्तन करो। इसमें संकोच किस चीज का है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराजें तो सही ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता का नाम लेकर, आप विराजें तो सही ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता से सुनो तो सही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नेता, प्रतिपक्ष फरमायें ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कह रहे हैं कि मैं सीधा आदमी हूं तो फिर टेढ़ा कौन है। इनसे ज्यादा तो टेढ़ा मुझे तो नजर आया नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई टेढ़ा-मेढ़ा नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता, 'समय समय सुंदर सबै, रूप-कुरूप ना कोई'। समय-समय पर सब सुंदर होते हैं, कोई कुरूप नहीं होता है। आप तो फरमायें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हमारे भी एक राठौड़ थे और इनके भी एक राठौड़ हैं पार्टी में। यह राठौड़ी का काम दोनों का एक सा ही है। जो हमारे राठौड़ किया करते थे वही यह करते हैं। खैर, इनका काम है वह करें।

सभापति महोदय, इनको यह डर लगने लग गया कि कहीं कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सोनियाजी से मिले, मदेरणा साहब ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस पार्टी के हम सभी सदस्य चिंतित हैं। राजस्थान के लोग उनसे मिलेंगे कि किसी तरह से किसानों को मदद इस पाले में केन्द्र से भी मिलनी चाहिए, तो इनको चिंता लग गयी। तकलीफ हो गयी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको ही क्रेडिट नहीं मिल जाये। जो कुछ होता है वह तो यही करवाते हैं और नहीं होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इनका एक ही सोच है, उसके सिवाय दिमाग में कोई बात फिट नहीं बैठती है। जो हुआ? क्या वह हमने किया, कोई आदमी एक्सीडेंट होकर के मर गया तो क्या करें भई, ईश्वर ने ऐसा ही कर दिया, अब ईश्वर के आगे किसका जोर है और किसी का कोई काम हो गया तो यह मैंने करवाया है। यह मेरे सिवा कोई नहीं करवा सकता था, यह मैंने करवाया है, आपने जो किया वह भी तो ईश्वर ने ही करवाया है, आपने कहां करवा दिया जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, करने वाला सब ईश्वर है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): किसानों का यह मामला आपकी तरफ से आया है, हम आपके आभारी हैं। (व्यवधान) सारा गंगानगर और हनुमानगढ़ टोटल पाले की चपेट में आया हुआ है और आप इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दें, हम आपके आभारी हैं। किसान टोटल आपका आभारी रहेगा, यह प्रस्ताव ले आओ आप, हम आपका समर्थन करेंगे, यह क्लीयर बात है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप पहले यह प्रस्ताव लाओ कि केन्द्र सरकार ने चार साल में जितनी भी धनराशि आपको दी है उसके लिए हम केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): केन्द्र सरकार का दिया हुआ सी आर एफ का 421 करोड़ रुपया आपके पास पडा है, आज तक इसको आपने किसानों में नहीं बांटा, यह 421 करोड़ रुपया आप किसानों को देने की घोषणा कर दें, हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। (व्यवधान) आपकी सरकार किसानों को सी आर एफ का बकाया दे दे, आज ही आप घोषणा करिए। (व्यवधान) सरकार 421 करोड़ रुपये देने की घोषणा करे, हम आपका समर्थन करेंगे। (व्यवधान)

(श्री जुबेर खान)

421 करोड़ रुपये की पहले आप घोषणा करिए तब हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, ठीक है, ठीक है। (व्यवधान) मंजूर है। सभापति महोदय, कांग्रेस के सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है हमें मंजूर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सी आर एफ के अंदर जो पैसा है वह पैसा किसी की बपौती नहीं है, इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है और यह सारा पैसा नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सब राज्यों को मिलता है और उसमें बचत हर राज्य में रहती है। अब इन्हीं पैसों से हम मदद करना चाहते हैं, इन्हीं पैसों से हम सहायता करना चाहते हैं किसानों की तो जब तक नार्म्स यह रहेंगे पाला शामिल नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पैसा आपका अपना है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): केन्द्र सरकार आपको रोकने नहीं जा रही है। (व्यवधान) सी आर एफ के पैसे के अपने कायदे-कानून हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने पैसे से सहायता दे सकती है। हरियाणा और पंजाब की सरकार इस तरह से सहायता दे रही है, मुआवजा दे रही है, इनकी तरह से आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आपके टाइम में सी आर एफ नहीं था क्या? (व्यवधान) उस समय गंगानगर में किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, सी आर एफ उस समय नहीं था क्या? अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को गंगानगर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। आपके टाइम में भी सी आर एफ था, उस समय फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्र सरकार ने चार साल में हजारों करोड़ रुपये दिए हैं, आप धन्यवाद क्यों नहीं देते, आप इसका धन्यवाद प्रस्ताव रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह बात आप बाद में कर लेना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप धन्यवाद प्रस्ताव उसका रखें कि केन्द्र सरकार ने 4 साल में कितने हजार करोड़ रुपये दिए, उसका धन्यवाद प्रस्ताव रखो। केन्द्र को धन्यवाद तो दो नहीं, पैसा आप ले लो और आलोचना और करो। केन्द्र को धन्यवाद आप क्यों नहीं देते? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। केन्द्र को भी अब की बार पैसा देना पड़ेगा। (व्यवधान) मैं दावे के साथ कहता हूं कि केन्द्र को किसानों को सहायता देनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर सी आर एफ के नाम पर राजनीति करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए बेनीवाल साहब। (व्यवधान) आप बेनीवाल साहब को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसमें आपको एतराज है क्या कि जो सी आर एफ का पैसा है उससे प्रभावित लोगों को मदद मिले और यह प्रस्ताव आपके यहां से चला जाए कि उसमें नार्म्स यह तय हो जाएं कि जो ओलावृष्टि है और जो पाला पीड़ित हैं वह शामिल हो जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बात नहीं है। 420 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है, एक टाइम के बाद यह आपका अपना निजी हो जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम आपकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को मिला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसमें केन्द्र स्वीकृति दे दे, उसमें आपकी स्वीकृति है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने 2006 में कमिटमेंट किया कि नहीं किया? फिर आप केन्द्र की ओर क्यों देख रहे हैं? आप अपने फण्ड से कीजिए न, कुछ कर सकते हैं तो, आपने वादा कर लिया अभिभाषण में, कुछ भी बोल गए, गवर्नर से असत्य बुलवा दिया और फिर यह कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): केन्द्र सरकार की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि राज्य सरकार भी केन्द्र सरकार के अधीन है, इस देश का भाग है राजस्थान। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, आज पूरा सदन जनवरी और फरवरी में ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सदन का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): पाले से राजस्थान के किसानों को जो नुकसान हुआ है ...(व्यवधान) मैं प्रस्ताव करता हूं और पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि यह प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से आग्रह किया जाए कि ओलावृष्टि, शीत और पाले के सी आर एफ के नार्म्स में परिवर्तन कर किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए अनुमति प्रदान करे।

श्री सभापति: बेनीवाल साहब।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप चर्चा करवाते न स्थगन प्रस्ताव पर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके नेता नियमों के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आज राजस्थान में सबसे गम्भीर विषय शीतलहर और पाला है। यदि आप किसानों के सच्चे नुमाइन्दे हैं तो सदन में प्रस्ताव पास करवाकर केन्द्र सरकार को भेजा जाए, कृषि मंत्रीजी को भेजा जाए, मनमोहनसिंहजी को भेजा जाए, प्रस्ताव सर्वसम्मति से जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्र सरकार ने जितना पैसा दिया उसके लिए तो आप धन्यवाद प्रस्ताव पास करवाओ, इतनी भी इन्सानियत नहीं है कि हजारों करोड़ रुपये देने के बाद भी आप उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, समर्थन करें या नहीं करें पर केन्द्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा, मजबूरी है। मेरा नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि राज्य सरकार ने जो घोषणा की है उसके लिए केन्द्र सरकार को मजबूर होकर काश्तकारों के लिए सहायता करनी पड़ेगी, नहीं तो काश्तकार बर्बाद हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि काश्तकारों को सहायता दें, काश्तकारों की तरफ यदि ध्यान नहीं देंगे तो ज्यादा समय नहीं रहेंगे इस देश में। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ सीधे हैं लेकिन जलेबी की तरह सीधे हैं, आप उन पर आरोप मत लगाया करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। बेनीवाल साहब।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं शर्माजी को कह रहा हूं कि आप आमने-सामने होकर कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, यहां पर सभी सदस्य मेरे ख्याल से एक दूसरे को कह रहे हैं कि राजनीति करो तो यहां क्या आप लोग मेरे ख्याल से पूजा या भजन करने के लिए आए हैं, क्यों झूठ पाखण्ड कर रहे हैं। राजनेता होकर कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, नेतागिरी मत करो। सारे यहां राजनीति कर रहे हैं और जनता है बेवकूफ बनी जा रही है, उसको लूटे जाओ, खाए जाओ, अपनी-अपनी ढपली बजाए जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप। बेनीवाल साहब। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, आधा घण्टा खराब हो गया। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान में पूरे देश की 40 प्रतिशत से अधिक सरसो का उत्पादन होता है और 30 लाख हैक्टेयर के लगभग बीजान यहां पर हो चुका था। उसमें से अधिकांश खराबा हो गया। इसके साथ-साथ सब्जियां पूर्णत चौपट हो गई, बैंगन-टमाटर तो पूर्णतया नष्ट हो गए, आंवला जैसी फसल भी हमारे यहां पर नष्ट हो गई। इसका एक और मुख्य कारण था अत्यधिक ठण्ड का पड़ना और पाले का पड़ना, वहीं दूसरा मुख्य कारण इसका जो है उसके ऊपर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इससे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 3 को पढ़ना चाहता हूं। जिसमें उन्होंने कहा कि ''हमारी सरकार पारदर्शी, संवेदनशील व लोक कल्याणकारी प्रशासन के माध्यम से जन-जन का सपना पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।''

सभापति महोदय, अगर सिंचित क्षेत्र के अंदर नहरों में पूरा पानी चल रहा होता, किसान को पूरा पानी मिला होता, अगर ट्यूबवैल क्षेत्र के अंदर कृषि कुओं को पूरी बिजली मिली होती तो यह खराबे का प्रतिशत जो यहां निकलकर आया है इसका एक चौथाई नहीं होता। अगर यह स्थिति है, यह सत्यता है तो ये जो शब्द इसके अंदर लिखे गये हैं ये शब्द उचित प्रतीत नहीं होते ''पारदर्शी प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन''।

आज के दिन की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा। बीकानेर जिले के वजू क्षेत्र में 961 हैड के पास हजारों की संख्या में काश्तकार धरने पर बैठे हैं। आज उनका धरना चलते हुए कई दिन हो गये हैं, लेकिन संवेदनशील प्रशासन ने वहां पर जाकर उनसे वार्ता करने और उनकी समस्या का समाधान करने के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बारे में अपनी कोई सोच नहीं रखी है और उनकी मांग सिर्फ यही है कि हमें हमारे हक का पानी दो। आज एक तुगलकी आदेश जारी कर सिंचित क्षेत्र के अंदर सिंचाई का पानी बंद करके पेयजल के नाम पर केवल पेयजल आपूर्ति की जा रही है जबकि एक ओर हम खराबे से जूझ रहे हैं। हम सीआरएफ के नार्म्स को बदलने की बात कर रहे हैं, हम राहतों की बरसात करने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसानों की जो बची-खुची फसल है उस फसल को पानी नहीं देकर उसको इन्होंने लाइन में लाकर पीछे खड़ा करना चाह रहे हैं जहां रोते हुए किसानों की कतार लगी है और महज एक पानी की बारी आज के समय में उनके लिए और आवश्यक थी जिससे उनकी बची-खुची सरसों पक सकती थी, उनके जीने का कुछ सहारा हो सकता था, लेकिन यह संवेदनशील प्रशासन कह रहा है कि हम सबको एक समान बनाने की सोच रखते हैं, सबको बर्बाद करने की सोच रखते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इन हालात को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उन किसानों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अगर एक पानी कम से कम और उपलब्ध कराएं ताकि हजारों की संख्या में जो किसान वहां बैठे हैं, जो अपनी पिटी हुई बारियों की, अपने सिंचाई के पानी की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की बात कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान करें।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपदा प्रबंध की बहुत सी बातें बतायीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी गत समय में अभावग्रस्त गांवों की सूची पेश की गई। जिला बीकानेर के मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक तहसील विशेष के अंदर आपके माध्यम से यह सूचना दी गई कि सब जगह पर जो गांव 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के अंदर हैं उन सब गांवों के अंदर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो भूख से जूझ रहे हैं, जिनको आपने चिह्नित किया है, आपने स्वयं ने जाना है कि वो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, क्या वास्तव में आपने ईमानदारी से वहां पर कार्य शुरू कर दिया है? क्या वास्तविक रूप से हकीकत यही है? उसका कोई जवाब आज दिन तक आपकी जानकारी में लाये जाने के बावजूद भी नहीं आया है और न ही स्थिति में परिवर्तन आया है और यही स्थिति निकलकर आयी है कि वहां पर किसी भी प्रकार के अकाल राहत कार्य 6 गांवों में आज दिन तक प्रारम्भ नहीं हुए।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, आज बात आ रही है हमारे यहां राज्य के हालात की। राज्य के अंदर स्थिति बहुत अच्छी है, सभी क्षेत्रों के अंदर हम बहुत विकास कर रहे हैं। पिछले समय में सेना ने अनेक स्थान पर कुछ भूमि चिह्नित करके राज्य सरकार से यह जानना चाहा था कि इस भूमि को अवाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके चलते बीकानेर जिले के 56 गांवों की भूमि को भी उन्होंने चिह्नित किया था। उन्होंने उस प्रस्ताव को अंतिम रूप तो नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार ने बड़ी तत्परता दिखलाते हुए उन 56 गांवों में जिनको अवाप्त किये जाने का निर्णय नहीं हुआ, आज लगभग 7 महीने से ज्यादा समय हो रहा है वहां पर हर तरीके के विकास कार्य पर रोक लगा दी। एक ओर हम दुहाई देते हैं अभिभाषण के अंदर भी दिया गया है कि हमने वाटरशैड का इतने करोड़ रुपये का कार्य किया। उन गांवों में भी अनेक गांवों के अंदर वाटरशैड स्वीकृत किये गये और उनके तहत कार्य प्रारम्भ किये गये। पौधारोपण का कार्य भी वहां पर हुआ। निर्माण के कार्य के लिए तो हम यह कह सकते हैं कि उनकी सार-संभाल अगर दो महीने, छह महीने, दो साल नहीं हो तो हो सकता है उसका कुछ नहीं बिगड़े, लेकिन क्या एक पौधा एक दिन की सार-संभाल के बिना जी सकता है? विकास कार्यों पर लगी रोक के कारण उन 56 गांवों के अंदर लगे हुए लाखों पौधे नष्ट होने की कगार पर आ गये हैं। आज दिन तक बार-बार इस संवेदनशील प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया और जो विकास कार्यों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया उसके ऊपर आज तक भी उस आदेश को वापस लेने की बात नहीं की गई। यह द्योतक है हमारे वर्तमान प्रशासन का।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर अस्पतालों की जो स्थिति है, डाक्टरों को छूट मिली हुई है कि वो चाहे क्वालिफाइड न हों फिर भी हैड आफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं एक सिम्पल डिप्लोमा करके वे वहां पर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती और उनको खुली छूट मिली हुई है। अस्पतालों में मनमाने तरीके से बने-बनाये भवनों को तोड़ा जा रहा है, केवल अपने शिलालेख लगाने के लिए नये भवन बने, नये शिलालेख लगे। मनचाहे तरीके से कहीं पर भी द्वार निकाल दिये जाते हैं दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण देने के लिए। इलाज के नाम पर आज बात की जाए डाक्टर उपलब्ध नहीं है, पोस्टिंग जहां है वहां डेपुटेशन हो गया है। विधान

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभा का सत्र चले, मुद्दा उठने लगे तो उनके डेपुटेशन निरस्त कर दिये जाते हैं। इसी क्रम में अभी पिछले दिनों में क्योंकि विधान सभा सत्र चलना तय था, दिनांक 5.2.2008 को निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा एक आदेश जारी करके सभी डेपुटेशन निरस्त कर दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं ये डेपुटेशन क्यों किये जाते हैं? जिस जगह पर उनकी ड्यूटी लगी है उस जगह पर सेवाएं देना उनकी जिम्मेदारी है। आप उनका स्थानान्तरण दूसरी जगह पर कर दीजिए। लोगों को भ्रमित करके कागजों में ही आंकड़े पेश करना कि हमने इतने लोगों की नियुक्ति कर दी है इससे कुछ कार्य बनने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में जो किसानों को बहुत बड़ी राहत देने के नाम पर वहां पर खोला गया था, नई रिसर्च करने के नाम पर खोला गया था उस कृषि विश्वविद्यालय में लम्बे समय से अनेक पद रिक्त हैं, रिसर्च के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनकी तरफ कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान देने के लिए भी वर्तमान सरकार कुछ देखेगी। सिंचाई के पानी को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए इस बात पर कुछ ध्यान दिया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभी इसी अभिभाषण में बहुत सी बातें दी गईं। आईटीआई के जो कालेजेज चल रहे हैं जगह-जगह पर, बीकानेर के आईटीआई में और कोटा व 3-4 जगह, उन आईटीआई में एक नया प्रयोग शुरू किया गया सेंटर आफ एक्सीलेंस के नाम से। जिसके चलते एक साल के अंदर चार ट्रेड के अंदर स्टूडेंट्स को घुमाया जाता है, तीन-तीन महीने का उसमें कोर्स करके अपनी डिग्री लेकर, अपना डिप्लोमा लेकर किसी भी संस्थान में नौकरी प्राप्त कर सके यह उसका उद्देश्य है। लेकिन महज एडमिशन देने के नाम पर, महज सेंटर आफ एक्सीलेंस खोलने के नाम पर कुछ कार्य होने वाला नहीं है। यह पिछले समय में उनका रिजल्ट उसकी बानगी है, 250 में से महज दो छात्रों का पास होना इस बात का सूचक है कि यह आप बिना व्यवस्था के प्रवेश देकर, बिना अध्यापकों की नियुक्ति के प्रवेश देकर जो व्यवस्था बनाने वाले हैं, इससे हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट ही हो सकता है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। इस सैमेस्टर में महज दो छात्रों का पास होना इस बात का सूचक है कि यह जो आप बिना व्यवस्था के यह प्रवेश देकर के, बिना अध्यापकों की नियुक्ति करके प्रवेश देकर के जो व्यवस्था बनाने वाले हैं इससे हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट ही हो सकता है।

श्री सभापतिः थोड़ा सा कन्क्लूड करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जी, बिलकुल। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने वापस मेरा शार्ट करने के लिए फरमाया। इसके साथ-साथ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, शहरों में बहुत से कार्य अभी हुए, विकास की हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, यह हम बार-बार देख और सुन रहे हैं। आरयूआईडीपी के तहत राज्य के बड़े शहरों में कुछ निर्माण कार्य हुए और अभी भी हो रहे हैं। बीकानेर में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ हुए, बहुत लम्बा समय हो गया, शोभासर गांव में एक बहुत बड़ा स्टोरेज, टैंक का निर्माण किया गया, जलाशय का निर्माण किया गया, उस जलाशय में पानी डालते ही दरार आ गई और एक ओर हमने बहुत बड़ी राशि खर्च करके एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ति करने के लिए कि हम बीकानेर शहर को कभी भी पेयजल संकट नहीं आने देंगे, जिस कार्य की शुरूआत की उस कार्य पर आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। ठोस कचरे के निष्पादन के लिए करोड़ों रुपये की लागत से एक कचरा निष्पादन केन्द्र की स्थापना की गई, उसके भवन में दरारें आ गई, समझ में नहीं आता कि उस कार्य को करने वाली एजेंसी के ऊपर आज दिन तक कार्यवाही न करते हुए उसको काफी कुछ राशि का भी भुगतान कर दिया गया।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, आज बात आती है, हमारे परिवहन विभाग के माननीय मंत्री महोदय बहुत जागरूकता के साथ में कार्य कर रहे हैं और उन कार्यों का नमूना हमारा संभाग मुख्यालय बीकानेर है जहां पर आपकी एकमात्र एक्सप्रेस बस चलती है, जिन बस का किराया प्राइवेट चलने वाली बस से ज्यादा है, जिस बस को बीकानेर से जयपुर आने में घंटे ज्यादा लगते हैं, अगर प्राइवेट बस 6 घंटे में आती है तो आपकी बस साढ़े 7 घंटे में आती है। यह सारी व्यवस्था इस बात की सूचक है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड वह एरिया दे रखा है, आसपास के कस्बों तक जाने वाली बसों का किराया आपका अधिकांश जगहों पर बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पर आपका बेशक किराया काम्पीटिटिव है। रोडवेज बस स्टैंड की आपने व्यवस्था नहीं की, लूणकरणसर जैसा बड़ा कस्बा आज तक आपका लम्बे समय से मुंह देख रहा है कि शायद कुछ करेंगे लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आप वोल्वो बसें चला रहे हैं, कहीं पुष्कर को जोड़ रहे हैं, कहीं जैसलमेर को जोड़ रहे हैं, कहीं अपने क्षेत्र को जोड़ रहे हैं लेकिन उस सम्भागीय मुख्यालय को आप पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। हम तो बहुत कुछ तरक्की कर रहे हैं, अभी आपने अपने बेड़े में बहुत सी बसों को शामिल किया तो क्या कारण है कि आप इतने लम्बे समय से उस क्षेत्र को नजरअंदाज किए हुए हैं, यह मेरी समझ से बाहर है।

श्री सभापति: माननीय, अब आप विराजें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यह अंतिम दो वाक्य हैं। एक, सभापति महोदय, हालांकि समय तो मेरा पूरा माननीय मंत्री महोदय ने ले लिया था, एक इसके साथ-साथ, मैं यह और कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि अभी हमारा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में राशि की कोई कमी नहीं है, यह बार-बार बताया जाता है, लम्बे समय से हमारे यहां एक मांग चल रही है कि डूंगरगढ़ को लूणकरणसर से अगर जोड़ दिया जाए, ब्राड रोड से, तो शायद 80 किलोमीटर का सफर गंगानगर जाने वालों का कम हो

(समय : 16.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जाएगा लेकिन वह बात भी आज दिन तक हवा में है। हालांकि अभिभाषण में तो हमने बहुत कुछ कहा है कि हमने इतने हजार किलोमीटर सड़कें बना दी, हमने इतना कुछ किया और इतना कुछ किया लेकिन उपयोग जहां हम प्राथमिकता से अगर देख रहे हैं तो वहां शायद कुछ स्थानों पर पा रहे हैं, प्राथमिकताओं का चयन कुछ और आधार पर किया जा रहा है।

एक महत्वपूर्ण बात मैं, सभापति महोदय, आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा। अभी पिछले समय में अखबारों की सुर्खियां बना रहा कि बार्डर बिक रहा है और रजिस्ट्रियां जो हुई उन रजिस्ट्रियों के ऊपर जांच शुरू हो गई कि किन व्यक्तियों ने जमीनें खरीदी, वह कैसे आए और कैसे रजिस्ट्रियां कराने के लिए वहां तक पहुंचे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये जाने चाहिए, यह बात भी प्रकाश में आई लेकिन यह बात कहीं भी प्रकाश में नहीं आई कि राज्य सरकार ने 15.7.2007 को जो एक अपना ही परिपत्र जारी किया गृह विभाग द्वारा जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि कुछ ऐसे जिले जिन जिलों को चिन्हित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण और जहां पर हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता उसमें छूट देने के लिए मांग की गई थी, आज उस छूट देने की मांग पर जो अंतिम निर्णय लिया जाना था, वह निर्णय आज दिन तक लंबित है और ऐसे लोगों को इसमें उलझाया जा रहा है जिन लोगों द्वारा भूमि की खरीद करने के लिए आज अगर विशेष आबंटन करने की बात करें, जब आप वहां पर आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे जिले के लोगों से, तो वहां पर अगर कोई आवेदन करने के लिए जा रहा है तो वह भी ट्रेस पासर की श्रेणी में आ गया। आज अगर वहां से कोई बस निकल रही है, उस बस में यात्री बैठे हैं, वह भी ट्रेस पासर की श्रेणी में आ गए, उस क्षेत्र विशेष से अगर कोई जिले का उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहा है, वह भी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ट्रेस पासर की श्रेणी में आ गया तो हम उस श्रेणी जो हमने ट्रेस पासर की मानी और जानी है, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरा निवेदन यह है कि जिन व्यक्तियों ने वहां पर भूमि खरीदी है, अगर उनकी पात्रता सही है तो उस पात्रता को देखते हुए यह जो उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, उस कार्यवाही पर तो रोक लगे और गृह विभाग द्वारा जो जारी किया गया एक पत्र है, उस पत्र की अनुपालना में इस क्षेत्र को जिनको कि हम इससे मुक्त करना चाह रहे हैं जिसमें जोधपुर बीकानेर संभाग के बहुत से, यह कह लीजिए कि उस सम्भाग के सारे ही नागरिकों को प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर निकाल कर वहां उनको आने-जाने की छूट मिले क्योंकि उनकी वहां पर परिवारजनों की भूमि भी है, ऐसा मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ कार्य किया जाएगा जिससे कि बहुत से लोग बिना मतलब के एक समस्या का शिकार हो गये हैं और पुलिस उनको परेशान करने का जो प्रयास कर रही है उसके ऊपर भी रोक लगेगी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मतलब बार्डर को बिकने दें?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जी? मैं सुन नहीं पाया, साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मतलब बार्डर को बिकने दें?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपने शायद मेरा निवेदन सुना नहीं कि जो व्यक्ति पात्र है, वह पात्र व्यक्ति जो ....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा कि वहां जो रोक लगी है उस पर प्रतिबंध हटाया जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यह आपका परिपत्र है, मैंने नहीं बनाया है, इस परिपत्र को आप चाहें तो मैं टेबल कर सकता हूं जिसके अन्दर आपने उसमें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो ठीक है लेकिन आपने कहा कि वह जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले सिर्फ शुरू में चुनाव लड़ने वाला बार्डर पर कैसे जाएगा? अगर वह ...(व्यवधान) आपको पता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप तो बलाय मेहरबानी उन बसों का चलना बंद कर दीजिए। कोटा से अनूपगढ़ बस वाया खाजूवाला जाती है, आप सवारियों को उतार दीजिए, जाने मत दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बार्डर की बात आपके समझ में थोड़े ही आएगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आप वहां पर मोहरबंद आवेदन करने के लिए किसानों को बुला रहे हैं, आप उस पर रोक लगा दीजिए। आप धर्मेन्द्रजी को चुनाव लड़ाने के लिए वहां ले आए उस पर रोक लगा दीजिए।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए मैं बात को ज्यादा लम्बा न करते हुए सार में यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में किसान के हालात बहुत खराब हैं, वर्तमान समय में सिंचाई के पानी की समस्या इस फसल को बचाने के लिए प्रमुख कारण है जिसके ऊपर प्राथमिकता से कोई निर्णय लिया जाना चाहिए, ट्यूबवैल के क्षेत्र के अन्दर प्राथमिकता से विद्युत की आपूर्ति पूरी कराई जानी चाहिए और किसानों को सही गिरदावरी करके उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उनको मुआवजा मिले, शब्दों के जाल में बात को उलझाया न जाए, सीआरएफ किसान नहीं जानता, किसान अगर इतना ही कुछ जानता होता तो आज वह खुद ही अपने नियम कायदे बना लेता, किसान आपदा प्रबंधन कोष नहीं जानता, किसान यह जानता है कि वह आज जो बदहाली के कगार पर जो पहुंचा है, एक हैक्टेयर में बिजान के लिए सरसों की उसका जो दो हजार, तीन हजार रुपये से ज्यादा मूल में चला गया, उत्पादन तो बहुत दूर की बात है, वह आशा करता है कि अगली बार वह बिजान के लायक रहे, कम से कम सरकार उसके आंसू पोंछे, इस दुःख और तकलीफ के अन्दर सही गिरदावरी होकर के उनको राहत मिले, हमारे यहां पर खराबे के क्या कारण रहे हैं, इन कारणों पर ध्यान दिया जाए, संवेदनशील प्रशासन सही शब्दों में संवेदनशील प्रशासन बने, आज हजारों की संख्या में किसान जो धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग पर ध्यान दिया जाए, ऐसे कई आदेश जो आदेश होने बताये हैं उन आदेशों को जारी किया जाए, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की बात जो की गई है तो वह वास्तविक रूप से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किए जाएं, इलाका जो चिन्हित करके विकास कार्य पर रोक लगा दी गई है, उस रोक को हटाया जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय हमारे यहां का पुनः ऐसा अच्छा समय बने कि जैसी खरीफ की गिरदावरी आज हमारे कागजों में दर्ज है कि एक-एक इलाके के अन्दर बीकानेर में अकेले में हम 11-11 लाख हैक्टेयर का जब यहां पर उत्पादन बता रहे हैं। वास्तव में आपके कागजी आंकड़े सही साबित हों, ऐसा समय बने, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, कल से उपाध्यक्ष महोदय को बराबर लिखित में दे रहा हूं कि हमारा भी समय है तो हमें भी पुकार लिया करो समय रहते हुए। (व्यवधान) बी. जे. पी. वाला तो हूं पर मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं। हमारा भी समय है निर्दलियों का, यह ध्यान है क्या आपको? खैरात नहीं मांग रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): निर्दलीय हो या बी. जे. पी. के हो?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यहां निर्दलीय हूं और बोल रहा हूं तथा निर्दलीय की हैसियत से बोलूंगा। (व्यवधान) अच्छा काम कर रही है बी जे पी इसलिए समर्थन करता हूं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का जो मौका दिया है, इतने दु:खी मत होइये कासनियाजी, मेरे बाद में बोल लीजिये।

सभापति महोदय, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, अच्छे शासन का पूरक जो नाम होता है वह राम राज्य होता है। राम राज्य वही होता है जहां अच्छा शासन होता है और मुझे यह कहते हुए बड़ी ग्लानि पैदा होती है मन में कि जिस राम राज्य को अच्छे शासन की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी है उस राम के नाम को केन्द्र की सरकार ने किस तरीके से मजाक का नाम बना दिया है। अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात को मजाक में ले रहे थे, यह बड़ा मजाक का कहा। (व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं, वही कहूंगा, सुनोगे तो कान बहरे हो जाएंगे। राजस्थान पर भी आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले 4 वर्षों से एक अच्छा शासन यशस्वी मुख्य मंत्री ने देने की कोशिश की है और दिया है। एक छोटी सी, जो अभी बात निकली थी, प्रतिपक्ष के नेता ने खजाने वाली बात याद दिला दी थी। अच्छे शासन का पूरक, बाहर से अच्छे-अच्छे लोग, अच्छे-अच्छे निवेशक जब ही आयेंगे जब आप अपने घर की गुडविल, एक अच्छा प्रारूप रखें। पिछली सरकार ने तो भीख का कटोरा लेकर घूमने के अलावा, हमारा खजाना खाली है, खजाना खाली है, इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी मुख्य मंत्री को कि इन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं कहा कि इस योजना के लिए पैसे नहीं है। एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ और उसी का कारण यह हुआ कि निवेशकों ने देखा कि राजस्थान की सरकार का एक भी दिन ओवर ड्राफ्ट नहीं

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

है, कहीं डूबत खाते में नहीं है, सरकार हमें पूरी सहायता देगी और वो आये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हेमारामजी इस बात को आप अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दो दिन की घटना, मैं प्रतिपक्ष के नेता के मन का दु:ख जानता हूं, वे किसान परिवार के, साधारण परिवार के बेटे हैं क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं, उनके दु:ख-दर्द को जानता हूं। जिस तरह से उनकी पार्टी के तानाशाह नेताओं ने उनको इतना भावुक कर दिया कि पहली बार कहीं पर कोई नेता इतना भावुक होकर इतना रोया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप थोड़ा सा ध्यान से बोलें। आप अपने कारनामे दूसरे के कंधों पर क्यों डालते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं तो वो बात वापस आ जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर कुछ कहना पड़ेगा। गड़े मुर्दे आप क्यों उखाड़ते हो? राजेन्द्रजी, आप इनको समझाओ। अब गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर मैं वापस कुछ बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, आप आगे बढ़ें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर वही मुख्य मंत्रीजी वाली बात आ जाएगी कि उन्होंने कैसा व्यवहार किया। वो बात आ जाएगी इसलिए बोलो मत।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए यह बात अब नहीं। ये कह रहे हैं मेरी तकलीफ की बात तो इनको पता नहीं, बता दूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्रीजी ने तो आपको दुलार किया, प्यार किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका पता नहीं चलता कि कब मुख्य मंत्रीजी की तारीफ और कब आलोचना। आप एक रोल तो करो, डबल रोल मत करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो बात है वह सब कहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी ने मुझे तो प्यार से बुलाया पर आपको कभी प्यार से नहीं बुलातीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो पास ही रहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वो मुझे प्यार से बुलाये और आपको नहीं बुलातीं तब आपने यह महसूस किया होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आप ही बतायें कि आपका एन डी पी सी वाले में नाम है या नहीं है। एन डी पी सी का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें आपका नाम है या नहीं है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्री और मुख्य सचेतक का क्या सम्बन्ध है यह पता है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे याद है एन डी पी सी एक्ट पर फंसने के लिए आपको अब यही बोलना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री और मुख्य सचेतक के बीच में किस प्रकार का सम्बन्ध रहता है उसमें संवैधानिक क्या व्यवस्था है, वह पता है क्या आपको?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको अगर चुनौती देनी थी तो आप प्रहलाद गुंजल की तरह चुनौती दो। उसने कहा है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मुख्य मंत्री के सामने ही लड़ूंगा। आप तो मैदान छोड़कर भाग गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न तो हमने मुख्य मंत्री का या किसी का विरोध किया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका हमने टी.वी. पर इंटरव्यू सुना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या सुना है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोलूं या नहीं? मुख्य मंत्रीजी के प्रति आपने जो टी.वी. में इंटरव्यू दिया न वो हमने सुना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने यह कहा है कि हमारे घर की बात है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब ठीक है, अब चुनाव आ गये, अब आप शरणम् गच्छामि हो गये। सब मामला नक्की हो गया, अब आप क्यों वापस ला रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम तो पार्टी और मुख्य मंत्री सब के प्रति शरणम् गच्छामि हैं पर आपकी तरह नहीं हैं कि नेताओं को ही खा जाएं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर जसौल में क्यों पधारे आप? आप जसौल में किस वास्ते पधारे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ....अध्यक्ष को खा गये। और तो और हमारे वरिष्ठ नेता शिवचरणजी माथुर को भर्ती होना पड़ा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या होना पड़ा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूर्व मुख्य मंत्री और आपके सबसे वरिष्ठ नेता शिवचरणजी माथुर को हास्पिटलाइज होना पड़ा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसलिए?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इतना डांट-डपट करके आपने जो व्यवहार किया यह शर्मनाक नहीं है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, आपके अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने, आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप किस कारण से चुप हुए? डांट-डपट से हुए या एन डी पी सी के मुकदमे की वजह से चुप हुए?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): .... वो मिसाल हैं, ऐसा प्यार और आदर मुझे कोई दे ही नहीं सकता, मैं उनको पिता तुल्य समझता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसको? सी.पी. जोशीजी को?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): शिवचरणजी माथुर को पिता तुल्य समझता हूं। सी.पी. जोशी तो मेरे भाई हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सी.पी. जोशी आपके अध्यक्ष हैं या नहीं हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वो मेरे भाई हैं और वो मेरे पिता तुल्य हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने आपके सामने कहा था या नहीं? (व्यवधान)

श्री सभापति: मुख्य सचेतकजी, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके सामने कहा था या नहीं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अभिभाषण पर बहस कराओगे या आपकी और मेरी.....

श्री सभापति: मुख्य सचेतकजी, आप विराज जाएं। आप विराज जाएं तो मेरे ख्याल से आदरणीय सदस्य अपनी बात कह दें। मेरे ख्याल से हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस कर रहे हैं, ऐसे भाषण बीच में आ गये जिसका कोई मतलब नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये स्वयं साक्षी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष नहीं सभापति महोदय। सभापति महोदय हैं, उपाध्यक्ष नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोलो, कहा था या नहीं कहा?

श्री सभापति: मेरे ख्याल से अगर हम सब संयम रखें तो माननीय सदस्य अपनी बात कह पायें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए कहा था, अगर तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा याचना करता हूं।

श्री सभापति: शायद आप भी अपना वक्तव्य अभिभाषण तक सीमित रखें नहीं तो कई संवेदना और संवेदनशील वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए कह रहा हूं, अभिभाषण में, सत्ता में, सरकार में कहीं न कहीं मानवीयता झलकती है और मानवीयता के नाते अगर कोई नेता यहां दु:खी होता है तो हमारा उसके दु:ख-दर्द में सहयोग होना चाहिए इसलिए मैंने कहा। माननीय सभापति महोदय, अच्छे वित्तीय प्रबन्धन के कारण जो सरकार की इमेज चारों तरफ बढ़ी है, यही तक नहीं, निवेशक मतलब जो एन आर आइज हैं, प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने लगभग एक लाख बासठ हजार करोड़ रुपये के निवेश का एम ओ यू जो हुआ है, यह हकीकत है। अशोकजी गहलोत की सरकार में एक बार ऐसा का ऐसा प्रवासी भारतीयों के साथ में कार्यक्रम हुआ था पर उसमें खाली चांदी की चम्मच और थालियां गिनने का काम इनके नेताओं ने किया। एक भी रुपये का निवेश उसमें नहीं हुआ और उल्टा यह हुआ कि इन्होंने तो कहा कि कमाकर खाओ और उन्होंने सुना टमाटर खाओ। यह दुर्भाग्य है, यह राजस्थान का दुर्भाग्य हुआ है। माननीय सभापति महोदय, एक अच्छे शासन में सुरक्षा, रक्षा और सभी वर्गों को न्याय मिले इसलिए छोटे से में ही कह देता हूं कि पुलिस प्रशासन में, आज हम गृह विभाग में हिन्दुस्तान के अच्छे राज्यों की श्रेणी में आ गये। यह हमारा एक अचीवमेंट है और पहली बार......

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कितने लोगों को गोली से मारा है वह भी बता दें। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): और पहली बार, वह आपने मरवाया है और आपके पास कामरेड के लोगों ने मिलकर मरवाया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। अभी सभापति महोदय, एक मानवीय दृष्टिकोण से सभी राज्यों में जैसे काम हो रहा है। अभी बात चली कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र का पैसा, अब यह पैसा, यह पैसा कोई इटली से नहीं आया है और अगर इटली से आया है तो आपका हक है और आप कुछ भी कह सकते हो। केन्द्र के पैसों पर राजस्थान का हक है। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि सोनियाजी विदेशी हैं। मैं यह कभी नहीं कहूंगा...(व्यवधान) लेकिन एक बात सभापति महोदय जरूर कहूंगा, सुरक्षा का मामला इस देश में खतरा जो बना हुआ है। सोनियाजी का नाम आया, एक बात याद आ गई। पिछले वर्ष...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): on a point of order, सभापति महोदय, जो सदन का माननीय सदस्य नहीं है, उनके बारे में यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं नहीं कहूंगा, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा। मैंने यह कहा है कि हम नहीं कहेंगे कि सोनियाजी विदेशी हैं। यह मैंने कहा है कि...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह क्या तरीका है, वह हमारे देश की बहू हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं नहीं कहूंगा। मैंने मना किया है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह किसी बहस का स्तर है क्या? यह अभी अपनी वसुन्धरा है। यह चीफ व्हिप भी कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह आपकी बात ही गलत है। आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं? आप अपने घर की बहू को भी ऐसे कहते हो। यह आपका घटिया स्तर है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये चीफ व्हिप कह रहे हैं उस पर आओ ना।

श्री सभापति: आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपने अभी कहा है कि बताओ बताओ। इनको ध्यान में ही कुछ नहीं है। आपने क्या किया है, इनको तो पता ही नहीं है। क्या कुछ किया है। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और एक अच्छी सरकार के लिए एक राज्य के अन्दर भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि पिछले वर्ष इटली से जो इस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, के एक मेहमान आये, वह इटली से...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, on a point of order. हमारे देश की संसद में ऋग्वेद की एक ऋचा लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है "अयम् निजबरोबेति गणनाम् लघुचेष्टाम् उदाराम् चरितानाम् वसुधैव कुटुम्ब भव" हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि यह तेरा है, यह मेरा है, यह भारतीय संस्कृति नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति विशाल है, जिसमें सारा संसार एक कुटुम्ब की तरह है और यहां पर ये देशी और विदेशी करते हैं। वे राज़ीव गांधी की पत्नी हैं और इस देश की बहू हैं। उनके बारे में यह बात कहना, यह भारत का सम्मान घटाना है इसलिए यह लघु सोच छोड़कर अपने विषय पर आइये, ये विषयान्तर हो रहे हैं इसलिए आप इनको टोको कि ये अपने विषय पर बोलें। राज्यपाल के अभिभाषण में कहां इटली, कहां देशी और विदेशी, इस तरह की बातें करके गलत बात कर रहे हैं। सोनिया गांधीजी इस देश की बहू हैं और इस देश की नागरिक हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात कहने जा रहा था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिये। मैं सिर्फ आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि समय सीमित है और आपको अगले पांच मिनट में अपनी बात को कन्क्लूड करना है, इसलिए आप विषय पर अगर बोलें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, मुझे जो समय दिया है, उससे पहले कर दूंगा कन्क्लूड। मैं यह जो कहने जा रहा था कि ये बार-बार कह रहे थे कि केन्द्र का पैसा है। यह कोई कहीं से पैसा आया हुआ नहीं है, राज्य के हक का पैसा है और राज्य के हक का पैसा मिला है और अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आब्जेक्शन किया कि किस प्रकार से नरेगा में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी केस हुए हैं। उन्होंने झालावाड़ का उदाहरण दिया। मैं यह कहने जा रहा हूं, मेरा निवेदन है

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोतजी की सरकार में अकाल राहत के काम में अगर राजस्थान में कहीं घपला हुआ था, जिसमें 11 केस अगर उसमें नोट हुए हैं तो वह सिरोही में हुए हैं और उस समय के सिरोही के वर्तमान एम.एल.ए. उसमें सहयोगी थे। उनको बचाने के लिए उनके सहयोगी थे और अगर उसके बाद में सात केस अकाल राहत में हुए हैं तो वह बीकानेर में हुए। बीकानेर में अकाल राहत के गेहूं का घपला हुआ, बीकानेर में सात केस दायर हुए थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, बीकानेर में हुआ है या कहीं हुआ है, आप उन अपराधियों को दण्डित क्यों नहीं करते? आप कौनसी सरकार के प्रतिनिधि हैं या मेम्बर हैं, जिन्होंने कबाड़ा किया, उनको जेल में फैंको। आप क्या बात करते हो?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): हमने दण्ड दिया है। माननीय सभापति महोदय, जालौर जिले में नरेगा के मामले में सर्वोच्च स्थान लिया है। एक अच्छे काम का प्रारूप और पूरे देश में नरेगा के काम में राजस्थान सर्वोच्च स्थान पर है और यह मुख्य मंत्रीजी की कार्य व्यवस्था और उनकी व्यवस्था पर, उनके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि आज राजस्थान अच्छे स्थान पर है। पैसा देना ही बात नहीं है। अटलजी की सरकार ने आपको खूब अन्न दिया था, अन्न के भण्डार खोले थे, पैसा भी दिया, लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाये थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो अटलजी की सरकार ने दिया, वह और हमारी सरकार ने आपको दिया, उसका कम्पेरिजन यहां व्हाइट पेपर में पेश कर दो तो पता लग जायेगा कि क्या स्थिति है? हां-हां, पता लग जायेगा, आप रखो ना यहां। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): पिछले पांच साल के समय में...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान में 50 लोग जो थे, 50 लोग पुलिस की फायरिंग में मरे, उस पर तो बोलो। भूख से मरे हैं आपके यहां भी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके राज में भूख से मरे हैं लोग लेकिन आप लोग व्यवस्था नहीं कर सके इसलिए भूखे मर गये। हमने कहा कि अनाज ले जाओ मर्जी आये जितना, लेकिन उठा नहीं सके। शर्म की बात है और उनको मरवा दिया, आपकी कांग्रेस पार्टी का हाथ था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस पार्टी का हाथ था उनको मरवाने में। उनको उकसा-उकसा कर आपने बिना बात के मरवाया, आप लोगों ने मरवाया है, आप दोषी हैं। कांग्रेस पार्टी के माथे पर उनकी हत्या का कलंक है। इसमें गलत तरीके से उकसा-उकसा कर उनको मरवाया है आप लोगों ने, आप लोग दोषी हैं। (व्यवधान) यह आपका किया हुआ अपराध है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...जाति वालों का तो कार्ड बना नहीं, न मेडिकल रिलीफ कार्ड बना, न दूसरा कार्ड बना डेढ़ साल में। हर साल 12,500 लोगों के मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाने थे। आप वैसे ही भाषण दे रहे हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका भी कार्ड बनवा दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो पंचायती राज में उलझे हुए हो। एक तो कार्ड आपसे बना नहीं है डेढ़ साल में, आदमी बेमौत मर रहे हैं और उनका सारा इलजाम आप पर लगा है, आपने मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनाये हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सारे कार्ड बने हुए हैं और ज्यादा कार्ड बनाये हैं, पांच लाख लोगों के बनाये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक भी आदमी का नहीं बनाया है, एक आदमी को आपने गेहूं नहीं दिया। 17 लाख आदमियों में से एक आदमी को गेहूं नहीं दिया आपने। पुराने वालों में आपने एक को भी गेहूं नहीं दिया और बात कर रहे हो आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केन्द्र सरकार उस समय की थी, नहीं दिया, हमने तो वापस दिया है उनको। नाम कर रहे हो केन्द्र की सरकार का।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं कह रहा हूं कि बी.पी.एल. परिवार वालों का शोषण कर रहे हो आप। उनको भूखा मरने के लिए मजबूर कर रहे हो आप। उनके लिए गेहूं नहीं दे रहे हो और आप ऐसे ही बात कर रहे हो। आपकी वफादारी बार-बार उठने से नहीं होगी, काम करने से होगी। मत सत्यानाश करो राजस्थान का।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम आपकी तरह नहीं हैं। आपकी भी इससे नहीं होगी, ज्यादा ऊल-जलूल बोलने से नहीं होगी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, पूरे देश के गेहूं को यू.पी.ए. की सरकार खा गई है। अटलजी ने इतना गेहूं भेजा, अब की बार तो इनकी केन्द्र ने सारा गेहूं किसानों का लूट लिया, सस्ते दाम पर लूट लिया, आठ रुपये किलो में खरीदकर, बढ़िया गेहूं तो इन्होंने लूट लिया और खराब कचरा गेहूं लाकर खिला रहे हैं। सारी यू.पी.ए. सरकार किसानों की दुश्मन है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, किसान के दुश्मन आप हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसान का समर्थन मूल्य किसने किया है, गेहूं का समर्थन मूल्य किसने किया, आपको याद नहीं है। 1,000 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने किया है। यह पहली बार इतना पैसा मिला है किसानों को।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): यह किसान के नाम पर वोट लेकर इन्होंने 40 साल तक राज किया। आप लोगों ने किसानों को लूटा है, किसानों का गेहूं लेकर खा गये हैं आप, किसानों का बढ़िया गेहूं खरीदकर सारे देश का गेहूं खा गये...(व्यवधान) तुम्हारा तो राम ही निकल गया, अब तुम्हारा बचा क्या है, कुछ ही नहीं बचा है तुम्हारा तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमने तो गेहूं खाये हैं, तुम तो करोड़ों रुपये ही डकार रहे हो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): वोटों की खातिर तुमने तो राम को ही भुला दिया। शर्म आनी चाहिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, एक अच्छे राज्य के विकास के लिए सड़क, पानी और बिजली, ये तीनों चीजें अच्छे रूप में होंगी तो बाहर के लोग उस राज्य की ओर देखेंगे। सड़क के मामले में आज हमारा राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में सर्वोच्च स्थान पर है। पी.एम.जी.एस.वाई. में हम पहले स्थान पर हैं। पूर्व सरकार द्वारा चार किलोमीटर पर डे सड़क ली जाती थी और हमने 18 किलोमीटर पर डे सड़क लेकर छह गांवों को जोड़ा है और उसके साथ एक बड़ी परियोजना, मेगा हाइवे, पश्चिमी भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाली योजना, 460 करोड़ रुपये की योजना है, यह अपने आप में एक इतिहास इन्होंने बनाया है। सभी देवस्थानों को जोड़ने की योजना है, यह अपने आप में एक इतिहास बनाया है।

पानी की योजना ले लीजिये। माननीय सभापति महोदय, मेरे जालौर जिले में, जालौर और बाड़मेर जिला पिछले 20-25 वर्षों से फ्लोराइड वाला पानी पी रहा था। 600 करोड़ रुपये गुजरात सरकार को राजस्थान सरकार की

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

ओर से देने थे 15 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई। उस पैसे को वसुन्धराजी ने आते ही पहले पेमेंट किया कि मेरे जालौर और बाड़मेर की जनता अच्छा पानी पिये और स्वस्थ बने, इसके लिए 600 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया और आज नर्बदा की पेयजल योजना पूरी क्रियान्वित हो गई है, पाइप लाइन फीटिंग होने की तैयारी हो गई है। इसीलिए पूरे राजस्थान के अंदर पेयजल की स्कीम, अशोक गहलोतजी की सरकार ने खाली पत्थर और शिलालेख लगाने का काम किया था, उस योजना के लिए फण्ड अगर एडजस्टमेंट किया है तो वसुन्धराजी की सरकार ने किया है इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आंकड़ों में नहीं जाकर, जो नौकरी वाला विषय होता है, स्कूलों के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती, यह कहेंगे कि केन्द्र का पैसा है, इन्होंने तो सी.पी. साहब अध्यापक और कल्ला अध्यापकजी, राजीव गांधी टीचर, पैरा टीचर, इन्होंने अपने-अपने नाम से टीचर बना दिये थे। एक टीचरों का झमेला खड़ा कर दिया था, हमारी सरकार ने आते ही इन टीचरों को, सब को परमानेंट करके 82 हजार अध्यापकों की भर्ती की है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह एनडीपीएस एक्ट में शायद आपका नाम है इसलिए आप बचने के लिए व्यर्थ की तारीफ मत करो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): वह तो ताकत थी, हम तो जहर भी पियें, आप जहर पिलाना जानते हो क्या। नाम शंकर है, जहर पियेंगे हम तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जहर पियेंगे?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): बिलकुल पियेंगे जहर। माननीय सभापति महोदय, एक अच्छे शासन के लिए सड़क, पानी, बिजली, आज बिजली के अंदर मैं खाली इतना कहूंगा कि जो एफआरपी का काम एक बहुत बड़े लेवल पर, कृषि कनेक्शनों में भी लाख-लाख कृषि कनेक्शनों को देने के बाद एफआरपी के माध्यम से घरेलू लाइट भी बराबर आये और छीजत में कमी हो इसकी प्रेरणा को लेकर एक काम प्रारम्भ किया गया। मैं, सभापति महोदय, आपके-सामने आज इस सदन में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एफआरपी का काम राज्य में सबसे पहले मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में हण्ड्रेड परसेंट गांवों में पूरा करके आज बीस प्रतिशत छीजत की कमी की और मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में, हण्ड्रेड परसेंट गांवों में चौबीस घंटे उनको घरेलू

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लाइट सप्लाई होती है, यह राजस्थान में पहली हमारी कांस्टीट्वेंसी है। यह काम हुआ है। यह काम बोलते हैं। और सड़कों के मामले में, हमने जो सड़कों के नवीनीकरण का काम है, इतना फण्ड दिया है सरकार ने, इतना फण्ड दिया है कि हम बड़ी हिम्मत के साथ में अप्रैल के बाद में कह सकते हैं कि आहोर के अंदर टूटी हुई सड़क बताओ और ईनाम पाओ, एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी, एक इतिहास बनाया है। इतिहास बनाया है शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, लाइट के मामले में।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर तो मुख्य मंत्रीजी की खिलाफत करने क्यों गये वहां पर। खिलाफत करने जसोल चले गये..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपसे मिलने गये थे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आप तो नमकहरामी हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह आप से मिलने गये थे। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): वह सब बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं, रघुवीरजी, सब। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आपके चौबीस घंटे बिजली आ रही है क्या?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): चौबीस घंटे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): चौबीस घंटे कहीं आ ही नहीं रही है राजस्थान में। जयपुर में नहीं आ रही है। जयपुर में नहीं आ रही है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): आ जाओ, आओ, आहोर में बताता हूं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): इतना असत्य तो मत बोलो, असत्य बोलना तो सीखो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, यह जो असत्य कह रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि आहोर में आयें और हम बता दें। इसका कारण है, डिस्काम ने यह तय किया है कि जहां पर अठारह से बीस प्रतिशत छीजत कम होगी उनके गांवों को हण्ड्रेड परसेंट बिजली दी जायेगी। आपके एरिया में चोरियां ज्यादा होती होंगी इसलिए लाइट नहीं मिलती होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिजली चोरी में झालावाड़ का रिकार्ड देख रखा है या नहीं देख रखा, सर्वाधिक है, नम्बर एक पर झालावाड़ जिला।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्रतिपक्ष के नेताओं से भी, यह जो अभी पाला और सीआरएफ के नार्म्स वगैरह वाला विषय हुआ, हकीकत में देखिये, किसान का दुःख-दर्द किसान जानता है। जब वह फसल बोता है न, अपने घरों के गहने भी गिरवी रखता है। मतलब उसके पीछे जब फसल उगती है उसके दिल में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अगर एक दिन कोई प्राकृतिक आपदा का विषय हो, भगवान उससे रूठ जाय तो उस किसान का तो सर्वस्व नाश हो जाता है, उसके तो परिवार वाले जैसे चले जाते हैं और आज यह हुआ है कि राजस्थान का मेक्जिमम किसान इस पाले के कारण से इतना दुःखी हो रहा है, इस सदन में चाहे प्रतिपक्ष लाये या हमारी सदन की नेता लाये, हम तो यह कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, दोनों नेताओं से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि सीआरएफ के नार्म्स बदलवाओ या कुछ भी करो, किसानों को मदद दो और किसानों के हित में वसुन्धराजी ने 126 करोड़ का जो पैकेज दिया है वह तो काबिले तारीफे है। अब प्रतिपक्ष को चाहिए, आओ इसको और आगे कैसे बढ़ायें, सीआरएफ के नार्म्स बदल कर हम केन्द्र के पास जाकर इस बात की भी हम किसानों की गारंटी लें, उनके दुःख-दर्द को सुनें, उनके दर्द को सुनें। अंत में, माननीय सभापति महोदय, अच्छा शासन हो, यह सारी जातियां झगड़ों से दूर, ऊपर उठ कर सभी को सुखी करें, सभी सुखी रहें, एक राम राज्य की स्थापना जो हुई है उसे हम लेकर दो लाइन कह दूंगा मैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): नागौर का भी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): नागौर का बता दिया न। बता दिया, बता दिया मैंने। पेयजल की स्कीम वास्तव में नागौर में एक ऐतिहासिक हुई है। नागौर की, हमारे मंत्री महोदय, वास्तव में यह हकीकत बात है, ऐतिहासिक 2750 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें से 761 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो गया, मतलब काम कम्पलीट सा हो गया है, यह अपने आप में एक इतिहास बनाया है। अंत में, दो पंक्तियों के साथ वसुन्धराजी जिस ओर जा रही हैं, जिस ओर चल रही हैं, कारवां उनके साथ चल रहा है, बस उनकी जो प्रेरणा है वह प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि वसुन्धराजी की इच्छा यह है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन बढ़ते जाना, सभी समाज को लिये साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती स्नेहलताजी।

श्रीमती स्नेहलता (डग): माननीय सभापति महोदय, सभी विषयों पर तो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, आगे भी बोलना चाहेंगे, मैं महिला होने के नाते सिर्फ महिलाओं के बारे में जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है चार वर्षों में, जो महिलाओं को तोहफे दिये हैं सिर्फ उसका उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं के लिए किया है, उसको महिला समाज हमेशा-हमेशा याद रखेगा। महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर ग्यारह प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत किया उसके उत्साहवर्द्धक परिणाम आये हैं। एग्रीकल्चर लैण्ड पर महिलाओं को काफी फायदा हुआ है, इससे महिलाओं को काफी सम्बल मिला है, इसके लिए मैं हमारी सरकार, मुख्य मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। माननीय सभापति महोदय, आगे और बताना चाहूंगी, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, छोटे परिवार की अवधारणा को विकसित करने के लिए इस वर्ष मुख्य मंत्री बालिका सम्बल योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत यदि कोई दम्पत्ति एक बालिका या दो बालिकाओं के होने पर नसबंदी आपरेशन कराता है तो प्रत्येक बालिका के नाम पर राज्य सरकार दस हजार रुपये की राशि जमा करायेगी जो बालिका को अठारह वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर देय होगी। माननीय सभापतिजी, मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगी कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं को भागीदारी दी है, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जो नियुक्तियां दी गई उसमें हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह दिखा दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। महिलाओं, पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को नियुक्तियां दीं, महिलाओं की सुविधाओं के लिए सभी थानों पर महिला डेस्क स्थापित किए गए। जिससे प्रताड़ित महिलाएं अपनी बात अच्छे ढंग से बता सकें और मुख्य मंत्रीजी ने विधवाओं की पुत्रियों के लिए विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस सरकार ने विधवाओं की पुत्रियों को 5 हजार रुपये का प्रावधान किया था जो हमारी सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिए हैं। राज्य में पांच सूत्रीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व स्व-रोजगार के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही जगह-जगह आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए, गांव-गांव में नगरपालिका क्षेत्र के हर वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए।

(श्रीमती स्नेहलता)

जिससे महिलाओं को कार्यकर्ता सहायिका के रूप में, हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है और उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी महोदया ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम महिलाओं के लिए सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत जगह-जगह अनेकानेक समूह बनाए। जिससे विधवाओं को, बेरोजगार महिलाओं को जोड़कर स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं। जिससे हज़ारों की तादाद में महिलाएं काम कर रही हैं। इसके लिए मैं सम्पूर्ण महिला जाति की ओर से और मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। अंत में मैं, यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि वर्तमान में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। जिनमें 1 लाख 72 हजार 886 महिला सदस्य हैं यह भी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। यह हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कई सरकारें आई और कई चली गई लेकिन महिलाओं का दुःख-दर्द किसी भी सरकार ने नहीं जाना। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर महिलाओं को मजबूती प्रदान की है। मैं मुख्य मंत्रीजी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। आगे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार कटाक्ष के रूप में कहते हैं, बार-बार कटाक्ष करते रहते हैं तो मैं उनको हिदायत देना चाहती हूं कि नारी का सम्मान करना सीखे। हमारी मुख्य मंत्रीजी महिला हैं और आप हमेशा जब भी सदन चलता है आप कटाक्ष करते हैं, बुराइयां करते हैं, मैं भी दो पंक्ति कहना चाहूंगी:-

''नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान,
नारी से उत्पन्न हुए राम कृष्ण भगवान''

जय हिन्द।

श्री सभापतिः डा. सी.एस. बैद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) मैं जब से हाउस चल रहा है चार साल से हमारा नम्बर आखिर में ही आता है।

श्री सभापतिः आप चिंता न करें, आपको पूरा समय दूंगा। आप विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर तक समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की मंजूरी है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आदरणीय सभापति महोदय, राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में, सरकार ने बिन्दु नम्बर-9 से उनसे कहलवाया है राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है और राज्य में लाभ का बजट देने के बाद में सारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं उनमें लगातार सुधार हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि 2007 के अंदर माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी ने जो फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया उसके अंदर उन्होंने जो लिखा है यह पाइट नम्बर-30 ''6ए'' Rajasthan Development and Poverty alleviation Fund. "There shall be created a fund called 'Rajasthan Development and poverty alleviation Fund' in the public account of a state." आज एक साल होने को आया, क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि यह पावर्टी और एलिबिएशन फण्ड का क्रिएशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? यह सिर्फ वित्तीय बिल के अंदर प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। इसका कोई लेखा-जोखा यदि सुदृढ वित्तीय स्थिति है तो उस सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का सबसे ज्यादा लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए और उनके लिए जो फण्ड राज्य सरकार ने क्रिएट किया, उस फण्ड की क्या स्थिति है? इसका लेखा-जोखा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं किया है। न तो इस फण्ड को क्रिएट किया गया, न इस फण्ड का आज तक कोई अकाउंट है।

माननीय सभापति महोदय, यह बिन्दु नम्बर-9 इसमें यह कहा है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो 1999-2000 में 72 हजार 370 करोड़ रुपये था वह 2006-07 में बढ़कर 1 लाख 25 हजार 656 करोड़ रुपये हो गया। यह जो इंडीकेटर है वह इंडीकेटर मैं यह दो लाइन में आपकी अनुमति से पढ़कर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बताना चाहूंगा जिसमें मोंटेकसिंह आहलुवालिया ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में इन दो लाइनों में टिप्पणी की है। यह जो जीएसडीपी का इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया जाता फाइनेंसियल इंडिकेटर्स के अंदर और यह कहते हैं "It's debt GSDP ratio i.e. Gross State Domestic Product ratio, was much higher in the State of Rajasthan than what was expected and if it continues to be high then it is not good for their financial status of the State." अब यह जीएसडीपी जो इंडीकेटर है इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह फिस्कल इंडीकेटर 2006-07 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की जो किताब है जिसमें सारे राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है उसके अंदर डैट जीडीपी रेश्यो राजस्थान का 50 प्रतिशत से अधिक है और दूसरे राज्यों से तुलना करें तो मध्य प्रदेश का यह रेश्यो सिर्फ 43 प्रतिशत है और महाराष्ट्र का 32 प्रतिशत है तो यह जो जीडीपी रेश्यो को यह कहना कि हमारा जो ...(व्यवधान) पूरी सूची है मेरे पास, खाली यही नहीं बताना है दूसरी बात भी करनी है।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, पढ़कर बता दो, मुझे भी मालूम है कितना-कितना है किसका?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जीएसडीपी राजस्थान का जिसमें बढ़ाने का उल्लेख किया गया है...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): वह तो मुझे मालूम है बता दिया है आपने।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वह राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अनुपात से देखा जाए तो वह अच्छा नहीं है और दूसरे राज्यों को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वह अच्छा नहीं है। इसका मतलब जो जीएसडीपी में बढ़ोतरी हो रही है...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, बाकी राज्यों का बताइए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उसके बारे में यह कह कर कि हमने सिग्नीफिकेंट जीएसडीपी में बढ़ोतरी की है और खुद की पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। नेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो इसमें कोई सिग्नीफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसी तरह पाइंट नम्बर-8 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जो इन्होंने कहा है कि 14 हजार करोड़ रुपये की योजना 2008-09 की वार्षिक योजना का गठन किया गया है। अब 14 हजार करोड़ की योजना का गठन किया गया है कितनी हास्यास्पद बात है कि आन्ध्र प्रदेश के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अंदर जो योजना बनाई गई है वह 43 हजार करोड़ की बनाई गई है और पिछले वर्ष की योजना के अनुपात में 14 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की गई है तो 14 हजार करोड़ रुपये की 2008-09 की जो योजना बनाई है वह कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है यदि आप नेशनल लेवल पर और तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों को देखेंगे तो इसके अंदर यह बढ़ोतरी इन-सिग्नीफिकेंट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने साल की योजना बता दें। 2003-04 वह बता दें। 4200 करोड़ की योजना बनाने वाले हम से बात कर रहे हैं 14 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाने वालों से।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमको इमोल्यूमेंट्स 2 हजार करोड़ रुपये का मिलता था अब आपको 8 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं, चार गुणा इमोल्यूमेंट्स बढ़ गया है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सेण्टर स्टेट जो टैक्सेज में रेश्यो हैं जो प्रतिशत है 29 प्रतिशत वो बढ़ गया क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चार गुना एमोल्युमेंट्स बढ़ा है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या बढ़ा है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमको 1998-99 में दो हजार करोड़ रुपये मिलते थे और आपको आठ हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो उसी हिसाब से हमारा स्टेट शेयर ज्यादा है हमारा स्टेट शेयर ज्यादा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और हमें केन्द्रीय सहायता 1352 करोड़ रुपये मिलती थी आपको मिल रही है 5200 करोड़ रुपये चार-चार गुना पैसा लिये बैठे हो। बातें आ रही हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो सारे हिन्दुस्तान में बढ़ा है सारे हिन्दुस्तान में एहसान थोड़े किया है ...(व्यवधान)

साढ़े उनतीस प्रतिशत से ज्यादा थोड़े बढ़ा है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) उतना फायदा प्रदेश को नहीं दे पाये आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके पास मेचिंग ग्रांट के पैसे नहीं थे इसलिए तो आप पैसा नहीं उठा पाते थे, आप किसको बोल रहे हो? आपके पास मेचिंग ग्रांट का पैसा नहीं था पच्चीस प्रतिशत इसलिए पिचहत्तर प्रतिशत भारत सरकार से उठा नहीं पाये पैसा और हमको कह रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सारा पैसा उठाया। पैसा तो आपने नहीं उठाया। कल ही सर्व शिक्षा अभियान में पता लगा है कि इन्हीं के प्रश्न के जवाब में आपने पूरा पैसा मैचिंग ग्रांट का नहीं दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसके अलावा जो आन्ध्र प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं आन्ध्र प्रदेश ने लोन कितना लिया है जरा वो भी बता दें। आन्ध्र प्रदेश ने लोन कितना लिया वो भी बता दें जरा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपके मंत्री बनने के बाद आज पहली बार जब आपने प्रश्न का उत्तर दिया तो उसमें आप बौखला गये तो वो खीज मेरे ऊपर काहे को निकाल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं मेरी बात तो सुनने दें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैंने आपकी पोल खोली है जो किसान के हितैषी बनना चाहते हैं न आप, वो पोल खोली थी मैंने कि 2001 में आपने अमेंडमेंट किया और हमारे ऊपर थोपना चाहते हो वो पोल खोली थी मैंने। एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लोन ले रखा है आन्ध्र प्रदेश ने जिसकी आप बात कर रहे हो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वित्तीय स्थिति का पूरी दुनिया में जब आकलन किया जाता है तो रिलेटिवली किया जाता है ये नहीं किया जाता कि पहले दस साल पहले क्या थी और आज क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये पान खाकर बोलना अच्छी बात नहीं है, सभापति महोदय।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कहां खा रखा है? आपको लग रहा है खा रहा हूं पान खा रहा हूं यह लग रहा है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बैदजी इशारा कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): वो तो सीएस बैदजी ने गोली दी थी वो खा रहा हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये तो केवल एक्शन करते हैं मुंह में कुछ नहीं होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप दोनों की एकता सदन में प्रदर्शित हो रही है वो काबिले तारीफ है लेकिन समाज इस एकता को मान नहीं रहा है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मान लें वो ही बहुत है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, 2003 के अन्दर राज्य सरकार पर जो टोटल कर्जा था वो 53 हजार करोड़ रुपये था और आज की तारीख में राज्य सरकार ने जो कर्जा लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का दावा कर रही है आज की स्थिति में 76752 करोड़ रुपये का कर्जा है। पिछले चार साल के अन्दर इन्होंने 23 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान की जनता के ऊपर कर्जा बढ़ाया है और कर्जा बढ़ा कर लाभ का बजट देना, कर्जा बढ़ाकर वित्तीय स्थिति को ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप इनको बोल लेने दो।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं थोड़ा इतना पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने कितना लोन ले रखा है इतना और बता दें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मध्य प्रदेश का बताया है मैंने मध्य प्रदेश का बताया है महाराष्ट्र का नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश ने कितना लोन लिया है यह भी आप बता दें।

श्री सभापति: वो लाख से भी ऊपर है वो तो। आप विराज जाएं। मेरे ख्याल से जानते हैं ये सब ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक इसमें जो महत्वपूर्ण फीगर है वो यह है, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो लोन लिया है 2003 के बाद वो 46109 करोड़ रुपये का लोन लिया है और आपने लोन चुकाया कितना है सिर्फ 23950 करोड़ रुपये का लोन चुकाया है तो यह सब आंकड़े देकर मैं यह साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो खोखला प्रचार किया जा रहा है पूरी सरकार द्वारा कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो गयी। पहला प्रमाण तो उसका यह मिला कि आपने खुद ने कहा कि एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है फसल का और दिया कितना 126 करोड़ रुपये। जब आप लाभ का बजट बता रहे हैं आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पैसा आपके पास खूब है तो आपको देने से कौन रोकता है? क्यों सीआरएफ की आड़ लेकर आप केन्द्र सरकार के ऊपर यह टालना चाहते हैं और आज जब यह मालूम पड़ा कि केन्द्र सरकार बड़ी गम्भीरता से इसके ऊपर विचार कर रही है और आगे आने वाले दो दिनों के अन्दर यूपीए सरकार कोई अच्छा पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए घोषणा करने वाली है तब जाकर यह बात आयी कि साहब कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है तो ये इनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का द्योतक है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक महीने बाद तो विचार कर रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ जो महिलाओं का हमारी बहन विधायिका ने अभी कहा महिलाओं और बच्चियों की बात हुई उसके लिए ये जो एक अभियान चलाया गया था जिसके अन्दर हण्ड्रेड परसेंट सौ की सौ प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना किशोरी शक्ति योजना इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 साल की बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाना था जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके और इसके अन्तर्गत 2004 से लेकर अब तक राज्य सरकार एक पैसा खर्च नहीं किया, इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का दायित्व सिर्फ इतना होता है कि वो अपने माध्यम से इस योजना की क्रियान्विति करे और ये योजना उन बच्चियों के लिए बनायी गयी है जो ग्रामीण इलाके के अन्दर रहती हैं और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली है और इस योजना के अन्तर्गत 2004-05, 2005-06, 2006-07 में टोटल मिलाकर 7.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए केन्द्र सरकार से और इन्होंने खर्च कितने किये सिर्फ तीस प्रतिशत पैसा खर्च किया और मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा है कि इनको ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली 11 से 18 साल की बच्चियां नहीं मिलीं इसलिए ये पैसा खर्च नहीं कर पाये। कितनी शर्मनाक बात है ये इस चीज को दर्शाता है कि राज्य सरकार का इन गरीब ग्रामीण बच्चियों की तरफ क्या रुख है। इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बालिका समृद्धि योजना है, यह शुरू की गयी थी 2 अक्टूबर, 1999 को और इस योजना के अन्तर्गत ये इसलिए शुरू की गयी कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। यह इसलिए शुरू की गयी कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। यह इसलिए शुरू की गयी कि 18 साल की जब बच्ची हो जाए तो उसे एकमुश्त राशि प्रदान करके उसके जीवन को संबल मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत और ये इन बच्चियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए जब ये बच्चियां 6 से 7 साल की हो जाएंगी स्कूल में जाएंगी तो इनके लिए छात्रवृत्ति

(डा. चन्द्रशेखर बैद)
निर्धारित की गयी। केन्द्र सरकार से आता है सारा पैसा लेकिन आज स्थिति यह है कि जितनी बच्चियों को यह स्कोलरशिप मिलनी चाहिए थी आज एक लाख 16 हजार बालिकाओं को स्कोलरशिप मिलनी चाहिए थी पूरे राजस्थान के अन्दर इस बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत लेकिन इसमें से कितनी बच्चियों को मिल रही है वर्तमान में सिर्फ 518 बच्चियों को। ये आप दे रहे हैं सिर्फ 518 को इसका ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब मेरे पास है यदि आप चाहें तो मैं उसको टेबल करने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें तो दस-दस हजार रुपये के बांड दिये जाते हैं इसमें सहायता कहां दी जाती है?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मंत्रीजी, बड़ी शर्म आ रही है मेरे को कि आपको इसकी जानकारी ही नहीं है बालिका समृद्धि योजना के अन्दर आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तैंतीस जिले हैं राजस्थान में उनमें से सिर्फ दो जिलों में कुछ बालिकाओं को मिल रही है और उन जिलों में चूरू जिला भी शामिल है जिनमें 518 बच्चियों को मिल रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप कहां का प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जहां के वो करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर आपको यह भी ज्ञान नहीं है और यहां पूरी पंचायत आप ही करते हो मंत्रिमण्डल की तरफ से।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, इस योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों के अन्दर एक अभियान चलाया गया जिससे कि जो ग्रामीण बच्चियां अपना घर छोड़ कर पलायन करके दूसरे गांव में या शहर में चली गयीं उन बच्चियों को भी ट्रेकिंग करके यह सहायता, स्कोलरशिप उपलब्ध करायी जा सके। ये अभियान कर्नाटक में भी चला, केरल में भी चला, मध्य प्रदेश में भी चला लेकिन अभी तक राजस्थान में इस तरह का कोई अभियान शुरू नहीं किया गया। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि बालिका भ्रूण हत्या को रोकना है और बालिका को शिक्षा संबल अभियान के अन्तर्गत, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा सम्बल अभियान शुरू किया लेकिन उस अभियान के अन्दर इन बालिकाओं को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गयी और आज जैसा कि अपने पड़ोसी राज्य दिल्ली के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत जो लाड़ली योजना शुरू की गयी है उसमें इन बच्चियों को जब ये 18 साल की हो जाएंगी तो स्कालरशिप के अलावा एक मुश्त एक

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लाख रुपये प्रदान किये जाएंगे। महिला मुख्य मंत्री हैं और महिला अध्यक्ष हैं और इस तरह की बालिकाओं और किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं मॉनीटरिंग करती हैं, आजकल अखबारों में यह खूब आया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बुलाकर मानीटरिंग कर रही हैं। उनको न तो मंत्रिमण्डल पर विश्वास है, न सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास है, खुद मानीटरिंग करने के बावजूद यदि इन योजनाओं को जिनमें हण्ड्रेड परसेंट सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड पैसा आ रहा है उनकी अनदेखी हो रही है तो यह बहुत ही शर्मनाक विषय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अभी मंत्री महोदय गुर्जर साहब फरमा रहे थे कि सारे लोगों को बीपीएल का कार्ड मिल गया। राजस्थान पूरे देश में अकेला राज्य है जिसमें दो बीपीएल की सूचियां आज की तारीख तक प्रचलित हैं। आज आपको इंदिरा आवास देना है नई वाली बीपीएल सूची से इंदिरा आवास दिया जायेगा। आज आपको राशन का गेहूं देना है या कैरोसिन देना है तो पुरानी बीपीएल की सूची से दिया जायेगा। दूसरा सारे राज्य के अस्पतालों में यह निर्देश दे दिये गये कि बिना बीपीएल मेडिकल रिलीफ कार्ड के उनको निःशुल्क मेडिकल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाये और आज तक सारे जिलों में सारे बीपीएल परिवारों को यह मेडिकल रिलीफ कार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। लाखों परिवार बिना बीपीएल कार्ड के इलाज कराने से वंचित रह रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है और जब आपने 2006 में और 2007 के सितम्बर में नयी बीपीएल की सूची जारी कर दी तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपने मेडिकल रिलीफ कार्ड इन बीपीएल परिवारों के आज तक जारी नहीं किये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसका सीधा-सीधा उत्तर यह है, कि आपको भी पता है मैंने विधान सभा में भी कहा था कि प्रावधान यह किया गया था कि जिनके नाम नहीं आये हैं या जिनके गलत आ गये उनको जोड़ने घटाने की अपील का प्रावधान है और अपील का प्रावधान होने के कारण लाखों की तादाद में अपीलें दर्ज हुई हैं उन अपीलों का निस्तारण होगा, निस्तारण होने के बाद जोड़ने की आज्ञा होगी और अब उनके कार्ड बन रहे हैं, काफी कार्ड बन चुके। ऐसा नहीं है कि नहीं बने, काफी कार्ड बन चुके हैं और बन रहे हैं। अभी महीना डेढ़ महीना पहले से बनना शुरू हुये थे उसके पहले चूंकि निस्तारण में टाइम लगा था इसलिए यह टाइम लगा। परन्तु जो नई सूची जारी की गई थी उसके कार्ड पहले ही बन चुके हैं उनको कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने जो नार्म्स बनाये उससे संख्या कम हो गई, हमारी सरकार ने यह कहा था कि जो संख्या कम हुई ऐसे

(श्री कालूलाल गुर्जर)
लोगों को भी हम दो सुविधाएं, एक तो मेडिकल की और एक फूडग्रेन की यह दोनों सुविधाएं सरकार देगी और इसीलिए हमने सब के नाम भी जुडवाये और उतनी ही संख्या में और संख्या बढ़ रही है, करीब 5 लाख लोगों का नाम और जुडने की सम्भावना है जो हमारी अपीलों के माध्यम से जुडेंगे। इसलिए मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, देर इसलिए लगी है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप करेक्ट कर देते हैं लेकिन आपने बीपीएल की सूची जारी की थी सितम्बर, 2006 में, सितम्बर 2007 तक डेढ़ साल होने को आया आपने स्वयं ने अभी कहा है कि डेढ़ महीना पहले हमने कार्ड वितरित करने शुरू कर दिये तो एक साल तीन महीने तक आपने कार्ड वितरित क्यों नहीं किये। दूसरी बात आप यह कह रहे हैं कि हमने नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया चालू कर रखी है। वह आपने मजबूरी में कर रखी है क्योंकि सुप्रिम कोर्ट ने सारी राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया है ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में समय की भ्रूण हत्या हो रही है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, इसमें देरी का कारण यह था मैं फिर बता रहा हूं कि उसमें अपीलें हुई हैं और अपीलें होने के बाद जब तक नाम जुडेंगे नहीं और जांच होकर नहीं जुडेंगे तब तक यदि सूची जारी भी कर देते तो वह अधूरी रहती फिर बाद में उनको कैंसिल करना पड़ता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं बिलकुल गलत। अपील करने की नियमित प्रक्रिया है कोई भी आदमी कभी भी अपील कर सकता है आप इस बहाने से चल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): (व्यवधान) अब तो चलती रहेगी प्रक्रिया वह बात नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपील के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है नियमित प्रक्रिया है और कभी भी अपील की जा सकती है आप उन अपीलों का बहाना बना कर उन सब ग़रीबों का ही सत्यानाश कर रहे हो। सब अपीलों का फैसला होगा, सरकार ने कितने महीने तक अपीलें पेंडिंग रखीं और कितने महीने बाद फैसला किया गया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपीलों का फैसला हो गया, सूचियां बन रही हैं। वह तो पहली बार सूची जारी हुई इस कारण से काफी लोगों ने अपील की, अब थोड़े ही होगी, अब तो रूटीन में थोड़ी बहुत होती रहेगी तो वह चलती रहेगी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप इस 13 अंक को बढाने की सोचते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अंक बढ़ाने का काम भारत सरकार के पास है या राजस्थान सरकार के पास है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह 13 अंक राजस्थान सरकार का नहीं है भारत सरकार का है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यही तो मैं कह रहा हूं, भारत सरकार ने कम कर दिये। 21 लाख रुपये की जगह 17 लाख 36 हजार रुपये कर दिये फिर भी हमारी सरकार ने कहा, सदन में काफी बहस हुई तो मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि जितनी संख्या भारत सरकार ने कम कर दी उनको राज्य सरकार अपने खर्चे से दोनों सुविधाएं देगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जितनी भारत सरकार ने तय की उनका ही मेडिकल रिलीफ कार्ड आप नहीं बना सके, उनको ही आप गेहूं नहीं दिलवा सके। जो संख्या भारत सरकार ने तय की है उनको ही आप नहीं दिलवा पा रहे हैं तीन लाख की क्या बात करते हो। उस बजट का ही उपयोग आप नहीं कर रहे हो, उस पैसे को ही आप अपने पास रखे हुए हो और कहते हो कि साहब हमने तीन लाख की कर दी। उन साढे 17 लाख रुपये को तो दिलवाओ, उनका ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 16 लाख अपील हुई हैं हरिमोहनजी। 16 लाख 62 हजार अपील हुई हैं। (व्यवधान) 16 लाख अपीलों का कोई एक दिन में निस्तारण होता है क्या।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्रीजी 16 लाख अपीलें होने का मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों के नाम बीपीएल सूची में आ गये हैं उनके नाम काट दिये जायेंगे। यह नहीं है उसका मतलब। 16 लाख अपीलें होने का मतलब यह नहीं है कि बीपीएल सूची में जो सूची घोषित की है उनके नाम काट दिये जायेंगे। नाम काटने की कितनी अपीलें होगी मुश्किल से हजार-पांच सौ। नाम लिखवाने की हो सकती हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम काटने की अपीलें भी काफी हुई हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितनी हुई हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह भी लाखों में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हजार पन्द्रह सौ अपीलें हुई हैं पूरे राजस्थान में नाम काटने की, नाम जुड़वाने की हो सकती हैं लेकिन नाम काटने की नहीं होगी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम काटने की भी हुई हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने जगह-जगह पंचायत में कैम्प लगा दिया कैम्प लगाने के बाद फैसला कर दिया वह कौनसी अपीलें थीं जो साढ़े 17 लाख में नाम काटने की थी, मुश्किल से 10 हजार, 5 हजार, 2 हजार उनको क्यों नहीं दिया सवाल यह है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सभापति महोदय, नाम काटो चाहे नाम जोड़ों लेकिन जिनको बीपीएल परिवार में शामिल कर लिया गया सितम्बर, 2006 में उनको कम से कम मेडिकल रिलीफ कार्ड तो उपलब्ध करा देते जिससे कि वह चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा करवा सकते।

सभापति महोदय, इसी के कंटीन्युएशन में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ओल्ड एज पेंशन इसका भी 50 पर्सेंट पैसा केन्द्र सरकार से आता है और 50 पर्सेंट पैसों की मैचिंग ग्रांट देती राज्य सरकार। इसके अन्तर्गत सारे बीपीएल परिवार के वृद्धजनों को 400 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाते हैं। आज की तारीख में जो राज्य सरकार मानती है बीपीएल परिवारों की संख्या 26 लाख 44 हजार है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी केवल 4 लाख 45 हजार वृद्धों को पेंशन दी जा रही है इसके अलावा पेंशन नहीं दी जा रही है। जब मैचिंग ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है और 200 रुपये केन्द्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है तो ऐसी कौनसी मजबूरी आ गई कि आप इन वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।

(समय : 15.07 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इसी क्रम में मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य सरकार द्वारा एक तो जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का दावा किया जा रहा है, वह खोखला है और दूसरा जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो दलित

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लोग हैं जिनको सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिये, समुचित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार उपलब्ध कराने में विफल रही है। राज्य में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं के द्वारा माना गया कि 16 लाख से अधिक विधवाएं हैं। इन विधावाओं को पेंशन दी जानी चाहिये। लेकिन इन विधवाओं का भी आपने ध्यान नहीं रखा और अभी सिर्फ 2 लाख 15 हजार विधवाओं को ही पेंशन उपलब्ध करायी जा रही है।

साथ में अभी बात हुई राम के नाम की, अभी बात हुई हिन्दुस्तान की संस्कृति की, कई चीजों की दुहाई दी गई। 2004 में पहली बार जब आप राज में आये तो सबसे पहला काम क्या किया कि एक्साइज में दारू के माध्यम से स्टेट की रेवेन्यु कैसे बढ़े इसके लिये क्या प्रयास किये जाये, पहला काम जो राज्य सरकार ने किया आमजन की भलाई का कोई काम नहीं किया, सबसे पहला काम यह किया कि राज्य में जो दारू की दुकानें थीं वह 5700 दुकानों से बढाकर एक साल में आपने यह दुकानें कर दी 11500। एक साल में यह दुकानें बढ़ा कर डबल कर दीं और दुकानें बढाने के अलावा दारू पीने के लिये जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती है सरकार द्वारा सारे कानून कायदे, सारी नैतिकता, राम के नाम सब को भुलाकर आपने यह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थल के 200 मीटर में दुकान नहीं होनी चाहिये, शिक्षण संस्था के 200 मीटर में दुकान नहीं होनी चाहिये, मजदूर बस्ती के पास दुकान नहीं होनी चाहिये तो सारे नियमों में जो नियम बने हुए हैं नियम नंबर 75 आबकारी जो बना हुआ है उसमें स्पेशली शिथिलता देते हुए आज 352 दुकानें पूरे राजस्थान में ऐसी है जो कि मंदिरों के नजदीक बनी हुई हैं। आप एक तरफ तो राम के नाम की दुहाई देते हो, एक तरफ गंगाजल से अभिषेक करते हो, आप क्या गंगा जल की जगह दारू से अभिषेक करना चाहते हो भगवान राम का। 352 दुकानें, इसमें स्पेशल रिलेक्सेशन दिया गया, जिसकी मंदिर के पास दुकान है खोल ले, 200 मीटर के भीतर है खोल लो और शिक्षण संस्थाओं के पास में हो उनको भी खोल लो। पूरे देश के अधिकांश राज्यों में सात सूखा दिवस है वह राज्य सरकार ने कम करके कि दारू पीने वालों को तकलीफ होती है सात दिन बिना दारू के रहना पड़ता है, उनके आठ के ठाठ नहीं हो पा रहे इसलिए उनको घटकर इन्होंने तीन कर दिये। सात की जगह तीन दिवस कर दिये। बड़ी मुश्किल से एक दिवस और जोड़ा और आज की तारीख में चार सूखा दिवस हैं जबकि अधिकांश राज्यों में पूरे देश के अंदर सात सूखा दिवस हैं। शराब की दुकान पर ..(व्यवधान) शराब की दुकान पर छूट देने की पराकाष्टा यह पार हुई कि पहले यह नियम बना हुआ था कि

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जिस दुकान पर दारू बिकती है उस दुकान पर कोई आदमी दारू नहीं पी सकता लेकिन आपने पुलिस को उस दुकान पर जाने के लिए रोक लगा दी कि पुलिस वाला नहीं जाएगा। दारू की दुकान को मदिरालय में तब्दील कर दिया।

अभी आप कह रहे थे कि एक गिलास दूध जरूर पीओ, तो दूध की दुकान तो बाद में खुलती है आपने दारू की दुकान खुलने के समय को भी परिवर्तित कर दिया। सुबह नौ बजे के पहले दारू की दुकान खुल जाती है और रात के दो बजे तक दारू की दुकान खुली रहती है और सारी दारू की दुकान पर बैठकर वहां मदिरा का सेवन कर सकते हो। वह मदिरालय में तब्दील हो गई। यह सारा किसलिए किया? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सारी रात पीते हैं आप जाते हैं क्या देखने? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): इनके पास कई सूचनाएं आती हैं कि वहां पड़ा है इंजेक्शन लगाओ इसलिए पता रहता है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने बता दिया होगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह सारा वर्ष 2004 के प्रारम्भ में यह कहकर किया कि एक्साइज से होने वाली आय को बढ़ाया जा सके लेकिन आय कितनी बढ़ी आपके सरकारी आंकड़े, आपकी एक्साइज की वेबसाइट बताती है कि 2005-6 में आय 1183 करोड़ रुपये थी वह 2006-7 में घटकर 1167 करोड़ रुपये रह गई। आपके सारे प्रयासों के बावजूद खाली यह सोच लेकर कि हमारी एक्साइज की आय बढ़े, एक्साइज की आय कम हो रही है और सारी छूट आपने दे दी, सरकार ने यह कहकर कि ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाएगी, रिटेल दारू के दुकान वालों को लाभान्वित किया जाएगा, सारा का सारा सरकार ने दारू का ठेका अपने पास ही सीमित कर लिया, तो यह कहकर आप कौनसी संस्कृति की दुहाई देना चाहते हो मेरी तो समझ से परे है।

इसी सन्दर्भ में एक बात आपके माध्यम से और अर्ज करना चाहूंगा कि बिजली के मामले में राज्य सकरार द्वारा बार-बार अनेको बार यह दावे किये गये कि हमने बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, बिजली मंत्रीजी यहां बैठे हैं, आपने यह कहा कि 1411 मेगावाट बिजली का उत्पादन राज्य में बढ़ गया है पिछले चार साल के अंदर। कहां से बढ़ गया है? इसका जब ब्रेकअप लिया गया तो जानकारी मिली कि गिराल के अंदर 125

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मेगावाट की यूनिट बनी तो गिराल में आपसे कोई यह पूछे कि गिराल की जो यूनिट बनी उसमें यूनिट का उदघाटन होने से अब तक आपने कितनी बिजली का उत्पादन किया तो मालूम पड़ेगा अधिकांश समय यह खराब रही और जितनी करोड़ यूनिट का, बिजली का उत्पादन किया जाना था उसकी जगह 25 प्रतिशत से भी कम बिजली का उत्पादन हुआ।

दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं आप यह कहते हैं कि 110 मेगवाट की तीन यूनिट धौलपुर जिले के अंदर, 110 मेगावाट की पहली यूनिट, 110 मेगवाट की दूसरी यूनिट और दोनों यूनिट पर आधारित तीसरी 110 मेगावाट की यूनिट का प्रारम्भ किया। लेकिन तीनों यूनिटों के अंदर जब से आपने इसका उदघाटन किया तब से लेकर आज तक आप स्वयं का हिसाब लगाकर देख लें कि कितने यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। आज इसमें चार यूनिट, चार यूनिट आपके शासन में आने के बाद 2004 के बाद में प्रारम्भ की गई और चारों यूनिट की स्थिति यह है कि इसके अंदर मिलाकर जो टोटल बैठता है 455 मेगावाट बिजली का उत्पादन आपने किया। आप कहते हो कि 1411 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लिया, बाकी आप किनको जोड़ते हो कि विंडएनर्जी जो केप्टिव उसके अंदर है और दूसरी बायोमास से बनी उसको भी हमने जोड़ लिया है, जो सेन्ट्रल से मिलती है उसको भी हमने जोड़ लिया। आपने अपनी मेहनत से पिछले चार साल में किन नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना करके बिजली पैदा करनी शुरू की, आज यह बिजली की हालत किसलिए हो रही है, यह इसलिए हो रही है।

दूसरा आरएपीपी के अंदर जो पहली यूनिट आपकी है, आपको मालूम था कि 25 साल बाद इसकी आफ लाइफ 25 ईयर्स हैं, 1973 में इस यूनिट की शुरूआत की थी, 25 साल बाद इस यूनिट को बंद होना है। सौ मेगावाट बिजली जो आपको मिलती थी वह बंद हो गई उसके बाद दूसरी यूनिट जो 1981 में शुरू हुई थी उसको भी 25 साल पूरे होने के बाद....

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य अपना होमवर्क करके नहीं आये। सबसे पहले तो गिराल की यूनिट है वह गिराल की यूनिट चल रही है। गिराल की यूनिट की जो सैंक्शन दी थी और इनहोंने भेल को जो कान्ट्रेक्ट दिया था आज की तारीख तक भेल ने हमें हैंड ओवर नहीं किया क्योंकि उसमें समस्याएं आ रही हैं, उसके अंदर परेशानी आ रही है। इनकी सैंक्शन की हुई, इन्हीं की सरकार की वह गिराल की परियोजना भेल को अवाड़ की थी और यह ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हैं।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

जहां तक धौलपुर का मामला है, धौलपुर की तीनों इकाइयां सही समय पर चालू हो गई थी लेकिन बीच में केन्द्र सरकार ने हमें गैस बंद कर दिया, गैस हमें देना बंद कर दिया इस कारण यह इकाइयां करीबन 8-10 दिन के लिए बंद हो गई। आज गिराल भी पूरी चल रही है, आज की तारीख में धौलपुर भी पूरी चल रही है।

यह बात करते हैं कि बिजली का संकट आ रहा है हमारी वजह से आ रहा है सभापति महोदय मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आरएपीपी की आज राजस्थान के अंदर, आप जाकर देखें कोटा के पास एटोमिक यूनिटस लगी है इतनी हमारी वाटरबाडी, इतनी बढ़िया-बढ़िया झीलें ली हुई हैं। आरएपीपी की दोनों यूनिट हैं 220 मेगावाट की दोनों यूनिट डिले हो गई है। हमारा जो शेयर था हमें जो मिलना था वह जीरो हो गया दोनों यूनिट के अंदर। केन्द्र सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्रीजी को इतनी चिट्ठियां लिखी उसके बावजूद उन्होंने हमें कुछ भी कम्प्नसेशन नहीं दिया। धरती राजस्थान की यूज हो रही है, पानी राजस्थान का यूज हो रहा है आज कोई वेरिएशन होता है तो राजस्थान की जनता प्रभावित होती है, लेकिन उन्होंने हमें एक भी मेगावाट बिजली उसके अंदर से नहीं दी।

माननीय सदस्य मैं छाती ठोककर बोल सकता हूं कि इस वर्ष हमारी जो नौ यूनिट प्रोग्रेस में आयेगी उनका काम चल रहा है, अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमें केन्द्र की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मंत्रीजी, आपने मेरे को तो कह दिया होमवर्क के बारे में। मैं एक छोटी सी बात सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करूं कि आपने गिराल की यूनिट का उदघाटन कब किया था, नम्बर वन (व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिए मेरी, आपने गिराल की यूनिट के बाद में धौलपुर, गैस के ऊपर बैस, धोलपुर की यूनिट का, पहली यूनिट का उदघाटन कब किया था? आपने गिराल की यूनिट का उदघाटन 28 फरवरी, 2007 को और उसके बाद गिराल की 110 यूनिट का उदघाटन किया 29 मार्च, 2007 को तीसरी और चौथी यूनिट का उदघाटन आपने किया 1 सितम्बर, 2007 को। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं आप एक व्हाइट पेपर रिलिज कर दो और जितनी मेगावाट विद्युत का इन यूनिटों में उत्पादन किया जाना चाहिए था और कितना उत्पादन आपने आज की तारीख तक किया, स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं Everyday the unit production is being recorded. हर दिन कितने यूनिट प्रोडयूज हुआ वह

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

रिकार्ड किया जाता है, आप जब वह निकालोगे तो आपको स्वयं को यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अभी तक इन यूनिटों का उदघाटन करने के उपरान्त 50 प्रतिशत से कम बिजली का उत्पादन किया है। यह जो घाटा हुआ है 50 प्रतिशत बिजली कम पैदा करने का, आपने बहुत मंहगे दाम के अंदर जो दूसरी ग्रिड से बिजली खरीदी वह खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ा।

साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहली और दूसरी यूनिट आर.ए.पी.पी. की जो 25 साल पूर्ण होने के बाद में बंद हो गई थी, तीसरी और चौथी यूनिट के अन्दर आपने कल आदरणीय कल्ला साहब के सवाल के जवाब में आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि कितने यूनिट आपने मध्य प्रदेश को देने का वादा कर लिया था। यह रहा आपका दिया हुआ सवाल का जवाब है, आपने यह कहा कि आर.ए.पी.पी. की तीसरी और चौथी यूनिट में चूंकि बिजली हमको मंहगे दाम पर मिल रही है, इसलिये यह बिजली आसपास के पड़ोसी राज्यों को उपलब्ध करा दी जाए। उस समय एनर्जी में राज्य की अनदेखी करते हुए आपने उस बिजली को पड़ोसी राज्यों को, मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय चुनाव होने वाले थे, इसलिये आपने बेवजह मध्य प्रदेश के अन्दर उस बिजली को देने की हामी भरी। उसका खामियाजा आज तक राज्य भुगत रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य के पास फेक्ट्स और फिगर्स जो हैं, मुझे यह अचम्भा हो रहा है कि आप जो अपना होम-वर्क करके आये हैं You have not done your home work properly. आप मेरे साथ विराजें I will prove you are wrong on every point.

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह मैं आपको पढ़कर बता दूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): गिराल की यूनिट तो अभी भेल ने, हमें, राजस्थान स्टेट को हैण्डओवर नहीं की है। और जो कुछ भी चली, दिसम्बर में 65 प्रतिशत पी.एल.एफ. में चली है। अभी हमारे को हैण्डओवर नहीं की है। और भेल को आपने दी थी। हमने काण्ट्रेक्ट भेल को नहीं दिया? भेल ने आज तक राजस्थान को नहीं दी, वह पैनल्टी दे रहे हैं उसके ऊपर। तो यह जो भेल को आपने दी थी, आपकी सरकार ने दी थी। हमें तो हैण्डओवर ही नहीं हुई अभी तक यूनिट।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ताबड़तोड़ में यह कहने के बाद, शुरू के तीन साल तो आपकी नींद खुली नहीं। तीन साल बाद आपको मालूम पडा कि एक विद्युत उत्पादन इकाई शुरू करने में 24 से 30 महीने का समय लगता है, फिर आपने ताबड़तोड़ इनके उदघाटन कर दिये। उदघाटन करने के बाद में वह समय पर चल नहीं पाई। और आप तो यह बता दें कितने दिन ब्रेक-डाउन हुआ। उदघाटन करने के बाद में कितने दिन गिराल की यूनिट बंद रही। उदघाटन करने के बाद कितने दिन धौलपुर की यूनिट बंद रही। आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। इसका दूसरा...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कोई भी यूनिट चालू होती है उसके अन्दर टीजिंग प्राब्लम्स होती हैं। It is machinery. यह कोई आटो-मेटिक चीज नहीं होती है कि चलाते ही, बटन दबाते ही चले। उसके अन्दर प्राब्लम्स आती हैं। और धौलपुर के अन्दर पहली यूनिट तैयार हुई, एक साथ तीन यूनिट तैयार नहीं होती हैं। माननीय सदस्य, जो तीसरी यूनिट है वह दो यूनिट्स की जो स्ट्रीम और फ्री एनर्जी पर तीसरी यूनिट चलती है। शायद आपको इसका ज्ञान नहीं है। तीन यूनिट एक साथ चालू नहीं होती हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मेरे को सारा ज्ञान है। आपका बिजली का उत्पादन और बिजली की जो सप्लाई है, वह आपके कार्यकाल में फ्लाप-शो रहा, यह साबित हो चुका है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मंहगी बिजली की बात कर रहे हैं, 10 रुपये ग्रिड की बिजली किसने की केन्द्र सरकार ने की। सात रुपये ग्रिड की कीमत थी, सभापति महोदय, हम जो ओवर-ड्रा करते थे, जबकि फ्रिक्वेंसी बिलकुल डाउन हो जाती थी, 7 रुपये यूनिट थी, केन्द्र सरकार ने कहा, नहीं, इसको 10 रुपये कर दिया जाए। 10 रुपये का किया, मतलब कि जो राज्य उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उनको पनिश किया जाए कि उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं तो 10 रुपये किया जाए। परन्तु हम जो, जो आपकी दसवीं पंचवर्षीय योजना थी, हम केवल तीन स्टेट थे इण्डिया के अन्दर, जिन्होंने जनरेशन के अन्दर फुलफिल किया। तो यह तो जिन प्रदेशों ने जो जनरेशन नहीं किया था उनको पनिश करना चाहिए था तो 10 रुपये यूनिट जब आप मंहगी बिजली की बात कर रहे हैं, यह निर्णय तो केन्द्र सरकार ने किया था। हमें तो बिजली खरीदनी पड़ी, हमारे पास कोई आप्शन नहीं था।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सभापति महोदय, मैं एक बात और करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम। अब आपके मंत्रीजी नाराज हो गये क्योंकि आप बिजली उत्पादन नहीं कर पाये।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नाराज नहीं, मुझको अचम्भा हो रहा है कि आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स ही नहीं हैं। You don't have correct facts & figures. (व्यवधान) You are talking baselessly without facts & figures.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मान्यवर, यह सही है। (व्यवधान) फैक्ट यह है कि किसानों को 6 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके समय में कितनी मिलती थी बिजली। आपके समय में कितनी मिलती थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे समय को तो मारो गोली। आप आये इसी आधार पर हो यहां पर कि हमने बिजली टाइम पर नहीं दी। लेकिन आप जो वादा कर रहे हो उसको तो निभाओ। आप किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कितने धरने हुए थे आपके टाइम पर। आपके टाइम पर क्या हुआ था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सारे शहरों में बंद पड़ी है। जयपुर में आपको कटौती करनी पड़ रही है। सारे गांवों में अंधकार है। किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं और किसानों की हालत बिगड़ी हुई है और आप फिर भी कह रहे हो कि हमारी व्यवस्था ठीक है। आप खुद को मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में किसानों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, समय बर्बाद हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोलासर में बिजली के मामले में पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को भगाया था, क्या, क्या, बोलासर में पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान अशोकजी गहलोत को बिजली के मामले में भगाया, जूते छोड़कर भागे हैं। क्या इन चार सालों में यह नौबत आई। क्या 4 सालों में नौबत आई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप राजधानी में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, खुद के यहां ही। विधायकों को नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने में असुविधा होती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसानों को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप चेलेन्ज को मंजूर करें। आप मेरे साथ चलें। चाहे किसी भी आथोरिटी को भेज दें, किसानों की क्या हालत है, नहीं मिल रही है बिजली उनको। (व्यवधान) आप चलें ना। मंत्री महोदय, चलें ना, हिण्डौली ले चलता हूं आपको। और सीधे किसानों से बात कर लें। किसानों से बात कर लें, मेरे साथ चलकर।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): नहीं, नहीं, 6 घण्टे बिजली किसानों को मिल रही है। यह सही है कि बीच में इण्टरविन कभी होती है। (व्यवधान) लगातार 6 घण्टे बिजली दी जा रही है। (व्यवधान) और आपको अगर कहीं देखना है, 6 घण्टे मिल रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बस्सी में मिल रही होगी, मेरे यहां नहीं मिल रही है, मैं वह बात कर रहा हूं। (व्यवधान) हो सकता है राजनीतिक पक्षपात हो। हो सकता है, राजनीतिक पक्षपात हो। लेकिन नहीं मिल रही है बिजली। आप बूंदी में आ जाइये, हर कांस्टीट्एैंसी में लेकर चलता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप वहां रहते नहीं हो, इसलिये नहीं मिलती है। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आपने तो बिजली के मामले में शहर और गांवों में खाई पैदा कर दी थी। 5 हजार की आबादी है, 15 सौ की आबादी में कम समय मिलती थी। यह खाई पैदा कर दी थी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आपने बिजली के मामले में खाई पैदा कर दी थी। (व्यवधान) इस सरकार ने आते ही उस खाई को मिटाया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप करते रहो 6 महीने और। 6 महीने इसी प्रकार कर दो, नतीजा सामने आ जाएगा।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सभापतिजी, मैं कह रहा हूं कि इतनी बिजली आ रही है....(व्यवधान). हरिमोहनजी, और मैं कह रहा हूं, हम देख रहे हैं, सुबह से बिजली इनमें भी आ रही है। आज हाउस में बिजली सुबह से ही आ रही है, इतनी बिजली है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): बूंदी में तो ममताजी कहेंगी तब मालूम पड़ेगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। आप हिण्डौली की बात करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बूंदी में तो ममताजी बताएंगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सदस्य जो चुनकर आता है केवल सीमित क्षेत्र के लिये नहीं है। (व्यवधान) आप चलिये मेरे साथ में दिलावर साहब, आप तो खाली एक जगह घूमकर जहां के तहां। कांस्टीट्ऐंसी बदल गयी तो परेशानी और आ गई। सरकार से लड़ाई अलग है, मुसीबत अलग है। आप तो जब तक एन.डी.पी.एस. का मुकदमा नहीं निपटे इसी तरह से चलते रहो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, बिजली का हाल यह है कि किसान जो आज की तारीख में, वह भरभरी, जिस तरह से कटकटाता है ना, दांत कट-कट इस तरह से किसान दांत कट-कटा रहा है और इंतजार में है कि कब चुनाव आयें और कब हिसाब-किताब निपटे। यह हाल है आज। इतनी ठण्ड में किसान खेत में जाए और वापस बटन दबाने आये, खेत में जाए और वापस आये। पूरी रात किसान कंपकंपाता रहे और उस कंपकंपी की वजह से वह दांत कट-कटा रहा है कि कब चुनाव आयें और कब हिसाब किताब निपटाये, यह है हिसाब-किताब।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): आप लोगों के समय में जो बिजली आती थी, वह अभी तक नहीं भूले हैं। अभी तक याद है आपके कार्यकाल में जो बिजली आती थी ना, वह अभी तक याद है। (व्यवधान) उसको कभी नहीं भूलेगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हमारे कार्यकाल में हमने गलती की तो हम सज़ा भुगत रहे हैं। आप भी वही सज़ा भुगतना चाह रहे हो क्या, आप अगर ऐसी सज़ा भुगतना चाह रहे हो तो हमें कुछ नहीं कहना है। हमें उधर बैठना है, उधर बैठ जाएंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना की शुरूआत हुई फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम। फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम आप द्वारा हजारों-करोड़ों रुपये की एक योजना शुरू की गई। यह कहकर शुरू की कि इससे बिजली की छीजत कम होगी और इसमें जिन-जिन गांवों के अन्दर बिजली की छीजत कम होगी वहां हम 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराएंगे। यह आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है। छीजत कम होगी, ज्यादा लोगों को बिजली उपलब्ध होगी। बहुत सराहनीय कदम था, हुआ क्या? आपने फीडर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

रिनोवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जिन गांवों में छीजत ज्यादा हो गई और जिनमें सारा रिनोवेशन आपने कम्पलीट कर लिया, जहां 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करना शुरू कर दी गई, वहां छीजत वापस बढ़ गई। यह किस चीज का द्योतक है। यह बताता है कि जिन गांवों में आपने छीजत कम की थी, करोड़ों रुपये खर्च करके फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत, उससे आपकी छीजत कम नहीं हो पायेगी। आप यह बता दीजिए कि कितने ऐसे गांव हैं जहां पर आपने 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत और बाद में उन गांवों के अन्दर आपको वह कटौती लम्बित करके उन्हें पहले के हिसाब से बिजली उपलब्ध करानी शुरू कर दी। यह दर्शाता है कि आपका फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम जो हजारों करोड़ रुपये का है उसके अन्दर बहुत बड़ा घपला है जिसके कारण यह कामयाब साबित नहीं हो पा रहा है इसलिए आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दें, साहब।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, आज से छह महीने पहले राजस्थान के केवल 400 गांव थे, एक प्रतिशत गांव थे जहां बिजली 24 घंटे आती थी। आज की तारीख में 18 हजार गांव, 24 घंटे बिजली आ रही है। 24 घंटे बिजली का मतलब है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। यह अमरीका जैसा सिस्टम नहीं है कि बिजली उड़ेगी ही नहीं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। जयपुर शहर में भी कई बार फाल्ट आ जाता है, बिजली चली जाती है। लोग इसको, सिस्टम को पंक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब सिस्टम को डिफीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें भी और भी कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे इसको डिफीट नहीं होने दें। कुछ जो हर्डल्स आएंगे, कुछ हिचकिचाहट आएगी लेकिन हम इसका सुधार कर देंगे और जो आपने कहा, आपने सही बोला कि कई गांवों के अन्दर जहां पर छीजत रुक गयी थी, कुछ लोगों ने फिर वापस चोरियां शुरू कर दीं। उनको फिर वापस 24 घंटे से काट दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने हमारी मीटिंग के अन्दर यह बात उजागर की गयी तो उन्होंने कहा कि कुछ चंद चोरों के पीछे पूरे गांव की बिजली क्यों काटी। वापस 24 घंटे से काट कर कम क्यों की जाए तो अब यह जो सिस्टम है कि इसको नहीं किया जाएगा। उल्टा हम जो लोग इस सिस्टम को पंक्चर कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान हम केन्द्रित करेंगे और यह नहीं होने देंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने यह तो माना न कि आपका फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम फ्लाप हो गया कुछ गांवों के अन्दर। आपने माना इस बात को, आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): फ्लाप नहीं हुआ। यह आप फ्लॉप कर रहे हो। अपनी परिभाषा से फ्लाप कर रहे हो। कैसे फ्लॉप हो गया? (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप कह रहे हैं कि वापस चोरी होना शुरू हो गयी तो फ्लाप रिनोवेशन प्रोग्राम हुआ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 18 हजार गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है 400 से तो आप उसको फ्लाप मानते हो? आप 400 से 18 हजार को फ्लाप मानते हो? मुझे अचम्भा है कि आप जैसे एजुकेटेड आदमी, 400 से 18 हजार गांवों में जा रहे हैं और आप उसको कहते हैं फ्लॉप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जो हजारों करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हो छीजत कम करने के लिए और चोरी कम करने के लिए, वह वापस छीजत बढ़ गयी। वापस चोरी बढ़ गयी तो फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम तो आपका फ्लॉप ही रहा। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 43 प्रतिशत से 30 प्रतिशत पर अगर चोरी आ जाए तो उसको आप फ्लाप कहते हो? (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जितना पैसा मिला उतना पैसा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, आज 2004 से अब तक केन्द्र सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम लाने जा रही है उस प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य सरकार को जो हजारों करोड़ रुपया उपलब्ध कराया, आज आपने पिछले चार साल में 807 करोड़ रुपये कम खर्च किये। आपने यह कहा है कि 75 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का है और 25 परसेंट मेचिंग ग्रांट आप देते हैं तो यह पैसा आपने क्यों कम खर्च किया? आपने यह भी कहा कि विभिन्न मदों के अन्दर जिनमें टीचर की सेलेरी भी है, नये टीचरों की नियुक्ति भी है, कक्षा-कक्ष का निर्माण भी है, कम्प्यूटर सुविधा भी है, सारे मदों के अन्दर जो निर्धारित पैसा आपको केन्द्र सरकार ने उपलब्ध कराया, वह आप खर्च ही नहीं कर पाएं। कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप उस ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये-सुनिये, ऐसा है कि सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा हमारी सरकार बनने के बाद आया, हर साल पूरा खर्चा किया। उससे ज्यादा ही खर्चा किया है पर इस वर्ष क्योंकि अभी जनवरी फरवरी चल रही है, इस बार का पैसा थोड़ा बकाया है, बाकी सब हमने खर्चा कर दिया। यदि आप कल हल्ला नहीं मचाते तो आपको जवाब देता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह खर्च नहीं किया इसीलिए शिक्षा मंत्री बदल दिये गये। उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थीं, काम ठीक नहीं किया, विकास ठीक नहीं किया इसलिए शिक्षा मंत्री बदल कर सर्राफ साहब को बना दिया। इस बात को छोड़िये आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब आप केन्द्रीय सरकार की स्थिति का बयान कर रहे हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): लास्ट में, मैं बस यही, आपने जो कहा उसी के ऊपर 2-3 यह फिगर बताना चाहता हूं कि देखिये, आपने वर्ष 2005-06 के अन्दर आपके पास टोटल पैसा केन्द्र और राज्य सरकार का मिलाकर, 75 परसेंट एण्ड 25 परसेंट, 735 करोड़ रुपये था। आप कह रहे हो कि पूरा खर्च कर दिया। आपने 577 करोड़ रुपया खर्च किया, 157 करोड़ रुपया कम खर्च किया आपने और मैं यह खुल्लम-खुल्ला आपको कहता हूं, आरोप लगाकर कि केन्द्र सरकार से 75 परसेंट पैसे जो आपको मिले वह तो आपने खर्च कर दिये लेकिन जो मेचिंग ग्रांट 25 परसेंट आपके द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी वह आपने खर्च नहीं की इसीलिए जितने भी टीचर की नियुक्ति के लिए आपको केन्द्र सरकार ने एस.एस.ए. के अन्तर्गत पैसा दिया था वह आप टीचरों की नियुक्ति आज तक नहीं कर पाए। आपने समय दिया, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह कहता हूं कि यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामप्रतापजी। केवल मात्र 7 मिनट दिये जाएंगे आपको।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं-नहीं, फिर नहीं बोलूंगा। सात मिनट देनी है तो नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में 18 फरवरी को जो अभिभाषण दिया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

मान्यवर, मैं आंकड़ों की राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा और न ही कोई ऐसी असत्य बात कहूंगा जो सदन को अखरे। मान्यवर, इस अभिभाषण में सरकार की पिछले चार वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उसका बखान किया गया है तो मोटे रूप में मैं एक विषय पर, काश्तकारों का जो विषय है, जमीन से जुड़ा हुआ जो विषय है, उसके संबंध में, चार साल तो बहुत बड़ी बात है, माननीय सभापति महोदय, प्रथम चरण के अन्दर नहरी यात्रा के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं कीं, काश्तकारों का जिससे हित हुआ, भला हुआ उसका मैं पूरा बखान करूं तो रामायण लिखी जाएगी परन्तु उसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं, उनका मैं यहां बखान करना चाहूंगा।

जब से इंदिरा गांधी नहर आयी है तब से लेकर आज दिन तक काश्तकार जो है लगातार एस.डी.एम., तहसीलदार, पटवारियों के चंगुल से नहीं छूटे और गांधी बाबा की जो फोटो लगी हुई है, ऐसे कागजों के वह जो चित्र छपे हुए हैं उनके बिना कुछ नहीं होता था। परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को, राजस्व मंत्रीजी को, जिन्होंने काश्तकारों की वर्षों से लम्बित जो समस्या थी उसका समाधान किया। टी.सी. से पुख्ता बालिग पुत्रों का आबंटन, हजारों की संख्या में निस्तारण हुआ है। धारा 13 (ए) के तहत जिन काश्तकारों ने बिना मंजूरी के भूमि खरीद ली, कांग्रेस के समय उन लोगों को खातेदारी नहीं मिल रही थी। पैनल्टी लगा दी। उसका निस्तारण किया। सन् 1955 के बाद के हजारों की संख्या में काश्तकार गैर खातेदार थे, जिनको खातेदारियां नहीं मिल रही थीं, उन सबको खातेदारी देने का काम लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। 1955 से पूर्व के लोग वर्षों से खातेदारी के लिए तरस रहे थे, उनका भी 80-85 परसेंट से ऊपर काम हो गया और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि 2-3 महीने में ही आबंटन से संबंधित कोई काम वहां बकाया नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं स्माल पेच, स्मॉल पेच जो है, जैसे किसी व्यक्ति की एक मुरब्बा जमीन है उसमें से 20 बीघा है, पांच बीघा उसके चिपटी हुई भूमि है तो वह स्माल पेच अलाटमैंट कराने के लिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिना गांधी बाबा के नहीं होते थे, जो आज फ्री हो रहे हैं। सभापति महोदय, मीडियम पेच, काश्तकारों के चिपटी हुई कोई भूमि है। 10 बीघा, 15 बीघा तो सरकार ने उस काश्तकार को आबंटन की जो प्राथमिकता दी है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। सभापति महोदय,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

इतना ही नहीं जिन लोगों के पास सरकारी भूमि पर कब्जा था, ट्रेसपासर जिनको कहते थे, कुड़की, कुंता, तमाम जिन लोगों के लगता था, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका नियमन करने का जो आपने फैसला किया है, यह बहुत बड़ा एतिहासिक काम है। सभापति महोदय, सूरतगढ़ तहसील, लूणकरणसर का भी काफी क्षेत्र है और माही परियोजना, इधर का भी काफी एरिया ऐसा था, जिसको सिंचित एरिया में सम्मिलित तो कर लिया पर सरकार सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकी। उनके ऊपर उपनिवेशन क्षेत्र के काले कानून लग गये। सीलिंग सीमा और आबंटन में पैसा वसूल करते थे। सभापति महोदय, हम यह सोच ही नहीं सकते थे कि इस तरह की समस्या, और मुख्य मंत्रीजी के दौरे में हमने प्रार्थना पत्र दिया और 47 गांवों को डि-कोलोनाइजेशन करके काश्तकारों को नि:शुल्क भूमि आबंटन करने का जो फैसला किया, उसके लिये मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं है। सभापति महोदय, और भी तरह तरह की काश्तकारों से संबंधित, आबंटन से संबंधित (व्यवधान) हरिमोहनजी माननीय सदस्य, मैं जो बात कह रहा हूं सौ प्रतिशत सही है। अगर एक भी मेरा शब्द असत्य हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपकी बातों को गलत नहीं मान रहा। मैं तो इनसे यह कह रहा था कि अब कम से कम बी.जे.पी. के टिकट की गारण्टी तो हो ही गयी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मुझे टिकट की परवाह नहीं है। सरकार से दस हजार रुपये प्रति बीघा, घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, मुआवजा तय करवा दो प्रति बीघा, जाओ, मैं आपके गीत गाऊंगा। करो न, कुछ करके दिखाओ। मैं व्यक्ति का पुजारी नहीं हूं, मैं काम का पुजारी हूं। जो किसान का काम करेगा, मैं उसकी सदन में तारीफ करूंगा। अब चाहे यह किसी को पीड़ा पहुंचे, नहीं पहुंचे, कम से कम चाहे कोई सरकार हो, काम करने वाले की पीठ थपथपानी चाहिये ताकि उसको हौसला रहे कि यह अमुक काम किया, इसके लिए पक्ष-विपक्ष ने तारीफ की तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ता है। खाली महज हम अपोजिशन में हैं इसलिए विरोध करेंगे, यह कोई तरीका है। अच्छे को तो अच्छा कहो, बुरा कोई करता है तो उसको बुरा कहो। सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था डि-कोलोनाइजेशन का इतना ही नहीं, कुछ गांव ऐसे हैं जिन गांवों में सन् 1970 के नियमों के तहत काश्तकारों को खातेदारी दे दी। ऐसे हजारों काश्तकार हैं, उन काश्तकारों के उपनिवेशन

(श्री रामप्रताप कासनिया)

क्षेत्र में सम्मिलित होते समय, कांग्रेस के समय एक धारा 15 ए नाम का कीटाणु था, जिसके कारण से वह वापस गैर खातेदार हो गये और गैर खातेदार होने के बाद में आबंटन दुबारा करवाना पड़ता है और किश्तें लगती हैं। इस सरकार ने नियमों में संशोधन करके हजारों काश्तकारों को जो उपनिवेशन क्षेत्र में कीमत लगती थी, वह नहीं, आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी. और सामान्य वर्ग के लोगों पर 20 प्रतिशत की राशि लगाई है, बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहने काबिल बात की है। यह सरकार (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हेमारामजी, पीछे दो ही बचे हैं अब, बाकी सब गये।

एक माननीय सदस्य: इनको तो रोककर रखना।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपके तीन मैम्बर ही बैठे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम एक हमारे दो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): काश्तकारों के हित में हमारी सीमा के ऊपर जिन लोगों ने इस देश की ...(व्यवधान) सीमा क्षेत्र के हमारे देश के पूर्व सैनिक और शहीदों ने हमारी जो आन-बान सीमा पर रखी है, उनके हजारों प्रकरण सन् 1973 से लगातार फाइलों के अंदर चक्कर लगा रहे थे। इस सरकार ने ऐसे सब लोगों को भूमि देने का काम कर दिया। इससे अच्छा पुण्य का कोई कार्य और हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं कांग्रेस के समय जो अच्छी भूमि थी, उसको गजट में प्रकाशित करवा दिया तो सैनिकों को भूमि कहां से दें? अच्छी किस्म की भूमि तो बची नहीं। सभापति महोदय, इस सरकार ने हमारे पूर्व सैनिकों व शहीदों का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए उस भूमि को वापस गजट से निकलवाकर और उन सैनिकों को आबंटित कर दी। सभापति महोदय, इसी तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जो हजारों की संख्या में काश्तकार आबंटन की पात्रता रखते हुए भी जैसे किसी को 15 एएए के अंदर खातेदारी मिल गयी, पटवारी ने रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया यानि अंकन नहीं किया तो पटवारियों ने जान-बूझकर रकबा राज की सूची में उस रकबे को पकड़कर काश्तकार का टाइटल होते हुए भी 13 ए में बेचने के लिए गजट में साया करवा दिया। ऐसे ही पोस्ट वाली है, बालिग पुत्रों की है, टी.सी. की भूमि है। हजारों की संख्या में धारा 13 ए के अंदर गजट में प्रकाशित करके और विशेष

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आबंटन में बेचने के लिए आरक्षित कर दी। बड़े ही खेद का विषय है कि कोई कलक्टर, एस डी एम और कोई चाहे प्रतिनिधि हो, उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि काश्तकार का टाइटल है। हम उसको बेदखल नहीं कर सकते, भूमि उसको देनी पड़ेगी फिर भी, यह क्या प्रथा थी? यहां प्रथा यह थी मैं रिकार्ड उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर दूं इस सचिवालय का, पूर्ववर्ती सरकार में कभी पांच फाइलें निकल गयीं, कभी दो फाइलें निकल गयीं। अप्रोच वाला व्यक्ति तो यहां फाइल निकलवाकर गजट से ले गया और जिस व्यक्ति की अप्रोच नहीं थी, जो यह भी नहीं जानता था कि गजट क्या बीमारी है, उसको यह पता ही नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को और माननीय राजस्व मंत्रीजी को, जो यहां बैठे हैं। मैंने पर्ची के माध्यम से यह विषय उठाया था कि इस तरह के हजारों प्रकरण हैं, उनको एकजाही एक कलम के साथ निकालने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसे-ऐसे गरीब लोग जिनके जूते फट गये, वर्षो से यहां चक्कर लगाते रहे, उनको न्याय नहीं मिला, परन्तु इस सरकार ने न्याय दिया है और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं, खिंचाई भी कर रखी है, परन्तु अभी तक भी धारा 13 ए के कुछ प्रकरण पेंडिंग हैं। मैं आपसे आशा करता हूं, मुख्य मंत्रीजी से आशा करता हूं कि अलाटमेंट नाम का पशु नहीं बचे आपके कार्यकाल में, ताकि आप पुनः दुबारा लौटकर आओ। मैं यह कहना चाहता हूं और मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने पहले प्लेटो पर लिखा हुआ देखा था समस्याओं का आखिरी पड़ाव। मैं माननीय मंत्री महोदय के पास में सचिवालय में जाता था तो कई बार मैं यह कहता था मंत्री महोदय, अभी तक समस्याओं का आखिरी पड़ाव नहीं है। तो इन्होंने कहा धैर्य रखो, वो मुख्य मंत्रीजी की यात्रा हमारे लिए इतनी लाभदायक रही कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वर्षो से इस हाउस में मैं सेम के लिए चिल्ला रहा हूं, उस सेम के लिए मुख्य मंत्रीजी ने वहां मौके पर घोषणा की, पहले भी पाँच करोड़ रुपये दिये। यह कोई मेरे एक विधान सभा क्षेत्र का मामला नहीं है, कई विधान सभा क्षेत्रों का मामला है। सरकारें पहले भी आयीं हैं, इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी के यह शब्द थे कि मैंने सोचा यह विधायक बोलने के लिए बोलते हैं विधान सभा में, कोई छोटी-मोटी सेम होगी, वहां जाने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि मैं तो सोचती थी कोई छोटी बीमारी है, यहां आने के बाद में पता लगा है कि पाँच करोड़ तो कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, यह समस्या बड़ी भयंकर है, इसका स्थायी समाधान करने के लिए विशेषज्ञों से राय

(श्री रामप्रताप कासनिया)

लेकर के और इसका स्थायी समाधान कराया जायेगा। वहां यह भी लोगों ने मांग की कि इस ड्रेन को, जो वर्तमान में बनी हुई है, जिसके काफी अच्छे परिणाम आ चुके हैं, इसको, मुख्य मंत्रीजी एक मीटर गहरा और कर दो तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मौके पर ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी इसलिए मैं बखान कर रहा हूं।

सभापति महोदय, लिस्ट बहुत लम्बी है। मोटे रूप से बारानी क्षेत्र के जो काश्तकार हैं, चाहे बरसिंगसर है ...

श्री सभापति: माननीय श्री जीतमलजी खांट। अंकित नहीं होगा आगे आप जो भी बोलोगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापति: मैं भी 27 साल तक मास्टर रहा हूं, आपको पूरे निर्दलियों को 16 मिनट का समय दिया है, 16 मिनट बोल चुके हो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री सभापति: बैठिये आप, विराजिये। माननीय जीतमलजी खांट।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ भ्रमित बातें यहां पर कहीं तो उसका मैं यह जवाब देना चाहूंगा।

इन्होंने कहा कि केन्द्र से जो पैसा मिलता है उसका राज्य सरकार समुचित उपयोग नहीं करती और उसमें से राशि शेष रहती है। हां, बहुत बढ़िया, आप आ गये। अब मैं इनको बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान का जो यह कार्यक्रम है यह 2001-02 में चालू हुआ, उसमें यहां राजस्थान में इनकी सरकार थी। उस समय इन्होंने 36.34 प्रतिशत पैसा खर्च किया और 2002-03 में इन्होंने 47.70 प्रतिशत पैसा खर्च किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और हमने 2003-04 में 102.43 प्रतिशत पैसा खर्च किया, 2004-05 में 115.04 प्रतिशत पैसा खर्च किया और 2005-06 में 98.69 प्रतिशत पैसा खर्च किया और 2006-07 में 106.19 प्रतिशत पैसा खर्च किया और अभी 2007.08, जनवरी तक के आंकड़े मेरे पास हैं, हम 82.14 प्रतिशत पैसा खर्च कर चुके हैं और दो महीने के पैसे बाकी हैं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक नया पैसा भी शेष नहीं रहेगा, निश्चित रूप से खर्च होगा परन्तु आपकी जब सरकार थी तो आपने केवल 36.34 प्रतिशत पैसा खर्च किया। धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूं, सब को जब इस तरह से समय मिलता है ...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 2003-04 में सरकार आपकी नहीं थी? आपने जो आंकड़े दिये उसके अन्दर आपने राज्य का अंश शामिल नहीं किया है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): शामिल किया है, मैं यही बता रहा हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं किया, आपने शामिल नहीं किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये, वो भी सुन लीजिए। हां, सुन लीजिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने कहा है केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं वो ही आंकड़े बता रहा हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह आंकड़ों की जिगलरी करके आप मूर्ख नहीं बना सकते हमारे को। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। सुन लीजिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपके राज का ...(व्यवधान) इसमें शामिल नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बात तो सुनिये, 2003-04 में ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): सभापति महोदय, मंत्रीजी यह भी दें ... (व्यवधान) दस परसेंट लीकेज की भी बात कही थी, वह हां है कि नहीं? वो भी बता दो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल गलत, मनगढ़न्त। (व्यवधान) मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। जिस पत्र में भी छपी है वो गलत छपी है। मेरा खण्डन भी आया है। मैंने खण्डन भी दे दिया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): श्रीमान, आप दूसरे दिन बांसवाड़ा में थे, बांसवाड़ा के अखबारों में आया था। (व्यवधान) आपने खण्डन क्यों नहीं किया?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने खण्डन कर दिया। ऐसा है, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अख़बार में आया बांसवाड़ा में ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अख़बार में गलत आया है, मनगढ़न्त आया है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आपने खण्डन क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह, माननीय मंत्रीजी, कांग्रेस का दुष्प्रचार था मतलब दस प्रतिशत कमीशन की जो बात है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इन्होंने कहा, अभी फिर भ्रमित करने की कोशिश की ...(व्यवधान) सुनिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अख़बार में आया है। (व्यवधान) माननीय विधायकजी, आप भी बी.जे.पी. के लिए तैयार हो, अख़बार में आया है और अख़बार में, दूसरे दिन श्रीमानजी वहीं बांसवाड़ा में थे, खण्डन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह कांग्रेस के लोगों ने, वहां पर पूरी जिला परिषद कांग्रेस की है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मनगढ़न्त आपने कहा है ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): कोई कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सबसे ज्यादा यही करते हैं, यह दस प्रतिशत कमीशन वाला सारा, जिला परिषद कांग्रेस की इसलिए कांग्रेस वालों को ही आपत्ति है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने अभी फिर भ्रमित करने की कोशिश की, यह तो केन्द्र का पैसा था, आपका राज्यांश का क्या हुआ? वह भी बता दूं। 2003-04 में पैसा मिला केन्द्र से 152.52 और हमारा राज्य का अंश था 65.55, कुल हुआ 218.7 और खर्चा किया 220.19 यानी 102.43 प्रतिशत ...(व्यवधान) आंकड़े नोट कर लीजिए। 2004-05 टोटल केन्द्र से पैसा मिला ...(व्यवधान) सुनिये आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपके इस सवाल के जवाब में आया हुआ है कि केन्द्र का अंश कितना था। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठिये, बैठिये। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं न, बैठिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप यह मान रहे हो, आप यह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): प्रूव करने की कोशिश नहीं है, आंकड़े हैं, कागज, आप ले लेना, मेरे पास हैं। में यही कह रहा हूं, बैठिये आप, जरा सुन लो। सुन तो लो, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह पढ़े-लिखे हुए हैं, आंकड़े सब रखते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप यह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि आप घनश्यामजी से ज्यादा ...(व्यवधान) जबकि आप हो नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब देखिये, 2004-05 में केन्द्र का अंश है 230 करोड़, राज्य का अंश है 105.43, टोटल 335.43 और व्यय हुआ 365.89 यानी 115.4 प्रतिशत। इसी प्रकार से 2005-06 केन्द्र का अंश 588.29 राज्य का अंश 166.37, कुल खर्चा हुआ 753.66 और इसका प्रतिशत हुआ 98.69, 2006-07 केन्द्र का अंश 751.38 राज्य का अंश 290.84 यानी 106.19 । आप कहां से आंकड़े लाये हो? भ्रमित कर रहे हो ...(व्यवधान) यह रहे आंकड़े, ले लेना। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय जीतमलजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): गलत आंकड़े देकर सदन को भ्रमित मत करिये, गुमराह करने की कोशिश मत करिये। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता रहेगी। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने सर्व शिक्षा अभियान में यदि पूरा पैसा खर्च किया है तो आप अपने सारे पेपर टेबल कर दो, मैं भी कर देता हूं, आपका ही दिया हुआ उत्तर है यह। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं भी टेबल कर दूंगा ... (व्यवधान) आपने यह भ्रमित किया है कि इसमें अभी तक 807 करोड़ रुपये कम खर्च हुए हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हो गये, हो गये, दोनों ही विद्वान हो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह आपका दिया हुआ उत्तर है, प्रश्न संख्या मैं आपको बताऊं, 349, कल लगा था दूसरे नम्बर पर, इसी में दिया है आपने यह। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं तो आपको पूछता हूं, सुनिये। (व्यवधान) 2001-02 में कितना पैसा आया सेण्टर से? यह तो आंकड़े हैं न आपके पास?

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आपने जवाब दे दिया, आप बैठिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बताइये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह 2004 के बाद की बात है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 2004 में कितने पैसे आये? (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, यह शिक्षा पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 2004 से लेकर आज तक आपने जो केन्द्र सरकार का हिस्सा आया और उस पर ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आपने मेरे को एक मिनट नहीं दी ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हमने खर्चा कर दिया। राज्य का अंश भी मिला, तो मैं यही कह रहा हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): और जो खर्चा आपने किया वो 807 करोड़ कम किया ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मेरे लिए तो कह दिया अंकित नहीं होगा और यह वाद-विवाद बीच-बीच में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप। चलिये, आप दोनों ने अपना-अपना विषय रख दिया है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मेरा एक विषय छूट गया, अगर इनको बार-बार अनुमति मिलती है ...

श्री सभापति: अगली बार समय देंगे आपको। माननीय जीतमलजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मेरा यही आग्रह है कि काश्तकारों की जो शीत लहर से फसल नष्ट हुई है उसके लिए यहां मैंने सुना है, चर्चा भी हुई है, में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष-विपक्ष स्टेट का हिस्सा स्टेट दे, 127 करोड़ दे दिये, और भी देने की बात कही है और मैं यह प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको नम्बर बढ़ाने हैं, वाह-वाही करानी है तो प्रति बीघा पांच हजार मुआवजा दिलवा दो नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव सर पर हैं, कुछ न कुछ तो देना आपकी मजबूरी है। अगर वाकई में ही कुछ देना चाहते हो पांच हजार रुपये बीघा, एक हर बार कहते हैं केन्द्र का पैसा, केन्द्र का पैसा, केन्द्र क्या खैरात दे रही है, हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है राजस्थान? हर बात पर कह दिया जाता है केन्द्र का पैसा, कोई खैरात नहीं है अलग से दी हुई है तो आंकड़े देकर बता दो कि कौन से मद में कितनी राजस्थान को आपने एक्स्ट्रा राशि दिलवाई? अब देखते हैं इससे बड़ी आपदा नहीं है राजस्थान पर, अगर उदार दिल करके केन्द्र सरकार खजाना खोल देगी किसानों के लिए तो तो हम मान जायेंगे।

श्री सभापति: आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, आपके सुझाव को अंकित कर लिया गया है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अंकित मेरे करने से नहीं आप पहुंचाओ वहां पर, प्रस्ताव पास करो सर्वसम्मति से, विरोध में मत रहो, एक राय होकर भेजो।

श्री सभापति: जीतमलजी, आपका भी सात मिनट का समय है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में जो अभिभाषण हुआ उसका मैं समर्थन करते हुए इस पवित्र सदन में माननीय पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने जो बहुमूल्य विचार रखे हैं, अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष हम सब मिलकर के राजस्थान की विधान सभा में हम लोग यहां पर चर्चा और परिचर्चा जब करते हैं तो राजस्थान के समग्र विकास के बारे में सभी लोग हम सबका, राजस्थान की जनता हमारा बेसब्री से इन्तजार करती है कि आखिर इस राजस्थान की विधान सभा में पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्माननीय विधायक मिल बैठकर के राजस्थान के समग्र विकास में कोई ऐसा नया कानून तैयार करेंगे, समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई न कोई उसका निदान करेंगे, चिन्तन मनन करेंगे लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि पिछले दो दिन से विधान सभा में इतना जबर्दस्त

(श्री जीतमल खांट)

गतिरोध चला जिसके परिणामस्वरूप पूरे राजस्थान की जनता के दिलो दिमाग में कितनी बड़ी ठेस पहुंची।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान की माननीय वसुन्धरा सरकार के समय में कई ऐसे लोक कल्याणकारी इस तरीके के कानून पारित होने से आज मैं यह कह सकता हूं कि हमारा उदयपुर सम्भाग जो राजस्थान का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जहां पर लम्बे समय से शिक्षा के अभाव में कई सारे हमारे विद्यार्थी साथी शिक्षक नहीं होने के कारण अंधकार की स्थिति में थे, पिछली बार राजस्थान की सरकार ने पूरे प्रदेश में आर पी एस सी की परीक्षा में कई हजारों छात्रों को सम्मिलित किया। जिसमें उदयपुर डिवीजन से कम से कम पन्द्रह से सोलह हजार आदिवासी छात्र और छात्राएं जो आर पी एस सी से चयनित होकर के अध्यापक के पद पर लगे। उस आदिवासी इलाके के अन्दर जहां लम्बे समय से शिक्षकों के अभाव में विद्यालय नदारद पड़े हुए थे, यह कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जो मिड-डे-मील भारत सरकार ने कुछ ही ब्लाक को चिन्हित किया था और मिड-डे-मील का कार्यक्रम कक्षा एक से लगाकर पांच तक था लेकिन इस सरकार ने मिड-डे-मील को एक से लगाकर आठ कक्षा तक के बालकों को मिड-डे-मील का लाभ देकर के उस आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़े वरदान के रूप में आपने यह योजना लागू की है।

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहूंगा कि आज उस सम्पूर्ण आदिवासी इलाके के अन्दर भारत सरकार से, जब एन डी ए की गवर्नमैंट थी और एन डी ए की गवर्नमैंट में भारत सरकार ने काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी, हमारे देश के महामहिम उप राष्ट्रपति तत्कालीन भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में काम के बदले अनाज योजना शुरू की और उस आदिवासी इलाके में काम के बदले अनाज योजना में लाखों क्विंटल गेहूं आया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार गेहूं विदेशों से खरीद रही है 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, आज उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं नहीं है, गेहूं का अभाव है। मैं चाहता हूं कि कम से कम राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी के माध्यम से राजस्थान में प्रथम स्थान पर हम चल रहे हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी के माध्यम से जिन मजदूरों को 35, 40, 45 रुपया दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी के माध्यम से जिन मजदूरों को काम पर लगाया

(श्री जीतमल खांट)

जाता है, भारत सरकार द्वारा 73 रुपये का प्रावधान है तो कम से कम उसमें साठ और सत्तर रुपया दिया जाय।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अभी बी.पी.एल. के बारे में बहुत जोर-शोर के साथ दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे, मैं कहना चाहता हूं बी.पी.एल. परिवार जैसा पिछली बार हमारे महामहिम के अभिभाषण में लिखा हुआ था कि वह गरीब आदमी जो जीवन के आखिरी क्षणों में अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, यानि कि आखिरी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि बी.पी.एल. के बारे में पिछली बार भारत सरकार ने जो कोटे को सीमित किया है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, आबू, प्रतापगढ़ जैसे इलाके के, आदिवासी को अगर समुचित लाभ देना है तो तेरह अंकों के आधार पर हम लोगों का कोटा सीमित करके आज हजारों आदिवासी जो भारत सरकार की खाद्यान्न सुविधाओं से वंचित हैं, मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि भारत सरकार राजस्थान सरकार यह एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके हम गरीबों को मिलने वाली जो सुविधा है उससे अपनी कन्नी काटने का प्रयास नहीं करें।

मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो हमारा मतदाता वार्ड पंच से लगाकर पार्लियामैंट के आदमी तक को वोट देने का काम करता है। आज हम राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं है भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम बी.पी.एल. परिवार से जो सुविधा जिनको मिल रही थी, आज हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, ऐसी महिलाएं और बूढे, माताएं और बहनें हमारे सामने आती हैं जिनकी आंखों में आंख डालकर हम देखते हैं तो दुःख भरी नजरों से देखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कोटा तेरह अंक लगाकर के सीमित कर दिया है राजस्थान सरकार भारत सरकार से पहल करे और कहे कि इस आदिवासी इलाके में जिनके घर में दो दिन की रोटी नहीं है, जिनको छप्पर नहीं है, जिनके बाल-बच्चों के पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी ए.पी.एल. के अन्दर घोषित कर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार हो, भारत के अन्दर यू पी ए सरकार हो, हम सबको मिलकर के ऐसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए और मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारी सर्वदलीय बैठक बुलाकर के भारत

(श्री जीतमल खांट)

सरकार को ज्ञापन दिया जाय ताकि लाखों लोग जो बी पी एल की सुविधा से वंचित हैं उनको कम से कम उसका लाभ मिले। मैं इसके साथ ही साथ यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे यहां पर मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूं लेकिन जो राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी राजस्थान और भारत सरकार का संयुक्त कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारा 73 रुपये देने का अधिकार बनता है। जब और किसी के लिए मैनेजमैंट नहीं बनता है तो उस मजदूर को मैनेजमैंट के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है।

मैं कहना चाहूंगा कि आज इस मौके पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के माध्यम से हजारों, लाखों लोगों को हम सौ दिन का रोजगार देकर के सौ दिन पूरे हो जाने के बाद में उस परिवार के लिए कोई सहारा नहीं रहता है, आज बड़े पैमाने पर उस आदिवासी बैल्ट का पलायन हो रहा है, मैं चाहूंगा कि सौ दिन की नहीं यह 365 दिन की रोजगार गारण्टी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए गुजरात पलायन करता है, इन हालातों से कम से कम वह बचे। और राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का सही लाभ उस व्यक्ति को मिल सके।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जिस सरकार में दाल, रोटी, सब्जी महंगी हो जाए वह सरकार हमारी सरकार नहीं कहलाती। जनता की सरकार नहीं कहलाती। आज हालात क्या हो गये हैं? गरीब आदमी रोजगार गारण्टी पर लगता है उसको दिन का 45 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया मिल रहा है और बाजार भाव के अन्दर अगर गेहूं खरीदने पड़ते हैं तो हजार रुपया, बारह सौ रुपया प्रति क्विंटल उसको गेहूं मिलता है। आज हालात बड़े भयंकर हैं। गरीब आदिवासी इलाके के हालात बड़े बेकार हैं। मैं कहना चाहता हूं जो दिल्ली के अन्दर यू.पी.ए. की सरकार है वहां पर आज हालात क्या हो गये? आज जो गेहूं अटल बिहारी वाजपेयीजी के जमाने में पौने दो रुपये किलो मिलता था आज उस गेहूं का भाव हमें आठ रुपये किलो मिल रहा है। दस रुपये किलो अनाज मिल रहा है। गरीब आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में किसी जमाने में काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी और एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने लाखों क्विंटल अनाज राजस्थान की धरती पर भेज करके गरीब आदमी को जिन्दा रखने का काम किया था। क्यों नहीं सरकार आज यह व्यवस्था लागू कर रही है? मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस तरीके की कल्याणकारी योजना चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सहायता मंत्रीजी यहां नहीं हैं पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयीजी, एन.डी.ए. की गवर्नमेंट

(श्री जीतमल खांट)

में कितना गेहूं आया था राजस्थान सरकार को? उस समय हमारे गहलोत साहब की सरकार थी। उस समय एन.डी.ए. की गवर्नमेंट में कितना गेहूं आया था यह स्पष्ट करना चाहिये और आज भारत सरकार हमको कितना गेहूं दे रही है राजस्थान सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये ताकि पता चले कि राजस्थान के अन्दर गरीब जनता के प्रति कौन कितना जिम्मेदार आदमी है? कौन पारदर्शी है? कौन संवेदनशील है? इस बात का पता चलना चाहिये।

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कह देना चाहूंगा कि सड़क के मामले में काफी कुछ आज गांव, ढाणी और मजरो में हम घूमते हैं। जहां भी जाओ हमें पी.एम.जी.वाई. सड़क देखने को मिलती है। प्रतिपक्ष में कई सारे बंधु बैठते हैं वह कहते हैं यह तो हमारे मनमोहनजी की योजना है। मैं माननीय सभापति महोदय, बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जार्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार नहीं बनती और यह प्रधानमंत्री सड़क योजना अगर लागू नहीं होती तो हम साठ साल और गुलाम थे। साठ साल और गुलाम रहते हम। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच है। यह जार्ज फर्नांडिस, अटल की जोड़ी का काम है कि हिन्दुस्तान के अन्दर गांव, ढाणी, मजरों में रहने वाले आदिवासी गरीब किसान और मजदूर, हमारी किसी बहन के डिलीवरी होती थी तो आदिवासी इलाके में हम खाट में उसको डाल करके माथे पर पकड़ उठा कर चार-चार, छह-छह किलोमीटर पी.एच.सी. तक पहुंचाने का काम हम करते थे। आज उसकी जगह पर उस पारदर्शी सरकार ने इस पूरे भारत देश और दुनिया में एक नया नक्शा बनाने का काम किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन.डी.ए. के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना आज लागू करके पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, किसी भी एरिये में चले जाओ सड़कों का जाल बिछ गया है तो मैं चाहता हूं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अन्दर यू.पी.ए. की सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारा यह जितना भी ढाई सौ की आबादी वाला इलाका है वह तो जुड़ जायेगा लेकिन इसके नीचे क्योंकि हमारा आदिवासी जितना इलाका है, कई सारे ढाणी और मजरे कई पहाड़ों और जंगलों के अन्दर पूरा फैला हुआ इलाका है। हमारी सरकार में बैठे हुए हमारे पी.ए.डी. मिनिस्टर हैं, कई सारे मंत्री, महानुभाव भी बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारा गांव पूरा-पूरा भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है तो उस गांव को किस तरीके से, जहां ढाई सौ की आबादी नहीं हो रही है, चूंकि वह गांव बहुत बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से। दूर-दूर पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं। इनको किस तरीके से एक दूसरे गांव को जोड़ा जाए इस पर भी विचार किया जाए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अंत में एक बात कह देना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि जिस तरीके से राजस्थान के इतिहास में शिक्षा के माध्यम से जो क्रान्ति आयी है, साठ साल से शिक्षा का एक बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा था पढ़ने-लिखने का ढिंढोरा लेकिन भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में जो साक्षरता का एक आन्दोलन चला और इस साक्षरता के आन्दोलन में इस हमारे आदिवासी बैल्ट उदयपुर सम्भाग के अन्दर जो क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज इसका ताजा उदाहरण है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के इलाके में किसी भी विद्यालय में चले जाएं छात्रों के अनुपात में छात्राओं का अनुपात भी देखने को मिलता है और हमारी सरकार की मुखिया हमारी मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन है कि छात्र-छात्राओं के अनुपात में छात्र भी बराबर हैं, छात्राएं भी बराबर हैं पर अध्यापकों की कितनी नियुक्ति, कृपया वह भी बता दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): वह भी मैं बता दूं। मेरे साथी हैं। मेरे साथी ने यह पूछा है मुझे। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी ने जो एक बात पूछी है मैं बड़े अच्छे ढंग से आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संयोग रहा है कि अशोकजी गहलोत जो 156 की मैजोरिटी ले करके जब यहां बैठते थे तो हम प्रतिपक्ष में यहां बैठते थे। मुझे आप यह बता दो कि पांच साल के दरम्यान अशोकजी के राज में अगर एक चपरासी भी भर्ती हुआ हो तो मुझे बता दीजिये आज आप खड़े होकर। अशोकजी के राज में मास्टर तो ठीक है अगर एक चपरासी की भी भर्ती हो जाती तो हम कहते कि वाकई आप लोगों ने कुछ काम किया लेकिन यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि राजस्थान की धरती पर एस.टी., एस.सी. को तो इस सरकार ने नौकरी दी है लेकिन पैराटीचर के नाम पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये। सुनिये आप। यह व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। आप बोलें पूर्व कांग्रेस पार्टी। कोई व्यक्ति की सरकार नहीं होती है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ठीक बात है मैं इसमें सुधार करुंगा। अशोकजी नेतृत्व था ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, वसुन्धराजी की सरकार, वसुन्धराजी की सरकार तो यह बेचारे मजबूर हैं इसलिए कह रहे हैं वरना पार्टी की सरकार है।

श्री सभापति: मैं उधर भी टोकूंगा चिन्ता न करें आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): यह बेचारा शब्द एक्सपंज करें आप। बेचारा शब्द। माननीय सभापति महोदय, बेचारा शब्द आपने जो काम में लिया उसको एक्सपंज कर दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय खान साहब, आपको बेचारे शब्द का मैं कह देना चाहूंगा कि बांसवाड़ा की तीन सीट हैं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इतना फर्क है माननीय सभापति महोदय, अशोकजी की सरकार थी उसमें मुख्य मंत्री नम्बर एक थे वह इसीलिए नाम लेना बहुत जरूरी है तो आपने जो नाम लिया उसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय खान साहब, बेचारे के बारे में मैं कह देना चाहूंगा कि जब 156 की सीट थीं तब भी बांसवाड़ा जिले की तीन सीट जनता दल की आती थी और दो सीट पूरे हिन्दुस्तान में 1952 से लगाकर जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से जनता दल मामा बालेश्वर दयाल के सामने जितने भी आ रहे हैं इसलिए बेचारे जैसी कोई बात नहीं है। हम आपको यह आगाह करना चाहते हैं कि हम आपके विचारों के साथ सहमत हों या नहीं हो लेकिन निश्चित रूप से आपके साथ हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पैराटीचर शब्द को हटाकर पूरे राजस्थान के युवाओं में एक नयी शक्ति का संचार किया है इस सरकार ने। इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस सरकार को। पूरा उदयपुर डिवीजन किसी जमाने में शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा कलंकित था। आने वाले समय में इस सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि हजारों में शिक्षकों का चयन होगा और इसी इलाके के लोगों का चयन होगा। आने वाले समय में इस इलाके में कोई ऐसा विद्यालय नहीं रहेगा, कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां पर बालक पढ़ने से वंचित होगा यह मुझे पूरी उम्मीद है।

मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अंत में इतनी ही बात कहूंगा कि राजस्थान सरकार की जो पारदर्शिता और संवेदनशीलता है निश्चित रूप से आने वाले समय में, कांग्रेस के लोगों को तो एक बात हो रही है। वागड़ी में एक कहावत है कि दूध का सेवता वह लटका हुआ है। यह कब टूटेगा और कब खाऊं, यह स्थिति है इनकी। इसलिए आने वाले समय में यह इंतजार करके बैठे हुए हैं कि निश्चित रूप से यह सेवता टूटेगा और खाने को मिलेगा। यह मुझे नहीं लगता है। यह मजबूत सेवता है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय सदस्य, सबने कसम खायी है सिर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर कह दें कि आपकी विधान सभा में सलूम्बर का नहीं है। शेरगढ़ और जौलाना जैसे स्कूलों के क्या हालात हैं यह आप बता दें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह टूटने वाला नहीं है आपको यह खाना नहीं मिलेगा। यह मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आपकी विधान सभा में सलूम्बर, शेरगढ़, गांगतलाई और जौलाना जैसे स्कूलों में क्या हालत है वह बता दें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र नहीं पूरे जिले के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि अभी नरेगा कि बात हुई। आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी के नरेगा के नाम से पार्टी की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन करके इन गरीबों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसकी तो आज दिन तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। आज जो 45 की रेट बतायी है आपने पर डे की, वह वकालत तो नहीं करते। जिसने जिंदगी में गेंती नहीं पकड़ी, ना कोई तगारी पकड़ी वह वहां आकर के ट्रेनिंग में, मजदूरी में जा रहा है। कहते हैं कि यह हमारा काम है, केन्द्र का है। केन्द्र का करके इन गरीबों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। आज यह स्थिति है कि हम हिमायती तो सब बनते हैं लेकिन जिस तरह से गरीब की परेशानी बढ़ रही है और मजदूरी में जिस तरह से राजनीति का काम किया जा रहा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, मैं सोचता हूं कि शायद ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। इसके बारे में सोचना चाहिए। आप और हम सब फील्ड में रहते हैं। इसका कोई जवाब है तो बतायें।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मंत्रीजी इसका जवाब है।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इतना समय हो गया ...(व्यवधान) इस प्रकार से क्या ट्रेनिंग देंगे ...(व्यवधान) वहां ट्रेनिंग देंगे मजदूरों को जो रात-दिन काम करते हैं ...(व्यवधान) उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): सरकार में बैठे आप हो ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, सरकार में बैठे आप हो। अधिकारियों को निर्देशित आप करो कि कौन ट्रेनिंग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है।

श्री सभापति: माननीय श्रवण कुमारजी ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दल भेजे जा रहे हैं और लोगों में कहा जा रहा है कि यह काम हमारा है ...(व्यवधान) इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्रवण कुमारजी, पिलानी ...(व्यवधान)

(अनुपस्थित)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है यह उचित नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): यह रहा तीन साल का रिकार्ड। जब आप खुद मंत्री थे तो जीरो पर्सेंट और चार पर्सेंट रिजल्ट दिया था वहां रोजगार गारण्टी में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्रवण कुमारजी ...(व्यवधान)

(अनुपस्थित)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह बात सामने आ रही है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रोजगार गारण्टी में मजदूरों को मजदूरी बहुत कम दी जा रही है। हमारे यहां, मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर सी.ओ. को तैनात करें क्योंकि दोनों जिलों में जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के हैं, वहां बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है। गरीबों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है और बांसवाड़ा की जिला परिषद में दो-तीन लोगों ने मिलकर 90 लाख का घोटाला किया है। आप उसकी जांच करायें, उसमें अपने आप सामने आ जायेगा कि किसने क्या किया है।

श्री सभापति: माननीय लालचंदजी मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, उसकी जांच हो रही है, उसके आदेश दे दिये हैं, जांच चल रही है ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): महावीरजी, एक तो आप हो जो मुख्यमंत्रीजी के ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अभिभाषण के समर्थन में मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह आदमी देखो, जनता दल का है, लेकिन कितना मक्खन लगाया ...(व्यवधान) और एक आप हो जो मुख्य मंत्री को उखाड़ना चाहते हो और इन्होंने कितना मक्खन लगाया है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मक्खन लगाने का काम आप करते हैं। हम तो स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का माद्दा रखते हैं इसलिए आप बिलकुल निश्चिंत हो जायें। यह मक्खन लगाने का काम आपने किया है ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मामा बालेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि आप बीजेपी की तारीफ करना, मामा बालेश्वर ने हमेशा बीजेपी की खिलाफत की थी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट दे देना लेकिन बीजेपी को मत देना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको जो समय दिया गया है उसमें आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का समय दें।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): कनकमलजी सिफारिश करने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा तीनों माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): जनता पार्टी बनाकर के कांग्रेस को उखाड़कर के फेंक दिया वह थे मामा बालेश्वर दयाल।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मामा ने कभी नहीं कहा था कि बीजेपी की तारीफ करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह तो आपका वोट लेने का तरीका है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब भी आप अपने चुनाव क्षेत्रों में जायें तो एक मंच बना लें और वहां पर बहस करें।

माननीय मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): महामहिम राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के सर्वोच्च सदन में आकर के अभिभाषण प्रस्तुत किया उसके लिए निश्चित रूप से हम सब उनके आभारी हैं। अभिभाषण के पक्ष और विपक्ष में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। आश्चर्य तो यह है कि विपक्ष में बैठने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं था। वह किसी भी सरकारी योजना की आलोचना नहीं कर पाये। उनके पास में मुद्दा है ही नहीं, केवल ऐसी अनर्गल बातें करते रहें जिनका इस अभिभाषण से कोई लेना-देना नहीं था। यह बात सही है कि यहां राजनीति करने के लिए वह आये हैं और राजनीति करने के लिए कुछ भी बोलना है, इसलिए सदन में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी है।

सभापति महोदय, हमारा आंकलन जनता भी करती है, चौपाल पर भी चर्चा होती है, जनता की चौपाल पर जो चर्चा होती है उसके बारे में भी यदि हमें थोड़ी जानकारी मिल जाये तो निश्चित रूप से एक लेखा-जोखा सामने आये। जब राजस्थान में वर्तमान मुख्य मंत्री श्रद्धेय वसुन्धराजी ने परिवर्तन यात्रा की थी और जब देखा कि राजस्थान में दयनीय हालत है, बहुत दुर्दशा है, बिजली का अभाव है, टूटी-फूटी सड़के हैं, चारों ओर अभाव ही अभाव है। जब जनता का दुःख-दर्द उन्होंने देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि यदि जनता आर्शीवाद देती है और यदि सत्ता हमें मिलती है तो हमें जनता के साथ न्याय करना चाहिए और विकास के काम करने चाहिए। उन्होंने जनता से कुछ वायदे किये, मुझे इस बात की खुशी है कि वसुन्धराजी ने जनता से जो वायदे किये थे उन वायदों को पूरा करने में बहुत कुछ सफलता उनको मिली है।

सभापति महोदय, आज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बांध इन सब के बारे में भी कई सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। यह बात बिलकुल सही है कि बिजली आज पर्याप्त उपलब्ध हो रही है। अनेक ग्रामों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। फीडर रिनोवेशन का काम भी हुआ है। मेरे क्षेत्र में किसानों को सात घंटे बिजली मिल रही है और किसी प्रकार की आपत्ति वहां पर नहीं है। यह प्रयास हम कर रहे हैं कि आठ घंटे बिजली मिले।

सभापति महोदय, सड़कों के मामले में भी हम जानते हैं कि राजस्थान की सरकार ने 16 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनायी हैं और 6 ग्राम प्रतिदिन जोड़े हैं। यह कांग्रेस की सरकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि

(श्री मदन राठौड़)

इतना भी विकास हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में भी बताया गया, चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है और यही सब कारण हैं कि हमने सब चुनाव जीते हैं।

सभापति महोदय, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद में हमें मालूम है कि लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा की 25 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का अवसर मिला था। यही नहीं उसके बाद में कई उप चुनाव भी हुए, उप चुनाव में भी इनको शिकस्त खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की उसमें जीत हुई। डेयरी के चुनाव हुए, वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने डेयरी के चुनाव नहीं करवाये थे। लगभग 25 वर्षों से इन्होंने चुनाव नहीं करवाये और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने चुनाव कराये तो डेयरी में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा मिला। डेयरी के चुनावों के बाद में कृषि उपज मंडी के चुनाव हुए, उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आर्शीवाद दिया है। जनता ने हममें विश्वास कायम किया है। यही नहीं, कापरेटिव के चुनाव हुए, आपने कापरेटिव के चुनाव कभी भी नहीं करवाये। कापरेटिव के चुनाव, मैं सोचता हूं कि 1952 में हुए थे उसके बाद में इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं की कि यह सहकारिता के चुनाव करा सकें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के चुनाव कराये और उसमें भी विजयश्री हासिल की। यही नहीं, जिला परिषदों के चुनाव हुए और जिला परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पंचायत समितियों के चुनाव कराये, पंचायत समितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यही नहीं नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किये और जनता का विश्वास जीता है इस बात को कोई नकार नहीं सकता है।

सभापति महोदय, आज यहां हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य राम-राम की रट लगा रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि आपको आज राम दिखाई दे रहा है। जरा जाकर के केन्द्र में बोलें, आपकी वहां सरकार है केन्द्र में, वह राम के बारे में क्या बोलती है। वह राम के बारे में कपोल-कल्पित बोल रही है और वह लिखकर के शपथ-पत्र दे रही है, राम सेतु के बारे में किस प्रकार का शपथ-पत्र दे रही है। यहां आप राम नाम की रट लगा रहे हो। आज वहां जाकर के

(श्री मदन राठौड़)

बोलें तो समझ में आयेगा। उनको भी या तो सबक मिल जायेगा या तो उनको सीख मिल जायेगी या आप उस पार्टी से निकाल दिये जाओगे क्योंकि उस पार्टी में राम के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां तो राम के लिए स्थान है। वहां पर तो राम-राम चिल्लाओगे तब जाकर के आपको पुनः टिकट मिलेगा, फिर आप चुनाव मैदान में उतर सकें। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। आपको राम का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य तो कल्पना कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, यह सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आप लेते रहो। आप 156 से 53 पर आ गये। अब पता नहीं क्या स्थिति आपकी बनने वाली है यह तो आप ही जानें। आपकी दुर्गति निश्चित रूप से होने वाली है। हमारी आठ दिसम्बर को रैली हुई थी। सभापति महोदय, मैं आपको विश्वासपूर्वक कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी भी नहीं हुई जितनी 8 दिसम्बर को यहां पर जयपुर में रैली हुई। आप लोग तो सपने देख रहे थे, आप लोग तो कल्पना कर रहे थे कि कितने लोग वहां पर आएंगे लेकिन रैली समाप्ति तक लोग आते रहे और यह ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस राजनीतिक रैली का सारा खर्चा सरकार ने किया। राजनीतिक रैली में भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को सारी गाड़ियां सरकार ने सप्लाई कीं। कौनसा एहसान कर रहे हो, सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हो और गर्व कर रहे हो, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। इस रैली में आपने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। गारण्टीड किया है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग, मैं रिकार्ड से साबित कर दूंगा कि आपने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): पार्टी ने पैसों की भरपाई की है। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इनको दर्द हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): रोडवेज की कितनी बसें लाई गई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा चुकाया? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जनता हमारे साथ है, जनता ने विश्वास दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकारी धन का दुरुपयोग करके बसों में बैठ कर आ गए, सरकारी धन का दुरुपयोग करके बसों में बैठ कर आ गए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): पैसों का भुगतान किया है, भुगतान, भुगतान। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारतीय जनता पार्टी का नाम कर दिया, राजस्थान दिवस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन कर दिया, शर्म करो कुछ तो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, हमारे पक्ष में रैली होती है और वह सफल होती है तो इनको लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? अभी जाट समाज की रैली हुई, मैं बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक रैली हुई है। इस प्रकार की रैली ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मदनजी राठौड़, आप अभिभाषण पर बोल रहे हैं या रैली पर बोल रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान में इससे पहले कभी आपने जाटों को याद नहीं किया। सूरजमलजी को कभी इतने वर्षों में याद किया? जातिगत द्वेष फैलाकर अलग-अलग जातियों को सरकार उलझा रही है। पूरे राजस्थान में जातिगत द्वेष फैला कर राजस्थान के जन-जीवन को बिगाड़ रही है सरकार। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से अभिभाषण पर बोल रहा हूं लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जनता में विश्वास कायम हुआ है। केवल यहां पर राजनीतिक भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल राजनीति के कारण से विरोध करने से कोई साबित होने वाला नहीं है। जनता विश्वास करती है तब जनता आती है। (व्यवधान) जनता का विश्वास हमने अर्जित किया है। (व्यवधान) विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने क्या बोला। आपने बोला कि नहीं बोला, वह मैं आपको वापस बताऊं? ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गुर्जरों और मीणाओं को लड़ा कर सरकार ने राजस्थान के वातावरण को दूषित कर दिया। जाटों का अलग सम्मेलन पहले

(श्री हरिमोहन शर्मा)

याद नहीं आया। सूरजमलजी इनको पहले याद नहीं आए, चुनाव के समय में याद आए हैं, पहले कभी राजपूत याद नहीं आए, अब राजपूत याद आए चुनाव के समय। फिर वादा कर दिया गुर्जरों से, सारे राजस्थान का वातावरण गंदा कर दिया, जातिगत द्वेष पैदा करके राजस्थान के वातावरण को बिगाड़ दिया इस सरकार ने, इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर आप मजबूती से कह दो सूरजमलजी के खिलाफ आप, सूरजमलजी महापुरुष नहीं थे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको इतने सालों तक याद नहीं आए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कह दो, कह दो, सूरजमलजी महापुरुष नहीं थे, कह दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राठौड़ साहब, आपको सूरजमलजी चार साल याद नहीं आए, चुनाव के साल में याद आए हैं।

श्री सभापति: जो भी माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनका अंकित नहीं किया जाए, जो भी माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनका एक शब्द भी अंकित नहीं किया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापति: जो भी बोल रहे हैं उनका अंकित नहीं हो रहा है। जो भी माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनका बिलकुल भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री सभापति: किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: बिना अनुमति के जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके सबके गले खराब हो रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ की स्थापना की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब हमने डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ की स्थापना की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपार जन समूह उसमें आया था। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ की स्थापना हमने की, यह हमारी उपलब्धि नहीं तो और क्या है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान) बिना अनुमति के जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, उनका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज आप बैठिए, मेरा, आपसे आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सभापति: मुझे अत्यन्त पीड़ा से कहना पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: माननीय मदनजी, आप बैठिए एक बार। मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार में जब किसी बड़े-बूढ़े आदमी की मृत्यु होगी तो हम यह नहीं बोलें कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलें गत्य है, आप लोग यह शपथ ले लें।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सभापति: हां, आप बैठिए। माननीय मदनजी राठौड़, आप बोलिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो विकास के काम किए, उसमें कितने अवार्ड मिले हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि शिक्षा और साक्षरता में अन्तरराष्ट्रीय यूनेस्को कंफ्यूशियस अवार्ड, 2006 प्राप्त हुआ, यह कोई कम बात नहीं है, काम करने पर वह अवार्ड मिलता है। यही नहीं 2006 में हनुमानगढ़ और 2007 में चित्तौड़गढ़ जिले को साक्षरता के क्षेत्र में सत्येन मित्रा पुरस्कार मिला है। यह भी कोई कम बात नहीं है, काम करने पर ही मिलता है। विद्युत के क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि सूरतगढ़ और कोटा तापीय विद्युत गृहों को गोल्डन शील्ड मिली। यह कोई कम बात नहीं है, यह काम किया है उसका मिला है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह को 2005-2006 में कांस्य शील्ड मिली। यही नहीं जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत किए गए सुधार कार्यों पर केन्द्र द्वारा राज्य को द्वितीय और अजमेर नगर परिषद को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में रबी आबियाना अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 2005-2006 में केन्द्र सरकार से एक करोड़ रुपये की नकद राशि इनाम में मिली है। यही नहीं ग्रामीण और शहरी आधारभूत विकास की श्रेणी में इण्डिया टेक फाउण्डेशन, मुम्बई द्वारा प्रदत्त इण्डिया टेक एक्सीलेंस अवार्ड हेतु प्रथम पुरस्कार राजस्थान सरकार को मिला है। सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 32 अवार्ड राजस्थान सरकार को मिले हैं। यही नहीं 2007-2008 में सफल जलग्रहण विकास कार्यक्रम के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पशु धन विकास के अन्तर्गत वीर्य बैंक को आई एस ओ 9001:2000 प्रमाण पत्र दिया गया। साठे ओपन वर्ल्ड मार्ट, नई दिल्ली में अप्रैल, 2006 में राज्य को दक्षिण एशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थान का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जून, 2007 में राज्य को लोकप्रिय पर्यटन स्थल श्रेणी में सी एन बी सी आवाज ने सम्मानित किया। यह सब कोई कम बात नहीं है। बिना मेहनत किए, यह सब अवार्ड नहीं मिल सकते।

शिप्रा पथ थाना अपने जयपुर में ही है, वह आपको मालूम होगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित हुआ। यही नहीं 2007 में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में अमेरिका एनीमल वेलफेयर इन्स्टीट्यूट ऑफ क्लार्क और बेवन लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड राजस्थान पुलिस को मिला। जुलाई, 2007 में सिंगापुर में क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और सनसनीखेज अपराध खुलासा करने के मामले में

(श्री मदन राठौड़)

एशिया पेसीफिस रिस्क कांफ्रेंस अवार्ड मिला और आपको मालूम होगा कि जयपुर में कितने अपहरण के काण्ड हुए। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें आप लोगों ने कितने करवाए लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि सारे के सारे जितने भी अपहरण काण्ड थे सब के सब में मुलजिम पकड़े गए, अपहर्ता सारे उनके चंगुल से छूटे।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपने क्या किया, थोड़ा इतिहास की जानकारी लेते तो केन्द्र सरकार आज आपस में लड़ रही है, अभी आज यहां पर कहा गया, कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने प्रशंसा की प्रधान मंत्री मन मोहन सिंहजी की, मैं यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री वह है, अब वे कैसे प्रधान मंत्री हैं, ब्रेक तो वामपंथियों के पास में हैं, ब्रेन करूणा निधि के पास में है और स्टीयरिंग सोनियाजी के पास में है, अब वहां पर यह हालात है, कैसे वे प्रधान मंत्रीजी हैं, कैसे विकास के काम कर रहे हैं, रोज टांग खिंचाई हो रही है। कल के अख़बार में था कि परमाणु संधि पर क्या निर्णय लेने वाले हैं, उनकी निर्णय लेने की स्थिति उनकी नहीं है, वे कहते हैं कि हम इस करार पर कायम हैं, वाम दल उनकी गिरेबान पकड़ कर खींचता है कि आप परमाणु करार से पीछे हट जाइए। यही नहीं, आज चौपाल पर चर्चा हो रही है कि कितने भाव बढ़ गये, पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी बार बढ़ा दिये। यदि आपमें थोड़ा बहुत भी कुछ माद्दा है तो केन्द्र सरकार को जाकर के बोलो कि ये पेट्रोल के और डीजल के दाम मत बढ़ाओ, गरीब आदमी पर मार पड़ रही है। कितने दालों में भाव बढ़ गये, खाद्य पदार्थों के भाव कितने बढ़ गये? और जिस समय एन.डी.ए. की सरकार थी तो दाल 9 रुपये किलो थी, आज 27 रुपये किलो बिक रही है, आज तो दाल रोटी भी महंगी हो गई है। थोड़ा विचार करो, आप में यदि कुछ है तो वहां जाकर के बोलो, और आप यहां ढिंढोरा पीट रहे हो और कह रहे हो कि हम पाले के मामले में निश्चित रूप से केन्द्र सरकार यह घोषणा करने वाले है, हिम्मत है तो कोई भी सदस्य बोल दे, बोलो, ये बैठे हैं सिरोही से आने वालो माननीय सदस्य, हिम्मत है तो बोल दो कि हम दो दिन में करवा कर लाएंगे। जब इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा और जब यह बात कही गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब मैं कुछ भी बोलता हूं देखता आपकी तरफ हूं तो इनको लगता है मेरे अंगुली कर रहे हैं, मैं इनके अंगुली नहीं कर रहा हूं, क्यों लड़ रहे हो आप? मुझे आपकी अंगुलि करने में कोई रूचि नहीं है,

(श्री मदन राठौड़)

वैसे मेरे पड़ौसी हो, पड़ौसी होने के नाते मैं कुछ लाड आपका कर भी सकता हूं लेकिन मैं करता नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको बुरा लगता है। यह लाड भी आपको सहन नहीं होता तो आप जानों हालांकि आपका ...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री सभापति: नहीं, इस अंगुली के प्रकरण पर जांच बैठा देंगे, चिंता नहीं करें आप। (व्यवधान) नहीं मैं अत्यन्त गम्भीरता से कह रहा हूं। जो भी आप बैठे हो, चिकित्सा मंत्री आप रहे हो इसलिए जरूर जांच बैठाएंगे अंगुली पर।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री सभापति: वह जांच में सारा विषय आ जाएगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, जनता की चौपाल पर यह भी चर्चा है कि पहले बिजली में 50 पैसे से 90 पैसे यह रेट किसने बढ़ाई, यह आम चर्चा है यानी 85 प्रतिशत दरें बढ़ाई इन्होंने। जब कांग्रेस का राज था तो 85 प्रतिशत दरें बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी को आम जनता धन्यवाद दे रही है कि इन्होंने कोई दरें नहीं बढ़ाई और अभी भी वादा किया है, बिजली मंत्रीजी ने सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में वादा किया है कि हम दरें नहीं बढ़ाएंगे, हम आम जनता पर किसी भी प्रकार का भार डालने वाले नहीं हैं लेकिन आप कहीं भी ऊपर कहने की स्थिति में नहीं हो, आज केन्द्र से भी बिजली के मामले में सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां से भी योजनाओं के माध्यम से, केन्द्रीय योजनाओं से जो सहयोग मिलना चाहिए, वह राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी राज्य सरकार खूब काम कर रही है, बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर होने की बात अभी भी कही, अभी मंत्रीजी ने कहा कि हम निश्चित रूप से अक्टूबर, नवम्बर में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जनता निश्चित रूप से यह देख करके फैसला कर रही है, इसी कारण से हमने सारे चुनाव जीते, आगे भी इसी कारण से हम चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे, आप कितने ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, आपके सपने सपने ही रह जाएंगे और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। आज आपके मदेरणाजी ने भी मांग रखी है, मदेरणाजी ने भी पत्र लिखा है कि लेकिन आप में से कोई कहने की स्थिति में नहीं है, उनका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, आप में भी आपस में फूट है, आप एक तो हो जाओ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए तो आपस में लड़ो मत, इसके लिए तो आपस में टांग खिंचाई मत

(श्री मदन राठौड़)

करो। यहां पर जब राजनीतिक विद्रोही भी एक हो जाते हैं और साथ में बैठ करके कोई चर्चा कर लेते हैं, आप अपनी पार्टी में तो एक हो जाओ, पार्टी में एक होकर के और दिल्ली में जाकर के यह बात कहो कि राजस्थान की जनता का यह दर्द है और इस दर्द को मिटाने के लिए आप राजस्थान के हितों में कुछ न कुछ घोषणाएं करो।

श्री सभापति: आप मदनजी, यह नेक सलाह क्यों दे रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, हमारी सत्ता पार्टी का पूरा का पूरा संगठन एकजुट है, इन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि आप किसके साथ हो, मैं यह कहना चाहूंगा कि जसवंत सिंहजी वसुधराजी के साथ हैं और वसुंधराजी अडवाणीजी के साथ हैं, हम सब एक हैं किसी भी प्रकार की हममें फूट नहीं है, यह आपके संस्कार हममें पड़ने वाले नहीं हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप इसकी चिंता मत करो, क्या होता है, जो फैसला होना है, होता रहेगा। आपने कितना किया, आपको मालूम है।

श्री सभापति: माननीय मदनजी राठौड़, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं आप केवल बजट पर बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बजट पर नहीं, साहब, अभिभाषण पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभिभाषण पर, बजट का समय आएगा तो निश्चित रूप से आपकी आज्ञा से बोलूंगा।

श्री सभापति: जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण है, उसी पर बोलें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यही निवेदन कर रहा हूं। ये विषय ऐसे लाते हैं तो इनको जवाब भी देना पड़ता है।

श्री सभापति: तो कोई आवश्यकता नहीं जवाब देने की, अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जवाब देना।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह तो हमने दे दिया, और भी दे देंगे। मैं यह निवेदन करूं पेयजल के मामले में अभी आज आपके सामने मंत्रीजी ने सवेरे ही जवाब दिया था कि 1440 करोड़ रुपये की और योजनाएं स्वीकृत की हैं। मैं मेरे जिले की बात बताता हूं। मेरे यहां से जवाई बांध से पानी लाने के लिए 396 करोड़ की योजनाएं इन्होंने स्वीकृत की हैं, आज तक नहीं कर पाये इतनी, केवल एक जिले में इस प्रकार की। मैं बांध के बारे में भी बताना चाहूंगा। बांध के मामले में कई माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि सेई बांध की जो मैंने एक छोटी सी योजना इस सदन में रखी थी और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरंत इस मेरी मांग को स्वीकार किया, देई बांध अपग्रेड आधा हुआ है और आज भी नदी चल रही है। सभापति महोदय, देई बांध से जवाई बांध में आज भी पानी आ रहा है। आज पाली जिले में यानी बरसात कब बंद हुई, आप विचार कीजिए लेकिन बरसात बंद होने के आज सात आठ महीने गुजर जाने के बाद भी आज भी एक पाली जिले में नदी चल रही है, ये कोई कम बात नहीं है। यह जब पूरा अप्रगेड हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे 9 महीने नदी चलेगी और हमारे इलाके के सारे किसान खुश हैं। यह जनता के चौपाल की बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। जब कांग्रेस का राज था तो कोई उपयोग नहीं किया। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने चार वर्षों में 10,216 लोगों को 35 करोड़ 50 लाख की निशुल्क दवाइयां मुख्य मंत्रीजी ने दिलवाई है और पहले आपके राज में क्या हुआ, केवल 3,090 लोगों को 14 करोड़ 31 लाख रुपये की दवाइयां आप दिलवा सके यानी कितनी तुलना करना चाहोगे? गरीबों का हमदर्द आप बनने का ढोंग रचते हो लेकिन वास्तव में उन लोगों की चिंता कौन कर रहा है? जरा इसके बारे में आप चिंतन करो। केवल विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है। एक सरकार ने पांच वर्ष में एक भी आयुर्वेद चिकित्सालय नहीं खोला, एक भी होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं खोला, एक भी यूनानी चिकित्सालय नहीं खोला जब कि वर्तमान सरकार ने चार वर्षों में 95 आयुर्वेद और 65 होम्योपैथी और 24 यूनानी चिकित्सालय खोले हैं, यह कोई कम बात नहीं है।

कृषि के क्षेत्र में आप क्या सुनना चाहेंगे, उद्यान के क्षेत्र में 6 गुना और बीज दुगुना यह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया

(श्री मदन राठौड़)

है। आपके समय में कोई इस मामले में विकास के काम नहीं हुए। 42 कृषि उपज मंडी समितियों का उन्नयन करवाया, यह कोई कम बात नहीं है। यह मेहनत करने से होता है, यह मेनेजमेंट करने से होता है, पैसा आएगा कहां से, खर्च कहां करना है, इसके बारे में जब बैठ करके चिंतन करते हैं और जब परिवार की रचना करते हैं तो परिवार का मुखिया जिस प्रकार से व्यवस्था करता है कि आमदनी इतनी है उसको किस ढंग से खर्च करना है, जरूरी कौन सा काम है, पहली प्राथमिकता कौन सी है, जिस प्रकार से परिवार का मुखिया चिंतन करता है, उसी प्रकार से राजस्थान के मुखिया ने भी चिंतन किया है और सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास किया है।

सभापति महोदय, कॉ-आपरेटिव के मामले में यह फसली ऋण की आज बात कर रहे थे लेकिन फसली ऋण भी दुगुना किया है, कांग्रेस के राज में जितना फसली ऋण किसानों को दिया गया था, उससे दुगुना फसली ऋण वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दीर्घकालीन ऋण की भी आप करोगे तो चार वर्ष में 990 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यह कोई कम बात नहीं है। सभापति महोदय, बिजली के मामले में उत्पादन और प्रसारण तंत्र को भी बहुत सुदृढ़ किया है। इसके बारे में भी और विचार करने की आवश्यकता है। जब कांग्रेस का राज था दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8460 करोड़ रुपये का प्रावधान था जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25606 करोड़ का प्रावधान रखा। यह कोई कम बात नहीं है। आप इसके बारे में जरा विचार तो करो। आलोचना करने से पहले जरा आंकड़े पढ़ लेते।

एक माननीय सदस्य ने जब यहां पर रखा तो मुझे तो आश्चर्य है कि हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बहुत विद्वान मानता हूं, बहुत विद्वान हैं, अच्छा बोलते भी हैं, सदन में जब चाहें तब बोल भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने आलोचना भी की तो क्या की कि पहले आपके अभिभाषण में 52 पेज थे, दूसरे में 52 पेज थे, अभी आपने 37 पेज ही क्यों कर दिये? अब कमाल हो गया, पेज गिनकर आलोचना करें तो आपकी मर्जी है, आपकी इस बुद्धिमानी पर भी मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि आज बिजली नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पाये। अब पढ़ नहीं पाये तो अंधेरे में पेज गिन लिये होंगे। पेज गिनकर यदि आप इस अभिभाषण की आलोचना करें ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पेज 37 है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, ये केवल पेज गिनकर आलोचना करना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, लेकिन उन पेजों में लिखा क्या है? उन पेजों में क्या लिखा है इसको पढ़ लेते तो आलोचना के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं होता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने आपका पूरा भाषण सुना है, आपने अपने पूरे भाषण में एक भी लब्ज अभिभाषण के विरोध में नहीं कहा, आप एक शब्द नहीं बोले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें एक मिनट में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, अब आपका आदेश हुआ है..

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अंग्रेजों के जमाने में पुलिस एक्ट बना हुआ था और वही एक्ट ये सब भोगते रहे और वहीं अंग्रेजों के जमाने का पुलिस का कानून ये लागू करते रहे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना एक अलग से कानून बनाया है, मॉडल एक्ट बनाया है, इसमें सफलता प्राप्त की है, यह कोई कम बात नहीं है। आप इसके बारे में चिन्तन ही नहीं कर पाये। पुलिस एक्ट अभी बना है और हिन्दुस्तान में 3 ही प्रांत हैं जो यह कानून बना पाये। यह राजस्थान की और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है।

पुलिस के मामले में मैं यह बताना चाहूंगा कि सारे थाने हमने कंप्यूटराइज्ड भी किये हैं, पुलिस थानों में कंप्यूटर भी लगे हैं। यही नहीं 41 थाने तो आईएसओ सर्टिफाइड हैं, उन्हें आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। यही नहीं हाडी रानी आर्म्ड बटालियन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है जिसमें महिला पुलिसकर्मी लगाएंगे। कई पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा 10 हजार पुलिसकर्मियों के लिए आवासगृह बनाये जाएंगे। उनकी किसी ने चिन्ता नहीं की। सभापति महोदय, पुलिसकर्मी कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं इसके बारे में कांग्रेस सरकार ने आज तक चिन्ता नहीं की, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री मदन राठौड़)

पहली बार उनकी चिन्ता की है कि उनके घर भी होने चाहिए। 10 हजार आवासगृहों का निर्माण कराने की इन्होंने घोषणा की है और इस प्रकार काम इन्होंने प्रारम्भ किया है।

सभापति महोदय, अब मुझे मालूम है कि आप दुबारा मेरी ओर देख रहे हैं तो समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय को निश्चित रूप से यहां उन्होंने अभिभाषण प्रस्तुत किया है इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष माननीय हेमारामजी चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बत्तीलालजी को बुला दो। एक मिनट में ही बोल देंगे यदि आपकी अनुमति हो तो।

श्री सभापति: मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आपने एक मिनट मांगा है, आपको ढाई मिनट देते हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): एक मिनट लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसमें जो सरकार के चार सालों का कार्यों का वर्णन किया है उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे समय कम दिया है "जो नहीं देखा, नहीं सुना और सो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत कीन्हु वर्णन कहु विधि न जाय।" जो न कभी सुना, न कभी देखा और न किसी के समझ में आता है ऐसा कार्य चार साल में कर दिखाया उसको मैं दैविक चमत्कार कहूं या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन कहूं या प्रशासनिक दक्षता कहूं या देवी-देवताओं का वरदान कहूं, मान्यवर, किसी के समझ में नहीं आ सकता कि जो राजस्थान चार साल पहले दिवालिया खजाना लेकर, असंतुष्ट कर्मचारी लेकर, बेरोजगारों की फौज लेकर और न जाने कितनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं ऐसा राजस्थान हमें मिला था।

(समय : 18.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर, आज से चार साल पहले जब हम सदन में बोलते थे या कहीं जाते थे तो लोग कहते थे कि दिवालिया राजस्थान के नागरिक हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता था, लेकिन आज माननीय वसुंधराजी के अथक

(श्री बत्तीलाल)

प्रयासों से खजाना भरा हुआ है और जिस राजस्थान को चरणों की धूल समझते थे उसको मान्यवर, आज माथे का चंदन बना दिया है। आज पूरे हिन्दुस्तान के अंदर हम गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हैं।

मान्यवर, ये लोग कहते हैं कि हमारी नीति बहुत अच्छी है और आपकी नीति कमजोर है, लेकिन चुनाव होने के बाद में, चार-पांच चुनाव हुए हैं किस तरह हिन्दुस्तान के लोगों ने इन कांग्रेस बंधुओं की नीतियों को नकार दिया है। मैं बिहार से गिनाऊं, बिहार से सीधा आप यूपी में आ जाएं, आप गुजरात पर चलिए, आप हिमाचल में चलिए।

मान्यवर, मैं आज से 15 दिन पहले, एक महीने पहले हिन्दुस्तान के दौरे पर निकला था। मुझे कहीं कांग्रेस बंधुओं की सरकार चश्मा लगाने से भी नहीं दिख पायी। गुजरात में इनका हाल देखिए। इन्होंने और तो कुछ किया जो किया, नीतियों का वर्णन किया, सारा काम किया। इनको बोलना बहुत अच्छा आता है। इन्होंने कह दिया कि यह तो मौत का सौदागर है। यह भी लोगों के समझ में आया। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी के बच्चों को ले आये और उनको वहां सड़कों पर रोड मार्च करवा दिया। राहुल गांधी को, प्रियंकाजी को और उनकी नेता सोनिया गांधी को। कहा कि आप नीतियों की तरफ क्या देखते हो, हमारे नेताओं की पेंट और बुशर्ट की क्रीज तो देखिए, इनका चिकना चेहरा देखिए। आप दया करो। जैसे मान्यवर, भिखारी जाते हैं और वे बच्चों को ले जाते हैं तो लोग यह समझते हैं कि ज्यादा दया आएगी, लेकिन कोई दया नहीं आयी और पहले से भी ज्यादा वोटों से लोगों ने जीता दिया। अब कैसे मानेंगे कि इनकी सही नीति है। हम इनकी नीतियों पर चढ़कर हिन्दुस्तान का विकास कर सकते हैं? इनकी नीतियों को लोगों ने बिलकुल नकार दिया है।

मान्यवर, एक समय हुआ करता था, सन् 1972 में मेरे पिताजी के साथ में सन् 1977 से मैं ही चुनाव लड़ता था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं आई थीं, उनके नाम पर ऐसा चुनाव हुआ कि ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप समय को पहचानिए। सीएलपी लीडर को बोलना है, मुख्य मंत्रीजी को बोलना है और आप इस तरह के भाषण करा रहे हो, यह कोई ठीक नहीं है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप सुनिए। मैं यह कहूंगा इनके पास कोई नीति नहीं है। इन्होंने हिन्दुस्तान को जिस तरह दिवालिया बनाया आप वैसे ही

(श्री बत्तीलाल)

राजस्थान का करेंगे। आपने दिवालिया शब्द को लेकर राज्य के साथ धोखा किया है, आपने एससी, एसटी के साथ धोखा किया है ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब यह समय आ गया है कि पहली बार के माननीय सदस्य इंदिराजी को सर्टिफिकेट देंगे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आप इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, एससी, एसटी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप सुनिए, मैं सब बोलूंगा। माननीय कल्ला साहब, आपने सरासर धोखा दिया है। आपने एससी, एसटी ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसन से निर्देश देना चाहिए कि जो सदन के मेम्बर नहीं हैं उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपने एक को नौकरी नहीं लगायी। आपने एक को नौकरी नहीं दी, आपने एक किलोमीटर सड़क नहीं बनायी। आपके हास्पिटल्स की क्या हालत थी? आप तो इकोनोमिक्स के विद्यार्थी रहे हो, मैं भी इकोनोमिक्स का विद्यार्थी हूं, आप यह बताएं आपने आधारभूत ढांचे को क्या मजबूत किया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): क्या इनको बिलकुल नष्ट कर दिया? आपने कितने किलोमीटर सड़क बनायी? आपने सड़कों के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया। अस्पतालों में आपने एक नर्स की नियुक्ति नहीं की। आपने शिक्षा में 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। मान्यवर, अपने आका को राज़ी करने के लिए इस तरह का स्लो पोइजन दिया जा रहा था कि आठवीं फेल लड़का दसवीं को पढ़ा रहा था। अब उससे कंपीटिशन में उम्मीद करें कि गरीब का लड़का आई ए एस बनेगा, आई पी एस बनेगा तो क्या वह बन सकता है? कितना बड़ा धोखा था हिन्दुस्तान के अंदर।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार को जो उस स्लो पोइजन को हटाकर ..(व्यवधान) वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह की पाठशालाओं को बंद करके उनको प्राइमरी पाठशालाओं में बदल दिया। आपका मास्टर कितने रुपये का था? आपका 1200 रुपये का मास्टर था और अस्थायी था। क्या उससे पढ़वाकर आप स्वर्णिम भारत की कल्पना कर सकते हो, अच्छी शिक्षा की कल्पना कर सकते हो? नहीं। हमने उन सारों को बंद किया।

(श्री बत्तीलाल)

हमारा मास्टर 8 हजार रुपये में पढ़ाता है। आपने एक भी बेरोजगार को नियुक्त किया हो तो बताएं। आपके नाम से सिर शर्म से झुक जाता है। आपको पता तब पड़ेगा जब आप गांव में जाओगे। आपकी यह तस्वीर लोगों के सामने आई है कि ये वो लोग हैं जो कहीं भी विकास नाम की कोई चीज नहीं, केवल वोट लेते हैं तो चकमों के आधार पर लेते हैं। सड़कों का आधार देखिए। आपने एक दिन में केवल 4 किलोमीटर सड़क बनाकर के एक गांव को जोड़ा, हम 6 गांवों को जोड़ रहे हैं और 18 किलोमीटर सड़क रोज बना रहे हैं। आपने पूरे पांच साल में...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वहां जाकर के यह कह आये कि सड़क की तारीफ करो इसका मतलब मुख्य मंत्रीजी की तारीफ आपको अच्छी नहीं लग रही थी। आप वहां जाकर के कह करके आये हो कि सड़क की तारीफ करो। यदि नहीं तो वहां क्या करने गये थे?

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मैं सब की कहूंगा। (व्यवधान) मैं सब की कहूंगा। आप सुनिये, आप बैठिये न, आप सुनिये न। आजाद साहब, आप सुनिये। आजाद साहब मैं और आप एक पार्टी में रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? पहले आप हमारी पार्टी में थे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): आजाद साहब, ये एम.ए., एलएल.बी. हैं और आर. जे. एस. की नौकरी छोड़कर के आये हैं नहीं तो अब तक चीफ जस्टिस बन जाते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): केस्टो मुखर्जी की फिल्म इण्डस्ट्री में कई दिन से जगह खाली पड़ी है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): जब देश आजाद हुआ था तब इन्होंने देश का विकास, तत्कालीन हमारे जो राजनैतिक कर्णधार थे माननीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लालजी नेहरू, उन्होंने रूस के आधार पर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारे देश का विकास शुरू किया। अब मान्यवर, क्या किया कि सार्वजनिक पूंजी के आधार पर, सार्वजनिक पूंजी की लागत के आधार पर प्राइवेट हाथों में कारखानों के लाइसेंस दिये गये और उससे हुआ क्या कि लाभ तो चला गया प्राइवेट लोगों के हाथ में और नुकसान लिखा गये गरीबों के नाम पर इसलिए गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपके राज में यह बताइये कि आपने वोट लिये एस सी, एस टी, अल्पसंख्यक के नाम पर। विकास के नाम पर कभी आपने वोट नहीं लिया। यह तो माननीय शेखावत साहब की सन् 1977 की सरकार थी जिसमें मैं एम एल ए था जब यह अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना चली थी। बाकी हम जानते ही नहीं थे कि गरीब क्या होता है और राज कैसे किया जाता है। (व्यवधान) अब कहोगे कि हम 40 साल नहीं कर सके तो आपने 4 साल में ऐसा क्या जादू कर दिया। तो मैं कहूंगा कि यह मेरी जेब में मोबाइल रखा हुआ है, जब यह अनपढ़ आदमी को दे दिया जाए कि इसको सुधार दो तो वो 40 साल में नहीं सुधारेगा और मिस्त्री एक मिनट में ठीक कर देगा। तो तुम्हे राज करना आता नहीं तो तुम देश को क्या आगे बढ़ाओगे। शेरशाह सूरी ने केवल मध्यकालीन भारत पर 5 साल शासन किया था और उस 5 साल में जो भूमि सुधार लागू किये, जो सड़कें बनाईं वो कानून आज भी उसी के आधार पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय शेखावत साहब का सपना था कि मैं राजस्थान को हिन्दुस्तान के अन्दर टाप पर पहुंचाऊंगा। वो बढ़ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये इतने लोग थे, बेइमान लोग थे, हमारी 1980 में सरकार फेल की, इन्होंने 1990 में हमारी सरकार फेल की।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): फिर बहुमत नहीं मिला। पहली बार बहुमत मिला है तो आज जो वसुंधराजी एक देवी चमत्कार के रूप में कार्य दिखा रही है....(व्यवधान) मैं ही खाली धन्यवाद नहीं देता, यह पूरे राजस्थान का बच्चा-बच्चा कह रहा है कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण आदमी नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): भगवान कृष्ण को भी लोग जब वो गायें चराते थे तो ग्वाला ही समझते थे लेकिन जब पहाड़ उठाया तब उनको पता लगा कि क्या है। तो जब वसुंधराजी के राज का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लोग हमसे प्रेरणा ले रहे हैं कि राज हो तो राजस्थान जैसा हो। लोग हमसे सूत्र सीखने आते हैं। यह गुजरात, यू. पी., हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, यह हम पहले जीते थे (व्यवधान) और सारी की सारी योजना हमसे सीख कर जा रहे हैं। हमसे सीख रहे हैं कि सड़क कैसे बनानी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजेन्द्रजी घबरा रहे हैं, यह राजेन्द्रजी की कुर्सी को खतरा हो रहा है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): ... यह तो क्या है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री सारी जातियों की हैं इसलिए युद्ध पर जाने से पहले जैसे हम देवी-देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं वैसे हम सूरजमल के वंशजों से आशीर्वाद ले रहे हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशजों से आशीर्वाद ले रहे हैं, हम अम्बेडकर के वंशजों से आशीर्वाद ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि उनके लोगों के लिए हमने कुछ किया है और उनका चमत्कार क्या कि आप आशीर्वाद दीजिये ताकि हम हमारे जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकें और राजस्थान को हिन्दुस्तान में ही क्या, विश्व में ऐसा चमका देंगे कि लोग हमसे शिक्षा लेते फिरें कि वास्तव में राजस्थान कोई है जो हमारी वीर प्रसूति वीर धरा है, इसको हम वास्तव में असली रूप देना चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी यह वीर प्रसूति वीर धरा हमेशा यशस्वी रहे, समर्थशाली बने और पुनः वसुंधराजी का राज हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हेमारामजी चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मावली से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आज बहस शुरू हुई। आप सब लोग उसके समर्थन में बोले, समर्थन में आपने बोलने में कोई कमी नहीं रखी और आप हमसे भी कह रहे हो कि आप भी समर्थन में बोलें तो इतने लोगों ने समर्थन में बोलकर के मुख्य मंत्रीजी की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी कि फिर भी पेट नहीं भरा और अब मेरे से भी करवाना चाहो तो मेरे ख्याल से तो पेट में जगह तो होनी नहीं चाहिए पर फिर भी खाली रह गया तो रह गया, अब मैं नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक बात है, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करेंगे और अपने दूसरे तरीके से बात करने वाले दूसरे तरीके से ही कहेंगे। महावीरजी, आपके जैनियों के साधु हैं चन्द्रप्रभूजी और ललित प्रभुजी। दोनों सगे भाई हैं। उनका बाड़मेर में प्रवास है। चन्द्रप्रभूजी ने एक कलेण्डर निकाला है, मेरी टेबल के ऊपर पडा है, सामने हमेशा पड़ा रहता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रशंसा एक मीठा जहर है, इसको जितना कम ग्रहण करो उतना ही अच्छा है बाकी तो करो जितना करने वाले पर है कि वो कितना ग्रहण करते हैं। पर मैं समझता हूं कि प्रशंसा ज्यादा तो काम की नहीं है पर

(श्री हेमाराम चौधरी)

करने वाले तो करेंगे क्योंकि उनको भी कुछ काम निकलवाने हैं इसलिए करने वालों को तो करनी ही पड़ेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपना धर्म निभाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपनी जगह से बोलो। चीफ व्हिफ होकर के आपको नियमों का पता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिफ से लोग सीखते हैं, आप उनको सिखाओ कि वो अपनी जगह से बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चीफ व्हिफ महोदय, मैं मेरा ही धर्म निभा रहा हूं क्योंकि प्रशंसा करने के लिए तो आपके पास फौज बहुत है, आप बहुमत में हो, हम तो थोड़े ही हैं। आपके पास फौज भी बहुत है और फौज में भी हल्ला ब्रिगेड अलग से और है। जैसे हांडी रानी की फौज मुख्य मंत्रीजी ने बनाई है वैसी ही आपके पास एक हल्ला ब्रिगेड फौज भी है जो बोलने नहीं देने का काम करती है। खैर, कोई बात नहीं है, उससे मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन की बात सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कही, मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी बतायेंगी। अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़ों सहित फीगर्स के साथ डिटेल में मुख्य मंत्रीजी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के बारे में बता दिया जो मेरे ख्याल से आप सब ने सुन लिया होगा। कितना राजस्थान की प्रदेश की जनता के ऊपर आपने कर्ज लाद दिया है। आज प्रदेश की जनता को आपने कर्ज में इस तरह से डुबो दिया कि वह कर्ज कभी वापस चुक नहीं सकता। यह प्रदेश कर्ज से कभी उबर नहीं सकता इतना कर्जा आपने लाद दिया। आप इतना कर्ज नहीं लेते और कर्ज लेने के बजाय आप संसाधन जुटाते। अपने स्वयं के प्रदेश के संसाधन जुटाकर के वित्तीय प्रबन्धन अच्छा करते तो मैं समझता हूं कि शायद ठीक रहता। आपने टैक्स भी लगाया वैट से जो भी आपने राज्यपाल के अभिभाषण में बताया है कि वेट से इतना रुपया हमने कर के रूप में वसूल किया है। वह तो ठीक हो गया है, आप टैक्स की बात कर रहे हो पर मैं दूसरा सुझाव बताता हूं। जरूरी थोड़े है कि टैक्स ही एक जरिया हो राजस्व प्राप्ति का। राजस्थान में राजस्व प्राप्ति का टैक्स ही एक जरिया नहीं है, और भी बहुत जरिये हैं जिनके द्वारा राजस्थान में राजस्व अर्जित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर आप रिफाइनरी लगाते

(श्री हेमाराम चौधरी)

बाड़मेर में तो कितना राजस्व आपको प्राप्त होता? क्या आपने इस मामले में एक्सरसाइज की? क्या आपने इस मामले को कभी देखा? रिफाइनरी के मामले में क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रिफाइनरी का कहीं कोई जिक्र किया, नाम लिया? इस वर्ष 2007-08 का बजट भाषण भी मुख्य मंत्रीजी ने दिया है उसमें भी क्या आपने रिफाइनरी की कोई बात कही, एक शब्द भी बोले? पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहती मुख्य मंत्री जी रिफाइनरी के बारे में। मुख्य मंत्रीजी की क्या दिक्कत है यह मेरे समझ में नहीं आती, आप उत्तर दें तब बता दें। कोई बात नहीं पर मैं कहूंगा तो सही, कह तो सकता हूं न। मुझे इसलिए पीड़ा है क्योंकि वह रिफाइनरी मेरे ही बाड़मेर जिले में लगने वाली है और उसका राजस्व मिलेगा तो उसका फायदा पूरे राजस्थान की जनता को होगा, लोगों को रोजगार मिलता। एक बात तो यह है कि रिफाइनरी के मामले में आपनी पार्टी के लोगों ने मीडिया को, अख़बार वालों को इतनी कमाई दी कि लाखों रुपया इनको मिल गया एड के जरिये। एड छपवाये कि अमुक रिफाइनरी लेकर के आये हैं, यह रिफाइनरी लगवाई है इसलिए इनका आभार, इनका हार्दिक अभिनन्दन, हार्दिक स्वागत। यह तो सब को मालूम है न? अख़बार कई महीनों तक भरे पड़े रहते थे कि रिफाइनरी लाने वाले का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन। अब वह हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन भी हो गया, मैं उसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद में भी हुआ तो कुछ नहीं है तो फिर स्वागत और अभिनन्दन से क्या मिला, बताओ? एड दिया, उन अख़बार वालों को पैसा लोगों ने दिया, लोग तो देंगे ही क्योंकि सत्ता में रहने वालों से उनको काम निकलवाना होता है तो लोग पैसा खर्च करते हैं एड देने के लिए, मुझे मालूम है इस तरह से होता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। (व्यवधान) इसलिए रिफाइनरी आपको लगानी चाहिए। मुझे पता है, आप हमेशा हम यहां पर कोई भी मामला उठायेंगे तो आपके पास में एक ही रट, फिक्स, तयशुदा है, जैसे टेपरिकार्डर में फिट कर रखा हो, केन्द्र का। केन्द्र के बारे में बोलने के अलावा आपके पास उसका कोई उपाय नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई बात नहीं है। आप कहते हो कि केन्द्र सरकार ने हमको सहयोग नहीं दिया। क्या केन्द्र सरकार ने आपको सहयोग नहीं दिया? आपसे रियायतें मांगी थी। ओ.एन.जी.सी. और कैयर्न ने आपसे कहा था कि हमें यह रियायतें दीजिये या जो कुछ आपने उनसे बात की, उन्होंने क्या रियायतें आपसे मांगी थीं, आप

(श्री हेमाराम चौधरी)
क्या रियायतें दे सकते थे, क्या नहीं दे सकते थे, कहां आपका गतिरोध हुआ, कहां तक बात आई, कहां तक नहीं आई, क्या हुआ, कब-कब मीटिंग हुई, क्या हुआ। कुछ आपको सदन को बताना चाहिए था। मैं यह समझता हूं कि इस ओर सरकार इंट्रेस्टेड नहीं है, मुख्य मंत्रीजी इंट्रेस्टेड नहीं हैं, इस वजह से यह रिफाइनरी नहीं लग पाई और इसका जो राजस्व का घाटा हुआ, उसको हमारे प्रदेश की जनता आज भी भुगत रही है, पीड़ित है। आप कह रहे हैं कि टैक्स, वह टैक्स ही एक जरिया नहीं है, और भी बहुत जरिये हैं। आज आप राजस्थान के अन्दर बातें करते हैं रोजगार लोगों को देने की, विकास की, राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात, सेज लाने की, उद्योग लगाने की, अच्छी बात है कि आप सेज स्थापित करें। सेज के मामले में मेरे से ज्यादा घनश्यामजी वाकिफ भी हैं और पीडित भी हैं, इनके क्षेत्र की जनता भी पीड़ित हैं। इसी तरह से उद्योग लगाने की बात है।

आज गांवों में मैं देखता हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि भारत सरकार की योजना है, शत-प्रतिशत पैसा भारत सरकार से आता है। आप कहते हैं कि भारत सरकार कोई खैरात नहीं बांटती, कोई निहाल नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। है, जिसकी है, मैं कब कहता हूं कि खैरात बांटती है, पर है उनकी, यह तो कहना पड़ेगा तो आपकी भारत सरकार की पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क है, इस...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके टाइम में नहीं थी क्या योजना?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं नहीं, हमारे समय में नहीं थी। हमारे समय में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष हमने शुरू की थी। अब आप कह रहे हैं कि हमने उसमें 9 से 13 कर दिया तो आखिर शुरू तो हमने की थी तो इस तरह से जिसकी सरकार थी, वह कोई योजना शुरू करती है, फिर बाद में आगे की सरकार आती है, वह उसमें अगर कुछ काम करती है या ज्यादा ठीक करती है तो उसका बखान आपने भी तो किया ना। हमारा नाम लेते ही आपने कहा कि आपने शुरू की। मुझे पता है किसने शुरू की, किसने नहीं की? शुरू तो आपने की लेकिन जब आपकी केन्द्र में सरकार एन.डी.ए. की, उसने शुरू की लेकिन उस समय हमारे को, राजस्थान को कितना पैसा मिला पी.एम.जी.एस.वाई. में और अब जब से हमारी केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार बनी है, इस पी.एम.जी.एस.वाई. में कितना पैसा मिला है, उसकी भी तो आप

(श्री हेमाराम चौधरी)

तुलना कर लो ना, देखो ना, आप कहते हो कि हम ले आये। जो आप केन्द्र से ले आते हो पैसा, बड़ी राशि है, वह तो आप अपनी उपलब्धि मानते हो, वह तो आप अपनी होशियारी मानते हो, उसके लिए तो कहते हो कि हम बहुत होशियार हैं, कलेवर हैं, होशियारी से केन्द्र से इतना पैसा इसमें ले आये, इतना पैसा इसमें ले आये, इसमें इतना पैसा लाये, इसमें यह कर दिया, वह कर दिया, यह कर दिया और जब आपको वहां से कोई पैसा किसी बात से, कोई कारण से नहीं मिला तो आप केन्द्र सरकार को गाली दो, यह भी कोई सही बात है क्या? फिर पैसा वह दे और उसका श्रेय आप लेना चाहें इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सेज लाने और उद्योग लगाने की बात है, पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए अगर सरकारी जमीन नहीं है, रास्ता नहीं है, कटान रास्ता नहीं है या लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं या कोई कहे कि मेरे सड़क की जरूरत नहीं है, मेरे खेत के अन्दर से सड़क निकल रही है, उस सड़क से सड़क निकलेगी तो मैं क्यों जमीन दूं मेरी? मैं तो जमीन नहीं दूं। मैं दूं नहीं, मेरे खेत से सड़क शुरू नहीं होगी। आगे वाले को फिर भी जरूरत होगी, पीड़ा होगी तो वह दे देगा कि सड़क उसके खेत से निकलेगी लेकिन जिसके खेत के अन्दर से सड़क है, वह शुरू होने ही नहीं देता है तो सड़क निकल ही नहीं सकती। ऐसी राजस्थान के अन्दर हजारों सड़कें हैं जो जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से शुरू नहीं हो पा रही हैं तो वह सड़कें जैसे मान लो, वह सड़क शुरू नहीं होती है तो क्या आप उसकी जमीन एक्वायर करके, मुआवजा देकर उसकी जमीन लेकर सड़क का काम शुरू नहीं करवा सकते? वह तो आप करवा नहीं सकते क्योंकि वह जनहित का काम है, आम जनता के काम आएगी वह सड़क बनेगी तो और मुआवजे के तौर पर कितना पैसा देना पड़ेगा? आपके पास कितना पैसा है, ग्रामीण विकास का पैसा आता है, जिसमें बेशुमार पैसा है और उसमें से आप भुगतान कर दीजिये। किसी में से कर दीजिये, आप पंचायत को कह दीजिये, वह दे देगी। आप जन सहयोग के लिए कहिये, बहुत सी जगह लोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप उसके लिए तो जमीन एक्वायर करते नहीं हैं, आज दिन तक आपने यदि कहीं किया हो तो बताओ आप और स्टेट फण्ड से तो आप एक पैसा ही देना नहीं चाहते और जब भारत सरकार इतने पैसे दे रही है इस सड़क निर्माण के लिए तो थोड़ा सा आप अगर स्टेट फण्ड से कम्पन्सेशन के रूप में देकर, जमीन लेकर सड़क बनवाने में सहयोग कर दो तो आपको इसमें कहां तकलीफ होती है? यह अगर

(श्री हेमाराम चौधरी)
कर देते हो तो यह कौनसा खराब काम है। जिसकी जगह है, वह तो आप करते नहीं हो। सेज आज जो स्थापित कर रहे हो, जो उद्योग लगा रहे हैं, वह सेज कौन लगा रहा है, यह उद्योग लगाने वाले कौन लोग हैं? क्या हेमाराम जैसे लोग हैं? क्या यह राजस्थान के किसान लोग हैं? ये केपिटलिस्ट हैं, ये पूंजीपति हैं। ये केपिटलिस्ट, पूंजीपति यहां उद्योग लगाने के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि राजस्थान का विकास करने का उन्होंने जिम्मा लिया है। उनको बहुत चिंता है राजस्थान के विकास की, इसलिए कोई नहीं आता है। वह अपने मुनाफे के लिए आते हैं, धंधा करने के लिए यहां आते हैं और वह यहां चाहते हैं कि जमीन एक साथ हजारों बीघा एक्वायर कर लें, हमको दे दो, आपके यहां किस तरह से कैसे क्या होता है, वह तो आप करने वाले जानो लेकिन जिस तरह से जितनी हजारों बीघा जमीन है, जहां 100 बीघा की जमीन की जरूरत है, वहां आप 1000 बीघा जमीन उसको एक्वायर करके दे रहे हो। आने वाले समय में जमीन की कीमत बढ़ेगी और आप उसकी कोड़ियों के भाव में जमीन ले रहे हो।

हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर कपूरड़ी कोयले के नाम से कोयला जहां निकले, अभी आपको जैसे जहां-जहां जरूरत हो, लेते जाओ। आप एक साथ हजारों बीघा क्यों जमीन ले रहे हो? अभी इतनी कोई जमीन की जरूरत नहीं है। आपके सांसद महोदय खुद इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन आप उनकी परवाह नहीं कर रही हैं। वे एम.पी. हैं कि नहीं? एम.पी. और मुख्य मंत्रीजी के साथ 36 का आंकड़ा है इसलिए उस वजह से भी हो सकता है पर करने वाले ये हैं। यह केवल कपूरड़ी का, बाड़मेर जिले का मामला नहीं है, यह पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश में किसी जमाने में इस जमीन का मालिक राजा-महाराजा, जागीरदार हुआ करते थे। किसान का जमीन से कोई लेना-देना नहीं था। किसान तो फसल पैदा करता था और उसमें से राजा-महाराजाओं और जागीरदारों को हिस्सा देता था, बंटाई देता था परन्तु देश आजाद हुआ, कांग्रेस का शासन आया, लैण्ड रिफोर्म्स कायम किया, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के जरिये किसान को खेत का मालिक बनाया। उस समय भी बात चलती थी, लोगों को विश्वास होता ही नहीं था कि ऐसा क्या कभी हो सकता है क्या, जमीन का मालिक जो जमीन को बो रहा है, वह बुवाई कर रहा है, वह उसका मालिक हो जाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और यह हकीकत में हो गया। होने के बाद में उनको विश्वास हुआ कि हम जमीन

(श्री हेमाराम चौधरी)

के मालिक हो गये। मालिक तो कोई और हुआ करते थे, यूं बंटाई किस बात की देते थे...(व्यवधान) मैं आसन की ओर देखकर बोलूंगा। नहीं-नहीं, मेरा राठौड़ साहब से थोड़ा विशेष प्रेम है इसलिए मैं राठौड़ साहब की तरफ देखकर बोल रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमने तो किसानों को जमीन का मालिक बनाया और आपने जब आपकी सरकार आई तो आते ही आपने किसानों से उस जमीन को हड़पने का काम शुरू कर दिया, उन किसानों को सड़क पर लाकर पटक दिया। आज उनके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, रहने को एक इंच जमीन आप किसी के पास नहीं छोड़ोगे तो वह किसान कहां जायेगा, किससे कहेगा? आपसे कहेगा तो आप तो उसको उजाड़ ही रहे हो। वह आखिर पुकार किससे करे, यहां कोई है नहीं जिसके पास जाकर वह पुकार करे क्योंकि उसकी हत्या तो आप ही कर रहे हो, अब वह आपसे पुकार करेगा तो आप क्या सुनवाई करोगे? करने वालों की करोगे क्या? यह हालत हो रही है किसान की पूरे प्रदेश में। आज सब किसानों की हालत ऐसी नहीं है। बहुत कम किसान की हुई हैं, संख्या हजारों तो आज भी है। वह सोच रहे हैं शायद ली जिसकी ली, मेरी तो नहीं ली, इसलिए मैं क्यों चिंता करूं। आज मेरी जमीन नहीं ली, मैं चिंता क्यों करूं लेकिन अगर यह रवैया चलता रहा, यह इस तरह से अधिग्रहण का अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास ले रखा है, इसका उपयोग करते रहे और इन केपिटलिस्ट को, पूंजीपति को यह जमीन एक्वायर कर-करके कौड़ियों के भाव में उनको देते रहे तो एक दिन सारे किसानों के पास की जमीन छिन जाएगी, किसानों के पास कुछ नहीं रहेगा, फिर किसान की वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो आजादी से पहले थी इसलिए बहुत गम्भीर मामला है, सोचने का मामला है, आप सोचें, करें, जैसा आप उचित समझें। मैंने तो अपनी बात कही, जो आपने मुझे कहने का अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए अभी मुख्य मंत्री बिराज रही हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

आप रोजगार की बात करते हैं। इतने हजार लोगों को रोजगार मिल जायेगा। इण्डस्ट्री में लग जायेंगे क्योंकि कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। वह प्राइवेट किस तरह से कैसे कितना वेतन देते होंगे, किस तरह से कहां उनका शोषण करते होंगे, जहां जरूरत है रखते हैं, नहीं तो लात ठोककर निकाल देते हैं। प्राइवेट सैक्टर में अपन ही जानते हैं कैसे होता है, प्राइवेट सैक्टर में तो ठीक काम है तो राज की नौकरी में कौन आएगा। थर्ड ग्रेड, चपरासी बनने के

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिए राज की नौकरी चाहता है। वह कहता है कि राज की नौकरी मिल जाये चाहे चपरासी की हो भले ही, लेकिन राज की नौकरी मिलनी चाहिए। राज की नौकरी मिलती है तो प्राइवेट में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं चाहता, वह तो अब आखिर में आदमी के पास में कुछ है ही नहीं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किये पैसा प्राप्त नहीं होता, यह पेट पापी है, रोटी मांगता है इसलिए उसको कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप सोचें, कहने का मतलब उन किसानों की कीमत पर यह जो आप सेज, यह इण्डस्ट्रीज लगाने के नाम पर, यह बिजली घर लगाने के नाम पर, कोयले के नाम पर, पता नहीं इतने सारे अलग-अलग नाम से आप जमीनें ले रहे हैं तो मैं इसको ठीक नहीं समझता, इसलिए आप इस पर विचार करें, गौर करें और कहीं लेकर दो तो जरूरत है उतनी दो। बाड़मेर की कपूरड़ी का तो मुझे मालूम है, उसको सौ बीघा जमीन की जरूरत है तो वहां हजार बीघा लेकर के उसको दे रहे हैं, वह लेकर के पहले अपने कब्जे कर लेते हैं फिर बाद में उसकी जमीनों के आसमान पर भाव चले जाते हैं। अभी महंगाई की बात कर रहे थे। जमीनों के भाव तो नहीं बढ़े, जमीन के भाव कितने बढ़े, किस कदर बढ़े, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो, 90 बी में भी तो महंगाई बढ़ी है न। जब सारे ही महंगाई बढ़ी है तो उसमें भी महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, लोग कहते हैं कि 90 बी की आज रेट बहुत ज्यादा हो गई है। वह तो हो गई, जब महंगाई बढ़ेगी तो उसमें भी पैसा बढ़ेगा, जानते हैं आप 90 बी का मतलब। तो इसलिए जो है भूमि घोटाला, इस पर सोचें, मेरा आपसे निवेदन है, खासकर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। रिफाइनरी की बात मैंने आपसे कही, उसके बारे में भी सोच लें। पावर की भी बात कही, बिजली की भी बात कही। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली की बहुत अच्छी तरह से सारी बात कही। आपने राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में बहुत सारे मुद्दों पर तुलनात्मक विवरण दिया है पिछले पांच सालों में कांग्रेस ने क्या किया, गत सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने और हमारी सरकार ने चार साल में क्या किया। पर आपने इस बिजली वाले में तुलनात्मक नहीं दिया आंकड़ा, इसमें भी आप जरा थोड़ा दे देते तो ठीक रहता न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कुछ किया ही नहीं तो क्या देते।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने क्या किया और क्या नहीं किया, तो आपको देना था न इसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आठ साल में कुछ किया ही नहीं, क्या देते।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहता हूं, यही तो कहता हूं, हमने कुछ नहीं किया तो आपको देना था न, आपको सांप क्यों सूंघ गया। यह जो आपने कम्पेरेटिव स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया इस पावर पर, आपने क्यों नहीं यह स्टेटमेंट दिया। आपने इसलिए स्टेटमेंट कम्पेरेटिव पावर का इसमें नहीं दिया कि हमारे टाइम में पांच साल में जितना विद्युत का उत्पादन हुआ न, आप नहीं कर पाये उतना। इसलिए जिस मामले में आप पिछड़ रहे हैं उसमें तो आप कम्पेरिटिवली बात कहो तो आपके गले पड़ जाय और जिस मामले में आपको केन्द्र से राशि मिली, शेयर जो केन्द्र का ज्यादा, हर योजना में बढ़ा है यह तो, आप कहो तो मैं बता सकता हूं हर आंकड़े देकर के आज, हर विभाग के, आप कहो तो हर विभाग के बता दूं, नहीं तो मैं आपको मिसाल के तौर पर एक-दो विभाग की बता दूं। तो पैसा जब केन्द्र से हर योजना में कम्पेरेटिवली पहले के, हर साल बढ़ा है, हर साल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से जब पैसा बढ़ा तो आपने तुलना कर दी पिछले पांच साल की और इन चार सालों की, इसके सिवाय इसमें कुछ है ही नहीं। एक ही चीज मैंने तो देखी कि पिछले पांच साल में यह और इन चार सालों में यह। यह तो आपको पता है कि इन वर्षों में किस प्रकार से केन्द्र से आपको मदद मिलती है उस मदद की वजह से, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ले लो, कोई ले लो, आज आप देख लो, यह ''Financial assistance provided by the Ministry of Rural Development under its programmes to the States." स्टेट्स में राजस्थान स्टेट है, अब राजस्थान स्टेट का ले लो, डिपार्टमेंट आफ रूरल डवलपमेंट, अब इसका 2000-01, इसमें आपके मिले हैं 703 करोड़, 2001-02 में मिले हैं 660 करोड़, 2002-03 में मिले हैं 843 करोड़, 2003-04 में मिले हैं 866 करोड़, 2004-05 में मिले हैं 1451 करोड़, 2005-06 में मिले हैं 1629 करोड़, 2006-07 में मिले हैं 3102 करोड़ और 2007-08 में 3283 करोड़। यह फीगर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं हर साल?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राज्य का अंशदान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई अंशदान नहीं है इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्या है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, कोई इसमें अंशदान नहीं है। यह मैंने आपको कहा न, "Financial assistance provided by the Ministry of Rural Development under its programmes to the States." प्रोग्रामों का आप कहो तो, मैंने यह तो टोटल बताये, प्रोग्राम सारे इसमें दे रखे हैं, किस-किस में, अलग-अलग है, हर प्रोग्राम का अलग-अलग किसी में दे रहे हैं, इतना तो फिर कहूंगा तो यह तो फिर अभी आप, थोड़ी देर में मेरे को कहनी बहुत बाते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह टेबल करना पड़ सकता है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां-हां, लो। टेबल करने में क्या दिक्कत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार का है यह।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, अभी कर देता हूं, एकाध बात थोड़ी और कह दूं, नहीं तो मैं अभी टेबल कर दूं। टेबल में इसमें आपको क्या तकलीफ है।

श्री उपाध्यक्ष: यह है, इनके पास है जी। यह तो है इनके पास।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह है न। मैं आपको कोट करके कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आया कहां से, यह देखना पड़ेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आया कहां से, कोई एकाध हमारे भी पल्ले पड़ सकता है न। अब सारे आप अपने कब्जे, लाक करके रखे हैं क्या आपने। यह भारत सरकार से, वहां से, दिल्ली से ले आये। यहां तो मुझे पता है, आपने सबने मामला बड़ा काबू कर रखा है, लाक कर रखा है, मिलना बड़ा मुश्किल है, मुझे भी पता है। (व्यवधान) नहीं-नहीं, इनका काम पक्का है, इसलिए इन्होंने सोचा कि यह कहां से हो गया, कैसे हो गया, क्या कबाड़ा हो गया...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): इसीलिए आप इनकी तरफ ही देख रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसीलिए मैं। नहीं-नहीं, आप योजनाओं की बात करते हैं...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह घनश्याम तिवाड़ीजी ने दे दिया चुपचाप इनको।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब योजनाओं की बात करते हैं आप कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना चौदह हजार करोड़ की हो गई, पहले तो चार हजार करोड़ की थी, आप राठौड़ साहब बोल रहे थे, तो यह योजनाओं में भी तो केन्द्र का पैसा बढ़ा है न हर साल। यह इसमें आप देख लो, आपको नाइन्थ प्लान, टैंथ प्लान, इलेवंथ प्लान और 2007-08 में जो है, इसमें स्टेट का नहीं है, पूरे सभी स्टेटों का है पर इसमें अपने स्टेट का भी उस हिसाब से बढ़ा है, जो बढ़ा है। मैं आप कह दो तो बता दूं। 1997-98 के अंदर 8365 करोड़ ही है, 8365 करोड़ और अब हो गया है 41060 करोड़। इकतालीस हजार साठ करोड़।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लाख होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लाख होगा, लो पढ़ो, इनको दिखाओ। लाख होगा, लाख कर दो, हजार कर दो, कुछ भी करो, मर्जी आये जो मान लो। तो मेरे कहने का मतलब है, यह बताया है मैंने आपको कि इस तरह से है। कोई भी विभाग ले लो आप, मेडिकल ले लो, सर्वशिक्षा का इन्होंने आपको बता दिया कि किस तरह से पैसा इन्क्रीज हुआ, कितना पैसा कहां क्या मिला है। सर्वशिक्षा का पैसा मिला उसमें तो आपने अध्यापकों की कुछ भर्ती की पर पैसा तो सब सर्वशिक्षा का ही है। कुछ आपने स्कूलें भी खोलीं, काम किया, पैसा था। पर आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, आपने जो बजट पेश किया, मुख्य मंत्रीजी ने, उस बजट में सर्वशिक्षा अभियान का भी जिक्र किया पर उसमें एक और मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में बात कही है और उस टाइम मुझे याद है, मुख्य मंत्रीजी ने उसको रिपीट किया, दो बार, तीन बार और राठौड़ साहब ने कहा कि दोबारा कहो साहब, दोबारा कहो, यों उछल कर कहा, मैं देख रहा था, उछल कर कहा, कि यह दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ो कि सैकण्डरी स्कूलों का मामला आया है, कि कितनी खुली सैकण्डरी, कितनी सैकण्डरी स्कूलें, यूं, तब कहा कि पन्द्रह सौ, एक हजार पांच सौ यानि एक हजार पांच सौ सैकण्डरी स्कूल खुलेंगे, छह सौ सीनियर सैकण्डरी खुलेंगे। यह आपका बजट भाषण पडा है, मैं कोई मेरे मन से थोड़े ही कह रहा हूं। इसमें से आपने कितने सैकण्डरी स्कूल खोले, कितने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले, आप बता दें। क्यों नहीं खोलीं? क्योंकि सर्वशिक्षा का पैसा आपने सोचा कि इसमें आ जायेगा, इसलिए ठोक दो घोषणा, पैसा आने वाला है केन्द्र से। बहुत

(श्री हेमाराम चौधरी)

सारी योजनाएं, अभी केन्द्र का बजट आयेगा उससे पहले आपको कुछ चीजों का मालूम पड़ गया, तो आप अपने बजट में सब उनको डाल देंगे, फिर होगा तो होगा, नहीं होगा तो इसमें कोई नाक नहीं कटा, तो अब के कौन काटेगा। नाक इसमें ही कोई आपका काट नहीं सका तो उसमें भी कोई काट नहीं सकता। तो कहने का मतलब, इस तरह से आप होशियारी करके बजट पेश करो और लोगों को गुमराह करो और लोगों ने सोचा कि पन्द्रह सौ स्कूलें खुलेंगी तो एक एम.एल.ए. को कितनी स्कूलें मिलेंगी, सैकण्डरी स्कूलें, आपने बहुत तैयारी भी की, खैर, नहीं खुलीं, कोई बात नहीं, ठीक हुआ, क्योंकि हमारे कहने से नहीं खोलते हैं तो हमने देखा कि नहीं खुली तो चलने दो, क्या करें, आखिर आप उसमें यह भेदभाव करो। तो कहने का मतलब आप बजट भाषण में जो बात कहो, कम से कम वह करनी चाहिए न आपको। नहीं करना है आपको तो कहना नहीं चाहिए। आप कह देते हो फिर करते नहीं हो, क्या यह अच्छी बात है? एजुकेशन के मामले में यह है। अब आप सर्वशिक्षा की बात लें, उसमें तो आपका कुछ है नहीं, सीनियर सैकण्डरी आपने कुछ खोलीं तो खोलीं, पता नहीं खोलीं तो खोलीं, बंद कर दी, उनका भी क्या हुआ पर सैकण्डरी नहीं खोलीं। तो कहने का मतलब है कि यह शिक्षा का हाल है। आपने सर्वशिक्षा में मीडिल स्कूल भी खोले, प्राइमरी भी खोलीं। आज गांवों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था का हाल क्या है। आप स्कूलें खोल कर राज़ी हो जाते हैं, लोग भी राज़ी होते हैं, मैं मानता हूं, खुश होते हैं, हम भी खुलवा कर खुश होते हैं कि हमने स्कूलें खुलवा दीं। लेकिन स्कूलें खोल कर, उन गांवों में रहने वाले किसानों के बच्चों के साथ जो अपन अन्याय कर रहे हैं न, उसको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। यह अन्याय नहीं कर रहे हैं तो क्या है आप मेरे बताइए? आप स्कूल जिस टाइम खोलते हो उसमें स्टाफ की व्यवस्था करते हो क्या? आप जब स्टाफ की व्यवस्था करे नहीं तो फिर स्कूल खाली आदेश से ही क्रमोन्नत हो गई और उन बच्चों की पढ़ाई ठीक-ठाक हो गई। सब काम हो गया तो मुझे कुछ नहीं कहना। मगर स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए। आज इंगलिश का टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर नहीं है, विज्ञान का अध्यापक नहीं है बताओ उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आप कहें तो मैं ऐसी हज़ारों स्कूलों का नाम आपको लाकर दे सकता हूं। बाड़मेर ज़िले की सैकड़ों स्कूलें बता सकता हूं। जिनमें सबजेक्ट टीचर ही नहीं है। आज से नहीं जब से क्रमोन्नत हुई है, बरसों से नहीं है। थोड़े टाइम के लिए तो बात अलग है। अब आप भेजो तो कहां से

(श्री हेमाराम चौधरी)

भेजो, जब है ही नहीं आपके पास? इधर से उधर हो तो क्या है, इधर से कपड़ा फट गया, इधर से सीलो तो ईधर फट जाएगा, उधर से सीलो तो उधर से फट जाएगा, आखिर कपड़े की लम्बाई तो उतनी ही है ना, तो कहने का मतलब यह है कि हालात बहुत खराब हैं। आप तो स्कूल खोलकर खुश हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मेरा भी तो फर्ज बनता है कि गांवों की स्थिति जो मैं देखता हूं कि गांवों में जब जाता हूं लोग कहते हैं साहब यह स्कूल तो आपने खुलवा दी, इसमें मास्टर तो कोई है ही नहीं, इन टाबरा न पढ़ावे कौन? ये बेचारे दूसरे धंधे ही करते, खेती करते, कहीं मजदूरी करके पेट भरते, खौटी होवे, इनको एक आखर पढ़ाने वाला स्कूल में है ही नहीं, कहीं कोई बदमाशी हो रही है क्या स्कूल में? क्योंकि देखने वाला है ही नहीं तो स्कूल कैसे चलेगी? यह हाल है स्कूलों का, आपको तो अच्छा लगता होगा, कुल मिलाकर स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। आप इसे सुधारो, खाली राज्यपाल भाषण दिला दो, मुख्य मंत्रीजी भाषण सुंदर-सुंदर दे दें, आजकल बहुत सुंदर-सुंदर टाइप भी होते हैं। कैसे काम चले? अध्यापकों की व्यवस्था करे। मोटी कालेज है, महाविद्यालय है, टेक्नीकल एजूकेशन है, हायर एजूकेशन है इनकी बात तो अलग है उन तक तो कौन पहुंचे? माने तो यही कोई मास्टर गांव में भी क, ख, ग पढ़ाने वाला नहीं है, हमारे टाबर तो वहीं बर्बाद हो गये हैं, शहरों में रहने वालें जो हैं, पूंजी पर, जमीन पर कब्जा कर लेवे, जमीन हड़प ले, शहरों में टाबरों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा-पढ़ू लेवे, वे आगे जाए पर मेरा टाबर तो यही किसी काम का नहीं है। अगर आप टाइम रहते नहीं सतर्क होते तो बहुत खराब हाल है। मैं आपको कहूं, आप कहेंगे? क्या कहा मैंने, क्या कहा, क्या नहीं कहा उसमें क्यों जावें? उस बात के लिए हम चर्चा करने के वास्ते, बहस करने के वास्ते थोड़े ही बैठे हैं, इकट्ठा थोड़े ही हुए हैं। पांच साल हो गये मुझे शुरू-शुरू में हमने भी आपको नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा आप राज में आये, आते ही कोई जादू की छड़ी तो आपके पास में नहीं है, जादू का डण्डा है नहीं एकदम ही आप ठीक कर दो, पर मान लो चार साल तो हो गए। अब आपका भी टाइम थोड़े ही रहा है। ''थोड़ी गिन घणी गई आ भी छिन-छिन जाए'' इन वास्ते टाइम बहुत थोड़ा रहा है ध्यान दीजिए इसमें। ''घणी गिन थोड़ी रही, थोड़ा भी छिन-छिन जाए, एक घड़ी के कारण लाज गमाय होवे'' इन वास्ते कहने का मतलब है कि आप करो ठीक है, शिक्षा के मामले में, आप कहें वह विभाग बता दूं, हर विभाग में, शिक्षा का क्या हाल है, मेडिकल का क्या हाल है? गांवों में डाक्टर नहीं है। बड़े हॉस्पिटल को छोड़ें आप, आज एसएमएस हास्पिटल है, दूसरा है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

शहरों में फिर भी है, प्राइवेट भी है, वहां तो प्राइवेट स्कूलें भी हैं। गांवों में प्राइवेट स्कूले भी तो नहीं है, प्राइवेट स्कूल है तो गांव में गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल की फीस जो है वह थोड़े ही वहन कर सकता है। ऐसे तो सारा प्राइवेटाइजेशन ही कर दो जिनके पास दो रुपया हो वह बच्चे को दाखिल करा देगा, स्कूल में पढ़ा देगा, बकरियां तो चराय न, ऐसा ही रह जाए। तो इन वास्ते आप ध्यान दें।

मेडिकल साइड में भी हाल बहुत खराब है। मैंने आपको ग्रामीण विकास की बात बताई। राठौड़ साहब ने कहा यह कहां से लाये? वह मेडिकल का आपका ही प्रश्न का जवाब है। इसे भी कोट कर दूं तो क्या फर्क पड़ा? कहीं से भी लाया, आपने दिया है आप देख लो। हर साल कितना बढ़ा, आप देखो कितनी योजनाओं में केन्द्र का पैसा मिलता है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह जो अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन में तो आप देखो आपका पैसा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन में 6 अरब 66 करोड़ 86 लाख और परिवार कल्याण में है 3 अरब 96 करोड़ 25 लाख। इस तरह कुल आपके यह हैं 11 अरब 52 करोड़ तो इस तरह से पैसा बढ़ा है। शुरू में तो बहुत कम था, शुरू में पैसा जो है वह बहुत कम था। वह पैसा 05-06 में कम था, 06-07 में उससे बढ़ा फिर 07-08 में और बढ़ा तो हर साल में यह मतलब मैं तीन सालों का फिगर इसलिए बता रहा हूं कि हर साल पैसा केन्द्र से अधिक मिल रहा है। किस अनुपात में मिल रहा है? उसी अनुपात में आपने बताया कि इसमें हमारी इतनी प्रतिशत उपलब्धि है, इसमें हमारी इतनी प्रतिशत उपलब्धि ज्यादा है, किसी में 100 प्रतिशत से ऊपर, किसी में 32 प्रतिशत, कितनी में कितनी प्रतिशत, यह जो आपने बताया, आपकी उपलब्धि है जो प्रतिशत बढ़ा है, यह बढ़ा तो केन्द्र सरकार के पैसों से है, मानों या नहीं मानो यह तो आपकी मर्जी है, मनाना तो हमारे हाथ में है, जानते तो आप भी हो, जानते हम भी हैं, सभी जानते हैं। आपकी खुद की योजनाएं कौनसी हैं? आपकी तो कोई योजनाएं नहीं हैं इसमें बता दीजिए। इस अभिभाषण में बताइए आपकी कितनी स्वयं की योजनाएं हैं? जिसमें पूरा का पूरा पैसा आपका स्टेट का हो? केन्द्र से एक पैसे का लेना-देना नहीं हो, अलग से कोई हो, आपके कौनसी है? गुरु गोलवलकर है, उसमें भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

30 प्रतिशत पब्लिक कोंट्रीब्यूशन है पूरा उसमें भी आपका नहीं है, केन्द्र का नहीं तो पब्लिक से ही लो पर पूरा आपका नहीं है। दीनदयाल को ले लीजिए। उसमें भी पब्लिक कोंट्रीब्यूशन है। गुरु गोलवलकर में आपका जो काम हो रहा है...

एक माननीय सदस्य: माननीय नेता प्रतिपक्ष एक बार तो आसन को सम्बोधित कर दो, एक बार।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको ही समझाना है, आपको ही बताना है, आपका कहीं दिमाग इधर से रह जाए बाकी आप देखो, नहीं सुनना है तो मैं इधर ही सुना दूं...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्रीजी ने यह किताब क्यों लगा रखी है इतनी देर से? वह हमारे शादी होती है जब दूल्हा के रूमाल लगा देते हैं मुंह पर कुछ बोले नहीं, रोज थोड़े ही हंसी आएगी आपको जो आप किताब लगाकर हंस रही हो, आज तो आपने जब से बैठी हो तब से ही लगा रखी है यह बराबर, इसके पीछे भी कोई राज है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी यह सोच रही हैं कि हंसने पर यह नाराज नहीं हो, मैं नाराज नहीं हूं, आज नाराज नहीं होऊंगा, आज आप हंसोगी तो भी नाराज नहीं होऊंगा। अब मैंने भी तय कर लिया है नाराज होने से कोई काम चलने वाला नहीं है इसलिए कहना तो पड़ेगा। मेरे बात समझ में आ गई, अब यह मामला तो इस ढंग से तो कोई इसका हल निकलने वाला नहीं है अब तो हिम्मत ही रखनी पड़ेगी। अब तो हिम्मत रखकर के ही सुनाना पड़ेगा। मैं आपका आभारी हूं आज सुन रहे हो आप, मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरी बात सुन तो रहे हो और फिर करो या नहीं करो, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं सुनना ही पड़ेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर मेरी बात आप सुन रहे हो इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट कर दूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि गांवों में मैंने आपको स्कूलों की हालत बताई, आपको मैंने मेडिकल में बताया। गांवों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो इलाज कौन करेगा ...(व्यवधान) आज

(श्री हेमाराम चौधरी)

गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की बात है तो पीने के पानी के ऊपर पैसा तो बहुत खर्च हुआ है यह बात सही है। पैसों के आंकड़े आप देखकर के इसमें हमको बता रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। मेरा इसमें विवाद है ही नहीं, इसमें आपने पैसा खर्च होने के जो भी आंकड़े, जितने भी दिये हैं उसको मैं चेलेंज कर ही नहीं रहा हूं, वह तो ठीक है लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट क्या आया? इसका कुछ रिजल्ट भी है कि नहीं है, कोई परिणाम भी इसका आया कि नहीं आया? गांवों में आपने पानी की करोड़ों रुपये की कई-कई योजनाएं, करोड़ों रुपये की योजनाएं, पाइप लाइनें लगा दी, होदिए बना दिये, ट्यूबवैल भी कई जगह खोदे, बिजली के कनेक्शन ले लिए पर पानी का पता ही नहीं बताइए। अगर पानी का पता ही नहीं है तो उसमें वह पैसा धूल में गया और काम क्या आया? उन पैसों का क्या हुआ? आखिर मतलब क्या निकला? मैं तो कहता हूं आप पानी पहुंचा सके तो पानी की योजना बनाकर के नहीं हो तो उलटी गालियां देते हैं, लोग नहीं होता तब तक तो मांग करते हैं, हो जाने के बाद जब व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो और ज्यादा सुनना पड़ता है। लोग हमारे को कहते हैं कि साहब आप कहते नहीं हो तो मैं कहता हूं कि हम तो कहने में कोई कमी नहीं रखते हैं पर आगे सुनने वाला भी तो कोई हो, जब सुनने वाला नहीं है तो क्या करें, कैसे करें, किसको सुनाएं पर मुझे खुशी है कि आज सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं। अब अमल तो जैसा इनको...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अमल का नाम मत लेना।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज सुनाने का मुझे मौका जब मिल गया तो मैं आपको सुना रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी आप मानेंगे नहीं आपने परिवर्तन यात्रा की। आप मुख्य मंत्री हैं आपके मंत्री बहुत हैं आपके जो कुछ भी नहीं है वार्ड पंच भी नहीं है उनको भी आपने जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया। मंत्रियों के बराबर वो भी हैं, वो भी कौन से कम हुए जिले के प्रभारी मंत्री से भी भारी। कई मंत्री बेचारे प्रभारी ही नहीं हैं तो मतलब कहने का इनको भेजकर कहीं गांवों में पता तो करवाओ कि आपके पीने के पानी की योजनाएं हैं उनका हाल क्या है, कैसा है, वो ठीक है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पीने के पानी की पाइप लाइन है, सुबह वो कह रहे थे कि दूषित जल से लोगों की मौतें हुईं तो मैंने कहा कि यहां दूषित जल

(श्री हेमाराम चौधरी)

है, इसका मतलब है, इन शहर वालों से हम गांव वाले ज्यादा सुखी हैं कम से कम हम हमारी कैसे भी व्यवस्था करें जैसे हमारे बड़े चलाते थे पानी की कोई न कोई व्यवस्था अपनी करते ही हैं पानी की वजह से कोई आदमी मरता थोड़े ही है। कष्ट पाता है, दुःख पाता है राज की तरफ से व्यवस्था हो जाए तो आराम पाता है पर मरता तो नहीं है। हमारे वहां की पाइप लाइनें सूखी पड़ी हैं, होदियां सूखी पड़ी हैं, पानी जा नहीं रहा है, ट्यूबवैल खराब हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। कितने वर्ष हो गये आप देखें कितनी योजनाएं बना दीं उसमें हम भी शामिल हैं कभी नियुक्तियां तो इस पीएचईडी में की नहीं मतलब आप वहां लाइनें ही लगाते जाओ, जीएलआर ही बनाते जाओ, ट्यूबवैल बनाओ, उसको कोई चलाने वाला भी तो चाहिए कि नहीं? कोई जादू का डंडा है क्या? आपके पास, उससे चला रहे हो क्या? जादू के डंडे से तो योजनाएं चलेगी नहीं। आप हिसाब लगा लें, पता कर लें। पूर्व में कुछ लोगों को कई वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। कई वर्ष पहले हमारे टाइम की बात है अब है जो है पांच सौ रुपये में आदमी गांव में पंचायत रखती है पानी की योजना को चलाने के लिए पांच सौ रुपये में एक आदमी रखा हुआ है, जनता जल योजना में पांच सौ रुपये में वो भी कई वर्षों से काम कर रहा है। मुझे याद है कि दस-बारह वर्ष से भी ज्यादा हो गये। दस वर्ष से कम तो नहीं है और अभी भी उसके पांच सौ रुपये ही हैं। अब पांच सौ रुपये में एक आदमी से आप उम्मीद करें कि आपके पानी की योजना चलायेगा सही ढंग से, चौबीस घंटे वहां रहेगा, क्योंकि लाइट तो न जाने कब आती है ,रात को आये, दिन को आये पता नहीं कब आ जाए, किस टाइम, चौबीस घंटे हाजिर रहे बिना तो वो ट्यूबवैल कौन चलायेगा। चौबीस घंटे उसको वहां रहने की जरूरत है और रुपये देवें पांच सौ और वो भी बहुत सारे लोगों को तो टाइम पर मिलते ही नहीं हैं, वो भी नहीं मिलते हैं, वो भी कई जगह क्या है कि पंचायतों के थ्रू है और आपके विभाग वाले पंचायतों को देते हैं और पंचायत वाले उसके ऊपर राज़ी नहीं है तो वो भी उसको नहीं देते हैं। हमारे बाड़मेर जिले का एक मैं बता रहा हूं कि ग्राम पंचायत लूखू उसमें एक मेघवालों की तलाई में मेघवाल है शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है गरीब आदमी है बहुत। पांच सौ रुपये में तो कौन रहेगा गरीब ही रहेगा अमीर वहां क्या करेगा तो उसको दो साल से ज्यादा टाइम हो गया अभी तक उसको एक रुपया नहीं मिला वो पांच सौ रुपये भी उसको नहीं मिले। लूखू का बता

(श्री हेमाराम चौधरी)

रहा हूं मैं अभी भी आप सुन लें अगर आप इसकी व्यवस्था करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, राज की उसके ऊपर कृपा होगी, मेरे ऊपर भी कृपा होगी और नहीं करा सको तो आपकी मर्जी। कहने का मतलब आप करो कुछ। गलती होती है यह मत समझो आप कि राज से कभी गलती हो ही नहीं सकती, इंसान से कभी गलती हो ही नहीं सकती। इंसान गलती किये बिना कैसे रह सकता है इंसान से गलती हो नहीं यह तो हो नहीं सकता। अगर कोई इंसान कभी अपनी जिन्दगी में गलती नहीं करे तो वो तो फिर देवता है, वो इंसान है ही नहीं वो तो देवता रूपी है, देव है, और गलती कर दे और गलती करने के बाद वो गलती मान ले तो फिर वो इंसान है। गलती करके भी गलती नहीं मानें ... सारी मैं ज्यादा ही उस साइड चला गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नेता प्रतिपक्ष, मारीशस के प्रधान मंत्री अपने निर्धारित समय पर यहां आएंगे। अपन सब लोगों ने बैठकर यह तय किया है वो एक बार आयें और अपन सब उनका स्वागत करें। आपको भी उनके स्वागत में भाषण देना है इसलिए मैं माफी चाहते हुए कह रहा हूं मैं वैसे नहीं कह रहा हूं अगर अपना जल्दी कनक्लूड कर दें तो सी.एम. का रिप्लाई हो जाए 8.30 बजे वो आएंगे तो उससे पहले हाउस एडजोर्न भी होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पहले ही इतना ज्यादा विस्तार से कहता ही नहीं। ओ.पी. महेन्द्राजी यहां आये थे तो मैंने पूछा कि मेरे को टाइम कितना दोगे तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रतिपक्ष के नेता हैं आपके लिए तो कोई टाइम है ही नहीं, कोई टाइम है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वैसे आपका अधिकार है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो मैंने देखा कि आज मजा आ गया। आज मैंने कहा कि पूरा आनन्द लूंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): आज आप पूरा आनन्द ले रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): खैर कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात आज बहुत उचित तरीके से रखी है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, अच्छे तरीके की नहीं मैंने एक बात बतायी है आप इस पर विचार करें। मैं एक बार गलती की यों कह रहा था कि मैंने एक बार विधान सभा में यह मामला उठाया कि मेरे गुढामालानी बाड़मेर जिले का मामला है यह आपके पचपदरा से आने वाले अमरारामजी विराजे हैं और कांत साहब भी विराजें हैं। एक फसल बीमा योजना जो लागू की है उसमें गुढामालानी, सिवाना और पचपदरा उसका मुआवजा क्लेम खारिज कर दिया कि आपका कोई क्लेम नहीं बना और बाकी तहसीलों में क्लेम बने और फिर वो मामला मैंने यहां विधान सभा में उठाया और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि मैं दुबारा जांच करवा लूंगा। मैंने कहा कि आप जांच करवा लें जांच में अगर हमारे किसानों का हक बनता है, वाजिब है, सही है तो आप दिला दें और इन्होंने फिर दुबारा रेवेन्यु बोर्ड से जांच करवायी। जांच करवायी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उन बेचारे किसानों को मुआवजा मिल गया। मैं इनको हमेशा धन्यवाद देता हूं ये ही एक आपकी पार्टी में किसानों की पीड़ा को समझते हैं। मैं समझता हूं शायद मेरे को ऐसा लगता है मेरी तरह इनको किसानों की चिन्ता है। मैं तो कहता हूं कि मैं इनके बारे में वहां भी कहता हूं कि अगर वो प्रभुलालजी सैनी दुबारा जांच नहीं कराते तो तुमको एक कौड़ी नहीं मिलती। मैं हेमाराम भले ही औंधा लटक जाता तो भी एक कौड़ी नहीं मिलती। उन्होंने जांच करायी तब मिला न जांच ही नहीं कराते तो क्या होता। जांच तो करायी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मुख्यमंत्री महोदया इस बार फिर गड़बड़ हो गयी उस टाइम तो इन्होंने ठीक कर दी इस बार फिर गड़बड़ हो गयी अब इस बार फिर ठीक कौन करेगा? फिर अब के आप कर दो, करो तो, नहीं करो तो मर्जी आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कर देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बाड़मेर जिले में आठ तहसीलें हैं आठ तहसीलों में ..

एक माननीय सदस्य: पूरे राजस्थान के बारे में बोलें आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां पूरे राजस्थान की कह दूंगा जो मेरे को जानकारी है उसकी बात तो करूं न। नहीं-नहीं, यह एक बाड़मेर में ही ऐसा होता है बाकी सब राम राज्य थोड़ी है राज तो यहां का है न तैंतीस

(श्री हेमाराम चौधरी)

जिलों में राज तो ये ही करने वाले हैं न। मेरे वहां हो सकता है वो सभी जिलों में हो सकता है पर जो जानकारी है बाकी की मेरे को फसल बीमा योजना की जानकारी नहीं है इसलिए कह रहा हूं वहां गुढामालानी तहसील का क्लेम खारिज 'नौ क्लेम' और बाकी सातों तहसीलों में क्लेम आया।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): सिवाना में कहां आया?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट कह दूं। मैं आपकी बात कह दूंगा सिवाना में कहां आया, आया आप थोड़ा-थोड़ा उधर पूछ देते हो न इसलिए आपको थोड़ा सा टुकड़ा डाला। आपको थोड़ा सा टुकड़ा डाला, नाम आ गया उसमें सात में मतलब क्लेम देने वालों में आपका नाम है। आपको नाम मात्र का दिया सबसे ज्यादा जिसको मिला उसको मिला। अब किस तरह से कैसे यह होता है मुझे इसका समझ में नहीं आता है फारमूला केल्कुलेट कैसे किया। अब जब मान लो पहले मैंने उठाया उस टाइम फारमूला तो पहले भी वो ही था फिर वापस वो ठीक हो गया। इस साल ये कान्त साहब बैठे हैं गुढा तहसील का भी कुछ हिस्सा लगता है इनके और सिवाना तो इनका है ही पूरा। सिवाना में तो थोड़ा सा इनको दिया पर गुढा में भी इनके 13 पंचायतें हैं एक धैला नहीं मिला। इनको पूछो कि अगर एक दाना भी हुआ है क्या फसल बिलकुल नाम मात्र की कोई फसल हुई है क्या। बिलकुल कुछ नहीं हण्ड्रेड परसेंट लोस और गिरदावरी है फेमिन में डिक्लेयर कर दिया फेमिन है इस साल, फिर भी क्लेम नहीं आया तो बड़े ताज्जुब की बात लगती है पर अब यह होता है कई बार थोड़ा विचार करें इसमें कम से कम अगर राजनीति हो तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ..

श्री उपाध्यक्ष: हेमारामजी, वो तहसील को इकाई मानने की वजह से गड़बड़ हो रही है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, मैं समझता हूं साहब तहसील में ही हो जाता है साहब। मैंने तो कहा सातों तहसीलों में इकाई है आठों तहसीलों में इकाई से ही काम होता है पूरे राजस्थान में तहसील इकाई है एक गुढा में तहसील इकाई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: काफी जगह इसका नुकसान हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अब तो मुख्य मंत्रीजी के आपके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है सब काम हो जाएंगे और क्योंकि अपने को समय पर ...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, अभी तो मैंने दस प्रतिशत हीं नहीं बोला मेरे को जो बातें कहनी थी उसके हिसाब से तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरे तो सब पीछे रह जाएंगे मामले। नहीं-नहीं, जरूरी हो तो फिर मैं कभी बोल लूंगा पर बात मैं आपको कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: फिर बाद में मौका देंगे आपको।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, एक मिनट आप इसमें यह कह रहे हैं कि गुढा, गुढा की इसलिए बता रहा हूं कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं यह नहीं कहता कि आपने जानबूझकर दिया सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अब किस हिसाब से कैसे हमारे ही कर्म खराब समझो, हमारे बुरे कर्मों की वजह से या कैसे ही समझो गुढामालानी में इस बार यह हो गया पिछली बार सातों तहसीलों में अकाल, पिछले साल संवत 2063 की बात है सब सातों ही तहसीलों में और मेरे एक तहसील में एक भी गांव अकाल में नहीं बाकी सभी तहसीलों में अकाल और उससे पहले वो मैंने सुना दी तो ये पता नहीं बार-बार क्या है पर फिर खैर जो भी है ...(व्यवधान) ये तो बोलेंगे ही, ये तो बोलेंगे ही क्योंकि इनका विशेष ध्यान रखा जाता है मुझे पता है, रखें मुझे उसमें तकलीफ नहीं है पर हमारा भी थोड़ा रखें तो ठीक रहेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय मुख्य मंत्रीजी ने प्रभुलाल सैनीजी को बुलाकर निर्देश दे दिये कि आपके यहां भी दे दिया जायेगा मुआवजा। अभी बुलाकर कह दिया उन्होंने।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उनका तो मैं पहले ही कहता हूं उन्होंने सही काम किया, सही काम को तो सही कहेंगे गलत कैसे कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते। न कभी कहा और न अपने कहने की आदत है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि पैसा तो अलग-अलग योजनाओं में खर्च हो रहा है, यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इस अभिभाषण में अगर आप देखें तो सब में चार साल का तुलनात्मक दिया है। बिजली का जैसा मैंने आपको बताया आपने दिया नहीं। (व्यवधान) दो-तीन मिनट में मैं समाप्त कर

रहा हूं। बिजली के बारे में मैं कहना भूल गया था। बिजली कितने घंटे मिल रही है। अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष बिजली के बारे में अपन एक दिन पूरी चर्चा रखेंगे इसलिए बाद में अलग-अलग विभागों के बारे में चर्चा होगी उस समय आपको पूरा समय दिया जायेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बस एक मिनट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यह भारत सरकार की है आप मानोगे या नहीं मानोगे। (व्यवधान) राष्ट्र की है, भारत सरकार राष्ट्र में नहीं आती है क्या। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में सब जगह जो होर्डिंग्स लगे हैं सब जगह इसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें सब जगह एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी का फोटो है। पहले तो कुछ दिन मुख्य मंत्रीजी का ही था उसके बाद कालूलालजी ने पता नहीं कैसे कलाकारी कर के अपना भी साथ में घुसेड़ दिया। खैर, ठीक है कालूलालजी करें हमें उससे तकलीफ नहीं, मुख्य मंत्रीजी करें उसमें भी हमें एतराज नहीं है पर ऊपर एक फोटो प्रधान मंत्रीजी का और एक हमारे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी का फोटो भी लग जाये, ऊपर उनके लग जाये नीचे इनके लग जाये उसमें क्या बुराई है। थोड़ा बहुत हमारा भी नाम साथ में रख दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पूरे ही आप धणी बनना चाहो और हमारा तो कोई नाम ही नहीं रखो तो यह बात ठीक नहीं है। थोड़ा आप भी विचार करो।

श्री उपाध्यक्ष: कहीं केन्द्र वाले एतराज नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): थोड़ी ठगी करो तो थोड़ा सा कुछ साथ मिला हो ना फिर तो ठगी चल जायेगी आप तो धेला ही नहीं मिलाओ और पूरे धणी आप बन जाओ ऐसी ठगी थोड़ी ठीक नहीं है। इसलिए आप देख लेना। मेरे शब्दों से शायद मुख्य मंत्रीजी बुरा नहीं माने। (व्यवधान) मैंने इनके फोटो पर एतराज नहीं किया, मेरे को क्या तकलीफ है पर वह भी प्रधानमंत्री हैं, केन्द्र से पैसा देते हैं उनका भी फोटो लग जाये तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे फोटो के लिये तो मैं कह नहीं रहा हूं और फिर भी नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी हमारा कोई जोर तो है नहीं, हमारी तो पुकार है। आपको हमने कह दी सुना दी। मुझे आपको बहुत कुछ कहना था, बहुत पुकार सुनानी थी,

(श्री हेमाराम चौधरी)

बहुत बातें थीं पर चूंकि मारिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बातें तो वैसे पहले आ गईं ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आज मत कहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कुछ बातें थीं पर कोई बात नहीं आइंदा कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपको जो बातें कहीं उस पर ही आप थोड़ा विचार कर लें तो ही ठीक हो जायेगा, कुछ तो ठीक होगा। जितना कुछ ठीक हो जाये उतना ही ठीक है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जायेगा व सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जायेगी। इसके पश्चात् मारिशस के माननीय प्रधानमंत्रीजी के पधारने पर उनके सम्मान में समारोह होगा। माननीय प्रधान मंत्रीजी सदन में माननीय सदस्यों को संबोधित करेंगे। अंत: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह सदन में ही मौजूद रहने का कष्ट करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि बीमार होने के बावजूद भी वह इस पवित्र सदन में आये और उन्होंने अपना कांस्टीट्युशनल राइट निर्वहन करते हुए पिछले चार वर्षों में जो जो अच्छे काम हमारी सरकार ने किये थे उन्होंने प्रयास किया कि इसकी जानकारी वह हमारे हाउस को दे। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन लोगों ने बहस में भाग लिया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बहस की और अच्छे-अच्छे और रचनात्मक सुझाव हमारे सामने रखे। पूरे राजस्थान प्रदेश की निगाह इस हाउस पर है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठे हुए लोग हमारे सदन में क्या कार्यवाही हो रही है उसकी ओर बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रहे हैं। वह यह कोशिश में हैं कि हमारा हक और हमारे विकास के जो काम हैं वह तेज गति से होते रहें और एक अच्छी और सकारात्मक बहस हो ताकि उनकी बात हमारे इस सदन में आ सके। परन्तु पिछले तीन दिन से ऐसा गतिरोध हुआ है और मैं समझती हूं कि बहुत सारे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय सदस्य जो अपने अच्छे-अच्छे सुझाव यहां देना चाहते थे वह उन सुझावों को देने से रह गये। इस सदन की एक बहुत सुदृढ परम्परा है और इस हाउस को पूरे देश में माना जाता है। लोग हमारी और निगाह उठाकर देखते हैं और हम से एक किस्म से एग्जाम्पल लेते हैं और मैं समझती हूं इस इतिहास को हम लोगों को बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिये औरे सब लोग मिलकर एक सार्थक प्रयास करें कि हम उस दिशा में बढ़े। शोर-शराबे के बजाय रचनात्मक बहस की कार्यवाही हो इसके लिये मुम्बई में संसदीय मंत्रियों की और चीफ व्हिप की एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें देश भर के सब दलों के लोग वहां आये थे और वहां एक निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अभिभाषण है उसकी गरिमा को हम लोग बनाये रखेंगे और मेरी जानकारी के अनुसार प्रतिपक्ष के जो सचेतक महोदय हैं वह भी शायद वहां थे। और लोगों ने यह तय कर लिया था उसके बावजूद भी राज्यपाल के अभिभाषण को होने नहीं दिया। जबकि उन्होंने विशेष रूप से बार-बार यह आग्रह किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बात को आप लोग सुनने की कोशिश करें और उसके बाद वह अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर सके और वह वापस चले गये। दो साल से यह इस हाउस में होता रहा है जो मैं समझती हूं कि पहले नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं मैं इसको अपना सौभाग्य समझूं या मैं कहूं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बजट सत्र में सुझाव और मार्ग दर्शन के लिये मुझे हर बार कोई नई शख्सियत दिखाई दी और पहले तो प्रतिपक्ष के पूर्व नेता डा. बी.डी. कल्ला और आदरणीय रामनारायण चौधरी मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव और ज्ञान का अनुभव हम लोगों को दिया। हमारी सरकार का मार्ग दर्शन किया इसके लिये मैं उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। अब प्रतिपक्ष के भावुक और संवेदनशील नये नेता आदरणीय श्री हेमारामजी चौधरीजी का मैं यहां बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और मैं यह उम्मीद करती हूं कि आपके बहुत सारे अच्छे और रचनात्मक सुझाव जैसे अभी सुनने को मिले उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी।

जब से मैंने इस प्रदेश को टेक ओवर किया था, जो यात्रा करने के बाद इस कुर्सी पर सेवा करने का मौका हमें जनता ने दिया मैंने यह कोशिश की कि जो हमारी जनता जनार्दन है उनके विकास की जो प्राइमरी चिंता है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसको किसी भी तरीके से डील करें, उनकी बात को बैठकर तय करने की कोशिश करें और वाकई में जो पैसा है वह उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि शायद आपके राजीव गांधीजी ने जिन्होंने एक समय में कहा था कि रुपये में से शायद 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं 85 पैसा इधर-उधर खो जाता है। हम लोगों ने अपने समय में यह कोशिश की कि विकास पूरी तरह से उस आम आदमी तक पहुंचे। उसको एक किस्म के लिये एक मौके के लिये यह फील हो कि हां कोई हमारी सरकार बैठी हुई है और वह सरकार हमारे लिये कुछ कर रही है। मैंने कोशिश की अपनी सरकार के टाइम में कि किसी भी तरीके से विचहंटिंग न की जाये।

कोई ऐसा जिस तरीके से पिछली सरकारों ने किया है हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोगों ने जो भी पूरी शक्ति थी उसको लगाया कि गांव में जो बैठा हुआ किसान है या गांव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पैसा पहुंचे, उसका काम हम लोग कर सके। मैंने आपके काम को, आप ही के काम को आगे ले जाने की कोशिश की है। अब आप जैनपेक्ट को ही देख लीजिए, यह भी एक मल्टीनेशनल कम्पनी है। इस मल्टीनेशनल कम्पनी को जवाहर सर्किल के ऊपर बहुत अच्छी-अच्छी जमीन दी गई है परन्तु हमने यह सोचा कि राजस्थान के लिए अच्छा है और वह एक रात के अंदर तो आने वाला नहीं है। आज आपने उसकी परमीशन दे दी और कल उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई और परसों उसमें नौकरी मिल गई यह तो होने वाला नहीं है परन्तु पांच साल के अंदर जैनपेक्ट ने फ्लोरिश किया, जवाहर सर्किल के ऊपर उसकी बिल्डिंग बन गई,उसके अंदर काम होने लगे हैं और उसने अपने काम को और आगे भी बढ़ाया है, यह राजस्थान के लिए अच्छा था और इसलिए मैं सोचती हूं कि बी.डी. भी जो है वह हमारा क्रिएशन तो नहीं है, आप लोगों ने बनाया था और उसके पैरामीटर्स वगैरह भी आप लोगों ने सैट किये थे। आप भी चाहते थे कि कुछ डिसिजन्स ऐसे हों जो जल्दी-जल्दी लिये जाएं ताकि जनता को बेनिफिट हो और उसी चीज को हम लोग यहां फोलो कर रहे हैं। हमने कोशिश की जितने डिले को हम लोग काट सके हायर लेवल के ऊपर डिसिजंस लेने की कोशिश करें ताकि जनता को उसका लाभ सही तरीके से मिल सके। कुछ ऐसे इश्यूज हैं, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता और सब माननीय सदस्यगण जो यहां बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं ,जो विकास के मुददे हैं और जिनकी वजह से राजस्थान का भला हो सकता है, ऐसे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक किस्म से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कन्सेंसस होने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि उसके ऊपर हम लोगों को एक दफा ध्यान देने की जरूरत है।

आपने जो पाले की बात की है, फोर एग्जाम्पल, बिलकुल सही की, इधर के सदस्यों ने भी, उधर के सदस्यों ने भी, यह तय किया, यह चाहा कि पाले के अंदर जिस किसान के साथ मुसीबत हुई है उस किसान को स्ट्रेन्थन किया जाए, उस किसान को हम लोग मदद करें। शायद गलतफहमी है, सीआरएफ के पैसे को जब तक सेण्ट्रल नहीं बताती कि इसको किन-किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक हम उसको अपने मन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम कि यह चीज आपको मालूम है कि नहीं परन्तु मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाला इसमें इनक्ल्यूडेड नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने आगे बढ़कर, इतने साल हो गए, पचास साल के अंदर यह पहली दफा पाले के ऊपर इतना बड़ा डिसिजन हुआ है कि 126 करोड़ रुपये का पैकेज बनाकर, जिस तरीके से हमने पिछली बार ओलावृष्टि के ऊपर किया था उसी तरीके से अभी हम लोगों ने पाले के ऊपर एक पैकेज बनाकर जनता के सामने रखा। मैं तो यह मानती हूं, मैंने देखा था, टेलीविजन के ऊपर, बात चल रही थी, मैं यह मानती हूं कि आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर रिज्यूलेशन पास करा लेना चाहिए। मिलकर यह तय कर लेना चाहिए, सेण्ट्रल गवर्नमेंट पाले को भी उसके अंदर जोड़ दे ताकि हमारी जनता को फायदा मिल जाए। सबसे मुसीबत तो आप कह रहे हैं, हमें हुई है, प्रतिपक्ष के नेता अभी तो आप कह ही रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि हमको डरने की जरूरत क्या है। आपको हमको दोनों को जाकर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्रीजी से मिलकर या संबंधित मंत्री से मिलकर यह कह देना चाहिए कि पाले को जोड़ो, मैं तो समझती हूं कि राजस्थान की जनता इससे खुश होगी। उसमें मुसीबत क्या है, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। आपको तो खड़े होकर मेरे को अभी कह देना चाहिए कि हां हम लोग मिलकर इस चीज को करें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोशिश कर रहे हैं। हमारे मदेरणा साहब ने चिट्ठी लिखी है। हमारा प्रतिनिधि मण्डल गया हुआ है। हम भी बात करेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): फिर काहे का डर। फिर डिसिजन लेने में परेशानी क्या है। देखिये मेरे को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पता तो तब चलेगा जब होगा। हम तो चिट्ठी लिख चुके हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन के अंदर प्रस्ताव ले आये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): सदन के अंदर प्रस्ताव लाने में दिक्कत क्या है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सारी चीजें सदन से, प्रस्ताव से ही होती हैं। हमने जो बातें कहीं उसका भी प्रस्ताव ले लो कि यह ही हो जावे, यह ही हो जावे। गुढामलानी वाली फसल का भी प्रस्ताव ले लो कि उनका भुगतान कर दिया मुआवजे का। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं यह कह रही हूं, अब आप मेहरबानी करके...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष) आप हर चीज में टांग फसाने की कोशिश मत करो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष मैंने बहुत पेशंस के साथ आपकी बात को सुना। मैं समझती हूं कि हमारी बात को भी आप उतने ही पेशंस से सुन लेगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं दुःखी नहीं होऊंगी। आप मेरी बात सुन लें

मैं कहती हूं कि कुछ ऐसी बातें है जैसे ड्रिंकिग वाटर है, जैसे एजुकेशन है, जैसे हैल्थ है, जैसे न्यूट्रीशियन है इन चीजों के ऊपर हम लोगों को मिल बैठकर कन्सेंसस बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि राजस्थान का भला हो। मैं पूरे दिन से डिबेट को सुन रही हूं। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग किस तरफ मुडने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान को अगर बीमारू प्रदेश से निकालकर हमको अग्रणी प्रदेश बनाना है तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है।अगर हम लोगों को, दोनों को मिलकर राजस्थान को आगे करना है मैं समझती हूं कि आपका भी सपना है तो मुझे समझ नहीं आता कि इन चीजों के ऊपर मिल बैठकर बात करने में क्या मुसीबत है। आखिर में मुझे भी और हमारी पूरी पार्टी को भी जनता के बीच में जाने की जरूरत होगी और आपको भी जनता के बीच में जाने की जरूरत होगी। यह जो अपन यहां बहस कर रहे हैं कि जनता के सामने क्या हुआ,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्या नहीं हुआ वह तो फील्ड में जब जाएंगे तब पता पड़ेगी। मैं समझती हूं कि हम तो बार-बार इस चीज को पता करने की कोशिश करते हैं फील्ड में वाकई में क्या हो रहा है और मैं समझती हूं कि डवलपमेंट का काम उन तक पहुंच रहा है क्योंकि जब भी मैं इलाके के अंदर जाती हूं तो लोग कहते हैं कि ऐसा काम और इतना काम आज तक हुआ ही नहीं हैं। इतनी सारी मेलीशस चीजें कभी-कभी देखकर... मेरे तो आज कान ही पक गये पूरा केन्द्रित मुख्य मंत्री पर हुआ, मैं यह पूछती हूं कि यह तो पूरा केन्द्रित अपने को राजस्थान के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की भलाई की बात अपन कर रहे हैं यहां। मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री...भईया आप लोगों को राजस्थान की भलाई के लिए कुछ कहना नहीं है क्या? अगर मुख्य मंत्री के ऊपर कुछ कहना है कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप करेंगे तो हम सब आपसे सीखने को तैयार बैठे हुए हैं। कोई ऐसी कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे सामने आ जाती है और हम उसको अपने काम के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं समझती हूं कि नाम बदल दें। अच्छी बात आप कहेंगे, कोई भी कहता है, जनता जनार्दन कहती है उसको हम यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं समझती हूं कि हमारी पूरी शक्ति राजस्थान की भलाई में लगाने की जरूरत है। मैं अपनी पीठ को नहीं थपथपा रही हूं यहां, परन्तु मैं यह समझती हूं जितना समय हम लोगों ने दौरा करने में निकाला है, पिछले हिसाब को अगर आप देख लोगे तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनता के बीच में जाना, आना, किसने कितना काम किया।

हेलीकाप्टर के ऊपर आप खो जाते हो। महारानी है तो हेलीकाप्टर के ऊपर बैठकर ही चलती है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पचास डिग्री टैम्परेचर के अंदर चलती है उसको क्यों भूल जाते हो, वह कैसे याद में नहीं आता है? हेलीकाप्टर तो आपको, आज के जमाने में, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर हो गया है मुख्य मंत्री, उसको बीकानेर और बाड़मेर जाकर वापस जयपुर आने की जरूरत है। हेलीकाप्टर आज लग्जरी नहीं है नेसेसिटी है। अगर आप देखें तो यू.पी. और बिहार के 5-5, 6-6 प्लेन है और वह आज की नहीं यह मायावती की बात नहीं है, मुलायम सिंह की बात नहीं है, जब कांग्रेस की बात थी तब ही 6-6 प्लेन थे। बिहार की बात थी तब ही 6-6 प्लेन थे, तब तो आपने पूछा नहीं, तब तो किसान के बेटे की बात आपने की नहीं, न महारानी की बात की। मैं तो यह कहती हूं कि राजस्थान की भलाई की बात अपने को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करनी चाहिए। अपने को यह भूल जाना चाहिए। इस सरकार में जब हमने पहला पर्दापण किया और इस कुर्सी को जब हमने सम्भाला तो एक प्लेन हमको मिला था हमको जो शायद 25 साल पुराना था। आज भी वो ही चल रहा है। नया जो आया वह तो क्रेश वैसे ही कर गया। मेरे भाई के डैथ होने के बाद उस प्लेन के अंदर मैं तो नहीं समझती हूं कि किसी भी अनसेस प्लेन के अंदर मैं अपनी जिंदगी को या किसी भी मंत्रीगण की जिंदगी को सपुर्द करना चाहती हूं। इसलिए मैं समझती हूं कि आप इन सब चीजों को छोड़ें। इन सब चीजों का छोड़कर एक बिन्दु के ऊपर आकर्षित करें कि काम अपने को करना है। राजस्थान के किसान को, राजस्थान के गरीब को, राजस्थान की महिला को, राजस्थान के जवान को हमको किस तरीके से मजबूत करना है उसके लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे तो मैं समझती हूं कि हमारा कुछ फायदा हो सकता है।

मुझे गर्व है कि इतने सारे पुरस्कार पिछले चार साल के अंदर राजस्थान को मिले हैं। अब मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं, जो पुरस्कार हमारे हाथ में आए, जो अख़बार में लिखे गये हैं जिसके बारे में सब लोग यहां बैठे हुए हैं जानते हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूं। राष्ट्रीय पुरस्कार, अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार और मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूं जब मैं यहां सुनती हूं कि क्या कर लिया है राजस्थान के अंदर। यह तो सब आपके सामने प्रूफ रखा हुआ है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। सत्यमित्र पुरस्कार, ई-मित्र योजना के ऊपर पुरस्कार, भारतीय तकनीकी दक्षता पुरस्कार और विश्व बैंक। भूरि-भूरि प्रशंसा करें हमारी सड़कों के तंत्र के बारे में। अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार हमको मिले, सड़क निर्माण के ऊपर। फर्स्ट टाइम जो राजस्थान के अंदर अपने पास है कि जिन राज्यों में सबसे पहले ऐसी स्कीम बनी और अच्छी सराहनीय स्कीम बनी है वह है जननी कलेवा, फूड स्टम्प, राशन उसके लिये लोग यहां आये हैं उसको स्टडी करने के लिए, यह तो हम नहीं कह रहे हैं ना, वो तो लोग आये हैं। केरोसीन का समान दर पूरे राजस्थान के अंदर, विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना, राजस्थान मिशन आफ लाइवलीहुड इन सब चीजों को लोग स्टडी करने आये हैं। किसान कल्याण कोष, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, यह पन्नाधाय जीवन अमृत योजना इतना सक्सेजफुल रहा कि चिदम्बरमजी ने उसको ऊपर आम आदमी बना दिया, अब बताओ आप। यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्कीम हमारे यहां पहले खुली थी उसको आम आदमी के रूप में अपने बजट में चिदम्बरम जी ने कहा है। आप तो मेरे को कह रहे कि हम उनसे कापी करते हैं। परन्तु मैं मानती हूं कि इस बार तो उन्होंने हमसे यह लिया है। हैल्थ इन्श्योरेंस को हम लोगों ने दिसम्बर, 2007 के अन्दर शुरू किया। ये अप्रैल में चालू करने जा रहे हैं। तो हमने उनसे सीखा कि उन्होंने हमसे सीखा। उसके बाद मिड-डे-मील, उन्होंने लेगिंग ब्लाक्स के अन्दर, यह कहा कि जो पिछड़े हुए ब्लाक्स हैं, उनके अन्दर हम मिड-डे-मील करेंगे। हम लोगों ने सब ब्लाक्स के अन्दर उसको चालू कर दिया। उसके बाद अब मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब ब्लाक्स के अन्दर इस चीज को अनाउंस करें। अगर यूनेस्को पुरस्कार हमको एजुकेशन में मिला, विद्युत सुधार और वितरण की दृष्टि से पूरे देश के अन्दर इसको माना जा रहा है, लोग आते हैं, सुशील कुमारजी शिंदे ही हमारे पास 2-3 दफा यहां आये, उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की। अखबारों में इस बारे में लिखा हुआ है, जो कि हमारे मुंह से आई नहीं है यह बात। ओलावृष्टि और पाले के अन्दर भी हम लोगों ने किसानों की सहायता के अन्दर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। मेरा यह मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं किसी भी तरीके से मुख्य मंत्री नम्बर-1 नहीं बनना चाहती हूं। परन्तु, हां, मैं यह चाहती हूं और मेरी पार्टी चाहती है, और मेरे सब सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान नम्बर-1 हर काम के अन्दर बने, यह हमारी कोशिश है। बीमारू प्रदेश से हम सभी को शर्म आती है। यह राजस्थान वह राजस्थान है जो अपने स्वाभिमान के पीछे मर जाता है। लोगों ने अपना सब बलिदान कर दिया, अपने स्वाभिमान के ऊपर, हम गरीबी में मर जाएंगे, एक रोटी खाएंगे परन्तु अपनी इज्जत को नहीं बेचेंगे। उस राजस्थान को पूरे 5 साल के लिये कंगाली के रास्ते के ऊपर खड़ा किया, उसके स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर दी। आज उस स्वाभिमान को हमने राजस्थान को वापस दिया है, उसमें क्या गलती कर दी। उसमें तो आपको हमारी पीठ थपथपा कर यह कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे काम करते रहो। हम भी आपसे सीखेंगे। और अगर हमने इतना अच्छा काम नहीं किया होता तो 30 नवम्बर और एक दिसम्बर, 2007 के अन्दर हम हमने रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप सब्मिट किया,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फिक्की के साथ तो यह 300 सहमति पत्र हमने उनके हाथ पकड़कर थोड़े ही लिखवाये। यह तो खुद ने आकर, लोगों ने सहमति-पत्र भरे हैं, लैटर आफ इंटेंट किये हैं और एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये का निवेश उन्होंने कहा है कि हम सम्भावित यहां लाएंगे। मुझे मालूम नहीं, यहां सब लोगों को याद है कि नहीं, एक बहुत बड़ा ऐसा ही सम्मेलन पिछले 5 वर्ष के अन्दर हुआ था। बहुत सारे लोग बाहर से आये थे और उन्होंने निवेश की बात की थी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमने आपका काम सीख लिया तो आप क्या करेंगे। (व्यवधान) अगर हम आपका काम सीखेंगे तो आप क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): निवेश की बात की थी और मैं कह रही हूं कि 5 साल बाद, हमने पैसा तो खर्च कर दिया परन्तु निवेश नाम की चीज ही हमने नहीं देखी। और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 10-15 दिन पहले 3 यूनिट्स का हम लोगों ने अभी फीता भिवाड़ी के अन्दर काटा, जिन्होंने यह सहमति पत्र के ऊपर दस्तख्त किये थे। तो काम तो उसके अन्दर चालू हो गया है। करीबन 64000 लोगों को इससे नौकरी मिलने वाली है, एडिशनल। और इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं, उसको आप हंसी-मजाक में मत कहना कि वह तो प्राइवेट सैक्टर में है। नौकरी तो नौकरी होती है। आदमी का पेट अगर वह भर सकता है तो मैं समझती हूं कि उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। सरकार कुछ नौकरी दे सकती है। परन्तु वहां पर नौकरी के लिये हम लोगों को पी.पी.पी. के द्वारा और लोगों को राजस्थान के अन्दर इन्वेस्टमेंट के लिये लाकर हम लोगों को काम करवाना होगा। अभी होण्डा सी.एल. ने 5-6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनके साथ-साथ करीबन उनकी 37 स्माल इण्डस्ट्रीज साथ में आएंगी। वह भी कितने सारे लोगों को काम देंगी, उसके बारे में आप लोगों ने जरा विस्तार से सोचा है कि नहीं। मैं जानती हूं कि हम लोगों ने इसको देखा है और मैं मानती हूं कि इस वजह से हम लोगों को बहुत कुछ फायदा भी होगा। बी.आई.पी. के द्वारा 17 हजार करोड़ के 23 औद्योगिक और विकास परियोजनाएं मंजूर हुई थीं दिसम्बर, 2003 के अन्दर, और हमारे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पिछले 5 साल के अन्दर 9 हजार करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने यहां इन्वेस्टमेंट करवाया है।

फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं अभी जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। परन्तु मैं इतना जरूर कहूंगी कि यह फाइनेंशियल्स, मैंने बार बार कहा है, हाउस के अन्दर भी बार-बार इसकी चर्चा हुई है और हमने ही नहीं कहा है, यह तो प्लानिंग कमीशन के लोगों ने कहा है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने इसको सराहा है, बाहर के लोगों ने, विशेषज्ञों ने, हम सबने इसको माना है। तो मैं समझती हूं कि इसके बारे में आर्ग्यू करने से कोई मतलब नहीं है और तारानगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य बार-बार उस पाइण्ट पर वापस चले आते हैं, जी.एस.डी.पी., 50 प्रतिशत, और उस चीज के ऊपर मैंने पिछले साल भी आपसे बात की। अब इस साल भी बजट के अन्दर हम उसको वापस लाएंगे। क्योंकि मैं समझती हूं कि उसको बार-बार कहने से अपने को कोई मतलब नहीं है। इतना याद रखिये कि हम लोग सरप्लस बजट के अन्दर चले गये हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और आपका यह कहना, मुझे समझ में नहीं आता कि आपका यह कहना कि एन्युल प्लान की आपको इतनी बड़ी चिन्ता है कि 14 हजार करोड़ के प्लान को आप कहते हो कि छोटा प्लान है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये भूल गये अपने टाइम को जब हमने टेक ओवर किया तो चार हजार करोड़ रुपये मुश्किल से खींच-खींच करके कर रहे थे। और उसको आप कम्पेयर कर रहे हैं आन्ध्र प्रदेश से। पहले आन्ध्र प्रदेश तक पहुंचें तो सही। हमने तो बड़ी मुश्किल से आपको चार हजार करोड़ से तीन गुना आगे बढ़ाकर 14 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाया है। मैं समझती हूं कि इसी में बहुत बड़ी बात है। परन्तु मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ कहने को है नहीं, अब क्या करें, कुछ कहना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ मैं फाइनेंस के ऊपर तो नहीं, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान डवलपमेंट आफ पावर्टी एलिविएशन फण्ड का, आप कह रहे थे हमने गठन किया है कि नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 2006-07 के अन्दर सौ करोड़ और 2007-08 में 200 करोड़ रुपये इस कोष के अन्दर हमने हस्तांतरित किये हैं। इसको चैक कर लीजिये आप। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बार-बार हमको यह कहा कि सेण्टर का पैसा आता है। सेण्टर का पैसा आता है,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जैसे हम सब भिखारी यहां बैठे हुए हैं। और हम लोग उस पैसे के बिना कुछ काम कर ही नहीं सकते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है सेण्टर ने। यह तो हमारे आम आदमी का, टैक्स-पेयर, जो टैक्स पेयर है, उसका पैसा है। हम सबका उसके ऊपर राइट है और उसमें राजस्थान का हिस्सा है। यह तो आपकी मंहगाई इतनी बड़ी है, इस वजह से आप देख रहे हो कि ज्यादा डेवोल्यूशंस होने लगे हैं। और इतना डेवोल्यूशंस वैसे भी नहीं होना चाहिए। अभी एन.डी.सी. की मीटिंग के अन्दर हम लोगों ने यह कहा कि टाइड और अनटाइड फण्ड के अन्दर जिस तरीके से काम चल रहा है उससे आगे चलकर फैडरल स्ट्रक्चर को यह बहुत बुरी तरह से डेमेज करने वाला है। इन्दिरा गांधीजी के टाइम में, इन्दिरा गांधीजी ने एन.डी.सी. की मीटिंग में कहा था कि फाइव-सिक्स जो है, वह पैसा अनटाइड सब स्टेट्स को देना चाहिए and only one-six should come tied. आज वह बिलकुल ही उल्टा हो रहा है। और अगर आप उसके हिसाब को देखो, जो मैंने हिसाब उनको दिया था तो मुश्किल से 5 प्रतिशत रह जाता है मुख्य मंत्री के पास जिससे वह और राजस्थान, जैसे बाड़मेर है, चूरू है, ऐसी और जगहों के ऊपर पैसे लगाने का डिस्क्रिएशन सरकार के पास इतना कम रह जाता है, क्योंकि यह सी.एस.एस. के अन्दर इतना उन्होंने भार लगा दिया है। और सी.एस.एस. की बात आप कर रहे हैं वह सी.एस.एस. को आप भी इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे अटलबिहारीजी वाजपेयी के टाइम में भी जब सी.एस.एस. था तो डेरोल्यूशंस आपकी तरफ से नहीं हुए थे। परन्तु मैं यह कह सकती हूं कि जितना भी सी.एस.एस. में उन्होंने दिया है उस सी.एस.एस. को हमारा हिस्सा भी पूरी तरह से मिला है और इस वजह से हम इतनी बड़ी स्कीम्स को गांव के अन्दर ले जा सकते हैं। देखिये, पैसा तो आया और अगर पैसे को उस सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया तो जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तो इसलिये जनता का हो रहा है, नरेगा की बात आप कर रहे हो, दूसरी स्कीम्स की बात कर रहे हो, क्योंकि सरकार ने दौड़-दौड़ कर उन स्कीम्स को बहुत छोटे-छोटे गांव तक, छोटे-छोटे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया। इतना सक्सेसफुली पहुंचाया कि अरुणा राय हो या जान ड्रेज हो, उन सब लोगों ने यह माना कि हां छोटे से छोटे और गरीब से गरीब तक पहुंचा, यह बात उन्होंने कही। अब यहां, हमारे यहां माननीय सदस्य, अब हैं नहीं वे यहां, उन्होंने मनोहर थाना की बात

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की थी आज सुबह नरेगा के पीछे। अब आज आप कह रहे कि नरेगा में मेरी तस्वीर लग रही है या कालूलालजी की तस्वीर लग रही है। और आपको दुःख इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्रीजी की क्यों नहीं लग रही है। मैं समझती हूं कि उसकी लगेगी जिसने काम किया है। मुझे याद है अशोकजी गहलोत की पी.एम.जी.एस.वाई. और किस-किस में लगती थी, लगाया करते थे, वह तो ठीक है। वह पांच साल में जो हुआ, वह उस चीज को भूल गये। और मैं तो कहती हूं कि अपने को उसमें, मैं उसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हूं। मैं तो यह कहती हूं कि उस पैसे को मैं पहुंचा सकती हूं और अरुणा राय जैसे लोग और जान ड्रेज जैसे लोग अगर यह कह देते हैं कि आपने अच्छा काम किया है तो यह हमारे हक में बहुत बड़ी बात है। सोशल आडिट किया है। सोशल आडिट में यह पता किया है कि वह परिसम्पत्तियां एक्चुअली बनी हैं, 99.5 प्रतिशत, जो आपकी परिसम्पत्तियां बनी हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिये आज मैं इतना ही कहती हूं कि आप, आपने तो कापूरडी और जालिपा की बात की। इसके अन्दर मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगी कि कापूरडी और जालिपा की लिग्नाइट माइन्स हम नहीं देते, यह तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया देती है। और क्या आपको गर्व नहीं है कि आपके बाड़मेर जिले के अन्दर इतना बड़ा पावर हाउस हो जाएगा, जिसकी वजह से इण्डस्ट्रीज आपके यहां आ जाएंगी और आपके लोगों को फायदा होगा। आप तो चला-चलाकर, मैं समझती हूं कि आपको मुझे कहना चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी करवा दो ताकि मेरे लोगों को फायदा हो। अब आप देखिये कि एक-एक फैमेली को कम्पनसेशन के 30 हजार प्रति बीघा over and above the earlier DLC rate which is 4 times more, over and above this, हरेक फैमेली को 4 लाख रुपये का घर उनको मिला। मैं समझती हूं कि एक हेण्डसम हम लोगों ने कम्पनसेशन देने की कोशिश की है और आगे भी हम कम्पनसेशन देंगे। आपको तो हमारे साथ जुटकर उस पावर हाउस को बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों को वहां फायदा मिले।

मैं तो अब तो खाली पावर की बात, परन्तु पावर, पानी, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने भरपूर कार्य किया है। मैं उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी। इतना जरूर मैं कहूंगी कि जो महंगाई हुई है उसके ऊपर जरा हमारी मदद करिये आप। इतनी महंगाई हुई है कि हमारा तो आदमी बिलकुल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ही उसके अन्दर दब गया है। अभी मैं फिगर्स देख रही थी। चाहे गेहूं है, 2004 की तुलना में 2007 में गेहूं की कीमत 38 प्रतिशत, चने की दाल 63 प्रतिशत, चाय की कीमत 16 प्रतिशत, चावल की कीमत 14 प्रतिशत, डीजल की कीमत 56 प्रतिशत, पेट्रोल की कीमत 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, अब मैं समझती हूं कि इतनी महंगाई होने के बाद आप मेरे सामने बैठ कर यह कह रहे हैं कि आपको गरीब आदमी की चिन्ता हो रही है। गरीब आदमी की इतनी चिन्ता होती तो हम लोग मिलकर जाते दिल्ली और कहते कि हमारे राजस्थान के अन्दर तो लोग मरे जा रहे हैं। साथ में जो हमको मिलना चाहिए वह स्टेट को नहीं मिल रहा है। बी.पी.एल. की बात कही गयी यहां पर। बी.पी.एल. को आपने 17 लाख पर लाकर छोड़ दिया है। हमारी सरकार ने तो यह तय कर लिया है कि उनको जो पांच लाख लोग या तीन लाख लोग छूट गये थे उन तीन लाख लोगों को सरकार सम्भालेगी और आपने अभी गेहूं की बात मेरे से की तो यह गेहूं की बात जो है वह राशन कार्ड इनके रुके हुए हैं क्योंकि आपको भी मालूम है इस चीज को कि हाई-कोर्ट के आदेश की वजह से वह दिये नहीं जा रहे हैं। अब इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सारे पैरामीटर्स आपने बदले। मानी, दिल्ली की सरकार ने बदले और उसका फाल आउट अब स्टेट के ऊपर हुआ। अब फिर असेम्बली में हमको क्रिटीसाइज आप कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कितना फेयरनैस है परन्तु हमारी मदद फिर भी आप कर सकते हो।

मैं समझती हूं कि प्रमुख खनिजों के ऊपर जो रायल्टी का पुनर्निर्धारण नहीं हो रहा है और 40 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा नुकसान हो रहा है, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हो।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो 14 जिलों में है। बी.पी.एल. परिवार को घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाने के मामले हैं, उसके अन्दर आप हमारी मदद कर सकते हो।

बिजली का अन-एलोकेटेड सेण्ट्रल पूल से हम लोगों को जो कटौती हुई है, 20 प्रतिशत से लेकर अब 13 प्रतिशत, 11 प्रतिशत पर यह पहुंचे हैं जब कि राजस्थान पावर डेफिसिट स्टेट है। जम्मू और कश्मीर को काट-काट कर वह दे रहे हैं। उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सर्वशिक्षा अभियान का जो हिस्सा 75 : 25 था और जिसको इन्होंने 50, 50 करने की कोशिश की और अब 65, 35 करके रखी है, उसमें अगर आप हमारी मदद कर देते तो हम और कितने लोगों को उसमें लाभान्वित कर सकते थे।

11वें वित्त आयोग के वित्तीय सुधार सुविधा योजना के अन्दर जो 500 करोड़ रुपये हमको मिलने चाहिए थे और जो नहीं मिल रहे हैं, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हो और जो केन्द्रीय आपदा कोष के 400 करोड़ रुपये इन्होंने प्लान रिसोर्सेज के रूप हस्तांतरित नहीं किये हैं, उसमें हमारी मदद करके हमको यह पैसे वापस दिलवा दो और अभी फाइनली क्या करने जा रहे हैं कि 13 फाइनेंस कमीशन के अन्दर जो टर्म्स एण्ड रेफरेंस उन्होंने बदल दिये हैं। उनमें जो रिक्वायरमेंट अपने प्लान के लिए है, मानी, उनके प्लान के लिए है वह भी इसमें गिनती करवा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि स्टेट का शेयर जो है वह कम हो जाएगा, इसमें आप हमारी मदद करवा सकते हैं और आप किसान की बात इतनी कर रहे हो, कृषि बीमा योजना की बात आपने इतनी जोर-जोर से कही। 60 करोड़ रुपये हमारी जो राशि उनके पास पड़ी हुई है वह हमें दिलवा दो तो हमको फायदा यहां हो जाए।

शरद पवारजी ने हमको अभी चिट्ठी लिखी है कि गेहूं हम आपको नहीं देंगे। आपको गेहूं चाहिए तो आप इम्पोर्ट करिये और अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप ले लीजिए उसका, मानी, जो गेहूं उग रहा है आपके स्टेट के अन्दर वह किसान से आप ले लीजिए। जितना क्विंटल आप लोगे हम आपको वापस दे देंगे। तो यह क्या बात है? यह क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया और स्वजलधारा की बात अपन जब करते हैं तो जहां 90 : 10 का प्रतिशत पहले था उसमें 50, 50 प्रतिशत हो गया है। तो यह जो बातें हैं वह अपन यहां जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गहन तरीके से अपने को समझ लेना चाहिए और उसको आगे ले जाकर जहां जिसने गलती की है उसको अपने को कहने की जरूरत है ताकि हम और आप मिलकर राजस्थान का फायदा कर सकें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्रीजी यहां आने वाले हैं कुछ ही देर में। मैं एक कविता आपके सामने, एक शेर आपके सामने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रखकर छोड़ूंगी। पर मेरी पूरी बात और मैं समझती हूं कि मेरे सब माननीय सदस्यों की बात इस चीज के अन्दर है-

पूजा की तरह हम राज काम करते हैं,
जनता जनार्दन को नित्य प्रणाम करते हैं,
मुखालिफत से मेरी शख़्सियत सँवरती है,
मैं विपक्ष का बड़ा एहतेराम करती हूं।

और इतना कह कर मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूं, माननीय सदस्य और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मैडम।

प्रश्न यह है कि श्री शान्तिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.26 बजे सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं का क्रमोन्नयन

47. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं में प्रतिदिन 1000 से अधिक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जननी सुरक्षा योजना व टीकाकरण में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ब्लाक पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है?

(3) क्या सरकार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं का वर्ष 2007 में 1 लाख 30 हजार 934 का आउटडोर रहा है उक्त आउटडोर के आधार पर मरीजों की प्रतिदिन औसत संख्या 359 के लगभग रहती है।

(2) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर अभी तक कोई वरीयता सूची नहीं बनाई गई हैं।

पूर्ण टीकाकरण में 11 पंचायत समितियों ने उच्चतम 10 अंक प्राप्त किये थे, जिनमें गोविन्दगढ़ भी शामिल है।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किए जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना सम्भव हो सकेगा।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं

48. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पीपरोली, नयाबास, खिलौरा में पेयजल योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(2) उपरोक्त योजनाओं को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़, जिला अलवर के वर्णित गांवों हेतु हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक जल योजना में परिवर्तन की स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम खिलौरा की पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर माह जुलाई, 2007 से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्राम नयाबास एवं पिपरोली की जल योजना क्रमशः माह अप्रैल, 2008 एवं जून, 2008 तक पूर्ण करनी लक्षित है।

परिशिष्ट 'अ'

जिला अलवर के वर्णित गांवों हेतु स्वीकृत योजनाएं एवं इनकी प्रगति का विवरण

ग्राम का नाम	स्वीकृति का विवरण (माह/वर्ष)		स्वीकृत राशि रु. लाख में	योजना में सम्मिलित कार्य का विवरण	कार्यादेश दिनांक	योजना की वर्तमान स्थिति	योजना पूर्ण करने का माह/वर्ष	विशेष विवरण
	प्रशासनिक एवं वित्तीय	तकनीकी स्वीकृति						
पिपरोली	मार्च, 2006	अप्रैल, 2006	20.31	नलकूप-2 भू-तल जलाशय-5 पाइप लाइन-4.5 किलोमीटर	3 नवम्बर, 2006	नलकूप निर्माण कार्य पूर्ण। 4 भू-तल जलाशय का कार्य पूर्ण।	जून, 2008	1 नलकूप का निर्माण माह जनवरी, 2008 में पूर्ण हुआ है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य खेतों में फसल कटने के बाद प्रारम्भ करना है। भू-तल जलाशय निर्माण हेतु स्थान चयन प्रक्रियाधीन है।

1	2		3	4	5	6	7	8
नयाबास	मार्च, 2006 एवं संशोधित स्वीकृति अप्रैल, 2007	अप्रैल, 2006	7.00	नलकूप-1 भू-तल जलाशय-2 पाइप लाइन-1.3 किलोमीटर	25 नवम्बर, 2006	नलकूप निर्माण कार्य पूर्ण। 1 भू-तल जलाशय का कार्य पूर्ण। 1.0 कि.मी. पाइप लाइन का कार्य पूर्ण।	ढाणी लाभान्वित। मुख्य ग्राम को अप्रैल, 2008 तक लाभान्वित करना लक्षित है।	नरबाला बास ढाणी में 1 भू-तल जलाशय का निर्माण कर जून, 2007 से लाभान्वित कर दिया गया है। ग्राम में 1 भू-तल जलाशय निर्माण हेतु विद्यालय के समीप स्थल का चयन किया गया था परन्तु ग्रामवासियों द्वारा विरोध के कारण अन्य स्थान चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
खिलौरा	मार्च, 2006	अप्रैल, 2006	17.87	नलकूप-2 भू-तल जलाशय-2 पाइप लाइन-2.3 किलोमीटर	3 नवम्बर, 2006	समस्त कार्य पूर्ण।	योजना पूर्ण।	योजना से ग्राम में माह जुलाई, 2007 से 40 लीटर/व्यक्ति/दिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जयपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आरोपित व्यवस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही

49. श्री रामचन्द्र सराधना (जमआरामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कौन-कौन व्यवस्थापक गबन और अनियमितताओं के कारण निलम्बित/बर्खास्त किये गये? नाम, राशि, तिथि व आरोप का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गबन की राशि में से किस-किस व्यवस्थापक से कितनी कितनी राशि वसूल कर ली गई और कितनी राशि बकाया चल रही है? बकाया राशि के वसूलने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और अब कब तक यह राशि वसूल कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में गबन के कुछ इस प्रकार के प्रकरण भी थे जिनमें गबन की गई राशि में ऐसे सदस्यों की धनराशि भी थी जो व्यवस्थापक को जमा कराने के लिये दी गई थी? यदि हां, तो क्या रसीद के अभाव में उन सदस्यों से दुबारा से वसूली गई राशि को उन सदस्यों को वापस लौटाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में गबन और अनियमितता के कारण निलम्बित बर्खास्त व्यवस्थापकों के नाम, राशि, तिथि, आरोप का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वसूल की गई राशि, बकाया राशि एवं बकाया राशि की वसूली के लिये किये जा रहे प्रयास का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। वसूली कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के साथ सम्पूर्ण की जाने का प्रयास है।

(3) जी नहीं। ऐसे कोई मामले प्रकाश में नहीं आये हैं जिनमें राशि जमा कराने के बाद रसीद के अभाव में दुबारा वसूली कर ली गई हो।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में गबन/अनियमितता के कारण निलम्बित/बर्खास्त व्यवस्थापक एवं गबन राशि की वसूली बाबत स्थिति निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति जहां गबन हुआ	वर्ष	गबन राशि (लाखों में)	आरोप विवरण	तिथि		गबन राशि में से की गई वसूली	शेष राशि जो वसूल की जानी है (लाखों में)	वसूली के प्रयास
						निलम्बित	बर्खास्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री बद्री प्रसाद जाट	चंदवाजी	वर्ष 2004-05	1.45	गबन	3/8/2001	6/5/2004	-	1.45	उक्त गबन के प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57(1) के तहत जांच की जा रही हैं एवं प्रकरण में निर्णय उपरान्त ही राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 मे विही विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूली की जा सकेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	चौथमल शर्मा	चंदवाजी	वर्ष 2005-06	0.87	गबन	1/8/2005	-	-	0.87	श्री चौथमल शर्मा को सशर्त दिनांक 25.11.2005 को जांच लम्बित बहाल किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर खण्ड जयपुर के राजस्थान राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 57(2) के तहत दिये गये निर्णय दिनांक 19.09.2005 के अनुसार अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत वारन्ट जारी किया जा चुका है, प्रकरण में विक्रय अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री चौथमल के पास कोई संपत्ति नहीं है अतः श्री शर्मा का वेतन कर्क किया जाकर वसूली की जा रही है।

गोगुन्दा में प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

50. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कब से लगाई गई? इससे किस स्थान पर कितने-कितने काश्तकार लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी लिफ्टें चालू अवस्था में हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार अब लिफ्टें कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और लिफ्ट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक सर्वे कराकर चित्रावास, कमोल, पलासमा में काम प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जनजाति विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र गोगुन्दा में 7 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं लगायी गयी हैं। लिफ्ट सिंचाई योजना के नाम, लगाने का वर्ष, राशि, स्थान तथा लाभान्वितों की संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। चालू व बन्द लिफ्टों की (बन्द का कारण सहित) सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

बन्द लिफ्टों को पुनः प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना चित्रावास, कमोल, पलासमा के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम लिफ्ट सिंचाई योजना	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	लाभान्वितों की संख्या	वि. वि.
1	जोरमा	1992-93	1.38	8	चालू
2	कुण्डाऊ	1993-94	3.21	0	बन्द
3	उण्डीथल	1997-98	8.72	18	चालू
4	गुन्दाली	1997-98	3.85	13	चालू
5	पानेर	1985-86	2.18	7	चालू
6	रेबारियों का खेडा	1997-98	3.56	12	चालू
7	छिपाला	1999-2000	4.49	-	बन्द

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	नाम लिफ्ट सिंचाई योजना	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति	बन्द का विवरण
1	जोरमा	1992-93	1.38	चालू	
2	कुण्डाउ	1993-94	3.21	बन्द	विद्युत विभाग में लगभग राशि 45000.00 रु. बकाया होने से।
3	उण्डीथल	1997-98	8.72	चालू	
4	गुन्दाली	1997-98	3.85	चालू	
5	पानेर	1985-86	2.18	चालू	
6	रेबारियों का खेडा	1997-98	3.56	चालू	
7	छिपाला	1999-2000	4.49	बन्द	डीजल महंगा होने से लाभान्वित द्वारा योजना को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

निवाई की क्षतिग्रस्त सड़कें

51. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत कौन-कौनसी सड़क, कितनी दूरी की कहां-कहां व कितनी राशि से बनाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्मित सड़कों में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क अपने निर्धारित समय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समय से पूर्व सड़क क्षतिग्रस्त होने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?

(श्री हीरालाल)

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 1 जनवरी, 2004 के पश्चात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का वर्षवार विवरण लम्बाई एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	वर्ष	निर्मित लम्बाई कि.मी.	व्यय राशि लाखों में
1	2003-04	25.54	291.20
2	2004-05	18.93	201.27
3	2005-06	49.47	859.36
4	2006-07	55.41	935.80
	योग	**149.35**	**2287.63**

विधान सभा क्षेत्र निवाई में 1 जनवरी, 2004 के पश्चात बनाई गई सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त निर्मित सड़कों में से डागरथल से रम्भा सड़क बजरी के भारी यातायात के कारण तथा बनस्थली से मनोहरपुरा पर जलदाय विभाग की पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ स्थानों पर पेच हो गये थे।

(3) मरम्मत एवं रखरखाव अवधि (5 वर्ष) के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने पर निर्माण कर्ता संवेदक जिम्मेदार होता है। यदि कोई संवेदक मरम्मत एवं रखरखाव अवधि में मरम्मत कार्य नहीं करता है तो अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जाती है। क्योंकि उपरोक्त सभी सड़कें संवेदक द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव अवधि में हैं और संबंधित संवेदक द्वारा उनका मरम्मत कार्य अनुबन्ध के अनुसार सम्पन्न करा दिया गया है इसलिए किसी के खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी हां। उपरोक्त सभी सड़कें संवेदक द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव अवधि में हैं और संबंधित संवेदक द्वारा उनकी मरम्मत एवं रखरखाव कार्य अनुबन्ध के अनुसार सम्पन्न कराया जा रहा है।

परिशिष्ट- ''अ''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निवाई में निर्मित सड़कों का वर्षवार विवरण (01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक)

क्र. सं.	सड़क का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	निर्मित लम्बाई (किमी. में)
1	2	3	4
	वर्ष 2003-04		
1	बोर्ली निवाई रोड कि.मी. 32 से केरोद	33.00	3.20
2	कौथून लालसोट रोड कि.मी. 207 से जगसरा	19.87	1.70
3	मण्डावर से सीतारामपुरा	41.75	3.30
4	बगडी से अनवरपुरा खेडा	53.96	4.14
5	सुनारा से आंकौडिया	35.23	4.00
6	झिलाई सिन्दरा रोड कि.मी. 4 से मण्डलिया	46.21	4.20
7	नौहाटा से रामनगर धतुरी	61.18	5.00
	योग	291.20	24.54
	वर्ष 2004-05		
1	सम्पर्क सड़क रजवास से गुढा	16.50	1.53
2	बडा गांव से टोरडी वाया मेदारकलां	57.17	5.20
3	सुनारी से प्रतापपुरा	20.03	2.00
4	एन.एच. 12 से जयसिंहपुरा	47.53	4.20
5	चिरौज हथौना सड़क से सुकलपुरा	60.04	6.00
	योग	**201.27**	**18.93**
	वर्ष 2005-06		
1	निवाई डांगर थल सडक से हिंगोटिया	25.61	2.00
2	एन.एच. 12 से बहकवां	44.07	5.00
3	कोथून लालसोट सड़क से बुरटिया	14.88	1.00
4	नोहटा से रहड	46.87	4.00

1	2	3	4
5	बरोनी सिरस सड़क से दादीयान	43.73	2.68
6	देवपुरा से बिटोला	76.11	3.90
7	एन.एच. 12 से महाराजपुरा	15.39	0.70
8	डांगरथाल से रम्भा	91.56	4.10
9	बोनली निवाई सड़क से जीवली	82.58	3.22
10	चतरभुजपुरा से रतनपुरा रोहीडा	25.12	0.90
11	ललवाडी सड़क से भावती	33.37	1.90
12	निवाई डांगरल सड़क से चीकाना	37.29	1.84
13	वनस्थली से मनोहरपुरा	170.15	10.70
14	सोहेला डिग्गी सडक से काकराजकलां	57.19	3.05
15	बोरखंडी खुर्द से कारोलां	64.93	3.08
16	देवपुरा से हाजीपुरा (सुनैला)	30.51	1.40
	योग	**859.36**	49.47
	वर्ष 2006-07		
1	एन.एच. 12 से दोताना	61.61	3.03
2	सिन्दरा से बडोदिया उर्फ भंवरसागर	41.49	2.50
3	सम्पर्क सड़क बडागांव से खाजपुरा	25.37	1.50
4	केरोद से आन्नदपुरा	75.71	5.00
5	लुहारा से बीचपुडी	51.76	3.16
6	बस्सी से खेडा	55.13	3.68
7	राहोली सड़क से कनेशर	32.29	1.83
8	बनस्थली से लोदेड़ा	14.73	0.88
9	रहोली सड़क से काचरिया	32.70	1.24
10	दहलोद कुरावदा सड़क से सीपुरा	15.34	0.80
11	झीलाई सिरोही सड़क से गंगापुरा	11.97	0.86
12	बस्सी से खेडी मानपुरा	58.96	4.05
13	मुण्डीया से बाडदामोदरपुरा	43.37	2.75
14	सम्पर्क सड़क लुनेरा	16.19	1.00
15	बरोनी सिरस सड़क से अभेयपुरा	23.92	1.38
16	राहोली सड़क से पथराज नुस्तर्का	25.14	1.30

1	2	3	4
17	बरानी सिरस सड़क से नारवाडी	17.31	1.00
18	जुजारपुरा से दामोदरपुरा	29.37	1.05
19	रजवास से गिरधारीपुरा	32.22	2.11
20	सम्पर्क सड़क रामचन्द्रपुरा	11.38	0.61
21	सोहिला डिग्गी सड़क से जेबाडिया	38.93	2.05
22	राहोली सड़क से नगर वाया रामपुर	112.64	5.51
23	कोथून सड़क से जसोदानन्दपुरा	21.66	1.06
24	कोथून सड़क से बंसीपुरा	36.61	2.46
25	देवपुरा से करिरिया	50.10	4.60
	योग :-	**935.80**	**55.41**

तारांकित प्रश्न संख्या-52

(स्थगित)

झालावाड़ का नवनिर्मित चिकित्सालय भवन

53. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंज मण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ में 300 बैड के ए श्रेणी के अस्पताल का भवन निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उसके निर्माण में कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और अस्पताल कितने माह में बन कर तैयार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नये अस्पताल भवन में मरीजों का इलाज आरम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय एस.आर.जी. चिकित्सालय, झालावाड़ के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों पर 15 फरवरी, 2008 तक 25 करोड़ 53 लाख 58 हजार रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(2) उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य दिनांक 4.3.2005 को प्रारम्भ हुआ। राजकीय एस.आर.जी. चिकित्सालय का मुख्य भवन 31 माह में बन कर तैयार हुआ है।

(3) नये चिकित्सालय भवन में पैथोलाजी, रेडियोलाजी, सर्जरी एवं टेलिमेडिसन विभागों की सेवायें दी जा रही हैं।

पाली जिले के बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में निर्मित एनीकट

54. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 18 जुलाई, 2003 व 2 सितम्बर, 2003 को विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति गठित कर सिंचाई विभाग को बांधों के उपर बने हुये एनीकटों की स्थिति जानने का आदेश दिया था? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार ने शासन सचिव सिंचाई विभाग को उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला स्तरीय समिति बनाकर दिनांक 5 जनवरी, 2004 तक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति को भेजने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो उस अर्धशासकीय टीप दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शासन सचिव, सिंचाई विभाग ने दिनांक 15 नवम्बर, 2003 को जिला स्तर पर सर्वेक्षण के लिये कोई कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गये थे? यदि हां, तो कमेटी बनाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें और जिला स्तर की उन समितियों ने कब-कब बैठकें कीं और अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति को कब भेजी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पाली जिले के दीपावास लूणी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में कई एनीकट बने हुये हैं? क्या जिला स्तरीय समिति ने उन एनीकटों की सूची बनाई है? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायपुर में बने हुये, रायपुर दीपावास बांध, गजनाई बांध, जसवंत सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में बने हुए एनीकटों को माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1536/03 में दिये गये निर्देश के अनुसार तोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जल ग्रहण क्षेत्रों में हुए निर्माण एवं खनन कार्यो से जल प्रवाह में उत्पन्न हुए अवरोध की पहचान करने हेतु राज्य सरकार को विशेषज्ञों से सर्वेक्षण कराकर छह सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। जिला स्तर की समितियों की बैठक एवं विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट संबंधी विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। उन एनीकटों की भराव क्षमता बहुत कम होने एवं इनमें से अधिकांश सर्वेक्षण के समय क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण इनका दीपावास रायपुर लूणी बांध की भराव क्षमता पर नगण्य प्रभाव मानते हुए जिला स्तरीय समिति ने इनको अवरोधों की सूची में सम्मिलित नहीं किया है।

(5) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1536/2003 में जल ग्रहण क्षेत्रों में हुये ऐसे निर्माण जिनसे पानी की आवक में कोई अवरोध नहीं होता हो, को तोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया गया हैं।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

दी पाली सैन्ट्रल का-आपरेटिव बैंक, पाली के कर्मिकों का पदोन्नति प्रकरण

55. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में दी पाली सैन्ट्रल का-आपरेटिव बैंक लि., पाली के कर्मचारियों की ''डी'' ग्रेड हेतु पदोन्नति की गई थी? यदि हां, तो किस आधार पर?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति के वक्त कुछ कर्मचारियों की ए.सी.आर. में कांट-छांट या हेरा-फेरी पाए जाने पर बैंक प्रशासक या सक्षम अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदण्ड वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई। विभागीय परिपत्रों/अधिसूचना की प्रतियां परिशिष्ट-1 से 7 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में कांट-छांट पाये जाने पर बैंक प्रशासक द्वारा जांच के आदेश दिये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

जनजाति उपयोजना/सहरिया क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित राशि

56. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में गत दो वर्षो से कौन-कौनसी योजनायें संचालित हैं एवं संचालित योजनाओं में सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त योजनाओं में प्रत्येक में आबंटित राशि में से कितनी राशि विकास हेतु व्यय की गई एवं कितनी राशि अनुपयोगी अब तक शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आदिवासी एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु योजनाओं की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु ठोस उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) हेतु गत 2 वर्षों में संचालित योजनाओं में सरकार द्वारा निम्न राशि स्वीकृत की गई-

(राशि लाखों में)

मद	2005-06		2006-07	
	जनजाति उपयोजना क्षेत्र	**सहरिया क्षेत्र**	**जनजाति उपयोजना क्षेत्र**	**सहरिया क्षेत्र**
महाराष्ट्र पेटर्न	6291.18	414.55	5297.16	325.82
विशेष केन्द्रीय सहायता	1334.13	102.38	2078.03	109.65
धारा 275 (1)	930.94	3.00	2408.13	125.00
राज्य योजना	24.15	-	30.00	-
के.प्र. योजना	4.75	-	17.67	-
सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम	-	60.00	-	-
योग	**8585.15**	**579.93**	**9830.99**	**560.47**

(जनजातिय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

योजना का नाम व राशि का प्रावधान परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-08 में माह जनवरी, 08 तक निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित हुई राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

जनजाति उपयोजना क्षेत्र :			
योजनाएं	**राशि**	**व्यय**	**शेष व्यय की जानी**
कोषालय द्वारा संचालित	513.80	307.42	206.38
निजी निक्षेप खाते से संचालित	2364.93	1424.26	940.67
योग	**2878.73**	**1731.68**	**1147.05**
सहरिया क्षेत्र :			
निजी निक्षेप खाते से संचालित	175.75	65.88	109.87

योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार आदिवासी एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु योजनाओं की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु ठोस उपाय करने का विचार रखती है? योजनाओं की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर से राज्य स्तर तक नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य उच्च मार्ग संख्या-7 के निर्माण कार्यों की जांच

57. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राज्य उच्च मार्ग संख्या-7 का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो इस मार्ग की प्रति किलोमीटर लागत कितनी है?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांच के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो अब तक हुए कार्य की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई एवं जांच में क्या-क्या कमियां पाई गई? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण शिकायतों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि रिडकोर को राज्य के प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कार्य सौंपे गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य सौंपे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की रिडकोर के साथ किसी प्रकार की हिस्सेदारी है? यदि हां, तो कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है और आज तक राज्य सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया? दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मेगा हाई-वे का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं टोल टैक्स की राशि कितने वर्षो तक वसूलना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में उच्च मार्ग संख्या-7 का निर्माण किशनगढ़ से हनुमानगढ़ तक मेगा हाइवे परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसकी प्रति किमी. लागत रुपये 1.18 करोड़ है।

(2) जी हां। यह सही है कि राजस्थान सरकार ने मेगा हाइवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक स्वतंत्र अभियन्ता (कार्यवेक्षक) को मनोनीत किया है। जिसके कार्य क्षेत्र में सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांच सम्मिलित है। इस कार्य पर दिसम्बर, 2007 तक कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी प्रति संलग्न है। कार्य की जांच स्वतंत्र अभियन्ता द्वारा की जा चुकी है एवं कार्य की जांच में कोई भी कमियां नहीं पाई गई हैं। जांच की प्रति संलग्न है।

(3) प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य सरकार द्वारा रिडकोर के निदेशक मण्डल में मनोनीत सदस्य हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निदेशक से अपेक्षित सभी कार्य उनके द्वारा संपादित किये जाते हैं।

(4) रिडकोर की अंशपूंजी 50 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य सरकार की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक अंशपूंजी के रूप में कुल रुपये 25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जो निम्न है :-

1. रुपये 5 करोड़   10.1.2005
2. रुपये 20 करोड़   27.9.2005

(5) उक्त परियोजना का सड़क कार्य मुख्यतः पूर्ण कर लिया गया है

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष कार्य जिसमें आर.ओ.बी. एवं दो बाइपास सम्मिलित हैं, को अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा अनुबंध के अनुरूप परियोजना सड़क मार्गों पर रिडकोर द्वारा टोल टैक्स की राशि 30 वर्षों तक वसूला जाना प्रस्तावित है।

(जांच प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र के उप-खण्ड कार्यालयों का स्थानान्तरण प्रकरण

58. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिद्धमुख नोहर परियोजना में कितने उप निवेशन खण्ड कार्यालय कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त खण्ड कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्यों व कहां-कहां?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन का कोई खण्ड कार्यालय कार्यरत नहीं हैं।

(2) जब उपनिवेशन खण्ड कार्यरत ही नहीं है, तो स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं है।

मालपुरा एवं टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

59. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा एवं टोडारायसिंह के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा एवं टोडारायसिंह के चिकित्सा संस्थानों में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 2 पद एवं चिकित्सा अधिकारी के 8 पद रिक्त हैं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा एवं टोडारायसिंह के चिकित्सा संस्थानों में कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार है :

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	2/08
	चिकित्सा अधिकारी	2	10/07 6/06
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली	चिकित्सा अधिकारी	3	12/07 6/06 5/07
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडवास	चिकित्सा अधिकारी	1	03/05
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हमीरपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	10/07
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	1/07
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिग्गी	चिकित्सा अधिकारी	1	7/05

बांधों से अपूर्ण सिंचाई पर शुल्क वसूली में छूट

60. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थित विभिन्न सिंचाई बांधों के अंतिम छोर में स्थित भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध तरीके से पूरा पानी उपलब्ध नहीं करवा पाने तथा मात्र एक ही पानी पहुंचा पाने पर फसलें खराब होने के बावजूद भी सिंचाई शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के तहत?

(2) क्या फसलों को वांछित पानी नहीं मिलने पर होने वाले खराबे पर सिंचाई शुल्क वसूल नहीं किये जाने संबंधी निर्देश सरकार द्वारा जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो इस संबंधी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं तो अब सरकार इस संबंध में निर्देश कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई मैन्युअल के भाग IV के बिन्दु संख्या 14 की प्रति संलग्न है।

(2) सरकार समय-समय पर ऐसी परिस्थिति में अपने स्तर पर विचार कर रियायत संबंधी निर्णय भी लेती रही है।

सिंचाई मैन्युअल के भाग IV के सार की प्रति

भाग IV

माफी/छूटें (Remissions)

14. (i) नहर अधिनियम के अधीन नियम 17 एवं 28 के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी को निम्न प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए किसी खेत पर साधारण रूप से आरोप्य दर को कम करने की अधिकृति है-

(क) नहर से होने वाली जलापूर्ति नहीं होने या बन्द होने पर।

(ख) टिड्डी, ओलावृष्टि, बाढ, तुषार (Frost) या ऐसी अन्य आपदा जो जलापूर्ति नहीं या बन्द होने के सिवाय हो, वह चाहे सूखा या किसी अन्य समय हो

परन्तु यह है कि वह क्षति कृषक की ओर से किसी लापरवाही या यदि वह खरीफ की फसल है तो वह ऐसी भूमि पर नहीं उगाई गई है जो कि वर्षा ऋतु में सामान्यतया बाढ़ में आती है।

(ii) जब भी एक नहरी सिंचाई की फसल को ऐसी क्षति होती है तो खण्डीय अधिकारी को तुरन्त उसकी सूचना दी जायेगी। खण्डीय अधिकारी एक उत्तरदायी अधिकारी से उन खेतों के निरीक्षण करवाने की तुरन्त व्यवस्था करेगा, और निरीक्षण करने वाला अधिकारी वहां की स्थिति के हालात का एक विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र भेजेगा।

(iii) ऐसे मामले में छूट या माफी की सीमा का निर्धारण करने हेतु, खण्डीय, अधिकारी, साधारणतया, निम्नलिखित दरों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा :-

क्षति का प्रतिशत	छूटें/माफी
50% के नीचे	शून्य
50% तथा इससे ऊपर परन्तु 75 % से नीचे	आधी जल-दर
75% तथा इससे ऊपर	पूर्ण छूट/माफी

(iv) (क) जब बीज का प्रजनन अफसल होने के कारण, फसल असफल हुई है तो प्रभार योग्य दर से कम दर आरोपित नहीं की जायेगी अर्थात यदि वह उछाल सिंचाई (lift irrigation) है तो उछाल की निम्नतम दर से कम नहीं होगी।

(ख) नये रूप से उगाये गये गन्ने पर, जिसे पिलाई की गई है परन्तु प्रजनन असफल हो गया है या मानसून आने से पूर्व किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है, दखलदार की दर निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ग) पिलाई किये गये रतून (Ratoon) गन्ने, परन्तु जो नष्ट हो गया है तथा जिसे मानसून आने के पूर्व जोता गया है को दखलदार की दर की आधी छूट दी जायेगी।

कोटा जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु भू-आबंटन

61. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों में अनाज, खाद, कृषि उपज की भण्डारण व्यवस्था में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के उपयोग को ध्यान में रख कर गोदाम बनाना प्रस्तावित है या बनवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन-किन समितियों में गोदाम का निर्माण करवाया गया या फिर करवाया जाना प्रस्तावित है?

(श्री भरत सिंह)

(2) गोदाम निर्माण पर सहकारी समितियों को कितना अनुदान राज्य व केन्द्र सरकार से प्रदान किया जा सकता है तथा कितने प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समिति को अपने पास से व्यवस्था करनी पड़ती है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार सहकारी समितियों को पंचायत से गोदाम निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाती है? यदि हां, तो जिला कोटा में कितनी समितियों को सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई तथा कहां-कहां गोदाम निर्माण करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना एवं रीस्ट्रक्चर्ड सैट्रल सैक्टर स्कीम फार स्टोरेज योजनान्तर्गत 407(अ-1) सहकारी समितियों के गोदाम निर्माणाधीन हैं व 134, (अ-II) समितियों के गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं। सूची जिलेवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा रीस्ट्रक्चर्ड सैंट्रल स्कीम के अंतर्गत कुल लागत का 20 प्रतिशत अनुदान एवं क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजनान्तर्गत कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। दोनों स्कीमों के अंतर्गत समिति का अंशदान इकाई लागत का 10 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं है। दोनों स्कीमों के फंडिंग पैटर्न संलग्न है। (परिशिष्ट 'ब')

(3) जी हां। ग्राम पंचायतों द्वारा 394 सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। जिला कोटा में 4 समितियों को ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। जो परिशिष्ट 'अ'-I के क्रम संख्या के क्रमांक 195 से 198 तक पर अंकित है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ-I' एवं 'अ-II' के कालम संख्या 7 पर अंकित है।

(सूची/ सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास-मेहन्दीपुर बालाजी सड़क मार्ग का दोहरीकरण

62. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बामनवास से मेहन्दीपुर बालाजी 60 किलोमीटर है और इस दूरी पर 40 किलोमीटर सड़क डबल बनाई जा रही है?

(श्री बत्तीलाल)

(2) क्या यह सही है कि बन्दमोरा सागर से गुढाचन्द्रजी वाया दलपुरा होकर डबल सडक का निर्माण किये जाने पर दो जिलों की जनता को आवागमन की सुविधा हो जायेगी? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा जनहित कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बामनवास से मेहन्दीपुर बालाजी की दूरी 62.0 किमी. है। 62.0 किमी. में से 4.50 किमी. पूर्व में 5.50 मीटर चौड़ाई में बनी हुई है तथा 27.0 किमी. में 3.0 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है।

(2) इस सड़क का डबल लेन बनाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

बूंदी जिले में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत समर्पित भूमि का आबंटन

63. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि भूमि के समर्पण करने के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किन-किन आधारों पर कृषि भूमि का समर्पण करने के प्रावधान हैं?

(2) गत 5 वर्षों में बूंदी जिले में किस-किस अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्ग के लोगों ने किस-किस तहसील के किस-किस गांव में कितने-कितने खसरा नम्बर का कितना-कितना रकबा समर्पण करने हेतु आवेदन किया और उन आवेदनों को कब-कब स्वीकार किया?

(3) गत पांच वर्षों में बूंदी जिले के किस-किस पटवार सर्किल में किस-किस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि का समर्पण स्वीकार किया गया?

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य वर्ग के लोगों द्वारा समर्पित भूमि पर इस समय किस-किस वर्ग के लोगों का कब्जा है तथा समर्पित भूमि में से किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी भूमि सालाना नीलामी कर जोत के लिये किस-किस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा रही है?

(5) सरकार द्वारा उक्त वर्षों में बूंदी जिले में समर्पित भूमि को किन-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किन व्यक्तियों को कब-कब आबंटित की गई और कितनी भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध है तथा उस भूमि को कब तक आबंटित कर दिया जायेगा?

(6) क्या नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा समर्पित भूमि को इन जातियों के अलावा अन्य वर्ग के लोगों को आबंटित नहीं की जा सकती? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनिमितता बूंदी जिले में होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के अन्तर्गत कोई अभिधारी अपनी जोत का समर्पण कर सकता है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) सूचना परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) सूचना परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। तहसील हिण्डौली एवं नैनवां की 411.14 बीघा समर्पित सिवाचयक भूमि उपलब्ध है जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत आबंटन की उदघोषणा जारी कर पात्र व्यक्तियों को आबंटन किया जा सकेगा।

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वारा समर्पित भूमि को अन्य वर्गों के लोगों को आबंटन किया जा सकता है। यह अनियमितता नहीं है। राज्य सरकार के पत्र दि. 19.08.2000 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट 'ध') इस संबंध में शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गीतांजली मेडिकल कालेज/चिकित्सालय, उदयपुर में आरक्षित वर्ग हेतु छूट

64. **श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में गीतांजली मेडिकल कालेज व हास्पिटल खोलने की स्वीकृति उदयपुर में दी गई है? यदि हां, तो क्या गीतांजली मेडिकल कालेज व हास्पिटल को अनुदानित दर पर भूमि आबंटित की गई?

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(2) क्या गीतांजली मेडिकल कालेज में फ्री व पेमेंट सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या गीतांजली हास्पिटल में बी.पी.एल. कार्डधारी एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के रोगियों के लिये नियमानुसार कोई विशेष प्रावधान है? यदि हां, तो क्यो?

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा गीतांजली फाउण्डेशन, उदयपुर को मेडिकल कालेज चिकित्सालय हेतु दस एकड़ भूमि आरक्षित दर की 35 प्रतिशत दर पर आबंटित की गई।

(2) फ्री सीट का अब कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 5041/2005 में दिनांक 12.8.2005 को निर्णय पारित कर निजी मेडिकल/दन्त कालेजों की समस्त सीटों को प्रबन्धन सीटें निर्धारित कर दिया गया है। स्वीकृत सीटों में कोई राजकीय कोटा नहीं होने के कारण प्रबन्धन सीटों पर आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। फिर भी प्रबंधन की सहमति प्राप्त कर आरपीएमटी के माध्यम से आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी भर्ती करवाने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी हां। पालिसी टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हैल्थ केयर फेसिलिटी-2006 के बिन्दु जी (ए) (IV) के अनुसार 10 प्रतिशत बिस्तर बीपीएल रोगियों के लिए आरक्षित रखने होंगे। बीपीएल रोगियों का उपचार नि:शुल्क किया जायेगा तथा दवाइयों व परीक्षण पर व्यय होने वाली राशि की मात्र 25 प्रतिशत राशि ही वसूल की जा सकेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरदारशहर में हुई डीजल अनियमितताओं के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

75. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सरदारशहर में हुए डीजल घोटाले के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो आरोप पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लोकायुक्त द्वारा भी इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सी.आई.डी. (सीबी) के अनुरोध पर एक तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि डीजल घोटाले से सम्बन्धित कई लॉग बुकें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त लॉग बुक्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरदार शहर ग्रामीण उपखण्ड का रतनगढ़ राजस्व उपखण्ड में हस्तांतरण किया गया है? यदि हां, तो उक्त रिकार्ड किस अधिकारी को एवं कब हस्तांतरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 15.05.2006 की अनुपालना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रकरण वर्तमान में पुलिस विभाग में अनुसंधान में है।

(2) जी नहीं।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। समिति द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट (प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध) पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) डीजल चलित योजनाओं में से जल योजना ढाणी, तेतरवाल से संबंधित दिनांक 14.11.2002 से 6.5.2003 तक की अवधि की लॉग बुक विभाग को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में पुलिस विभाग के पास अनुसंधान में है। शेष लॉग बुक्स प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी हां। शासन उप सचिव-प्रथम की आज्ञा दिनांक 22.05.2007 के अनुसार ग्रामीण उपखण्ड, सरदारशहर का स्थानान्तरण राजस्व उपखण्ड, रतनगढ़ में किया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख सहायक अभियन्ता, राजस्व उपखण्ड, रतनगढ़ के अधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

खारची विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

76. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में जनवरी, 2004 से अब तक कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं कहां-कहां कितनी लागत की स्वीकृत हुई? सम्पूर्ण स्वीकृत कार्य मय हैण्डपम्प योजना के कार्यवार, वर्षवार, योजनावार मय कार्यस्थल सहित स्वीकृत/व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित योजनाओं की सूची मय अनुमानित लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक स्वीकृत विभिन्न जल योजनाएं एवं हैण्डपम्पों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील	स्वीकृत योजना	पूर्ण योजना	राशि रु. (लाख में)	
			स्वीकृत	व्यय
स्वीकृत पेयजल योजनाएं				
मारवाड़ जंक्शन	69	58	579.43	152.87
देसूरी	34	31	134.77	51.09
योग	**103**	**89**	**714.20**	**203.96**
स्वीकृत हैण्डपम्प				
मारवाड़ जंक्शन	370	356	224.21	208.37
देसूरी	125	113	61.50	53.28
योग	**495**	**469**	**285.71**	**261.65**

स्वीकृत योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के संदर्भ में वांछित विवरण मय व्यय राशि के क्रमश: संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र की किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की कार्यरत/बन्द पेयजल योजनाएं

77. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में कितनी पेयजल योजनाएं संचालित एवं कितनी बन्द हैं? योजनाओं के बन्द होने के क्या कारण हैं एवं उन्हें सरकार अब कब तक चालू करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में टोडाभीम तहसील के 1 शहर एवं 100 ग्राम तथा नादौती तहसील के 85 ग्राम सम्मिलित हैं।

उक्त क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	लाभान्वित शहर एवं ग्राम
टोडाभीम	पाइप्ड	4	1 शहर टोडाभीम व 3 ग्राम
	क्षेत्रीय	10	25 ग्राम
	पम्प एवं टैंक	34	34 ग्राम
नादौती	पाइप्ड	2	2 ग्राम
	क्षेत्रीय	8	43 ग्राम
	पम्प एवं टैंक	13	13 ग्राम
	योग	**71**	**1 शहर व 120 ग्राम**

शेष 65 गांव हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। समस्त योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं।

सहाड़ा की पेयजल योजनाएं

78. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाडा, रायपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से किस-किस गांव में किस-किस स्थान पर हैंडपम्प, ट्यूबवैल एवं पनघट योजनायें किस-किस मद से लगाये गये? उपरोक्त सभी में से किन-किन में पर्याप्त पानी आया व कितने में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा एवं रायपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 की अवधि में विभिन्न मदों में कुल स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूप एवं पनघट योजनाएं (सिंगल फेस पम्प सैट मय पी.वी.सी. टैंक) का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम	स्वीकृत संख्या	स्थापित संख्या	विशेष विवरण
हैण्डपम्प	445	443	2 (वेधन के समय असफल)
नलकूप	8	6	वर्ष 2003-04 में निर्मित 4 नलकूपों में से 3 नलकूप 2 वर्ष की अवधि तक कार्यशील रहे। तदुपरान्त कोलेप्स होने से वर्तमान में परित्यक्त हैं। 2 का निर्माण अप्रैल, 2008 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
पनघट	34	4	30 पनघट (सिंगल फेस पम्प सैट मय पी.वी.सी. टैंक) का वेधन कार्य पूर्ण। स्थापना का कार्य अप्रैल, 2008 तक पूर्ण करना प्रस्तावित।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपरोक्तानुसार वेधन के समय असफल रहे 2 हैण्डपम्प, 3 कोलेप्स नलकूप एवं 2 नलकूप (जिनका वेधन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है) के अतिरिक्त शेष निर्मित सफल हैण्डपम्प, नलकूप एवं पनघट में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पचेवर (मालपुरा) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

79. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम पचेवर में दूधली माताजी के चरागाह को आबादी में परिवर्तित किये जाने के आदेश निरस्त करने का कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार उक्त चरागाह को नियम विरुद्ध आबादी में परिवर्तित करने के आदेशों को निरस्त कर उक्त चरागाह भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला कलक्टर द्वारा चरागाह भूमि को आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 1.3.04 नियमानुसार नहीं होने के कारण उसे राजकीय आदेश दिनांक 23.10.07 के द्वारा अपास्त कर दिया गया है।

राजकीय आदेश दिनांक 23.10.07 की अनुपालना में अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

सम्भागीय आयुक्त कार्यालय अजमेर में लम्बित जांच प्रकरण

80. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से अब तक संभागीय आयुक्त अजमेर को किन-किन मामलों की जांच सौंपी गई? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) संभागीय आयुक्त अजमेर ने उक्त अवधि में किन-किन मामलों

(श्री संयम लोढ़ा)

की जांच रिपोर्ट कब-कब राज्य सरकार को सौंपी? रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक रिपोर्ट की कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक संभागीय आयुक्त अजमेर को जिन चार मामलों में जांच सौंपी गई उन आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) संभागीय आयुक्त अजमेर के द्वारा जिन तीन मामलों की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है, उनकी प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। प्राप्त रिपोर्टो पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) एक प्रकरण माण्डल (जिला-भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक घटना घटित होने के प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण पूरी नहीं की जा सकी है।

(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सम्भागीय आयुक्त कार्यालय जयपुर में लम्बित जांच प्रकरण

81. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 से अब तक जयपुर संभागीय आयुक्त को किन-किन मामलों की जांच सौंपी गई? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा उक्त अवधि में किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट कब-कब सरकार को सौंपी गई? रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक रिपोर्ट की कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक संभागीय आयुक्त, जयपुर को जिन 11 मामलों की जांच सौंपी गई उन आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) संभागीय आयुक्त, जयपुर के द्वारा जिन 8 मामलों की जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है जिनकी प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलगन है।

प्राप्त रिर्पोटों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) परिशिष्ट 'स' में उल्लेखित है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

धोद की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

82. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में तहसील सीकर की गोचर भूमि पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण सामने आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) गत 5 वर्षो में ग्राम धोद (सीकर) में गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमणों के संबंध में कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा इनमें से न्यायालय में कितने प्रकरण गये तथा उन पर क्या निर्णय हुआ तथा न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है? सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील सीकर क्षेत्र की गोचर भूमि पर गत 5 वर्षो में 1386 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हुए थे, जिन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई।

(2) गत 5 वर्षो में ग्राम धोद (सीकर) की गोचर भूमि पर अतिक्रमण के 4 प्रकरण तहसील कार्यालय, सीकर में दर्ज हुए, जिनमें नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में इस अवधि का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

पंचायत समिति क्षेत्र सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) के काश्तकारों के लम्बित पट्टे

83. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गत वर्ष सैटलमेन्ट के समय किन किन ग्रामों के नक्शे नहीं थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र सज्जनगढ़ का भी सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार कितने काश्तकारों को पट्टे नहीं दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गत वर्ष सैटलमेन्ट के समय 22 ग्रामों के नक्शे नहीं थे, विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1	काला खूंट	12	मैराना
2	लसोडिया	13	सज्जनगढ़
3	भीलकुआं	14	जीवा खूंटा
4	माण्डली कलां	15	भडवेल
5	अगोरिया	16	मोतीया
6	गोदवाडा मनजी	17	हैजामोगजी
7	हैजा भावजी	18	गोदावाडा नारेगं
8	टोडी कालू	19	चनावाला
9	सांगवा	20	टाडा मंगला
10	बिजलपुरहलिया	21	भूरा कुआं
11	बीछावाडा	22	महुडिया बज्जा

(2) जी हां। 138 काश्तकारों को पर्चा लेने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण पर्चे नहीं दिये जा सके हैं। इन पर्चो को कार्यालय की बी फाइल में रखा गया है। उनके उपस्थित होने पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। 7 काश्तकारों का मौके पर कब्जा नहीं होने एवं कृषकों की पहचान भू.अ.नि. पटवारी, वार्ड पंच,

(राजस्व मंत्री)

सरपंच एवं मौतबिरान द्वारा नहीं करने के कारण पर्चे नहीं बनाये गए हैं। विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

जिन 7 कृषकों का मौके पर कब्जा नहीं होने से जिनके पर्चे नहीं बनाये गये का विवरण

क्र.सं.	नाम कृषक	नाम ग्राम	खाता संख्या
1	जोती पिता बज्जा भील	मैराना	18
2	वरसिंग पिता मनजी भील	मैराना	51
3	सवला पिता दीपा भील	मैराना	63
4	खेमा पिता जोरजी भील	माण्डली (बी)	8
5	तेजा पिता चमना भील	माण्डली (बी)	13
6	आबादी भूखण्ड श्री सरकार	अगोरिया	67
7	चून्नी बेवा नूरा बगैरह	गोदावाडा मनजी	18

तहसील कुशलगढ़ के 22 ग्रामों में पर्चा वितरण की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	राज प्रत जमाबन्दी के खाते	भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खाते	कृषकों को वितरित खाते	जो कृषक पर्चा लेने नहीं आये उनके खाते	कब्जा नहीं होने से पर्चे नहीं बने नाम कृषक
1	2	3	4	5	6	7
1	बीजलपुर (हलिया)	81	89	89	-	
2	बीछावाड़ा	59	65	65	-	
3	चनावाला	119	130	130	-	
4	जीवाखूंटा	167	175	175	-	
5	म्हुड्या बज्जा	108	121	121	-	

1	2	3	4	5	6	7
6	सांगवा	194	292	292	-	
7	गोदावाडा नारेंग	86	86	86	-	
8	अगोरिया	69	68	68	-	आबादी भूखण्ड श्री सरकार
9	हैजा मोगजी	69	69	69	-	
10	कालाखूंटा	108	117	117	-	
11	गोदावाडा मनजी	54	52	51	-	चून्नी बेवा नूरा बगैरह
12	हैजा भावजी	68	68	68	-	
13	मोतिया	86	112	112	-	
14	भूराकुआं	199	208	208	-	
15	टोडीकालू	125	151	97	54	
16	मैराना	88	88	83	2	जोती पिता बज्जा भील वरसिंग पिता मनजी भील सवंला पिता दीपा भील
17	लसोडिया	110	120	104	16	
18	भडवेल	172	205	162	43	
19	भीलकुआ	59	59	49	10	
20	सज्जनगढ़	48	51	31	20	
21	माण्डली (बी)	35	35	33	-	खेमा पिता जोरजी भील तेजा पिता चमना भील
22	टांडा मंगला	311	362	362		

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

(स्थगित)

श्रीडूंगरगढ़ के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

85. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कुल कितने राजस्व गांव हैं व उनकी आबादी जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ढाणियों को नये राजस्व ग्राम बनाने के मानदण्ड कया हैं? विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में ऐसी कितनी-कितनी ढाणियां हैं, जो राजस्व ग्राम बनाने के मानदण्ड को पूरा करती हैं? क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नाम व जनसंख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील श्रीडूंगरगढ़ के 97 राजस्व ग्राम एवं तहसील क्षेत्र सुजानगढ़ के 45 ग्राम आते हैं, जिनकी वर्ष 2001 की ग्रामवार जनसंख्या की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) ढाणियों/मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड परिपत्र क्रमांक:प.9(16) ग्रुप-1/07 दिनांक 19.03.07 के अनुसार यह है कि मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे सुदूर आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई ढाणियों को नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए उनकी आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में 200 से कम न हो इसके बाद मूल राजस्व ग्रामों की आबादी क्रमशः 250 एवं 200 से कम नहीं रहे। जिन ढाणी/आबादी को नया राजस्व ग्राम घोषित किया जा रहा है वे ढाणियों/आबादी मूल राजस्व से कम से कम 1 कि.मी. की दूरी पर हो। एक राजस्व ग्राम से एक या एक से अधिक नये राजस्व ग्राम तो बन सकते हैं, परन्तु नवीन प्रस्तावित राजस्व ग्राम में किन्हीं दो या दो से ज्यादा ग्रामों का क्षेत्रफल नहीं हो।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र की श्रीडूंगरगढ़ में कोई ढाणी राजस्व ग्राम बनने के मानदण्ड पूरे नहीं करती है।

परिशिष्ट 'क'

श्रीडूंगरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

जनसंख्या 2001 के अनुसार

क्र.सं.	**नाम राजस्व ग्राम**	**जनसंख्या वर्ष 2011**
1.	बिग्गा	5374
2.	बिग्गा बास रामसरा	3476
3.	सातलेरा	965
4.	बासी हिरावतान	गै.आ.
5.	बासी मारनोतान	गै.आ.
6.	धीरदेसर चौटीयान	3944
7.	कीतासर भाटीयान	2294
8.	कीतासर बीदावतान	1550
9.	शीतलनगर	345
10.	मोमासर	10191
11.	लिखमादेसर	2817
12.	लालासर	699
13.	कुन्तासर	1969
14.	सत्तासर	1410
15.	रैवाडा	269
16.	इन्द्रपालसर सांखलान	1040
17.	इन्द्रपालसर हिरावतान	1172
18.	इन्दपालसर राईकान	543
19.	इन्दपालसर गुसाईसर	1324
20.	इन्दपालसर बडा	1584
21.	अमृतवासी	1128
22.	सूरजनवासी	147
23.	धर्मास	826
24.	नोसरिया	805
25.	मिगसरिया	1122
26.	रीडी	8439

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	जनसंख्या वर्ष 2011
27.	अभयसिंहपुरा	717
28.	बापेउ	2807
29.	बापेउ पुरोहितान	823
30.	सावंतसर	3706
31.	लिखमीसर उत्तरादा	3837
32.	लिखमीसर दिखनादा	1185
33.	राजेडू	2860
34.	बरजांगसर	2721
35.	केउ	1634
36.	जाखासर	2383
37.	जाखासर भौम सिंघावतान	745
38.	जाखासर भौम उदयकरणावतान	गै.आ.
39.	उपनी	3389
40.	कल्याणसर	2281
41.	कल्याणसर नया	2710
42.	बाडेला	2614
43.	धनेरू	4084
44.	सोनियासर मीठिया	1705
45.	सोनियासर उचाईडा	754
46.	सोनियासर शिवदानसिंह	1394
47.	सोनियासर गोदारान	469
48.	सोनियासर गोगलियान	387
49.	राणासर नरूकान	331
50.	राणासर हंसावतान	376
51.	कुणपालसर	1648
52.	तोलियासर	2771
53.	जैतासर	2578
54.	ठुकरियासर	4241
55.	आडसर	3172
56.	धीरदेसर पुरोहितान	1550

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	जनसंख्या वर्ष 2011
57.	सुरजनसर	2304
58.	उदासर चारणान	248
59.	उदारसर	2816
60.	धोलिया	794
61.	जालबसर	2033
62.	लखासर	1188
63.	लाघडिया	353
64.	बीरमसर	816
65.	गुंसाईसर	4141
66.	माणकरासर	1617
67.	डेलवा	1858
68.	बाना	4328
69.	खियाणी बास	55
70.	जैसलसर	1487
71.	सालासर	525
72.	सूड़सर	3917
73.	टेउ	2122
74.	देराजसर	2925
75.	दुलचासर	2661
76.	गोपालसर	1642
77.	बासी महियान	गै.आ.
78.	शेरूणां	4410
79.	नारसीसर	717
80.	पुनरासर	4686
81.	बींझासर	2243
82.	राजपुरा	406
83.	जोधासर	1526
84.	झंझेउ	1661
85.	समंदसर	2330
86.	लखावर	2786

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	जनसंख्या वर्ष 2011
87.	बेनीसर	2174
88.	गजपुरा	439
89.	पुन्दलसर	2247
90.	हेमासर	799
91.	भोजास	1047
92.	दुसारणा बडा	776
93.	दुसारणा पिपासरिया	709
94.	दुसारणा पुण्डरीकजी	795
95.	कोटासर	896
96.	लोडेरा	1756
97.	श्रीडूंगरगढ़ (कस्बा)	21818
98.	कातर बडी	2145
99.	शिवपुरी	584
100.	गेवरसर	2152
101.	साजनसर	1410
102.	रेडा	1620
103.	सोनियासर उदयकरणोतान	602
104.	सोनियासर सुखराम	755
105.	तेहनदेसर	3107
106.	आईदानपुरा	59
107.	कातर छोटी	1686
108.	अमरसर	2294
109.	मालासर	762
110.	कान्धलसर	1919
111.	बाढसर	3173
112.	लालगढ़	4738
113.	जोगलसर	4134
114.	नोहडिया	1809
115.	भौम सडू	138
116.	सडू बडी	1916

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	जनसंख्या वर्ष 2011
117.	सड्डू छोटी	2157
118.	आसरासर	1102
119.	उंटालड	2752
120.	भौम ईयारा	32
121.	ईयारा	4255
122.	बम्बू	3685
123.	बेरासर	2707
124.	ढाणी रावली	449
125.	ढाणी धोरां	455
126.	ढाणी सिंवरान	506
127.	ढाणी कालेरां	1472
128.	गोन्दुसर	272
129.	भौम गोन्दूसर	245
130.	गोन्दूसर नारणोतान	1162
131.	भौम ज्याक	131
132.	ज्याक	1837
133.	कल्याणसर	1673
134.	भौम नब्बसर	65
135.	नब्बासर	1420
136.	बीदासर	30107
137.	रामदेवरा	425
138.	ढाणी पोटलिया	410
139.	दडीबा	बींदासर शामिल
140.	चक दडीबा	बींदासर शामिल
141.	कोठीनाडा	328
142.	ढाणी स्वामीयान	608

रायपुर तहसील क्षेत्र (भीलवाड़ा) में कैम्प कोर्ट कार्यालय का स्थाइकरण

86. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के तहसील क्षेत्र रायपुर में सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी का कोर्ट कैम्प संचालित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाडा के तहसील क्षेत्र रायपुर में तहसील मुख्यालय के ग्राम रायपुर में सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी का कोर्ट कैम्प संचालित है।

क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये नये उपखण्ड सृजित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जब कभी ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा तब इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकेगा।

चम्बल की दाईं व बाईं मुख्य नहरों के रिसाव के जल उपयोग हेतु कार्य-योजना

87. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चम्बल की बाईं व दाईं मुख्य नहरों से कुल कितनी भूमि सिंचित होती है तथा रबी व खरीफ में कितनी सिंचाई हेतु यह नहरें डिजाइन हैं?

(2) दाईं व बाईं मुख्य नहरों में सिंचाई हेतु कुल कितना पानी पूरी क्षमता के अनुसार छोड़ा जा सकता है? वर्ष 2007-08 में क्या पूरी क्षमता के अनुसार नहरों में पानी छोड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) बाईं व दाईं मुख्य नहर प्रणाली से कितना पानी रिसाव होकर चम्बल नदी में व्यर्थ बह जाता है? इस पानी से कुल कितनी सिंचाई सम्भव है? दाईं व बाईं नहर में व्यर्थ बह रहे पानी का पृथक से विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस व्यर्थ बहते पानी का चम्बल नदी में डाउन स्ट्रीम उपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चम्बल की बाईं व दाईं नहरों से राजस्थान में कुल 2.29 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यह नहरें खरीफ में 21 प्रतिशत व रबी में 55 प्रतिशत सिंचाई के लिये डिजाईन है।

(2) चम्बल की दाईं मुख्य नहर में सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता पर 6656 क्यूसैक्स एवं बाईं मुख्य नहर में पूर्ण क्षमता पर 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। वर्ष 2007-08 में बाईं मुख्य नहर में पूर्ण क्षमता से पानी छोड़ा जा रहा है। दाईं मुख्य नहर में मध्य प्रदेश राज्य की मांग के आधार पर 6 अगस्त, 2007 को जल प्रवाह प्रारम्भ कर दिया गया था जो कि लगातार जारी है। नहरों में लगातार जल प्रवाह करने के कारण जलीय घास (खरपतवार) के जल्दी उत्पन्न होने तथा जल स्तर नहर के किनारों के ऊपर तक आने के कारण दांई मुख्य नहर में पूरी क्षमता से जल प्रवाह नहीं किया जा सका है।

(3) दाईं मुख्य नहर में 0 कि.मी. से 124 कि.मी. के मध्य पानी रिसाव का आंकलन वर्ष 1983 में किया गया था। नहरों के कच्ची होने के कारण यह रिसाव कुल पानी का 7 प्रतिशत माना गया था। वर्ष 1983 में सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पूर्ण द्वारा दाईं मुख्य नहर के रिसाव के सम्बन्ध में रिसाव के 12 प्रतिशत होने का आकलन दर्शाया था। नहरों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उक्त रिसाव के लगभग 19 प्रतिशत होने का अनुमान है। सम्भवतः यही स्थिति बाईं मुख्य नहर के सम्बन्ध में भी है। रिसाव हुए पानी का कुछ भाग जमीन के भीतर समाहित हो जाता है एवं शेष जल नालों के द्वारा नदी में बहकर चला जाता है।

(4) जी नहीं। चम्बल नदी में कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में बह रहे पानी के उपयोग के लिए पांच लिफ्ट योजनाएं क्रमशः धौलपुर लिफ्ट प्रथम, धौलपुर लिफ्ट द्वितीय, इन्दिरा लिफ्ट, पीपल्दा लिफ्ट एवं पांचना लिफ्ट विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

जयपुर में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

88. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमआरामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें स्वीकृत हैं और उनमें से कितनी दुकानें आबंटित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) आबंटन रहित दुकानों को अब तक आबंटित नहीं करने के क्या कारण रहे और कब तक आबंटन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2006 एवं 2007 में उक्त संचालित उचित मूल्य की दुकानों में से कितनी दुकानों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 1560 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं, जिसमें से जयपुर शहर में 710 व जयपुर ग्रामीण में 850 दुकानें हैं। जिसमें से 1465 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं एवं 95 उचित मूल्य दुकानें रिक्त हैं। रिक्त दुकानों का तहसीलवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) उचित मूल्य दुकानों की रिक्तियां एवं आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है। जिसके लिए समय-समय पर विज्ञप्ति जारी की जाती है। वर्तमान में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए गये हैं। आबंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

(3) वर्ष 2006 व 07 में 21 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिनका विस्तृत विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है। शिकायतों की जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किये गये जिनका विस्तृत विवरण प्रपत्र 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

रसोई गैस की बुकिंग/आपूर्ति हेतु जारी दिशा-निर्देश

89. **श्रीमती ममता शर्मा** (बूंदी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग कराने एवं बुकिंग पश्चात रसोई गैस सिलेण्डर वितरण करने के संबंध में वर्तमान में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शादी समारोह के अवसर पर भी रसोई गैस सिलेण्डर की व्यवस्था करने हेतु गैस एजेन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो उससे सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती ममता शर्मा)

(3) क्या गैस एजेन्सियों को 21 दिवस की अवधि में गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के बुक करने हेतु आदेश प्रदत्त किए गए हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में घरेलू गैस के संबंध में 21 दिन पश्चात बुकिंग बाबत दिनांक 22.10.05 को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ वार्ता में रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाये रखने तथा बैकलाग कम करने हेतु निर्णय लिया गया था। साथ ही बुकिंग के बाद डीबीसी कनैक्शनधारी को 7 दिवस में गैस उपलब्ध कराने तथा 21 दिन पूर्व केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। सिंगल सिलैण्डर गैस कनेक्शनधारी को प्राथमिकता के आधार पर रिफलिंग आपूर्ति करने तथा तत्काल आपूर्ति के संबंध में कारणों का रिकार्ड रखने बाबत निर्णय लिया गया था। मीटिंग कार्यवाही दिनांक 22.10.05 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। शादी, समारोह तथा अन्य समारोह में कैटर्स द्वारा घरेलू गैस सिलैण्डर का उपयोग न कर केवल वाणिज्यिक सलैण्डर्स का उपयोग करने के संबंध में खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 53/पीएस/एफएस/2005 दिनांक 24.01.05 के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जयपुर जिले में घरेलू रसोई गैस के संबंध में 21 दिन पश्चात बुकिंग बाबत दिनांक 22.10.05 को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ वार्ता में रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाये रखने तथा बैकलाग कम करने हेतु निर्णय लिया गया था। साथ ही बुकिंग के पश्चात डीबीसी कनैक्शनधारी को 7 दिवस में गैस उपलब्ध कराने तथा 21 दिन पूर्व केवल विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। सिंगल सिलैण्डर कनैक्शनधारी को प्राथमिकता के आधार पर रिफिल आपूर्ति तथा तत्काल आपूर्ति के संबंध में कारणों का रिकार्ड रखने बाबत निर्णय लिया गया था। मीटिंग कार्यवाही दिनांक 22.10.05 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में राशन डीलरों की नियुक्ति हेतु लम्बित प्रकरण

90. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) बूंदी जिले की विभिन्न तहसीलों में किस-किस स्थान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए डीलर नियुक्ति करने हेतु वर्ष 2007 में आवेदन मांगे गये? प्राप्त आवेदनों में से कहां-कहां के आवेदनों के आधार पर डीलर की नियुक्ति जिला स्तर पर कर दी गई तथा किन आवेदनों पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमेटी की सर्वसम्मति नहीं होने के फलस्वरूप जयपुर स्थित विभागीय मुख्यालय को भिजवाये गये हैं?

(2) बूंदी जिले की उक्त तहसीलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वांछित दुकानों पर डीलर नियुक्ति हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र किस किस स्थान के लिये प्राप्त हुये?

(3) क्या पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डीलर नियुक्ति करने का फैसला जिला स्तर पर भी किया जाता था? यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन करने के आदेश सरकार द्वारा कब प्रसारित किये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) बूंदी जिले में अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डीलर नियुक्त करने हेतु कितने पद रिक्त हैं, जिन पर पुनः आवेदन कर निर्णय किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) बूंदी जिलें की 5 तहसीलों हेतु वर्ष 2007 में दिनांक 24.05.07 को 69 उचित मूल्य दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, प्राप्त आवेदनों के आधार पर 24 उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति जिला स्तर पर की गई है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है एवं 26 उचित मूल्य दुकानों हेतु आबंटन सलाहकार समिति सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं होने के कारण प्रकरण विभाग मुख्यालय को प्रेषित किये गये हैं विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) बूंदी जिले की उक्त तहसीलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वांछित दुकानों पर डीलर नियुक्ति हेतु कुल 366 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 07.10.05 से पूर्व उचित मूल्य दुकानों के आबंटन जिला स्तर पर किये जाते थे। विभाग द्वारा जारी उचित मूल्य दुकान आबंटन दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 74 (7) खा. वि./सा. वि. प्र./87-III दिनांक 7.10.05 परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) बूंदी जिले में तीन उचित मूल्य दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं। (बलकासा तहसील केशोरायपाटन, गामछ तहसील बूंदी व दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़) जिन्हें शीघ्र विज्ञप्ति जारी कर आबंटित कर दी जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र

91. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यही सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन भवन विहीन चिकित्सा केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। जिनके नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम

1. गलथनी
2. नवाखेडा
3. राजपुरा
4. बलवना
5. बलूपुरा – वित्तीय वर्ष 2007-08 में एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
6. खिन्दरा गांव – वित्तीय वर्ष 2007-08 में एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
7. बमणिया – वित्तीय वर्ष 2007-08 में एनआरएचएम के अन्तर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
8. बलाना – भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
9. सलोदरिया – भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
10. बडली – भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बारां जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं

92. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में किन-किन स्थानों पर उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, स्वास्थ्य उप केन्द्र किस-किस दिनांक से संचालित हो रहे हैं? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा संस्थानों में कितनी-कितनी शैय्यायें स्वीकृत हैं? चिकित्सा संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले के किस-किस चिकित्सा संस्थान में एक्सरे, सीटी स्केन, ईसीजी तथा ब्लड व यूरिन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिले के किस-किस स्वास्थ्य केन्द्र पर आपरेशन थियेटर हैं एवं किस-किस केन्द्र पर रोगी आने पर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिले में किस-किस डिस्पेन्सरी एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, डिस्पेंसरी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का स्वीकृति वर्ष सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र अलग से संचालित नहीं हैं।

(2) बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, डिस्पेंसरी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत शैय्याओं का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मात्री)

(3) बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले ऐसे चिकित्सा संस्थान जिनमें एक्सरें, सीटी स्केन, ईसीजी एवं ब्लड तथा यूरिन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है उनका चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(4) बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले ऐसे चिकित्सा संस्थान जिनमें आपरेशन थियेटर हैं एवं आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है उनका चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर प्रस्तुत हैं।

(5) बारां शहर में कार्यरत सिटी डिस्पेन्सरी धर्मार्थ संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में संचालित है।

बारां जिले के अन्तर्गत आने वाले भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

93. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम-खियेरा, अर्जुनसर, शेरेरा, रूणिया बड़ा बास, कतरियासर तथा सूई में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम खियेरा, अर्जुनसर एवं सूई पंचायत समिति लूणकरणसर तथा शेरेरा, रूणिया बडाबास एवं कतरियासर पंचायत समिति बीकानेर के अन्तर्गत आते हैं। आगामी वित्तीय वर्षे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति बीकानेर के उक्त सभी ग्रामों में तथा पंचायत समिति लूणकरणसर के 2 ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजसमन्द-भीलवाड़ा-कोटा मेगा हाइवे का निर्माण

94. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा राजसमन्द से वाया भीलवाड़ा बड़ा महुआ, शाहपुरा,

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

देवली होते हुए कोटा को जोड़ने हेतु मेगा हाइवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। इस मार्ग को मेगा हाइवे बनाने का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

निवाई में सड़क मरम्मत कार्य

95. श्री हीरालाल निवाई (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में सड़क मरम्मत के कौन कौन से कार्य कहां-कहां चलाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रम्भा नदी पर पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निवाई से जामडोली तक सिंगल रोड को दोनों तरफ चौड़ा करके डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत सड़क मरम्मत के कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. मुण्डिया से बीडोली सड़क किमी. 0/0 से 2/500
2. सम्पर्क सड़क पावंता किमी. 0/0 से 1/0
3. बोली निवाई सड़क पर किमी. 34 पर जंक्शन सुधार का कार्य
4. बोली निवाई सडक पर किमी. 24 पर सुरक्षा दीवार का कार्य
5. बोली निवाई सड़क (निवाई शहर) किमी. 36 में नाली निर्माण कार्य

(2) जी नहीं।

(3) निवाई से जामडोली तक 3 मीटर की सिंगल केरीजवे की सड़क बनी है एवं उक्त सड़क की चौड़ाईकरण एवं डामरीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

अलवर-दिल्ली राज्य राजमार्ग पर टोल-टैक्स की वसूली

96. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर-दिल्ली राज्य राजमार्ग पर सरकार टोल टैक्स लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) उपरोक्त टोल-शुल्क किन-किन वाहनों से कितना-कितना वसूल किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त टोल-शुल्क से किन-किन वाहनों को छूट प्रदान की जायेगी?

(4) यह टोल-शुल्क कितने समय के लिए लागू किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर-दिल्ली मार्ग की परियोजना पूरी होने के बाद टोल टैक्स लिया जायेगा।

(2) टोल-शुल्क किन-किन वाहनों से कितना-कितना वसूला जावेगा, की सूची संलग्न है।

(3) रक्षा विभाग के यानों, पुलिस विभाग के यानों, अग्निशमन यानों, एम्बूलैंसों, अंत्येष्टि वेनों, डाक तार विभाग के यानों, केन्द्र और राज्य सरकार के यानों, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यानों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के यानों, लोकायुक्त के यानों, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों, संसद और विधान सभा के आसीन सदस्यों के हल्के निजी यानों और प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों को फीस के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त होगी।

(4) दिनांक 28.07.2018 तक टोल-शुल्क लागू रहेगा।

टोल दरें

हरियाणा सीमा से अलवर बाइपास कुल लम्बाई 34.90 कि.मी.

क्र.सं.	वर्ष	अकृषिक उपज ले जाने वाले ट्रेक्टर मय ट्रोली	टेम्पों कार टैक्सी प्राइवेट कार जीप	मोटर लारी बस मिनी बसें एवं भारी मशीनरी	5 टन तक भार वाहक ट्रक	5 टन से अधिक भार वाहक ट्रक	मल्टी एक्सल ट्रक/ट्रेलर
		श्रेणी 1(ए)	**श्रेणी 1 (बी)**	**श्रेणी 2**	**श्रेणी 3 (ए)**	**श्रेणी 3 (बी)**	**श्रेणी 4**
1	2007–08	5.00	20.00	55.00	70.00	110.00	180.00
2	2008–09	5.00	20.00	55.00	70.00	110.00	180.00
3	2009–10	5.00	25.00	60.00	80.00	120.00	195.00
4	2010–11	5.00	25.00	60.00	80.00	120.00	195.00
5	2011–12	10.00	25.00	65.00	85.00	130.00	215.00
6	2012–13	10.00	25.00	65.00	85.00	130.00	215.00
7	2013–14	10.00	30.00	70.00	95.00	145.00	235.00
8	2014–15	10.00	30.00	70.00	95.00	145.00	235.00
9	2015–16	10.00	30.00	75.00	105.00	160.00	260.00
10	2016–17	10.00	30.00	75.00	105.00	160.00	260.00
11	2017–18	10.00	35.00	85.00	115.00	175.00	285.00
12	2018–19	10.00	35.00	85.00	115.00	175.00	285.00

टोल दरें

हरियाणा सीमा से बगड़ तिराहा कुल लम्बाई 23.70 कि.मी.

क्र. सं.	वर्ष	अकृषिक उपज ले जाने वाले ट्रेक्टर मय ट्रोली	टेम्पों कार टैक्सी प्राइवेट कार जीप	मोटर लारी बस मिनी बसें एवं भारी मशीनरी	5 टन तक भार वाहक ट्रक	5 टन से अधिक भार वाहक ट्रक	मल्टी एक्सल ट्रक/ट्रेलर
		श्रेणी 1(ए)	श्रेणी 1 (बी)	श्रेणी 2	श्रेणी 3 (ए)	श्रेणी 3 (बी)	श्रेणी 4
1	2007–08	5.00	15.00	40.00	55.00	85.00	140.00
2	2008–09	5.00	15.00	40.00	55.00	85.00	140.00
3	2009–10	5.00	20.00	45.00	65.00	95.00	155.00
4	2010–11	5.00	20.00	45.00	65.00	95.00	155.00
5	2011–12	5.00	20.00	50.00	70.00	105.00	170.00
6	2012–13	5.00	20.00	50.00	70.00	105.00	170.00
7	2013–14	5.00	20.00	55.00	75.00	115.00	190.00
8	2014–15	5.00	20.00	55.00	75.00	115.00	190.00
9	2015–16	10.00	25.00	60.00	85.00	125.00	210.00
10	2016–17	10.00	25.00	60.00	85.00	125.00	210.00
11	2017–18	10.00	25.00	65.00	90.00	140.00	230.00
12	2018–19	10.00	25.00	65.00	90.00	140.00	230.00

टोल दरें

बगड़ तिराहा से अलवर बाइपास कुल लम्बाई 11.20 कि.मी.

क्र. सं.	वर्ष	अकृषिक उपज ले जाने वाले ट्रैक्टर मय ट्रोली	टेम्पों कार टैक्सी प्राइवेट कार जीप	मोटर लारी बस मिनी बसें एवं भारी मशीनरी	5 टन तक भार वाहक ट्रक	5 टन से अधिक भार वाहक ट्रक	मल्टी एक्सल ट्रक/ट्रेलर
		श्रेणी 1(ए)	श्रेणी 1 (बी)	श्रेणी 2	श्रेणी 3 (ए)	श्रेणी 3 (बी)	श्रेणी 4
1	2007–08	5.00	15.00	40.00	55.00	80.00	130.00
2	2008–09	5.00	15.00	40.00	55.00	80.00	130.00
3	2009–10	5.00	15.00	40.00	60.00	85.00	145.00
4	2010–11	5.00	15.00	40.00	60.00	85.00	145.00
5	2011–12	5.00	20.00	45.00	65.00	95.00	155.00
6	2012–13	5.00	20.00	45.00	65.00	95.00	155.00
7	2013–14	5.00	20.00	50.00	70.00	105.00	175.00
8	2014–15	5.00	20.00	50.00	70.00	105.00	175.00
9	2015–16	5.00	25.00	55.00	75.00	115.00	190.00
10	2016–17	5.00	25.00	55.00	75.00	115.00	190.00
11	2017–18	5.00	25.00	60.00	85.00	125.00	210.00
12	2018–19	5.00	25.00	60.00	85.00	125.00	210.00

डूमरा-देलसरकला (नलवगढ़) का अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

97. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना में डूमरा से देलसरकलां सड़क कब स्वीकृत हुई तथा कब पूर्ण होनी चाहिए थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण काफी गांवों में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है?

(3) सरकार उक्त सड़क को अब कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है तथा इसमें देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में डूमरा से देलसरकला सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के षष्टम चरण (पार्ट-I) भारत निर्माण के अन्तर्गत अप्रैल, 2006 में स्वीकृत हुई। उक्त सड़क की कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि दिनांक 27.08.07 थी।

(2) जी नहीं। उक्त सडक का डब्लू बी एम लेवल तक का कार्य पूरा हो गया है और डामर का कार्य शेष है। रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, और किसी भी गांव का रास्ता अवरूद्ध नहीं है।

(3) उक्त सड़क का कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण हो जायेगा। कार्य में देरी के लिये संवेदक जिम्मेदार है तथा क्षतिपूर्ति राशि रुपये 5.48 लाख संवेदक से वसूल किये जा चुके हैं।

उदयपुरिया मोड़-खेजरोली सड़क मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई

98. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुरिया मोड़ से खेजरोली जाने वाली सड़क सीकर, झुंझनूं, हनुमानगढ़ आदि जिलों को जोड़ने वाली सड़क है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं?

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) क्या यह भी सही हे कि उदयपुरिया मोड़ से इटावा-भोपजी के बीच 5 किमी. तक इस सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर कर दी गई है?

(4) क्या सरकार उदयपुरिया मोड़ से खेजरोली तक इस सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त सड़क पर यातायात का दबाव तो अधिक है पर दुर्घटनायें नहीं होती हैं।

(3) जी हां। इस सड़क की उदयपुरिया मोड से इटावा-भोपजी के बीच 5 कि.मी. तक की चौड़ाई 5.50 मीटर कर दी है।

(4) इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करवाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

मुख्यपीठ उच्च न्यायालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत बजट

99. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जोधपुर में राजस्थान हाइकोर्ट की मुख्यपीठ का भवन बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त भवन बनाने के लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ का नवीन भवन बनाया जा रहा है। उक्त भवन पेटे राशि 20.33 लाख का बजट आबंटित किया गया था, जिसका उपभोग कर लिया गया है। शेष बजट स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मावली में स्वीकृत तालाब/बांध निर्माण कार्य

100. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मावली के राजसमन्द जिले की रेलमगरा तहसील में बनास नदी पर गिलूण्ड काजवे का कार्य करवाने की वर्ष 2005-06 में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उस योजना को कब तक पूरा करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली की तहसील रेलमगरा के धनेरियागढ़ तालाब बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली के रेलमगरा क्षेत्र की खड़ बामनिया गांव में गुलाब सागर तालाब का सुदृढीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो अब कार्यारम्भ कब किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। धनेरिया तालाब बना हुआ है।

(3) गुलाब सागर तालाब पंचायत समिति के अधीन होने के कारण उक्त तालाब का सुदृढ़ीकरण करवाने हेतु पंचायत विभाग को लिख दिया गया है।

टिब्बी विधान सभा क्षेत्र के सेमग्रस्त क्षेत्र हेतु पायलेट परियोजना

101. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत ई.गां.न. परियोजना के अधीन मसीता वाली, आर.डी. 654 लूणावाली ढ़ाणी, डबली, मिर्जावालीमेर, गन्धेली, दासुवाली, 34 आर.डब्ल्यू.डी, जीवन नगर, 14 बी.पी.एम. रावतसर, ग्रामीण क्षेत्र, रावतसर चक 15-16 के.डब्ल्यू.डी. खेतावाली ढाणी, सिंहणा वाली ढाणी, कलाला वाली ढाणी, भैरूसरी खेदासरी, जाखड़ा वाली दौलतावाली मानक चेडी, बडोपल एरिया में सेम विद्यमान है? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि सेमग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सेम समस्या हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सेम की समस्या के निराकरण हेतु पायलेट परियोजना स्वीकृत है? यदि हां, तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

(3) क्या उक्त पायलेट परियोजना का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भविष्य में सेम समस्या का निराकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में वर्णित स्थानों की लगभग 13608 हैक्टेयर भूमि सेमग्रस्त है।

जी हां। रवतसर क्षेत्र में 5633 हैक्टेयर सेमग्रस्त क्षेत्र को सेम निवारण हेतु एक पायलेट परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा 460.66 लाख रुपये की स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत 18 कि.मी. मुख्य ड्रेन, 10 कि.मी. सीपेज ड्रेन व 8 कि.मी. सब ड्रेन का निर्माण कार्य कराना व मुख्य नहर की बुर्जी 96.300 पर पम्प हाउस का निर्माण कर मुख्य ड्रेन से सेम के पानी को मुख्य नहर में डाला जाना प्रस्तावित है। भैरूसरी, खेदासरी, जाखडा वाली, दौलतां वाली, मानक थेडी, बडोपल क्षेत्र के 4374 हैक्टेयर सेमग्रस्त क्षेत्र हेतु राज्य सरकार से राशि 557.85 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की गई जिसके अन्तर्गत 30 कि.मी. मुख्य ड्रेन, 28 कि.मी. सब ड्रेन का निर्माण, पम्प हाउस का निर्माण, डीजल व इलैक्ट्रिक पम्प का स्थापन, 3 कि.मी. पाइप लाइन द्वारा दौलतावाली पर स्थित पम्प हाउस से सूरतगढ़ शाखा में सेम का पानी डाला जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। इस योजना पर मार्च, 2003 तक 305.46 लाख रुपये का व्यय कर 15 कि.मी. मुख्य ड्रेन, मुख्य नहर की आर.डी. 96.30 पर पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है। शेष कार्य अपूर्ण है।

(3) जी नहीं। सब ड्रेन व सीपेज ड्रेन के निर्माण हेतु लाभान्वित काश्तकारों द्वारा भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने पर ही योजना का शेष कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव है।

(4) जी हां। सेम समस्या हेतु एक समेकित योजना तैयार कर शीघ्र समस्या का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

आमेर विकास प्राधिकरण में राज्य कार्मिकों की सहभागिता

102. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री लालचन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि सहकारी संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत आमेर विकास प्राधिकरण नामक संस्था ने जयपुर शहर अथवा राज्य के किसी अन्य जिले में पंजीयन करवा रखा है? यदि हां, तो उक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं संस्था के सदस्यों के नाम पते व विधान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था में राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भी सदस्य/पदाधिकारी के रूप में अभिलिप्त हैं? यदि हां, तो किस-किस पद पर व कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय पद पर सेवारत कोई भी राज्य सेवा का अधिकारी/कर्मचारी किसी संस्था में सदस्य/पदाधिकारी बन सकता है? यदि हां, तो उक्त बाबत नियमों/उप नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने सरकार से कोई पूर्वानुमति आमेर विकास प्राधिकरण नामक संस्था में सदस्य/पदाधिकारी बनने हेतु प्राप्त की है? यदि हां, तो कब व किस से व नहीं, तो क्या सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जयपुर में ''आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण संस्था'' नाम से एक संस्था पंजीकृत है। जिसके पंजीयन प्रमाण-पत्र, विधान व पंजीयन के समय संस्था के सदस्यों के नाम व पते की सूची क्रमश: परिशिष्ट एक व दो पर संलग्न है।

(2) संस्था के पंजीयन पत्रादि के अनुसार जो राजकीय अधिकारी/कर्मचारी आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य/पदाधिकारी रहे हैं, उनका विवरण परिशिष्ट तीन पर संलग्न है।

(3) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत राजकीय सेवा पर सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के किसी संस्था के सदस्य अथवा पदाधिकारी होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(4) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत राजकीय पद पर सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के किसी संस्था के सदस्य अथवा पदाधिकारी होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले में कार्यरत सहकारी समितियों द्वारा सम्पादित कार्य

103. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के किस-किस ग्राम में सहकारी समितियां किस-किस दिनांक से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों में कौन-कौन निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक सदस्य हैं? सहकारी समितिवार नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां जिले में कार्यरत किस-किस सहकारी समिति में कितने-कितने पुरुष एवं महिला सदस्य हैं? सहकारी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सहकारी समितियों द्वारा क्या-क्या कार्य संपादित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में कार्यरत सहकारी समितियों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट संख्या-1 पर संलग्न है। सूची में अंकित सहकारी समितियां उनके नाम के सामने अंकित पंजीयन दिनांक से कार्यरत है।

(2) जिला बारां में उक्त सहकारी समितियों में से वर्ष 2005 से अब तक निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सूचना परिशिष्ट संख्या-2 में अंकित है।

(3) बारां जिले में कार्यरत सहकारी समितियों के पुरुष एवं महिला सदस्यों की सूचना परिशिष्ट संख्या-1 में अंकित है।

(4) जिले में उक्त सहकारी समितियों द्वारा मुख्य रूप से किये जाने वाले कार्य की सूचना परिशिष्ट संख्या-1 में अंकित है।

(विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर व्यय

104. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) वर्ष 2004 से अब तक जिला चूरू में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अन्तर्गत सिंचाई हेतु कितना पानी उपलब्ध करा कर कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचित किया गया? उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा सहित वर्षवार व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक उक्त परियोजना अन्तर्गत जिला चूरू में कितने बजटीय प्रावधान के विरुद्ध कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये? वर्षवार व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला चूरू में उक्त परियोजना को शीघ्र पूर्ण कर पूर्व निर्धारित सिंचाई जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों में निम्न स्तर की सामग्री उपयोग में लाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक चूरू जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अन्तर्गत 30.43 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाकर 5890 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

तहसील	**वर्ष**	**पानी की मात्रा (क्यूसेक में)**	**सिंचाई हेतु क्षेत्र**
□	2004	–	–
□	2005	–	–
□	2006-07 (रबी फसल)	□	□
सरदारशहर	□	5.81	1093 है.
तारानगर	□	24.62	4797 है.
□	2007-08 (खरीफ)	□	□
सरदारशहर	□	5.81	1093 है.
तारानगर	□	24.62	4797 है.

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) जिला चूरू में वर्ष 2004 से अब तक परियोजना के बजटीय प्रावधान के विरुद्ध निम्नानुसार राशि व्यय कर निम्न कार्य करवाये गये।

वर्ष	बजट प्रावधान (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)	लाईनिंग कार्य (कि.मी. में)
2004-05	□	□	□
तारानगर तह.	1136.06	1136.06	47.63
सरदारशहर तह.	150.27	150.27	6.30
2005-06	□	□	□
तारानगर तह.	1299.91	1299.19	44.55
सरदारशहर तह.	384.08	384.08	13.17
2006-07	□	□	
तारानगर तह.	671.90	671.90	12.95
सरदारशहर तह.	126.32	126.32	1.90
2007-08	□	माह जनवरी तक	□
तारानगर तह.	750.28	600.50	0.80
सरदारशहर तह.	169.58	89.06	1.88

(3) जी नहीं। परियोजनान्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों को पूरा करवाया जा रहा है।

(4) जी हां। सरकार जिला चूरू में उक्त परियोजना को वर्ष 2011-12 तक पूरा कर निर्धारित जल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है।

(5) जी हां। निम्न स्तर की सामग्री उपयोग में लाये जाने की शिकायत की जांच करवाई गई एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत सही नहीं पाई गई। रिपोर्ट संलग्न है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले ग्रामों का माडा योजनान्तर्गत चयन

105. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी का निर्धारण किया हुआ है? यदि हां, तो जिलेवार कुल आबादी का प्रतिशत तथा संख्या कितनी-कितनी हैं? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के विकास उसकी सघनता आदि को ध्यान में रखकर तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से उसे विभिन्न क्षेत्रों में टाडा, माडा बिखरी जनजाति आदि के नाम से बांटा गया है? यदि हां, तो पिछली जनगणना (2001) के आधार पर जनसंख्या की सघनता एवं आबादी की संख्या सहित श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनेक ग्रामों की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत 40 से अधिक होने पर भी उन्हें माडा योजना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या अब ऐसे ग्रामों को माडा योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी?

(4) क्या माडा योजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने से वंचित रहे ग्रामों को इस योजना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये सरकार द्वारा परिपत्र/निर्देश जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या व प्रतिशत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी। हां अनुसूचित जनजाति विकास के संबंध में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र, माडा, माडा कलस्टर एवं बिखरी जनजाति व सहरिया क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है। सूचना परिशिष्ट-2 से 6 तक संलग्न है।

(3) जी। हां क्योंकि भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार माडा क्षेत्र के लघुखण्डों में जनजाति जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिये। वर्तमान में बने माडा लघुखण्ड 1991 की जनगणना के आधार पर गठित है। जनगणना 2001 के अनुसार माडा क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को दिनांक 5.4.07 को भिजवाये जा चुके हैं जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है

(जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जिसमें निर्धारित मापदण्ड जनजाति जनसंख्या के 50 प्रतिशत या इससे अधिक होने को आधार माना गया है।

(4) माडा क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। परिशिष्ट-7 संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले को जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आबंटित राशि

106. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत किन-कौनसी योजनायें राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही हैं? विवरण योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना बजट आबंटित किया गया? सूची जिलेवार, वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला नागौर में उक्त आबंटित राशि को उक्त वर्षों के दौरान पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत उपयोजना एवं गैर उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित व्यय का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नागौर जिले हेतु उक्त वर्षों में स्वीकृत राशि का व्यय हुआ है, लेकिन शत प्रतिशत व्यय नहीं हुआ है। (परिशिष्ट-3) व्यय कम होने का मुख्य कारण यह है कि राशि का आबंटन जिलेवार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता की गाइड लाइन के अनुसार उक्त राशि का व्यय बी.पी.एल. जनजाति पर ही किया जाता है। जिले की बी.पी.एल. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत से कम है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत अपूर्ण निर्माण कार्य

107. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत माडा योजना में खाखरा का खुणा (रावछ) के अपूर्ण एनिकट निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक भवन मुण्डीमाता कडेच व खुर्रा निर्माण भीलवाड़ा तिरौल में व अन्य स्थानों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इनकी कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद से प्राप्त पत्र अनुसार माडा योजना अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में निर्मित एनिकट खाखरा का खुणा (रावछ) पं.सं. गोगुन्दा में साइड का नाला टूट जाने से पानी नहीं रुक रहा था। एनिकट निर्माण खाखरा का खुणा की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी कर दी गई।

(2) सामुदायिक भवन मुण्डीमाता कडेच व खुर्रा निर्माण तिरौल का निर्माण करवाया जाना राशि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की समाप्ति

108. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एच.एम.एस. आदि में नियमों/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रवेश परीक्षा की समाप्त कर बारहवीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रवेश देना, प्रारम्भ करने का विचार रखती है, जिससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की महत्ता कायम रह सके? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालायों में एमबीबीएस एवं बीडीएस कोर्सेज में प्रवेश के लिए आरपीएमटी परीक्षा वर्ष 1969 से आयोजित की जा रही है। संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बीएचएमएस के प्रवेश के लिए राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का वर्ष 2003 से आयोजन किया जा रहा है। संबंधित नियमों एवं दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रवेश परीक्षा बेहतर विकल्प है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-44 की सूची)

अनुसूचित क्षेत्र नवगठित प्रतापगढ़ जिले में स्वीकृत/संचालित छात्रावासों की सूची

परिशिष्ट–अ

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति		आश्रम छात्रावास का नाम	क्षमता	स्तर	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
4	प्रतापगढ़	1. प्रतापगढ़	1	सुहागपुरा	100	सी.मा.वि.	15/7/81
			2	सुहागपुरा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	15/7/02
			3	देवगढ़	80	सी.मा.वि.	15/7/81
			4	रामपुरिया	100	सी.मा.वि.	8/11/83
			5	थड़ा	100	सी.मा.वि.	8/11/87
			6	बोरी	80	मा.वि.	15/7/90
			7	धमोत्तर	50	सी.मा.वि.	2/3/97
			8	बारावरदा	50	मा.वि.	26/5/97
			9	गन्धेर	50	उ.प्रा.वि.	3/3/97
			10	कुलथाना	50	सी.मा.वि.	3/3/97
			11	कुलथाना (कन्या)	50	सी.मा.वि.	18/7/04
			12	प्रतिभावान छात्रावास, प्रतापगढ़	50	सी.मा.वि.	15/8/97
			13	प्रतापगढ़ (कन्या)	100	सी.मा.वि.	20/7/95
			14	पण्डावा (कन्या)	50	मा.वि.	1/7/02
			15	अवलेश्वर (कन्या)	50	सी.मा.वि.	21/7/04

1	2	3	4	5	6	7	8
			16	देवगढ़ (कन्या)	50	मा.वि.	21/7/04
			17	प्रतापगढ़	50	सी.मा.वि.	21/7/04
			18	लौहारिया (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	7/06
		2. अरनोद	19	बड़ी सांखथली (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	7/06
			20	नागदी	80	मा.वि.	15/7/90
			21	अरनोद	80	सी.मा.वि.	15/7/90
			22	सालमगढ़	50	सी.मा.वि.	3/2/97
			23	दलोट (कन्या)	100	सी.मा.वि.	20/7/96
			24	दलोट	50	सी.मा.वि.	12/1/98
			25	जांजली	50	मा.वि.	7/11/97
			26	चपना	50	सी.मा.वि.	15/7/04
			27	थली थाना (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	15/7/04
		3. पीपलखूंट	28	पीपलखूंट	130	सी.मा.वि.	15/1/82
			29	घन्टाली	50	सी.मा.वि.	1/4/97
			30	डूंगलावानी (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	22/7/04
			31	पीपलखूंट (कन्या)	50	सी.मा.वि.	5/10/06
		4. धरियावाद	32	गोठड़ा	80	उ.प्रा.वि.	1/11/79
			33	धरियावद (कन्या)	70	सी.मा.वि.	15/1/88
			34	पारसोला	50	सी.मा.वि.	1/6/98
		5. छोटी सादड़ी	35	धोलापानी (कन्या)	140		
			36	करजू (कन्या)	50		
				योग	**2390**		

परिशिष्ट-ब

गैर अनुसूचित क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत/संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	आश्रम छात्रावास का नाम	क्षमता	स्तर	चालू वर्ष
1	चित्तौड़गढ	1. बड़ी सादड़ी	1	मुजवा	100	
			2	लक्ष्मीपुरा	100	
			3	रावतभाटा (कन्या)	50	
				योग	**250**	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-46 की सूचना)

तहसीलवार स्वीकृत पदों के विपरीत वर्तमान में रिक्त पदों की सूचना

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम पटवार मण्डल	रिक्त होने की दिनांक
1.	आसीन्द	अन्टाली	16.11.06
2.		बराणा	31.07.06
3.		भोजपुरा	16.10.06
4.		दांतडा	04.07.06
5.		दौलतगढ़	31.07.06
6.		गांगलास–प्रथम	15.07.05
7.		गागलास–द्वितीय	15.07.05
8.		ईरास	31.07.07
9.		जीवलिया	26.07.05
10.		जालरिया	31.07.07
11.		जगपुरा	31.07.07
12.		करजालिया	31.07.07
13.		कालियास	07.07.06
14.		कटार	24.06.06
15.		मोठी	15.07.05
16.		ओझियाणा	31.07.07
17.		पाटन	15.07.06
18.		रूपपुरा	31.07.07
19.		रूपपुरा (ला)	15.07.05
20.		रतनपुरा (ला)	31.07.07
21.		संग्रामगढ़	12.04.06
22.	कोटड़ी	सवाईपुर	31.07.07
23.		दांतड़ा	15.07.05
24.		गेन्दलिया	31.07.07

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम पटवार मण्डल	रिक्त होने की दिनांक
25.	कोटड़ी	गेगा का खेड़ा	15.07.05
26.		क. घाटी	31.07.07
27.		किशनगढ़	31.07.07
28.		मंशा	31.07.07
29.		रीठ	15.07.06
30.		सांखड़ा	31.07.07
31.		सुठेपा	25.07.05
32.	जहाजपुर	कुराडिया	31.07.07
33.		सरसिया	15.07.05
34.		टीटोडी	31.07.07
35.		विन्ध्याभाटा	31.07.07
36.	बनेड़ा	बबराणा	15.07.06
37.		डाबला	31.07.07
38.		जासोरिया	15.06.04
39.		खेडलिया	31.07.07
40.		लाम्बिया खुर्द	31.07.07
41.		महुआ खुर्द	31.07.07
42.		निम्बाहेडा कलां	31.07.07
43.		रूपाहेलीखुर्द	03.07.06
44.		राक्षी	31.07.07
45.		सरदारनगर	31.07.07
46.		सालरिया	23.11.07
47.		सुल्तानगढ़	31.07.07
48.		उपरेड़ा	13.10.06
49.	बिजौलयां	बिजौलियां	31.07.07
50.		चान्दजी की खेडी	15.07.05
51.		थडोदा	15.07.05
52.		लक्ष्मीखेड़ा	06.07.05
53.		सलावटिया	01.07.06

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम पटवार मण्डल	रिक्त होने की दिनांक
54.	भीलवाड़ा	आमलीगढ़	31.07.07
55.		बरडौद	31.07.07
56.		बिलीयांकला	31.07.07
57.		टुडिया	15.07.05
58.		गुरलां	18.08.07
59.		खायड़ा	07.08.06
60.		कोचरिया	31.07.07
61.		महुआ कला	31.07.07
62.		पीपली	11.07.06
63.		रामपुरिया	15.07.06
64.	भीलवाड़ा	तिलोली	16.07.05
65.	माण्डल	अमरगढ़	15.07.06
66.		बावडी	31.07.07
67.		बागोर द्वितीय	31.07.07
68.		बावलास	31.07.07
69.		भभाणा	22.01.08
70.		गोरधनपुरा	15.07.06
71.		ज्ञानगढ़	31.07.07
72.		गेगास	31.07.07
73.		हिसनिया	31.07.07
74.		जोरावरपुरा	31.07.07
75.		कीड़ीमाल	31.07.07
76.		लादूवास प्रथम	15.07.05
77.		लुहारिया प्रथम	15.07.05
78.		लुहारिया द्वितीय	31.07.07
79.		मोटा का खेडा	15.07.05
80.		निम्बाहेडा प्रथम	15.07.05
81.		रामपुरिया	31.07.07

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम पटवार मण्डल	रिक्त होने की दिनांक
82.	माण्डल	थाणा	15.07.05
83.	माण्डलगढ़	बीकरण	29.07.07
84.		धाकडखेडी	31.07.07
85.		धामनिया	31.07.07
86.		गेणोली	31.07.07
87.		जोजवा	15.07.05
88.		कल्याणपुरा	31.07.07
89.		काछोला	31.07.07
90.		मोहनपुरा	31.07.07
91.		महुआ	15.07.06
92.		माल का खेडा	31.07.07
93.		सुरास	31.07.07
94.		सराणा	31.07.07
95.		सरथला	31.07.07
96.	रायपुर	बागोलिया	15.07.06
97.		भीटा	31.07.07
98.		बागड़	16.01.06
99.		बकाण	31.07.07
100.		मौखुन्दा	15.07.07
101.		नाहरी	01.07.06
102.		नारायण खेडा	31.07.07
103.		नान्दशा	31.07.07
104.		पीथा का खेडा	27.08.01
105.		सरेवड़ी	16.07.05
106.		टुगंच	27.08.01
107.	शाहपुरा	अरवड़	31.07.07
108.		अरवड़ पेटा	31.07.07
109.		अरनिया रासा	31.07.07
110.		दौलतपुरा	31.07.07

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम पटवार मण्डल	रिक्त होने की दिनांक
111.	शाहपुरा	धनोप	20.11.05
112.		डोहरिया	07.04.07
113.		डेलास	15.07.06
114.		देवपुरी	13.10.06
115.		डाबला चान्दा	31.07.07
116.		डाबला कचरा	31.07.07
117.		फुलिया खुर्द	26.06.05
118.		फुलिया कलां	15.07.05
119.		गिरडिया	31.07.07
120.		हुकुमपुरा	05.07.06
121.		ईटड़िया	31.07.07
122.		करमडास	03.07.06
123.		खामोर प्रथम	31.07.07
124.		लसाड़िया	31.07.07
125.		मिण्डोलिया	31.07.07
126.		पैटा नाहरसागर	31.07.07
127.		रलायता	31.07.07
128.		रामपुरा	31.07.07
129.		रहड	31.07.07
130.		समेलिया	15.07.05
131.		ढीकोला प्रथम	31.07.07
132.		ढीकोला द्वितीय	20.11.07
133.	सहाड़ा	चीड़खेड़ा	31.07.07
134.		लाखोला	31.07.07
135.		नेगड़ियाखेड़ा	15.07.06
136.		नान्दशा	31.07.07
137.		सातल्यास	31.07.07

क्र.सं.	**नाम तहसील**	**नाम पटवार मण्डल**	**रिक्त होने की दिनांक**
138.	हुरडा	आंगूचा प्रथम	28.03.05
139.		बोरखेड़ा	15.07.05
140.		भीमलत	01.07.06
141.		दांतड़ा	31.07.07
142.		देवरिया	31.07.07
143.		फलामावा	31.07.07
144.		गढ़वालों का खेड़ा	12.04.06
145.		हुरडा सेजा	31.07.07
146.		लाम्बा	31.07.07
147.		रूपाहेली	26.06.04
148.		सणोदिया	31.07.07
149.		सरेरी	31.07.07
150.		सोडार	08.08.06
151.		सुल्तानपुरा	26.06.04

कलक्टर (भू. अभि.)
भीलवाड़ा)

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

पूर्व सैनिकों के पुर्नवास के संबंध में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के प्रतिवर्ष 40 से 45 वर्ष की अल्प आयु में करीब 5 से 6 हजार रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को उनके पुर्नवास हेतु राज्य सरकार ने कुछ संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर स्वरोजगार के अभाव में संस्था के माध्यम से नियोजन दिलाने हेतु विभिन्न सरकारी/अर्द्वसरकारी विभागों को निर्देश जारी किये हुए हैं। तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सैनिकों को शोषण से मुक्ति हेतु समय-समय पर पूर्व सैनिकों के वेतन में महंगाई को ध्यान में रखते हुए वृद्धि भी की गई है किन्तु यह जानकारी में आया है कि सुरक्षा कर्मियों का वेतन केवल मात्र 1550/ प्रतिमाह वर्ष 1977 से निर्धारित किया हुआ है, और इसके पश्चात कोई वृद्धि भी नहीं की गई है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया था आयोग द्वारा की गई अभिशंसा से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अपनी सहमति जताते हुए आवश्यक निर्देश भी जारी किये हैं। किन्तु अभी भी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा आदेश जारी नहीं किये गये हैं। उललेखनीय है कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को वन विभाग तथा राज्य कारागृह के लिए नियुक्त प्रहरियों को 4000/- रुपया प्रतिमाह एवं होमगार्ड के जवानों को प्रतिमाह 4500/- रुपया तथा केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पुर्नवास हेतु निर्धारित दरें एक सुरक्षा प्रहरी के 6171/ रुपया निर्धारित की हुई है। इस बाबत सैनिकों की समस्या समाधान हेतु मैं सदन से मांग करता हूं कि इस बाबत उचित निर्णय अतिशीघ्र लेकर भूतपूर्व सैनिकों को राहत पहुंचावें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़
(बनीपार्क)

चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले में पृथक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना के सम्बन्ध में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में दुग्ध संकलन एवं विपणन का कार्य कर रहा हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में भीलवाडा दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध अवशीतन केन्द्र संचालित किया जा रहा है, जहां पर चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले से दुग्ध संकलित कर भीलवाड़ा संयंत्र भेजा जाता है एवं प्रोसेस कर पुनः बिक्री हेतु चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भेजा जाता है। वर्तमान परिस्थितियों, दुग्ध उत्पादकों की मांग एवं जिले में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर पृथक दुग्ध संघ की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में भीलवाड़ा दुग्ध संघ द्वारा कुल लगभग 1386 पंजीकृत एवं लगभग 1200 क्रियाशील समितियों के माध्यम से कुल लगभग 1,82,000 किलो दुग्ध औसतन प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है एवं लगभग 1,15,000 लीटर दुग्ध औसतन प्रतिदिन बिक्री किया जा रहा है। जब कि चित्तौड़गढ़ अवशीतन केन्द्र पर लगभग 612 पंजीकृत एवं लगभग 550 क्रियाशील समितियों द्वारा लगभग 48,000 किलो दुग्ध औसतन प्रतिदिन संकलित कर लगभग 48,000 लीटर दुग्ध ही औसतन प्रतिदिन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बिक्री किया जा रहा है। आंकड़ों से स्पष्ट हैं कि चित्तौड़गढ़ की भीलवाड़ा दुग्ध संघ के दुग्ध संकलन में लगभग 30 प्रतिशत एवं विपणन में लगभग 40 प्रतिशत भागीदारी है। इसी के साथ राज्य के कुल 19 संघों में से लगभग नो संघ क्रमशः बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, चूरू, जालोर, झालावाड़, नागौर, टोंक व कोटा दुग्ध संकलन एवं विपणन में चित्तौड़गढ़ अवशीतन केन्द्र से पीछे है, एवं चार संघ लगभग बराबर हैं। अतः चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले को मिला कर पृथक संघ की स्थापना करने में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आयेगी।

प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से लगभग 200 कि.मी. दूरी पर स्थित है, अतः भीलवाड़ा मुख्यालय से इसे कवर पाना कठिन कार्य है, इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़ क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां डेयरी जीविकोपार्जन का सशक्त

साधन हैं एवं दुग्ध संकलन कार्य में अभी तक चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले का 60 प्रतिशत हिस्सा ही कवर हो पाया है। चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में चारे व पानी की भी समुचित व्यवस्था है। अतः चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले को मिला पृथक संघ बनने पर दुग्ध संकलन एवं विपणन बढ़ने की विपुल सम्भावनाऐं हैं।

इसके अतिरिक्त एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत लगभग 7 करोड़ की लागत से चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर 1 लाख लीटर क्षमता का डेयरी संयंत्र निर्माणाधीन है। जिसके इसी वर्ष तैयार होने की संभावनाएं हैं। इससे दुग्ध प्रोसेसिंग कार्य चित्तौड़गढ़ में ही हो सकेगा एवं परिवहन व्यय की भारी बचत होगी, जिसका लाभ सीधे दोनों जिलों के काश्तकारों को पहुंचेगा एचं चूंकि अवशीतन केन्द्र पर जितना दुग्ध संकलित किया जा रहा हैं उतना ही पुनः दोनों जिलों में बेचा जा रहा है, जो कि किसी भी दुग्ध संघ के लिए एक आदर्श स्थिति है। अतः चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले मिला कर पृथक संघ की स्थापना में भौतिक एवं वित्तीय रूप से कोई कठिनाई नहीं है।

अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया एवं सरकार से निवेदन करता हूं कि चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ को मिलाकर ''चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.'' की पृथक रूप से स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

धन्यवाद।

अशोक कुमार नवलखा
(निम्बाहेड़ा)

पी.सी.सी., कालाडेरा को सी.एस.सी. में क्रमोन्नत करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र में कालाडेरा चौमूं रेनवाल मार्ग पर चौमूं से 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है इस स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिदिन लगभग 100-150 व्यक्ति उपचार के लिये आते हैं टाकरडा, जयसिंहपुरा, घीनोयी, मलिकपुर, मण्डा, भीण्डा आलिसर, भीलपुरा, अनोपपुरा आदि ग्राम पंचायत के लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं।

महोदय, कालाडेरा में औद्योगिक केन्द्र होने के कारण लगभग 2000 फैक्ट्रियां स्थित हैं जहां पर आये दिन मजदूरों के बीमार होने तथा दुर्घटना होने पर संसाधनों के अभाव में उपचार हेतु चौमूं/जयपुर रैफर करना पड़ता है विगत वर्षों में भी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने परिवार नियोजन व टीकाकरण के क्षेत्र में राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्राथमिक स्वा. केन्द्र को लोगों की भावनाओं व समस्याओं को देखते हुए अविलम्ब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का श्रम करें।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

माही डैम की दायीं मुख्य नहर के कठांव माइनर के टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा में माही डैम की दायीं मुख्य नहर के सम्बन्धित कठांव माइनर के आखिरी टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों की फसलें सूख रही है।

अतः माइनरों पर तैनात चौकीदारों व मिस्त्रीयों को पाबन्द कराया जाकर गेहूं व मक्का की सूखती हुई फसलों को बचाया जावे तथा किसानों को राहत दिलाई जावे।

इसी आशा व विश्वास के साथ नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

आदर सहित।

नवनीत नीनामा

(घाटोल)

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। पेयजल की उत्पन्न समस्या के निदान हेतु मेरे क्षेत्र में 19 नलकूपों एवं 150 हैण्डपम्प स्थापना की स्वीकृतियां जारी की गई थी जिसमें से मात्र 7 नलकूपों की खुदाई ही की गई है। तथा शेष नलकूप एवं हैण्डपम्पों की खुदाई प्रारम्भ ही नहीं की गई है जिससे अभी से ही क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नलकूपों एवं हैण्डपम्पों तथा नवीन प्रस्तावित नलकूप एवं हैण्डपम्प की शीघ्र स्थापना करवाकर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

सुखलाल मीणा

(सपोटरा)

अलवर के राजकीय विद्यालयों में पंजाबी विषय की विभिन्न श्रेणियों के अन्याय की नियुक्ति बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि अलवर जिले की विभिन्न राजकीय विद्यालयों विशेषकर विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) अनेकों राजकीय विद्यालयों में पंजाबी भाषा पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए पंजाबी अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। विशेषकर राजकीय उच्च बा. माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, राज. उच्च मा. विद्यालय, रामगढ, नौगांवा, मुबारिकपुर, अलावडा विद्यालयों में पंजाबी विषय के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है जिसके कारण वहां पर पंजाबी समाज के छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर अलवर जिले के पंजाबी समाज में भारी रोष है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि जिला अलवर विशेषकर विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पंजाबी विषय के लिए विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

जुबेर खान

(रामगढ़)

सांचौर में एस.सी., एस.टी. बालिका छात्रावास खोलने बाबत

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र सांचौर जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से वृहद क्षेत्र है जहां वर्तमान में 136 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत एवं 32 विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं। इन विद्यालयों में कुल 43,749 छात्रायें अध्ययनरत हैं, जिनमें

8,107 छात्रायें एस.सी. (6222) तथा एस.टी. (1885) की अध्ययनरत है। वर्तमान में सांचौर में एक भी एस.सी./एस.टी. बालिका छात्रावास नहीं है। एस.सी./एस.टी. की छात्रायें उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे के अध्ययन से वंचित रह जाती हैं क्योंकि गरीब एवं पिछेडपन के कारण इनको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं इसी कारण सैकेण्ड्री वी सीनियर सैकेण्ड्री स्कूलों में इनका नामांकरण नगण्य है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र सांचौर में भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सांचौर में तुरन्त एस.सी./एस.टी. बालिका छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

धन्यवाद।

जीवराम चौधरी

(सांचौर)

वंचित लाचार व गरीब वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देकर लाभान्वित करने हेतु

महोदय,

राज्य में बीपीएल परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह 400 रुपये देना निर्धारित है। इसके अलावा गैर बीपीएल परिवारों के वृद्ध गरीब व्यक्तियों को भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

राज्य में कुल 26 लाख 44 हजार 620 बीपीएल परिवार हैं। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन सिर्फ 4 लाख 45 हजार 449 को ही प्रदान की जा रही है। इस प्रकार राज्य के लाखों बीपीएल तथा गैर बीपीएल वृद्ध व्यक्ति केन्द्र पोषित उक्त योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

जिला चूरू में कुल 50 हजार 807 बीपीएल परिवार हैं। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 25 हजार 937 वृद्ध व्यक्तियों को ही वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। इस प्रकार जिला चूरू के करीब 25 हजार बीपीएल तथा हजारों की ही संख्या में गैर बीपीएल गरीब वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही स्थिति राज्य के अन्य जिलों में भी है।

उक्त योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त की जाती है। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य के समस्त गरीब वृद्ध

व्यक्तियों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र वृद्धावस्था पेंशन प्रदान कर लाभान्वित करें, जिससे लाभान्वित वृद्ध व्यक्ति लाचारी से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

डा. चन्द्रशेखर बैद

(तारानगर)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या का निवारण करने बाबत

श्रीमान

अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। आज फुलेरा नगर, सांभर, जोबनेर, रेनवाल का आधा से ज्यादा कस्बा एवं 45 पंचायतों में लगभग 35 पंचायतें जलदाय विभाग के मापदण्डों के अनुसार डार्क जोन में है तथा फ्लोराइड की मात्रा 5.7 से लेकर 7.00 प्रतिशत से भी अधिक है। पानी की समस्या को लेकर फुलेरा के गांवों की जनता त्राह-त्राहि कर रही है। विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ अनेक बार मीटिंग कर पानी की समस्या का निराकरण करने की अनेक योजनायें बनवायी गयी परन्तु वह कागजी साबित हुई है। फुलेरा क्षेत्र के लिए दुदु को जोड़ते हुए बीसलपुर का पानी लाने की योजना लम्बित है। कार्य धीमी गति से चल रहा है यहां तक की पक्षपात पूर्ण एवं भेदभाव पूर्ण हो रहा है। दुदु में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत टेण्डर कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। फुलेरा में नहीं किया गया है क्यों नहीं किया गया है? इसका उत्तर अधिकारियों के पास नहीं है? मंत्री जी ही दे सकते है। फुलेरा एवं सांभर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 5.30 करोड़ की बोबास की योजना बनायी गयी स्वीकृत होने के बाद टेण्डर होने के बावजूद भी कार्य प्रगति पर नहीं है ना ही कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सेक्टर रिफार्म योजना, स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद योजनाएें आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। पानी के कुऐं सुख चुके हैं। टंकियां व पाइप लाइन आज तक नहीं डाली गयी है। शिकायतें करने के बावजूद ठेकेदारों को लाभ दिया गया परन्तु उन योजनाओं से पानी नहीं मिल पाया है। 500 से अधिक हैण्डपम्प स्वीकृत करने के बावजूद अधिकांश हैण्डपम्प सही स्थान पर नहीं लगाये गये। अपनी मनमानी से लगाये गये हैं। नकारा होकर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

हैण्डपम्प की योजना भी चौपट हो चुकी है 40 ट्यूबवैल लगाने के बावजूद पाइप लाइनों से नहीं जोड़ा गया है। आज मण्डाभीमसिंह, अणतपुरा, भदवा, भेसलाना, काजीपुरा, त्योद, नोरंगपुरा, त्येज्याकाबास, खण्डेल, जयसिंहपुरा, नान्दरी मुण्डोती, पचकोडिया, हिंगोनिया, करणसर, कालख, बबेरवालों की ढाणी, हरसोली, रामजीपुरा, छोटी डूंगरी, ईटावा, भदाल, रलावता, कुडियों का बास, जोरपुरा, सुन्दरियाबास, डहरा आदि ऐसी अनेक ग्राम पंचायतें हैं जिनकी पानी की समस्या जल्दी ही नहीं दूर की गई तो आने वाली गर्मी में जनता ओर भी त्राही करने लगेगी। सरकार का ध्यान इस और भी दिलाना चाहूंगा कि अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करवाना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। इस पर आवश्यक कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

नवरतन राजोरिया

(फुलेरा)

भीम राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं मंत्रालयिक कर्मचारियों के सृजित पदों को भरने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत में आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजकीय महा.वि. भीम में 7 विषय स्वीकृत हैं एवं सातों विषयों के व्याख्याताओं के पद भी स्वीकृत किये गये हैं। महा.वि. में 168 छात्र-छात्राऐं अध्ययनरत हैं। एवं 100 छात्र-छात्राऐं स्वयंपाठी के रूप में अध्ययनरत हैं। लेकिन अभी तक कॉलेज में केवल प्राचार्य के अलावा एक भी व्याख्याता एवं मंत्रालयिक कर्मचारी स्थाई रूप से कार्यरत नहीं है जिस की वजह से अध्ययनरत विद्यार्थीयों एवं प्राचार्य को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 मार्च से परीक्षाऐं भी प्रारम्भ होने जा रही हैं इधर महा. वि. का भवन निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। नया महा.वि. होने से पढ़ाई के साथ क. लेखाकार एवं अन्य कर्मचारी नहीं होने से प्रशासनिक कार्यो को करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष होने वाली परीक्षा केन्द्र भी भीम महा.वि. में ही रखा जाए कारण इस क्षेत्र के छात्र-छात्राऐं सभी गरीब परिवारों से है एवं भीम से अगर राजसमंद परीक्षा होती है तो भीम 110 कि.मी. हमेशा आना-जाना बड़ा

कठिन होगा जब कि परीक्षा केन्द्र पर चाही जाने वाली सभी फर्नीचर एवं अन्य सुविधाऐंें हमनें जन सहयोग से उपलब्ध करा रखी हैं एवं इस सम्बन्ध में उदयपुर खुवाडीया, यूनीवर्सिटी की कमेटी भी निरीक्षण कर चुकी है।

आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन सभी समस्याओं को मध्येनजर रखते हुए भी व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने या संविदा व्याख्ता यूजीसी के मापदण्डों की पूर्ति करते हैं जैसा कि संविदा डाक्टरों, नर्सिंग, शिक्षकों को नियमित किया उसी तरह संविदा व्याख्याताओं का नियमित कर दिया जाए तो छात्र-छात्राएं के भविष्य के हित में होगा। वर्तमान में इसी प्रकार कई राज. महा.वि. की तरह महा.वि. भीम में भी सभी विषयों में स्थाई व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं है। कालेज भवन आबादी से दूर होने के कारण एक रात्रि चौकीदार का पद सृजित किया जावे।

अतः निवेदन है कि तत्काल विभाग को निर्देशित कर परीक्षा केन्द्र भीम में खोलने एवं स्थाई व्याख्याताओं एवं कनिष्ठ लेखा एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं रात्रि हेतु चौकीदार का भी नया पद सृजित करा कर महा.वि. के विद्यार्थीयों को राहत दिलावें।

धन्यवाद।

हरीसिंह रावत

(भीम)

नगरपालिका एवं नगरपरिषद के चेयरमैन व नगर निगम के महापौर तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव मतदाताओं से सीधा ही करवाने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता स्थानीय निकायों तथा नगरपालिका के पार्षदों तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों का चुनाव इस उम्मीद से करती है वह प्रतिनिधि जनता की सेवा करते हुये अपने वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करवायेगा तथा आने वाली समस्या तथा लालफीताशाही से संघर्ष कर आमजन को राहत दिलायेगा। ठीक इसके विपरीत वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में यही चुने गये पार्षद/सदस्य अपने नेता अर्थात अध्यक्ष/महापौर/प्रधान/जिला प्रमुख का चुनाव करने में गलत

तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ताकतों का मोहरा बनकर रह जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावे के साथ-साथ अवांछित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन भी मिलता है।

ऐसी अवस्था में ईमानदार, मेहनती एवं सच्चे सेवकों को कार्य कराने व करने में काफी कठिनाइयां आती हैं जिसके परिणामस्वरूप आमजन को राहत दिलाने व क्षेत्र के विकास के जिस उद्देश्य से इनका चुनाव किया जाता है व व्यर्थ साबित होता दिखाई देता है। क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में इन चुने हुए पार्षदों/सदस्यों द्वारा ही अपने चेयरमैन/महापौर तथा प्रधान/जिला प्रमुख का चुनाव करना होता है जिसमें बाहुबली एवं धन्नासेठों द्वारा अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। जिसकी परिणिति आम जनता को दु:ख भोगने के रूप में होती है।

इस प्रकार धन्नासेठों द्वारा अध्यक्ष/महापौर/प्रधान/जिला प्रमुख का चुनाव जीतने पर अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा आमजन के कार्य नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि इन पूंजीपतियों द्वारा गलत तरीके अपनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाकर अध्यक्ष गिराने की मुहिम चलाई जाती है जिसके कारण वर्तमान चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के एक्ट में संशोधन के लिये एक कमेटी का भी गठन किया था उस कमेटी ने भी जरूरत के मुताबिक संशोधन कर राज्य सरकार को दो ढाई वर्ष पहिले अपनी अनुशंसा भेजी दी है।

अत: मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त बातों पर गौर फरमाकर नगरपालिका/नगर परिषद के अध्यक्ष तथा नगर निगम के महापौर एवं पंचायत समिति के प्रधान व जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव मतदाताओं से सीधे ही करने हेतु अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जावे ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके तथा विकास कार्य में तेजी लाई जा सके।

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

जहाजपुर महाविद्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं, जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्तमान में 15 उच्च माध्यमिक एवं 18 माध्यमिक स्तर के विद्यालय चल रहे हैं, किन्तु क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं होने के कारण इन विद्यालयों से उत्तीर्ण लगभग 500 छात्रों को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय तथा शाहपुरा स्थित महाविद्यालय में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जहाजपुर तहसील की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 186597 है जिसमें से भी 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार निवास करते हैं, जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर नहीं भेज सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। और इसी कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के छात्र आधुनिक तीव्र प्रतियोगिता के युग में उच्च एवं तकनीकी सेवाओं में चयन तो दूर की बात है भाग भी नहीं ले सकते हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के जहाजपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)